Impact Factor :
7.834

गीना देवी शोध संस्थान
द्वारा पटियाला, श्रीगंगानगर व नेपाल से प्रसारित
साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध का अंतर्राष्ट्रीय मासिक

ISSN : 2321-8037
Sept.-October 2025
Volume 13, Issue 9-10

Gina Shodh SANGAM

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

RESEARCH
EXAMINE
PROBE
SCAN
EXPERIMENTATION
KNOWLEDGE
PRACTICE
LINK
FACTS
THINK
SCIENCE
BOOK

Editor :
Dr. Rekha Soni

Chief-Editor :
Dr. Naresh Sihag Adv.

संस्थापक सम्पादिका :
स्मृति शेष
डॉ. विश्वकीर्ति

संगम SANGAM

बहुभाषिक बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

www.ginajournal.com

संस्थापक संरक्षक :
स्मृति शेष
श्री हरविन्द्र कमल चौधरी

वर्ष : 13 अंक : 9–10(2) सितम्बर–अक्टूबर : 2025 आईएसएसएन : 2321–8037

सम्पादक :
डॉ. रेखा सोनी
शिक्षा विभाग, टांटिया वि.वि.,
श्रीगंगानगर–335001 (राज.)

प्रधान सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
सचिव, गीना देवी शोध संस्थान,
भिवानी (हरियाणा)

मार्गदर्शन :
डॉ. राजेन्द्र गोदारा
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

डॉ. सुरजीत सिंह कस्वां
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

डॉ. लक्ष्मी जोशी
त्रिभुवन वि.वि. काठमाण्डू।

डॉ. सृष्टि चौधरी
लेक्चरर, इलेक्ट्रानिक्स
एंड कम्युनिकेशन,
सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर
गर्ल्स, पटियाला, पंजाब।

श्री श्रेष्ठ चौधरी,
सीनियर मैनेजर,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
साहिबजादा अजित सिंह नगर,
मोहाली, पंजाब।

कानूनी सलाहकार :
डॉ. रामफल दलाल एडवोकेट,
श्रीमती रूपिन्द्र कौर, एडवोकेट

सलाहाकार समिति (Advisory Committee)

डॉ. सुलक्षणा अहलावत
अंग्रेजी प्रवक्ता, शिक्षा विभाग
नूंह (हरियाणा)

डॉ. अरूणा अंचल
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,
रोहतक (हरियाणा)

डॉ. सुशीला
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी।

डॉ. अल्पना शर्मा
आईएएसई विश्वविद्यालय सरदारशहर

डॉ. विजय महादेव गाडे
बाबा साहेब चितले महाविद्यालय
भिलवडी (महाराष्ट्र)

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कॉलेज
धारवाड़ (कर्नाटक)

डॉ. रीना कुमारी
दशमेश गर्ल्स कॉलेज,
अल्ला बक्श, मुकेरिया, पंजाब।

श्री राकेश शंकर भारती
यूक्रेन।

श्री हेमराज न्यौपाने
नेपाल।

डॉ. ममता तनेजा
अबोहर, पंजाब।

डॉ. प्रियंका खंडेलवाल
बराण, राजस्थान।

डॉ. संदीप
ओम विश्वविद्यालय, हिसार।

प्रो. मधुबाला
राजकीय महिला महाविद्यालय, हिसार।

डॉ. पीयूष कुमार द्विवेदी
जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग
विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तरप्रदेश

डॉ. हवासिंह ढाका
राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

डॉ. मानसिंह दहिया
संस्कृत प्रवक्ता, शिक्षा विभाग हरियाणा

डॉ. राजेश शर्मा
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

डॉ. मोहिनी दहिया
माती जीतोजी कन्या महाविद्यालय,
सूरतगढ़ (राजस्थान)

डॉ. मुद्दस्सिर अहमद भट्ट
हिन्दी विभाग,
कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर, कश्मीर

डॉ. सीहेच वी. महालक्ष्मी
सीहेच एसडीएसटी थेरेसा महिला
महाविद्यालय, एलुरू, आंध्र प्रदेश

डॉ. मोरवे रोशन के.
यूनाईटिड किंगडम।

डॉ. अनुपमा, पूर्व प्रोफेसर,
अंकारा विश्वविधालय, अंकारा, टर्की

डॉ. आर.के विश्वास
अध्यक्ष होम्योपैथिक, टांटिया, वि.वि.

प्रकाशक, स्वामी एवं मुद्रक **डॉ. नरेश सिहाग**, एडवोकेट ने **मनभावन प्रिन्टर्ज**, पुराना बस स्टैण्ड रोड़, नया बाजार, भिवानी से छपवाकर 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी–127021 (हरियाणा) से जारी किया।

संगम SANGAM

बहुभाषिक बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

(Journal of Literature, Arts, Science, Commerece, Culture, Humanities and Social Sciences)

सचिव :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,
भिवानी-127021 (हरियाणा)
Email : grngobwn@gmail.com
मो. 09466532152

संगम मासिक पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं/लेखों की मौलिकता का दायित्त्व स्वयं रचनाकारों/लेखकों का है। उससे सम्पादक व प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायक्षेत्र केवल भिवानी (हरियाणा) होगा। सम्पादन और प्रबंधन के सभी पद पूर्ण रूप से अवैतनिक हैं।

Published by :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
202, Old Housing Board,
Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA
Email : grsbohal@gmail.com
Facebook.com/bohalshodhmanjusha
Website : www.bohalsm.blogspot.com
WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1300/-

Disclaimer :

1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdication only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

Impact Factor : 7.834
ISSN : 2321-8037
Gina Shodh
SANGAM
Peer Reviewed & Refereed Research Journal
International Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)
Publisher : Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

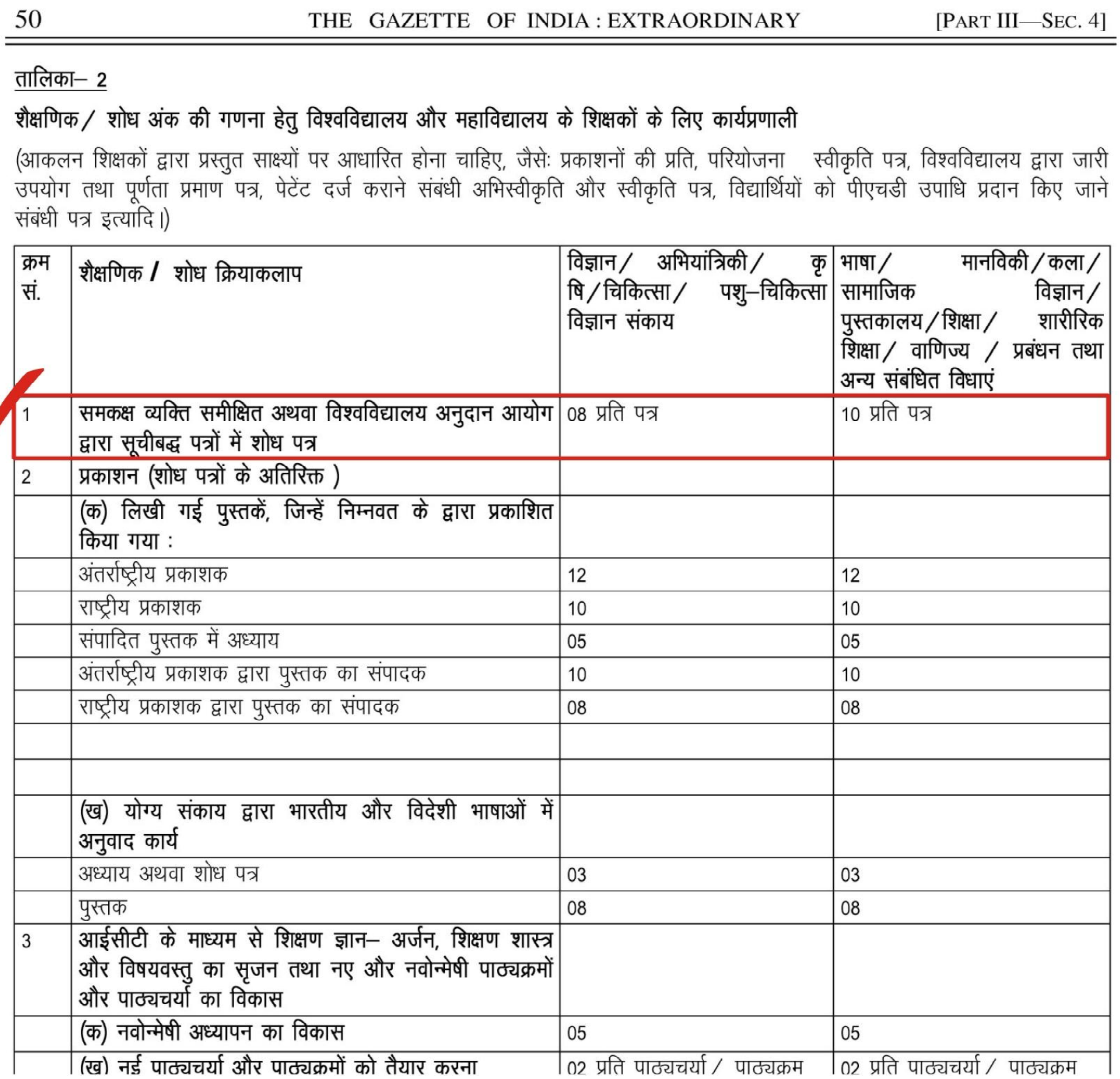

50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

तालिका– 2

शैक्षणिक/ शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसेः प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	**शैक्षणिक / शोध क्रियाकलाप**	विज्ञान/ अभियांत्रिकी/ कृषि/चिकित्सा/ पशु–चिकित्सा विज्ञान संकाय	भाषा/ मानविकी/कला/ सामाजिक विज्ञान/ पुस्तकालय/शिक्षा/ शारीरिक शिक्षा/ वाणिज्य / प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं
1	**समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र**	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र
2	**प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)**		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया :		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03
	पुस्तक	08	08
3	**आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान– अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास**		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या/ पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या/ पाठ्यक्रम

अनुक्रमाणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. रेखा सोनी	07–07
2.	हिन्दी पत्रकारिता के लोकनायक मुंशी प्रेमचंद	डॉ. मरजीना, मो. आरिफ अंसारी	08–11
3.	सतत् वृद्धि एवं विकास में पंचायती राज की भूमिका (दक्षिणी राजस्थान के संदर्भ में)	डॉ. विशाल चौबीसा	12–14
4.	प्रगतिशील चेतना और नारी अस्मिता के संदर्भ में सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कहानियों का अध्ययन	डॉ. सुमंगला वशिष्ठ	15–18
5.	भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन के विचारों का महत्व	रूपकला माधुरी खलखो	19–22
6.	मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समकालीन हिंदी कथा साहित्य का मूल्यांकन	डॉ. अफीफा फातिमा शेक	23–26
7.	असमीया अभिनय कला के गीतों में राग प्रधान गीतों की परंपरा	डॉ. अनिरुद्ध वायन	27–34
8.	संसदात्मक शासन पद्धति के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री की भूमिका	प्रो. डॉ. मन्जू सोलंकी, सुधीर कुमार	35–41
9.	हिंदी कहानी और आलोचना और नामवर सिंह	डॉ. हरिकृष्ण आचार	42–47
10.	**Assessing the Role of Uttar Pradesh Government Poised to Become a US$1 Trillion Economy : A Qualitative Analysis**	**Dr. Prashant Singh, Sejal Jaiswal**	**48-58**
11.	पंजाब के साहित्यकारों द्वारा रचित आदिवासी लेखन में समाज	अनीता रानी	59–63
12.	दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक दर्शन का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में योगदान	डॉ. सुनीता शर्मा	64–67
13.	प्रवासी हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श	अलका शर्मा	68–70
14.	राजनीति का दलित पक्ष और शिवमूर्ति : संदर्भ बनाना रिपब्लिक	प्रियंका श्रीवास्तव	71–76
15.	**Regional Political Parties in India : Balancing Local Interests and National Integration**	**Mamta Goutam**	**77-83**
16.	**A Socio-Legal Analysis of Female Foeticide in India : Unraveling the Roots, Re-evaluating the Laws, and Re-imagining the Future**	**Dr. Kamal**	**84-90**
17.	डॉ. सुशील कुमार फुल्ल के उपन्यासों में नारी विमर्श के आयाम	परमजीत सिंह डॉ. अजयपाल सिंह	91–102

18.	The Soundscape of Migration: Audio, Memory and Place-Making among New Urban Residents in Agra City	Dr. Arvind Kumar Gupta	103-118
19.	Green Schooling – A Healthy School Environment	Dr. Manoj Kumar Tyagi	119-122
20.	Sustainable Learning : Navigating the Tensions of Digital Ecology in Future-Ready Classrooms	Dr. Anuradha Aggarwal	123-127
21.	संस्कृत साहित्य में काव्य के प्रयोजन	Kalpanabahen Sangada	128-133
22.	To Study the Impact of Gamification on Student's Memory and Cognitive Development in Jind District Public School	Anu Rani, Dr. Rajpal Singh Yadav	134-141
23.	Education and Social Security: A Comparative Analysis of Rural Population in Varanasi Division, Uttar Pradesh, India	Alok Kumar Rai, Dr. Vivek Kumar Jaiswal	142-151
24.	Postcolonial Hybridity and Cultural Identity in The God of Small Things by Arundhati Roy	Dr. Mala Srivastava	152-160
25.	US Tariff Policies and Their Global Repercussion : A study of Trade Diversion and Realignment in Asia and Europe	Pro. Dr. Neetu Singh	161-168
26.	Exploring the role and Impact of Artificial Intelligence on the Retail Industry	Hema Verma	169-174
27.	नरेन्द्र कोहली के दीक्षा उपन्यास के परिपेक्ष्य में सांस्कृतिक अध्ययन	जोगिन्द्र कुमार	175–180
28.	क्षेत्रीय एकता को सुदृढ़ करने में सांस्कृतिक कूटनीति की भूमिका : सार्क के परिप्रेक्ष्य में	धर्मेन्द्र कुमार	181–186
29.	कुमारसम्भव में प्रकृति चित्रण	हिमांशु कुमार	187–192
30.	कबीर के साहित्य में सामाजिक चेतना	डॉ. बाल किशोर राम भगत	193–199
31.	उषा प्रियंवदा के कथा साहित्य में नारी के प्रति दृष्टिकोण	भारती अग्रवाल, डॉ. हुसैनी बोहरा	200–206
32.	परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मूल्यों का अध्ययन	डॉ. दया कुमारी	207–214
33.	रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित 'संस्कृति के चार अध्याय' के ऐतिहासिक रूप के तात्विक विवेचना	डॉ. सीमा कुमारी	215–227
34.	हिन्दी उपन्यासों में 'किसान विमर्श'	हेमचंद साहू	228–232

सम्पादक की कलम से......

प्रिय पाठको,

आपके हाथों में गीना शोध संगम का यह सितम्बर–अक्टूबर अंक प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। किसी भी पत्रिका का अस्तित्व तभी सार्थक होता है जब वह समाज, संस्कृति और शिक्षा जगत के प्रासंगिक प्रश्नों पर विचार–विमर्श का मंच बन सके। यही कारण है कि गीना शोध संगम के प्रत्येक अंक को हम केवल प्रकाशन नहीं, बल्कि शोध और चिंतन की सामूहिक यात्रा मानते हैं।

वर्तमान समय में शिक्षा, साहित्य, समाज और संस्कृति अनेक नई चुनौतियों से गुजर रहे हैं। तकनीकी प्रगति के साथ जहाँ अवसरों के नए आयाम खुले हैं, वहीं मानवीय संवेदनाओं का क्षरण और पर्यावरणीय असंतुलन भी एक गंभीर प्रश्न बनकर सामने आया है। ऐसे में शोध की दिशा केवल अकादमिक दायरे तक सीमित न रहकर समाज की जमीनी सच्चाइयों को भी छूनी चाहिए। इस अंक में प्रकाशित लेखों और शोध आलेखों में इन्हीं प्रश्नों पर गंभीर विमर्श किया गया है।

साहित्य के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा हमें यह सिखाती है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति की धरोहर भी है। इस अंक में शामिल लेख साहित्य की सामाजिक भूमिका पर विशेष प्रकाश डालते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े आलेख नई शिक्षा नीति, शोध की संभावनाओं और उच्च शिक्षा में अंतःविषयक दृष्टिकोण को उजागर करते हैं।

हमारे लेखकगण और शोधार्थियों ने जिस मनोयोग से अपने विचार साझा किए हैं, वह इस पत्रिका की सबसे बड़ी पूँजी है। हम यह मानते हैं कि गीना शोध संगम केवल शिक्षाविदों या शोधकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए है जो समाज, संस्कृति और मानवता के भविष्य को लेकर गंभीर चिंतन करना चाहते हैं।

अंत में, हम अपने सभी योगदानकर्ताओं, पाठकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हैं। आपकी सहभागिता और विश्वास ही हमें नित नए विषयों पर विचार करने और शोध संगम को निरंतर समृद्ध बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमें आशा है कि यह अंक आपको विचारों की नई दिशा देगा और शोध की यात्रा में मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

अंत में, हम अपने सभी योगदानकर्ताओं, पाठकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हैं। आपकी सहभागिता और विश्वास ही हमें नित नए विषयों पर विचार करने और शोध संगम को निरंतर समृद्ध बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमें आशा है कि यह अंक आपको विचारों की नई दिशा देगा और शोध की यात्रा में मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

सादर!

–संपादक मंडल

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 8–11
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

हिन्दी पत्रकारिता के लोकनायक मुंशी प्रेमचंद

डॉ. मरजीना,
शोध पर्यवेक्षक एवं विभागाध्यक्ष, हिन्दी

मो. आरिफ अंसारी,
शोधार्थी, हिन्दी विभाग

कला संकाय, मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय, जोधपुर।

सारांश :–

कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी का विस्तार केवल साहित्य तक सीमित न रखते हुए पत्रकारिता को भी सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का एक सशक्त माध्यम बनाया। 'हंस', 'जागरण', 'माधुरी', 'मर्यादा' और 'चाँद' जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता को सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय जागरण और साहित्यिक उन्नति के एक शक्तिशाली मंच के रूप में स्थापित किया। उनकी पत्रकारिता का मूल ध्येय समाज को जागरूक करना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और उच्च कोटि के साहित्य को आमजन तक पहुँचाना था। 'हंस' के संपादन काल में उन्होंने गरीबी, जातिगत भेदभाव, स्त्री शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन जैसे ज्वलंत मुद्दों को प्राथमिकता दी। 'जागरण' के माध्यम से उन्होंने किसानों और श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध एक वैचारिक संघर्ष छेड़ा। प्रेमचंद की पत्रकारिता की भाषा अत्यंत सरल, प्रभावशाली और व्यंग्यात्मक थी, जिसमें लोकोक्तियों और मुहावरों का सहज प्रयोग होता था। उनके संपादकीय लेखों ने न केवल तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक विसंगतियों को उजागर किया, बल्कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभाषा के विकास में भी अमूल्य योगदान दिया। महात्मा गाँधी के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने 'हंस' को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाया। गंभीर आर्थिक संकटों और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद, प्रेमचंद ने पत्रकारिता के माध्यम से नैतिक मूल्यों और सामाजिक परिवर्तन की मशाल जलाए रखी। उनकी लेखनी ने हिन्दी पत्रकारिता को एक नई दिशा प्रदान की।

मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्धि मुख्य रूप से एक उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में है, लेकिन पत्रकारिता के साथ भी उनका एक अटूट संबंध था। प्रेमचंद ने न केवल कथा साहित्य के माध्यम से बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक अमिट छाप छोड़ी हिन्दी साहित्य के अन्य रचनाकारों की भाँति उन्होंने भी पत्रकारिता को सामाजिक जागरूकता और वैचारिक परिवर्तन का एक प्रभावी उपकरण बनाया। प्रेमचंद के समग्र लेखन में राष्ट्रीयता और समाज सुधार का स्वर प्रमुखता से मुखर है, किंतु 'हंस' और 'जागरण' जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय चेतना को प्रज्वलित करने में एक ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया।

प्रेमचंद ने अपनी कलम को सामाजिक अन्याय, शोषण, आर्थिक असमानता और औपनिवेशिक दासता के विरुद्ध एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। वे हिन्दी पत्रकारिता की उस प्रगतिशील धारा के ध्वजवाहक थे, जो

साहित्य और समाज सुधार को अपने मूल दायित्व के रूप में देखती थी। उनके संपादकीय और लेखों में उस पत्रकारिता का आदर्श स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है, जो जनसाधारण की समस्याओं को अपने विमर्श के केंद्र में रखती है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और यह स्थापित करते हैं कि पत्रकारिता का कार्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करना भी है। मुंशी प्रेमचंद ने 'माधुरी', 'मर्यादा', 'हंस' और 'जागरण' जैसी पत्रिकाओं का कुशलतापूर्वक संपादन किया तथा मासिक एवं साप्ताहिक पत्रकारिता में नवीन मानक स्थापित किए।

प्रेमचंद की स्वतंत्र पत्रकारिता का आरंभ 1903 ईस्वी में हुआ और यह यात्रा 1930 में 'हंस' के प्रकाशन के साथ अपने शिखर पर पहुँची। इस लंबी अवधि में उन्होंने अनगिनत पत्र पत्रिकाओं के लिए लेख, संपादकीय और समीक्षाएँ लिखीं। उन्होंने स्वयं को केवल साहित्यिक लेखन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी निर्भीकता से अपनी कलम चलाई। प्रेमचंद ने 'हंस', 'माधुरी', 'मर्यादा' और 'जागरण' जैसे प्रकाशनों में नियमित लेखन और संपादन करते हुए समाज, राजनीति और संस्कृति से जुड़े गंभीर विषयों पर अपने प्रगतिशील विचार प्रस्तुत किए।

प्रेमचंद की आरंभिक साहित्यिक यात्रा को आकार देने में 'जमाना' पत्रिका का योगदान अविस्मरणीय है। पत्रिका के संपादक, दयानारायण निगम, ने प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों को प्रकाशित कर उन्हें प्रोत्साहित किया, जिसके कारण इस पत्रिका से उनका एक विशेष लगाव बना रहा। पत्रकारिता जगत में उनके प्रवेश के पीछे कई कारक थे, जिनमें उनकी आर्थिक विवशताएँ भी एक प्रमुख पहलू थीं।

अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रेमचंद ने अपनी 'सरस्वती प्रेस' की स्थापना की। वर्ष 1927 में उन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'माधुरी' के संपादन का दायित्व ग्रहण किया। इसके व्यवस्थापक विष्णुनारायण भार्गव ने संपादकीय मंडल में परिवर्तन करते हुए प्रेमचंद और कृष्णबिहारी मिश्र को संयुक्त संपादक नियुक्त किया। प्रेमचंद ने इस भूमिका को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। एक स्वतंत्र संपादक के रूप में कार्य करने की उनकी प्रबल इच्छा ने उन्हें एक नई पत्रिका आरंभ करने के लिए प्रेरित किया। वे अपनी पत्रिका को 'माधुरी' नाम देना चाहते थे, किंतु यह नाम विष्णुनारायण भार्गव के अधीन होने के कारण संभव नहीं हो सका। इसी समय, जयशंकर प्रसाद ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए पत्रिका का नाम 'हंस' रखने का सुझाव दिया। परिणामस्वरूप, मार्च 1930 में 'हंस' का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ, जो हिन्दी साहित्य को एक नई दिशा देने का ऐतिहासिक प्रयास था। इस पत्रिका का संपादन स्वयं प्रेमचंद लखनऊ से करते थे, जबकि इसके प्रकाशन और प्रबंधन की जिम्मेदारी बनारस में प्रवासीलाल वर्मा संभालते थे। 'हंस' के अस्थायी रूप से बंद होने के बाद, प्रेमचंद ने साप्ताहिक पत्र 'जागरण' का अधिग्रहण कर लिया। 22 अगस्त, 1932 को 'जागरण' का पहला साप्ताहिक अंक प्रेमचंद के संपादन में निकला।

अक्टूबर, 1935 में 'हंस' ने भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि पत्र के रूप में अपनी यात्रा का एक नया अध्याय आरंभ किया। इस नवीन कलेवर में 'हंस' के संपादक मंडल में प्रेमचंद के साथ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भी शामिल हुए, जिससे पत्रिका को एक नई वैचारिक ऊर्जा मिली। इस अंक में महात्मा गाँधी का एक विशेष संदेश भी प्रकाशित किया गया, जिसने पत्रिका के उद्देश्य और महत्व को रेखांकित किया। इसमें बड़े अक्षरों में गाँधी जी का संदेश छपा था कि ''हंस' हिंदुस्तान भर में अनोखा प्रयत्न है। यदि हिन्दी अथवा हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा

बनाना है तो ऐसे मासिक की आवश्यकता है।'' प्रेमचंद ने 'हंस' का संपादन करते हुए हिन्दी की मासिक पत्रिकाओं के संपादन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। उनके द्वारा किया गया संपादन न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने हिन्दी पत्रकारिता में भी एक मापदंड स्थापित किया।

प्रेमचंद की पत्रकारिता का मूल लक्ष्य समाज में व्याप्त विषमता, शोषण और अन्याय के विरुद्ध एक सशक्त वैचारिक अभियान चलाना था। उन्होंने अपने लेखों और संपादकीय के माध्यम से किसानों, मजदूरों, महिलाओं और समाज के अन्य शोषित वर्गों की पीड़ा को वाणी दी। उनकी पत्रकारिता पर राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और नैतिक मूल्यों का गहरा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने अपनी लेखनी से सोए हुए समाज को जगाने और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने का अथक प्रयास किया। प्रेमचंद की पत्रकारिता की शैली सहज, स्पष्ट और अत्यंत प्रभावी थी। उन्होंने गूढ़ विषयों को भी सरल और सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया।

प्रेमचंद ने पत्रकारिता के माध्यम से समाज में व्याप्त छुआछूत, जातिवाद, बाल विवाह, दहेज प्रथा और स्त्री शोषण जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। वह 'हंस' के मई, 1932 में प्रकाशित संपादकीय में लिखते हैं ''जाति के बंधन इस कल कारखानों के युग में बहुत दिन तक नहीं रह सकते। अब भी लोग होटलों में खाने नहीं जाते, कहीं बाहर भी जाते हैं, तो मित्रों या संबंधियों के घर ठहरते हैं, लेकिन राष्ट्रीयता इन भावो को तोड़े डालती है।''[1] उन्होंने अपने लेखों और संपादकीय टिप्पणियों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गहराई से प्रभावित किया और जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का प्रयास किया। 'स्वदेश' के 1918 में प्रकाशित अंक के संपादकीय 'स्वदेश का संदेश' में लिखते हैं ''हिन्दुस्तान का उद्धार हिन्दुस्तान की जनता पर निर्भर है। जनता में अपनी योग्यता के अनुसार यह भाव पैदा करना प्रत्येक स्वदेशवासी का परम धर्म है। स्वदेश तुम्हें संदेश दे रहा है कि तुम भी मनुष्य हो, तुमको भी ईश्वर के यहां से समान अधिकार प्राप्त हैं। तुममें भी उन्नति करने की, गौरवशाली बनने की शक्ति मौजूद है। उठो उससे काम लो। यह आलस्य छोडो, हिम्मत मजबूत करो और परमात्मा तुम्हारे सहायक होंगे।''[2]

किसानों पर महाजनों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। 'जागरण' में 2 जुलाई 1933 को प्रकाशित अपने संपादकीय में लिखते हैं ''हम यह नहीं कहते कि हमारे सामाजिक जीवन में महाजन का कोई स्थान नहीं है और न यह कि उससे जनता का कोई उपकार नहीं होता, मगर अभी महाजनों को अपने असामियों पर अत्याचार करने की जो कानूनी सुविधाएं प्राप्त हैं, उसमें कुछ कमी होने की परम आवश्यकता है। सूद की कोई सीमा होनी चाहिए और उसका कुछ दर भी निश्चित होना चाहिए। अभी तो यह हाल है कि किसानों से मूल का कई गुना ब्याज में वसूल कर लिया जाता है फिर भी मूल ज्यों का त्यों बना रहता है।'' उन्होंने अपने लेखों और संपादकीय टिप्पणियों के माध्यम से साहित्य और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को गहराई से विश्लेषित किया। अपने प्रसिद्ध लेख 'साहित्य का उद्देश्य' जो 'हंस' के जुलाई 1936 के अंक मे प्रकाशित हुआ था। इसमें लिखते हैं ''भाषा बोलचाल की भी होती है और लिखने की भी। बोलचाल की भाषा ता मीर अम्मन और लल्लूलाल के जमाने में भी मौजूद थी पर उन्होंने जिस भाषा की दाग बेल डाली, वह लिखने की भाषा थी और वही साहित्य है। बोलचाल से हम अपने करीब के लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं अपने हर्ष, शोक के भावों का चित्र खींचते हैं। साहित्यकार वही काम काम लेखनी द्वारा करता है। हां, उसके श्रोताओं की परिधि बहुत विस्तृत होती है, और अगर उसके बयान में सचाई है, तो शताब्दिया और युगों तक उसकी

रचनाएं हृदयों को प्रभावित करती रहती हैं।''[3]

उनकी पत्रकारिता की शैली की विशेषता उसकी सरलता, स्पष्टता और प्रभावशीलता है, जो पाठक के मन पर सीधा असर करती है। 'एक ओर प्रेमचन्द उर्दू से हिन्दी में आये थे, दूसरी ओर उनका सम्बन्ध आर्य समाज और गांधी की राष्ट्रीयतावादी चिन्तन पद्धति से था। सबने मिलाकर उन्हें भाषाविषयक जो चिन्तन दिया उससे प्रेमचन्द हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी के स्वरूप पर हो विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए बल्कि उनमें अंतरंग सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी वे प्रयत्नशील हुए और सारे प्रश्न को उन्होंने सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय भूमिका को कसौटी मानकर परखा। इस कार्य में वे एक ओर हिन्दू और मुसलमान के विभेद अथवा प्रादेशिक भाषाओं के द्वारा खींची गई सीमा रेखाओं से उत्पन्न देश विभाजन की शंका से आकुल हुए तो दूसरी ओर उनकी दृष्टि में अंग्रेजी की उपस्थिति भी राष्ट्रभाषा के विकास में बाधक तत्त्व के रूप में खटकती रही।'[4] प्रेमचंद ने अपने लेखों में भाषा, शब्द चयन, वाक्य विन्यास और विषय वस्तु की प्रस्तुति में एक अद्‌भुत संतुलन स्थापित किया, जो उनकी पत्रकारिता को अद्वितीय बनाता है। उनकी शैली में व्यंग्य, समालोचना और मार्मिकता का अद्‌भुत समन्वय देखने को मिलता है, जो पाठकों को आत्म मंथन के लिए विवश करता है। प्रेमचंद की पत्रकारिता की शैलीगत विशिष्टताएँ न केवल उनके साहित्यिक कौशल को प्रमाणित करती हैं, बल्कि उनकी गहरी सामाजिक और नैतिक प्रतिबद्धता को भी उजागर करती हैं।

उनकी पत्रकारिता का परम ध्येय सदैव जनहित का संवर्धन करना था, और इस आदर्श की पूर्ति के लिए उन्हें बार–बार गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद, प्रेमचंद अपने पथ से कभी विचलित नहीं हुए और पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी रखा। उनका यह अटूट समर्पण और निष्ठा पत्रकारिता के प्रति उनके असीम अनुराग को प्रमाणित करता है। प्रेमचंद का यह योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा, क्योंकि उनकी पत्रकारिता ने न केवल समाज को जागृत किया, बल्कि हिन्दी पत्रकारिता को एक नई नैतिक और वैचारिक पहचान भी प्रदान की।

संदर्भ –

1. प्रेमचंद रचनावली–8, पृ0 115
2. प्रेमचंद रचनावली–8, पृ0 17
3. प्रेमचंद रचनावली–7, पृ0 500
4. प्रेमचंदः एक सिंहवालोकन, प्रा0 ह0 श्री0 साने, पृ0 112

मो0 : 9411218242

ईमेल : arif.mcj@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 12–14
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

सतत् वृद्धि एवं विकास में पंचायती राज की भूमिका (दक्षिणी राजस्थान के संदर्भ में)

डॉ. विशाल चौबीसा
सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नयागांव खेरवाड़ा, राजस्थान।

संक्षिप्तीकरण (Abstract)

भारत गांवो का देश है। जहां 75 % जनसंख्या गांवो में निवास करती है। अतः गांवों की उन्नति एवं प्रगति पर ही भारत की उन्नति एवं प्रगति निर्भर करती है। गांधीजी ने एक बार कहा था की " यदि गांव नष्ट होते है तो भारत नष्ट हो जाएगा, वह भारत नहीं होगा, विश्व में उसका संदेश समाप्त हो जायेगा।" पंचायते ही हमारे राष्ट्रिय जीवन की रीढ है। दिल्ली के सांसद भवन में कितने ही बडे आदमी बैठे हो लेकिन असल में पंचायत ही भारत की चाल बनाएगी। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां अधिकांश समय राजा महाराजाओ का शासन रहा है आम जनता को अपना शासन चलाने के अधिकार देना अति–आवश्यक है।

उद्धेश्य (Objectives) :– (1) पंचायतीराज से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों मुददो और कार्यप्रणाली का अध्ययन करना। (2) पंचायतीराज के कारण सामाजिक–आर्थिक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना। (3) पंचायतो में जनसहभागिता में वृद्धि एवं कमी के कारणों को जानना। (4) दक्षिणी राजस्थान में पंचायती राज की आवश्यकता पर प्रकाश डालना।

परिकल्पना (Hypothesis) :– पंचायतीराज को बहुत सारे कारण जैसे समुह, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, चुनाव, स्थानीय राजनीति और सामाजिकताना जैसे कारण प्रभावित करते है।

शौध प्रविधि (Methodology) :– यह द्वितियक आंकडो पर आधारीत शौध है, जो मुख्यतः राजस्थान की पंचायती व्यवस्था का विश्लेषणात्मक विश्लेषण करेगा। शौध नियमों के अनुसार प्रस्तुत शौध सैद्धान्तिक, विश्लेष्णात्मक, तुलनात्मक एंव नवीन व्यवहारिक पद्धतियों को अपनाते हुए शौध लेख को मौलिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस शौध हेतु आवश्यक सामग्री विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय पूस्तकालयों, इन्टरनेट एवं शौध संस्थाओं आदि में उपलब्ध साधनों के अलावा प्राचीन सन्दर्भ राज्यों से एकत्र किया जाना अनुमान्य है। इस सन्दर्भ आधारीत पूस्तकों के अलावा विभिन्न आयोग के प्रकाशनों, आत्मलेखों, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, राजनीतिक दलों के घोषणा–पत्रों एवं राजनेताओं के भाषण इत्यादी से लेखन सामग्री संपादित कर विश्लेषणात्मक अध्ययन है।

Keywords – महिलाएं पंचायतीराज संस्थाएं, जनसहभागीता, जागरूकता, सरकारी,

प्रस्तावना :

भारत मे ग्राम पंचायतो का इतिहास बहूत पुराना है। इसी पूर्व भारत मे ग्राम पंचायते थी उस समय ग्राम पंचायत का मुखिया ग्रामत्रि कहलाता था। इसके बाद मौर्य शासन मे भी गाव का शासन ग्राम सभा द्वारा ही होता था । जिसका प्रमूख ग्रामिक कहलाता था दक्षिण भारत मे चौल शासको द्वारा ग्राम पंचायतो को सुदृढ बनाने मे महत्वपूर्ण भुमिका का निर्वाह किया गया। वही मुगलकाल मे भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही थी जिसका प्रबंध पंचायतो द्वारा किया जाता था। जिसका मुखिया मुकदम कहलाता था। प्राचीन समय मे आपसी झगडो का फेसला पंचायते ही करती थी। परन्तू अंग्रेजी राज के जमाने मे पंचायते धीरे–धीरे समाप्त हो गई । परन्तु उस समय भी लार्ड रिवन जिसे भारत मे स्थानिय स्वशासन का पिता कहा जाता है।

भारत में सर्वप्रथम 1882 में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। राजस्थान में बीकानेर पहली देशी रियासत थी, जहां 1928 ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतो को वैधानिक दर्जा दिया गया। पं. जवाहरलाल नेहरू एवं महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के पक्के हिमायती थे। नेहरूजी ने एक बार कहा था कि " गांवो के लोगो को अधिकार सोंपना चाहिए, इनको काम करने दे, चाहे वो हजारो गलतियां करे, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पंचायतो को अधिकार दो।" प्रौ. रजनी कोठारी के अनुसार " राष्ट्रिय नेतृत्व का यह दूरदर्शिता पूर्ण कार्य था, जो उन्होने पंचायती राज की स्थापना की। इससे भारतीय राजव्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है, और देश में एक सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उनकी एकता भी बढ रही है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज के लिए प्रयास :–

नेहरूजी का लोकतंत्र में अटुट विश्वास था। इसलिए जब संविधान निर्माण हुआ तो अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतो के गठन का निर्देश दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने भारत के ग्रामीण विकास में नागरीकों की सहभागिता के लिए अमेरिका के " ब्लॉक मॉडल " को भारत में अपनाया, और 1952 में सामुदायिक विकास प्रारम्भ किया। परन्तु यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सका क्योंकि गांव की जनता नें इसे अपना कार्यक्रम न मानकर मात्र एक सरकारी योजना या कार्यक्रम समझा, और वह इससे दूर ही रहे। इसकी कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए त्वरीत ग्रामीण विकास के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम एवं व्यवस्था पर विचार–विमर्श के लिए भारत सरकार ने बलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता में 1956 में एक समिति का गठन किया, जिसकी सिफारीशों को मानते हुए राज्यों को इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा गया। सर्वप्रथम आन्ध्र प्रदेश में प्रयोग के विचार से अगस्त 1958 में इसके कुछ भागों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण लागु किया गया। 2 अक्टुबर 1959 में प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से इसका श्री गणेश किया।
अमेरिकी लेखक रेनहार्ड बैडिक्स लिखते है कि " सामुदायिक विकास की सबसे बडी कमजोरी उसका सरकारी स्वरूप और नेताओं की लफाजी है। एक तरफ इस कार्यक्रम के सूत्रधार जनता के आगे आशा करते थे दूसरी और उनका विश्वास था कि सरकारी कार्यवाही से ही नतीजा निकल सकता है। कार्यक्रम जनता को चलाना था परन्तु वे बनाये उपर से जाते थे।
बलवन्त राय मेहता समिति ने ही सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, उन्होने प्रथम स्तर पर ग्राम पंचायत द्वितिय स्तर पर तहसील तथा सबसे उपर जिला परिषद की अनुशंसा की थी । इसके उपरान्त

1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसका मूल उद्येश्य यही था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर उसे संस्थागत रूप प्रदान किया जायें। इस समिति में जिला परिषद को मजबुत बनाने तथा द्वि–स्तरीय संघठन के निर्माण की अनुशंसा की। जिसने जिले को विकेन्द्रीकरण की धुरी मानकर जिला परिषद को समस्त कार्यो का केन्द्र बिन्दु मानने की सलाह दी। 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति गठित की गयी , जिसकी मुख्य सिफारिश ही यही थी कि पंचायती राज संस्थाओ को संविधान के अर्न्तगत सरकार का तृतीय स्तर घोषित किया जायें , और इस हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोडा जायें।

इस प्रकार कालकम के अनुसार देखा जाये तो भले ही 1959 से 1964 तक इसका उत्थानकाल 1965 से 1969 तक ठहरावकाल एवं 1969 से 1983 तक की कार्यअवधि ह्रासकाल कहा जाता है। इसका कारण यह था कि लम्बे समय तक इन पंचायती राज संस्थाओ में चुनाव ही नहीं करवाये गये थे। और इसे शासन का अनावश्यक अंग समझा गया। सबसे प्रमुख बात तो इनके पास वित्त का अभाव था। इनका कोई संस्थागत आधार नहीं था।

73 वां संविधान संशोधन एवं उसके बाद :–

सन् 1988 में पी.के.थुंगन समिति का गठन करके पंचायतीराज व्यवस्थाओं पर पुनः विचार किया गया। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाए। समिति की सिफारीशों को मान्यता देने के लिए 1989 में 64 वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। परन्तु यह विधेयक राज्य सभा द्वारा नामंजुर कर दिया गया। दिसम्बर 1992 में 73 वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ और 25 अप्रेल 1993 में इसे कियान्वित किया गया। पंचायत व्यवस्था के संबंध में प्रावधान संविधान के भाग 9 में है, जिसमें 16 अनुच्छेद शामिल किये गये है। अनुच्छेद 243 (ख) त्रि–स्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर, तथा जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जायेगा। परन्तु मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, जम्मु कश्मीर,दिल्ली राष्ट्रिय राजधानी क्षैत्र व मणिपुर के कुछ पहाडी क्षैत्रो को छोडकर संपूर्ण देश में लागु हो गया है। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातिय एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था चकानुकम में की गयी है। जिस राज्य में जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां पर मध्यवर्ती स्तर का होना जरूरी नहीं है। सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षैत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरे जायेंगे। जिनका कार्यकाल पांच वर्ष होगा। निर्वाचन के लिए एक अलग से राज निर्वाचन आयोंग का गठन किया जायेगा । पंचायतो की वित्तिय स्थिति निरक्षण के लिए एक वित्त आयोग का गठन भी किया जायेगा। इसलिए 11 वी अनुसूची में 29 विषयों को रखा गया है जिस पर पंचायत विधि बना कर कार्य कर सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारतीय शासन एवं राजनीति– डॉ पुखराज जैन।
2. राजनीतिक विज्ञान एक समग्र अध्ययन–राजेश मिश्र।
3. भारतीय शासन एवं राजनीति–एस.एस. नारंग।
4. भारतीय राजव्यवस्था, एम. लक्ष्मीकांत।

मोबाईल नं. 9001252758

ई मेल : dr.vishalchobisa@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 15–18

प्रगतिशील चेतना और नारी अस्मिता के संदर्भ में सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कहानियों का अध्ययन

डॉ. सुमंगला वशिष्ठ
एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, डी. एन. कॉलेज, हिसार (हरियाणा)

सारांश :–

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' हिंदी साहित्य के उन विरल सर्जकों में हैं जिन्होंने अपने लेखन से समाज के यथार्थ को नई दृष्टि प्रदान की। वे केवल कवि नहीं, बल्कि गहन संवेदना वाले कथाकार भी थे। उनकी कहानियाँ समाज में व्याप्त अन्याय, विषमता और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध करुणा और प्रतिरोध की सशक्त आवाज हैं। निराला ने कहानी को भावनात्मकता से ऊपर उठाकर विचार, संवेदना और यथार्थ के स्तर पर प्रतिष्ठित किया। उनकी कहानियों में दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ उभरकर आती हैं– प्रगतिशील चेतना और नारी अस्मिता का बोध। यह शोधपत्र इन्हीं दो धाराओं के विश्लेषण पर केंद्रित है। निराला का कथा–संसार यह सिखाता है कि साहित्य केवल विचार का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का उपकरण भी है।

बीज शब्द :– प्रगतिशील चेतना, नारी अस्मिता, समाज–यथार्थ, मानवीयता, संवेदना, समानता, कहानी।

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने शब्द को समाज की आत्मा से जोड़ा। यद्यपि उन्हें मुख्यतः कवि रूप में जाना जाता है, परंतु उनकी कहानियों ने भी हिंदी गद्य साहित्य को नई दिशा दी। निराला का समय भारतीय समाज में तीव्र परिवर्तन का युग था। औपनिवेशिक सत्ता, आर्थिक शोषण, सामंती मानसिकता और स्त्री की दयनीय स्थिति कृ ये सभी उस युग की सामाजिक वास्तविकताएँ थीं। ऐसे दौर में साहित्यकारों के समक्ष यह चुनौती थी कि वे समाज में उठते प्रश्नों को स्वर दें। निराला ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी कहानियों में उन मौन जनों को आवाज दी, जो प्रायः मौन रखे जाते थे। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ – 'कुल्ली भाट', 'संपत्ति', 'सुकुल की बीवी', 'प्रेमी', 'महाभारत का एक अंश' आदि– इस तथ्य की साक्षी हैं कि वे केवल घटनाएँ नहीं, बल्कि मानवीय चेतना का गहन चित्र रचते हैं। निराला का लेखन केवल कला के लिए कला नहीं, बल्कि समाज के लिए कला का उदाहरण है। वे मनुष्य के भीतर छिपे संघर्ष को पहचानते हैं और उसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्त करते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें आदर्शवादी भावुकता से अलग करता है और उन्हें सामाजिक यथार्थवाद का प्रतिनिधि बनाता है। उनकी कहानियों में व्यक्ति और समाज का संबंध द्वंद्वात्मक भी है और पूरक भी। यह द्वंद्व ही उनके रचना–संसार की सजीवता का स्रोत है।

निराला की कहानियों की प्रगतिशील चेतना :-

'प्रगतिशीलता' निराला के लिए किसी राजनीतिक विचारधारा का नाम नहीं, बल्कि जीवन की नैतिक भावना थी। उनका प्रगतिवाद मनुष्य की बहुआयामी मुक्ति से जुड़ा था– आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सभी स्तरों पर।

उनकी कहानियों में समाज के हाशिए पर खड़े पात्र न केवल करुणा के पात्र हैं, बल्कि परिवर्तन की संभावनाओं के प्रतीक भी हैं। वे अन्यायपूर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसके विरुद्ध सजग प्रतिरोध करते हैं– यही निराला की प्रगतिशील दृष्टि है।

"निराला की इन चरित्र प्रधान कहानियों में हमें जीवन की विविध छवियों की झलक मिलती है। गहनता से विचार करें तो हर पात्र हमारे ही बीच का है, जिससे हमें आत्मबल मिलता है।"[1]

निराला की प्रगतिशीलता का मूल केंद्र व्यक्ति की चेतना का जागरण है। वे चाहते हैं कि हर मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। उनकी रचनाएँ किसी राजनीतिक प्रचार की तरह नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना के आंदोलन की तरह कार्य करती हैं।

उनकी कहानियों में वर्गीय चेतना और मानवीय करुणा का अद्‌भुत संतुलन मिलता है। उदाहरणस्वरूप 'कुल्ली भाट' में उन्होंने दलित जीवन के संघर्ष को जिस ईमानदारी से चित्रित किया, वह हिंदी कहानी को नई सामाजिक दिशा प्रदान करता है। वहाँ कुल्ली दया का नहीं, आत्म गौरव का पात्र है– जो निराला के प्रगतिशील चिंतन का प्रमाण है। निराला के प्रगतिवाद में कोई बाहरी क्रांति नहीं, बल्कि अंतःकरण की जागृति है। वे मनुष्य के भीतर के विवेक और करुणा को परिवर्तन का वास्तविक साधन मानते हैं। यही कारण है कि उनका प्रगतिवाद स्थायी, मानवीय और संवेदनशील है।

नारी अस्मिता का स्वर और उसका विकास :-

निराला की कहानियों में नारी के प्रति दृष्टि अत्यंत आधुनिक और संवेदनशील है। वे स्त्री को केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे चेतना, आत्म सम्मान और प्रतिरोध की प्रतीक के रूप में चित्रित करते हैं। "जानकी" कहानी में नारी के प्रति उनकी दृष्टि स्पष्ट झलकती है– "ऐसी शांत दृष्टि और मंद गति मैंने नहीं देखी जैसी इस स्त्री की, विश्व की समस्त प्रकृति पर विजय हो। जैसे यह सब कुछ जानती है और बिना कहे बहुत कुछ कह रही है।"[2]

उनकी कहानियों की स्त्रियाँ अन्याय सहकर मौन नहीं रहतीं। वे अपने निर्णय स्वयं लेती हैं और समाज या परिवार से टकराने का साहस रखती हैं। यह उनका विशिष्ट नारी दृष्टिकोण है।

वैश्या समस्या और उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करते हुए निराला कहते हैं– "परंतु क्यों फिर उसने अपने पीछे मर मिटने वाले, पसीने की जगह खून की नदियाँ बहाने वाले बड़े–बड़े करोड़पतियों को टके–सा जवाब दे दिया... अगर वह वेश्या है तो वह उसी की क्यों ना हुई जिसके पास धन है।"[3] यह उद्धरण यह सिद्ध करता है कि निराला का नारी चित्रण दया या सहानुभूति पर नहीं, बल्कि सम्मान और समानता पर आधारित है। "सखी" कहानी में शिक्षा के प्रति लीला का संघर्ष स्त्री स्वतंत्रता का सशक्त उदाहरण है– "कॉलेज के अलावा पाँच घंटे पढ़ाती हूँ। डॉक्टर साहब बड़े आदमी हैं, लड़कियों की पढ़ाई के लिए साथ देते हैं। मेरी हालत भी जानते हैं।"[4]

निराला की स्त्रियाँ केवल परिवार या प्रेम के दायरे में नहीं बंधती। वे आत्मनिर्भर, विचारशील और परिवर्तनशील हैं। यह दृष्टि उन्हें प्रेमचंद की 'स्त्री–यथार्थवादी' रचनाओं से भी आगे ले जाती है। निराला की स्त्री पात्र 'लीला, श्यामा, जानकी या आभा' सभी में आधुनिक नारीवाद की चेतना के अंकुर स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनका स्त्री–विमर्श पश्चिमी 'फेमिनिज्म' से अलग है। निराला स्त्री को विरोध की प्रतीक नहीं, मानवीय सहअस्तित्व की वाहक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टि से उनका नारी विमर्श भारतीय सांस्कृतिक संवेदना से जुड़ा हुआ है।

समाज–यथार्थ और व्यक्ति–संघर्ष का संबंध :–

निराला का समाज–यथार्थ केवल बाह्य स्थितियों तक सीमित नहीं हैय वह व्यक्ति के भीतरी जीवन में गहराई तक प्रवेश करता है। वे मानते हैं कि समाज की जटिलताएँ व्यक्ति के भीतर भी जड़ें जमाए रहती हैं। उनकी कहानियों के पात्र परिस्थितियों से जूझते हैं, कभी टूटते हैं, पर पराजित नहीं होते। "श्यामा" कहानी की श्यामा पढ़–लिखकर दस्तकारी सीखती है और अपना जीवन सुधारती है –"श्यामा के भी पढ़ने और दस्तकारी सीखने का प्रबंध हो गया।"[5]

"सफलता" कहानी की आभा भी शिक्षा प्राप्त कर कला के क्षेत्र में नाम अर्जित करती है– "आभा चलो यहाँ से मेरे घर में बहुत दिनों से अंधेरा है, उसमें प्रकाश भर दो। मैंने तुम्हारी शिक्षा के लिए जायदाद बेची है।"[6]

इन पात्रों में सामाजिक संघर्ष और व्यक्तिगत जिजीविषा का संयोजन है। निराला व्यक्ति की हार में भी उसकी नैतिक विजय देखते हैं। यही उन्हें यथार्थवादी कथाकार से आगे ले जाकर मानवतावादी रचनाकार बनाता है।

नारी और समाज के मध्य निराला की दृष्टि :–

निराला की कहानियों में नारी और समाज का संबंध संघर्षमय है, परंतु वे इस संघर्ष को कटुता के रूप में नहीं, बल्कि संवेदनशील दृष्टि से देखते हैं। उनके नारी पात्र समाज से घृणा नहीं करते, बल्कि उसमें परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं। यही परिवर्तन की चाह उनकी कहानियों को प्रगतिशील बनाती है। निराला का दृष्टिकोण संवेदना आधारित नारी विमर्श का प्रतिनिधि है, जो समानता और संवाद की भूमिका पर आधारित है।

आधुनिक संदर्भ में निराला की प्रासंगिकता :–

निराला की कहानियाँ आज भी उतनी ही सामयिक हैं जितनी अपने समय में थीं। आज भी समाज में असमानता, भेदभाव, स्त्री पर हिंसा और आर्थिक विषमता मौजूद है। ऐसे में निराला की कहानियाँ साहित्य से अधिक सामाजिक दर्पण बन जाती हैं।

"बहुआयामी प्रतिभा के धनी निराला से हिंदी का साहित्य संसार पूर्णतः परिचित है। वे छायावाद के संधानक, प्रगतिवाद के समर्थक और मानवतावाद के पोषक थे।"[7] उनकी कहानियाँ यह सिखाती हैं कि सामाजिक परिवर्तन केवल सत्ता या कानून से नहीं, बल्कि संवेदना और विवेक से आता है। आज के उपभोक्तावादी युग में जब साहित्य बाजार की शर्तों पर ढलने लगा है, निराला की कहानियाँ यह याद दिलाती हैं कि सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्य के भीतर के नैतिक सत्य को पहचान सके।

निराला का कथा–संसार आधुनिक पाठक को यह सिखाता है कि समाज में समानता और गरिमा की स्थापना के लिए करुणा और आत्मबल दोनों आवश्यक हैं। यही कारण है कि निराला का साहित्य आज भी नारी

विमर्श, जाति विमर्श और प्रगतिशील चेतना के विमर्शों में उद्धृत किया जाता है।

निष्कर्ष :–

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कहानियाँ हिंदी साहित्य में मानवीय संवेदना, समानता और स्त्री गरिमा की सशक्त अभिव्यक्ति हैं। आलोचक नामवर सिंह ने लिखा है– "उपन्यासों और कहानियों में स्त्री जीवन से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया है। निराला की अधिकांश कहानियों के शीर्षक स्त्री–प्रधान हैं और उनके स्त्री–पात्रों के इर्द–गिर्द ही कथानक का ताना–बाना बुना गया है।"[8]

उन्होंने कहानी को केवल कथन नहीं, बल्कि विचार और करुणा की प्रयोगशाला बनाया। निराला की प्रगतिशील चेतना कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, बल्कि जीवन–दृष्टि है– ''जो हर मनुष्य में निहित करुणा और आत्मबल पर भरोसा करती है।" निराला की अपनी साहित्य चिंता बिल्कुल दूसरे स्तर और धरातल की वस्तु थी... वह इस बदसूरती के बावजूद उसके भीतर जीवित जन की आत्मा का सौंदर्य परखने से नहीं चूक सकती थी।"[9] निराला का कथा–संसार यह सिद्ध करता है कि साहित्य तभी जीवित रहता है जब उसमें मनुष्य की सच्चाई, करुणा और आत्मबल जीवित रहे। उनके लिए संवेदना ही समाज–परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन है और यही उनका सच्चा प्रगतिवाद है।

सन्दर्भ सूची :–

1. डॉ. मालती तिवारी : निराला का काव्य : विविध सन्दर्भ, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण (2001), पृ. 62
2. स. नंदकिशोर नवल : निराला रचनावली, भाग–4, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, चतुर्थ संस्करण (2006), कहानी : जानकी, पृ. 412
3. वही, कहानी : क्या देखा, पृ. 272
4. वही, कहानी : सखी, पृ. 353
5. वही, कहानी : श्याम, पृ. 315
6. वही, कहानी : सफलता, पृ. 377
7. रामस्वरूप चतुर्वेदी : प्रसाद, निराला और अज्ञेय, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, सातवाँ संस्करण (2014), पृ. 63
8. नामवर सिंह : छायावाद, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण (1995), पृ. 33
9. अर्चना वर्मा : निराला के सृजन–सीमान्त विहग और मीन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण (2005), पृ. 236

smonga1992@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 19–22

भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन के विचारों का महत्व

रूपकला माधुरी खलखो
असिस्टेंट प्रोफसर, दर्शनशात्र विभाग, महिला कॉलेज, चाईबासा, झारखंड।

सारांश :–

चार्वाक दर्शन जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, यह एक प्राचीन भारतीय भौतिकवादी दर्शन है जो इंद्रिय जनित अनुभव को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानता है। यह दर्शन वेदों, आत्मा पुनर्जन्म और स्वर्ग–नरक जैसी अवधारणाओं को अस्वीकार करता है। इसका मुख्य सिद्धांत "ऋण कृत्वा घृतं पिबेत" है जिसका अर्थ है "ऊधार लेकर घी पियो" जो जीवन का आनंद लेने पर जोर देता है।

चार्वाक दर्शन के मुख्य सिद्धांत :–

- **भौतिकवाद :–** चार्वाक दर्शन के अनुसार केवल भौतिक पदार्थ ही सत्य है और चेतना सहित सभी चीजे भौतिक तत्वों से बनी है।
- **इन्द्रिय-जनित अनुभव :–** ज्ञान का एकमात्र स्रोत इंद्रियां जनित अनुभव है।
- **नास्तिकता :–** यह दर्शन वेदों, आत्मा, पुनर्जन्म और स्वर्ग–नरक जैसी अवधारणा अस्वीकार करता है।
- **सुखवाद :–** जीवन का मुख्य उद्देश्य सुख प्राप्त करना है।
- **प्रत्यक्षवाद :–** केवल इंद्रियों द्वारा अनुभव की जा सकने वाली चीज ही सत्य है।
- **अनैतिकता :–** चार्वाक दर्शन में धर्म, कर्म और मोक्ष जैसी अवधारणा को अस्वीकार किया जाता है।
- **लोकप्रियता :–** इस दर्शन को लोकायत या जनसाधारण का मत भी कहा जाता है, क्योंकि यह आम लोगों के जीवन के प्रति सहज दृष्टिकोण को दर्शाता है।

मुख्य शब्द – सुख, भौतिकवादी, प्रत्यक्ष, परलोक, पुनर्जन्म।

प्रस्तावना :–

भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन के विचारों का बहुत महत्व है। खासकर भौतिकवादी और भोगवादी दृष्टिकोण के लिए चार्वाक दर्शन जिसे लोकायत या बृहस्पति दर्शन भी कहा जाता है। ऐसा सुना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति ने ही लोगों कों मोहित करने के लिए प्रिय वचनों द्वारा चार्वाक मत का उपदेश दिया था। भारतीय दर्शन एक महत्वपूर्ण और प्राचीन प्रणाली है। यह दर्शन अनुभवजन्य ज्ञान पर जोर देता है और अलौकिक या पारलौकिक सत्ता को नहीं मानता है। भारतीय दर्शन में जड़वादी का पर्याय चार्वाक दर्शन ही है। जड़वादी को लोकायत भी कहते हैं, क्योंकि यह लोगों में विस्तृत है यह सामान्य जन के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है।

डॉ. राधाकृष्णन ने कहा कि चार्वाक दर्शन को लोकायत मत की संज्ञा इस कारण से दी गई है कि वह

इस लोक में विश्वास करता है तथा परलोक का निषेध करता है।

आज चार्वाक दर्शन पर कोई स्वतंत्र ग्रंथ या मूलग्रंथ उपलब्ध नहीं है। परंतु अन्य दर्शनों के ग्रंथो में चार्वाक के सिद्धांत का खंडन करने की निमित कई सूत्रात्मक वाक्य दिए गए हैं, उन्हीं को चार्वाक दर्शन के मूलसूत्र माना जाता है। पूरे भारतीय दर्शन में विभिन्न प्रमाणों के संबंध में विवेचन किया गया है। भारतीय दर्शन में प्रमाण की संख्या को लेकर मतभेद है। चार्वाक प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकमात्र प्रमाण अर्थात साधन प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष एक मात्र प्रमाण है। इसका कथन है कि "प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्" केवल एक ही प्रमाण प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान निश्चित एवं संदेह रहित होता है।

प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती इसीलिए कहा गया है कि "प्रत्यक्ष किम प्रमाणं" प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण स्वीकार करने के कारण चार्वाक दर्शन अन्य प्रमाणों का खंडन करता है। चार्वाक दर्शन और भौतिक पदार्थ का निराकरण करता है। चार्वाक दर्शन के अनुसार तत्वों का स्थूल दृष्टि भूत स्वरुप ही यथार्थ है। उन स्थूल तत्वों के स्वरुप–लक्षण प्रयोजन आदि विचार चार्वाक दर्शन में विशद रूप से विहित है। चार्वाक दर्शन के अनुसार संसार की रचना पृथ्वी–जल–वायु और तेज ये चारो प्रमेय पदार्थ से हुई है क्योंकि इनका ही प्रत्यक्ष होता है। आकाश की सत्ता प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होती इसलिए यह मान्य नहीं है। इन्हीं चार भूतों के सहयोग से सजीव एवं निर्जीव दोनों ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। इन भौतिक तत्वों से चेतना की उत्पत्ति इस प्रकार होती है जिस प्रकार पान, कत्था, कसेली तथा चूना के सहयोग से लाल रंग का अविर्भाव होता है, यद्यपि इसमें लाली का अभाव होता है। भूत में विश्व की सृष्टि स्वयं होती है। चार्वाक के इस मत को "स्वभाववाद" कहते हैं।

आत्मा :–

चार्वाक के अनुसार आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए आत्मा का अस्तित्व नहीं है।

पुनर्जन्म :–

मृत्यु के पश्चात शरीर का नाश हो जाता है तथा शरीर के नाश होने से जीवन का भी अंत हो जाता है। अतः पुनर्जन्म, पूर्वजन्म, स्वर्ग–नरक इत्यादि सभी कपोल कल्पित बातें हैं। शरीर की मृत्यु के साथ ही आत्मा का नाश हो जाता है :–

"यावज्जीवेत सुखं जीवेत नास्ति मृत्योर गोचरः।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः।।"

परलोक :–

स्वर्ग एवं नरक का हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है इसलिए इनका अस्तित्व नहीं है। चार्वाक ने कहा है कि स्वर्ग एवं नरक इसी विश्व में स्थित सुखी व्यक्ति स्वर्ग का आनंद लेता है तथा दुखी व्यक्ति नरक का कष्ट इसी जीवन एवं विश्व में भोगता है।

ईश्वर :–

चार्वाक के मत में ईश्वर का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता क्योंकि यह निराकार है। ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान अनुमान से होता है, अनुमान चूकी अप्रामाणिक है इसलिए अनुमान पर आधारित ईश्वर ज्ञान भी अवास्तविक एवं अप्रमाणिक है। इस प्रकार चार्वाक अनीश्वरवादी का समर्थक है।

धर्म :-

धर्म चार्वाक वेद को अप्रमाणिक मानता है, इसलिए वेद में वर्णित धर्म एवं तत्संबंधी विचार भी दोषपूर्ण हैं। वेद की रचना ब्राह्मणों ने अपने जीवन यापन के लिए की। चार्वाक ने वैदिक धर्म कर्म की आलोचना की है। मृत आत्माओं को तृप्त करने के लिए श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, चार्वाक इसका खंडन करते हुए कहते है कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसके लिए भोजन प्रदान करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। कोई पथिक भोजन की सामग्री साथ लेकर क्यों चलता है? उसके परिवार के सदस्य क्यों नहीं उसकी क्षुधा शांति के लिए घर पर ही भोजन अर्पित कर देते हैं? यदि यज्ञ में बली दिया हुआ पशु स्वर्ग पहुंच जाता है तो हमें क्यों नहीं ब्राह्मण अपने वृद्ध मां–बाप की बलि देकर उसे स्वर्ग पहुंचा देते हैं। इस प्रकार चार्वाक ने धर्म के साथ–साथ धार्मिक रीति–रिवाज का भी खंडन किया है।

कर्म सिद्धांत :-

चार्वाक का अभिभूत है कि कर्म सिद्धांत का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता है इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

मोक्ष :-

दुख विनाश अवस्था को मोक्ष कहा गया है तथा इस अवस्था की प्राप्ति आत्मा को होती है, जब आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष की प्राप्ति कुछ दार्शनिकों के अनुसार इसी जीवन में तथा कुछ के अनुसार मृत्यु के बाद होती है। चार्वाक ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि मोक्ष की प्राप्ति जीवन काल में संभव नहीं है। मनुष्य के पास जब तक शरीर है उसे नाना प्रकार के सांसारिक दुखों का सामना करना पड़ता है। दुःखों से पूर्ण छुटकारा तो मृत्यु के बाद ही संभव है। चार्वाक के अनुसार मृत्यु ही मोक्ष है (मरण मेवा पवर्ग)

चार्वाक जीवन का चरम उद्देश्य सुख को ही स्वीकार करता है। इसीलिए इसके मत को सुखवादी भी कहा जाता है। शुभ जीवन वही है जिसमें अधिकतम सुख मिल जाये। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वही कर्म करना चाहिए जिसमें अधिकतम सुख की प्राप्ति हो।

चार्वाक ने बौद्धिक सुखों की अपेक्षा शारीरिक सुख पर अधिक बल दिया है। यह यथार्थ सत्य है कि सुख प्राप्ति में दुख भी यदा–कदा प्राप्त हो जाता है, परंतु इस दुख के भय से मनुष्य सुख प्राप्त करना छोड़ नहीं देता है। जिस प्रकार अन्न में भूसा मिश्रित होने से कोई अंश खाना कोई अन्य खाना नहीं छोड़ता है। इसलिए सुख में दुःख मिला हुआ रहता है। इस कारण मनुष्य का यह कर्तव्य होता है कि वह दुख से सुख को छांटकर केवल और केवल सुख का ही उपयोग करें दुख के भैंस से सुख का परित्याग करना महान मूर्खता चार्वाक ने कहा है मनुष्य को केवल वर्तमान सुख ही अपनाना चाहिए क्योंकि व्यक्ति का अस्तित्व इसी जीवन एवं कल तक ही सीमित है। अतः उसे वर्तमान जीवन में आधिकारिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष :-

चार्वाक दर्शन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि भौतिकवदी और नास्तिक विचारधारा है। यह दर्शन प्रत्यक्ष अनुभव को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानता है। चार्वाक प्रार्थना, पुनर्जन्म, स्वर्ग–नरक आदि जैसी अवधारणा को अस्वीकार करता है। इसका मानना है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख और आनंद प्राप्त करना है

और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। भस्मीभूत शरीर का पुनः आगमन नहीं होता है। इसलिए जब तक जियें, सुखपूर्वक जिये, ऐसा इनका निर्णय है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. झा, आचार्य आनद. (2013). चार्वाक दर्शन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ,
   ISBN : 978–93–82175–19–3
2. पाठक, डॉ. सर्वानन्द. (2015). चार्वाक दर्शन की शाश्त्रीय समीक्षा, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी।
3. गौतम, एस. एस. (2020). चार्वाक दर्शन, सिद्धार्थ बुक्स, दिल्ली. ISBN–9789393679321
4. शर्मा, लक्ष्मीनारायण. (2011). चार्वाक दर्शनम्, हंसा प्रकाशन, जयपुर. ISBN –8186120785
5. मौर्या, देवी प्रसाद. (2005). नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली. ISBN–8121401828
6. तिवारी, डॉ. नरेश प्रसाद. (1986). चार्वाक का नैतिक दर्शन, बिहार हिंदी रंथ अकादमी, पटना.
   ISBN–978–81–89880–58–3
7. सिन्हा, हरेन्द्र प्रसाद.(1986). भारतीय दर्शन की रुपरेखा, मतिलाल बनारसीदास, दिल्ली।
8. Prasad, Shiv Nath. (2008). Charvaka/Lkayata. Janki Prakashan, Patna,
   ISBN– 978–81–89880–58–3

मो. 8102572149

Khalkhomadhuri123@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 23–26

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समकालीन हिंदी कथा साहित्य का मूल्यांकन

डॉ. अफीफा फातिमा शेक
सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, स्टेल्ला मॉरिस कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु।

प्रस्तावना :–

साहित्य और मनोविज्ञान का रिश्ता अत्यंत गहरा है। साहित्य जहाँ मानवीय जीवन और अनुभवों का कलात्मक प्रतिबिंब है, वहीं मनोविज्ञान मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों, भावनाओं और विचारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। जब हम हिंदी कथा साहित्य की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि इसका मूल केंद्र सदैव मनुष्य और उसका अंतर्जगत रहा है। समकालीन हिंदी कथा साहित्य में मनोविज्ञान का समाकलन और भी सशक्त रूप में सामने आता है। आज के कथा साहित्य में केवल बाहरी यथार्थ या सामाजिक संघर्ष ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर की टूटन, अकेलापन, तनाव, दुविधा और अस्तित्वगत प्रश्न भी गहराई से व्यक्त होते हैं।

मन्नू भंडारी की कहानी "यही सच है" में स्त्री–पुरुष संबंधों की जटिलता को दर्शाती है। नायिका का आंतरिक द्वंद्व, प्रेम और सामाजिक मर्यादाओं के बीच फँसा हुआ मनोविज्ञान पाठक को गहराई से छूता है। यहाँ मनोविज्ञान इस रूप में प्रकट होता है कि पात्र अपने ही भावनात्मक निर्णयों से जूझते रहते हैं। मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानी 'यही सच है' आधुनिक नारी के भीतर चल रहे भावनात्मक और बौद्धिक द्वंद्व का अत्यंत सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत करती है। कहानी की नायिका दीपा के माध्यम से लेखिका ने यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि– "क्या जीवन में सुरक्षा, स्थायित्व और सामाजिक मान्यता अधिक आवश्यक है, या फिर प्रेम की रोमानी अनुभूति, जो मनुष्य को आत्मिक संतोष प्रदान करती है?"[1] दीपा का जीवन दो ध्रुवों के बीच झूलता है। संजय उसे वह सुरक्षा देता है, जो समाज में एक स्त्री के लिए आवश्यक मानी जाती है। संजय के साथ जीवन का ढाँचा स्थिर है, उसमें कोई जोखिम नहींय किन्तु उस स्थिरता में वह भावनात्मक ऊष्मा, वह आत्मीय स्पर्श नहीं है, जो दीपा को निलेश के सान्निध्य में अनुभव होता है। निलेश के प्रति उसका आकर्षण मात्र देहात्मक नहीं, बल्कि उसकी अंतःचेतना की वह लहर है, जो जीवन को अर्थ, संवेदना और गहराई प्रदान करती है। कहानी के अंत में दीपा का संजय के सामने बिखर जाना इस द्वंद्व की पराकाष्ठा है। कई समीक्षक इसे इस रूप में देखते हैं कि दीपा अंततः जीवन की सुरक्षा को रोमानियत पर वरीयता देती है– वह निलेश की भावनात्मक दुनिया से बाहर निकलकर व्यावहारिक यथार्थ को स्वीकार करती है। परंतु, कहानी के कई वाक्यों से यह भी प्रतीत होता है कि लेखिका ने भावनात्मक प्रेम को ही श्रेष्ठ माना है, भले ही वह जीवन में स्थायित्व न दे सके। "विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार

ही सच है, निलेश का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था।"[2] इस दृष्टि से कहानी में प्रेम की दो स्थितियाँ उभरकर सामने आती हैं। संजय के साथ का प्रेम, जो सुरक्षा, सामाजिक मान्यता और स्थिरता का प्रतीक है। निलेश के प्रति प्रेम, जो आत्मिक, रोमानी और जीवन्त भावनाओं का प्रतीक है। मन्नू भंडारी इन दोनों स्थितियों की तुलना के माध्यम से यह दर्शाती हैं कि मनुष्य का जीवन केवल सुरक्षा और व्यवस्था से पूर्ण नहीं होता। उसमें भावनाओं की वह सजीवता भी आवश्यक है, जो उसे जीवित बनाए रखती है।

उषा प्रियंवदा की कहानियों में आधुनिक जीवन, विदेशी सभ्यता और बदलते सामाजिक मूल्यों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उनकी कहानियाँ इस बात को बड़ी बारीकी से दिखाती हैं कि कैसे औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण के आने से भारतीय परिवारों में टूटन और दूरी बढ़ने लगी। पुरानी पीढ़ी जहाँ अपने परंपरागत मूल्यों को लेकर जीना चाहती है, वहीं नई पीढ़ी आधुनिक सोच और स्वतंत्र जीवन की ओर बढ़ रही है। यही टकराव परिवारों में संघर्ष और विघटन का कारण बन रहा है। उनकी प्रसिद्ध कहानी 'वापसी' इसका एक सुंदर उदाहरण है। इस कहानी में गजाधर बाबू पुराने संस्कारों और मूल्यों के प्रतीक हैं, जबकि उनका परिवार (पत्नी, बेटा, बहू, बेटी) आधुनिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। गजाधर बाबू सेवानिवृत्त होकर घर लौटते हैं और चाहते हैं कि परिवार पुराने ढंग से, आपसी सहयोग और आदर के साथ चले। परंतु उनका परिवार अब बदल चुका है। वहाँ हर संबंध में स्वार्थ और दूरी आ गई है। गजाधर बाबू की पत्नी अब नई परिस्थितियों के अनुसार ढल चुकी हैं। वह पति का साथ देने के बजाय अपने बच्चों और गृहस्थी की चिंता में उलझी रहती हैं। यहाँ तक कि बेटी बसंती भी घर के कामों से बचती है और आधुनिक जीवन में व्यस्त रहती है। धीरे–धीरे गजाधर बाबू को यह महसूस होता है कि अब परिवार में पुराने मूल्यों का कोई स्थान नहीं बचा है। बेटे की बातों से लेकर पत्नी के व्यवहार तक, सब जगह संवेदनहीनता और आत्मकेंद्रित सोच दिखाई देती है। अंत में गजाधर बाबू समझ जाते हैं कि अब इस माहौल में उनका रहना कठिन है, इसलिए वे फिर से अपनी नौकरी पर लौट जाने का निर्णय लेते हैं– यही उनकी "वापसी" है। नामवर सिंह के शब्दों में, यह "अकेलापन हर व्यक्ति के भीतर का सच्चा यथार्थ है, परंतु उसका कोई साथी नहीं होता।"[3]

'वापसी' के माध्यम से उषा प्रियंवदा ने यह दिखाया है कि आधुनिक युग में परिवार और समाज दोनों में भावनाओं की जगह स्वार्थ और दूरी ने ले ली है।

कमलेश्वर की कहानी "राजा निरबंसिया" में सत्ता, समाज और व्यक्ति के बीच के मानसिक तनाव का चित्रण मिलता है। पात्रों का व्यवहार केवल सामाजिक परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनकी मानसिक आकांक्षाओं और कुंठाओं से संचालित होता है। राजा निरबंसिया कमलेश्वर की एक संवेदनशील और प्रतीकात्मक कहानी है, जो एक तरफ लोककथा के ढांचे में 'राजा–रानी' के निःसंतान होने की पीड़ा को चित्रित करती है, तो दूसरी ओर आधुनिक कस्बाई जीवन में जी रहे निम्न–मध्यमवर्गीय दंपत्ति जगपती और चंदा के रिश्तों की टूटन और सामाजिक विवशता को सामने लाती है। जगपती बेरोजगार है, चंदा काम करती है और संतानहीनता उनके बीच तनाव और असंतोष को बढ़ाती है। कहानी में स्त्री–पुरुष संबंधों, सामाजिक दबाव, आर्थिक तंगी और इच्छाओं के कुचले जाने की गहरी व्यथा है। जगपती कहता है कि 'औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है... नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा।'[4] यह वाक्य उसकी कुंठा और विफलता का आईना है।

निर्मल वर्मा की कहानी "परिंदे" में एकाकीपन और असुरक्षा का गहन मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है।

नायक–नायिका के बीच संबंध की अस्पष्टता और भीतर की खालीपन की अनुभूति समकालीन मनुष्य की मानसिक स्थिति को उजागर करती है। 'परिन्दे' की लतिका का अकेलापन कोई दूर नहीं कर सकता। एक पहाड़ी हिल स्टेशन पर बतौर अध्यापिका और वार्डन के रूप में काम करने वाली लतिका मेजर गिरीश की मृत्यु के पश्चात जीवन में आए अकेलेपन और खालीपन को दूर नहीं कर पाती। लतिका के मेजर गिरीश नेगी के साथ जिए और भोगे गए अनुभव उसकी स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। उसके अनुसार प्रेम एक ऐसी अनुभूति है "जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोकर, संभाल कर, अपने में छिपाए रहती है, एक अनिर्वचनीय सुख, जो पीड़ा लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई, उमड़ते ज्वर की खुमारी... दोनों को अपने में समो लेती है... एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है...यहीं इसी देवदार के नीचे ... वह जी रही थी, उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच भिंचा था–बहका–सा पागल क्षण।"[5] निर्मल वर्मा की कहानियां पात्रों को बार–बार अकेलेपन से बाहर निकालती हैं लेकिन वे बार–बार अकेलेपन के घेरे में घुस जाने को विवश हों जाते है।" देवदार पर खुदे हुए अधमिटे नाम लतिका की ओर निस्तब्ध–निरीह भाव से निहार रहे थे।"[6] लतिका के लिए वह समय उसका शाश्वत वर्तमान बन गया है जो अपने साथ अतीत को समाहित किए है। 'परिंदे' कहानी की लतिका अपने जीवन में उपस्थित त्रासदी से बाहर नहीं आना चाहती।

मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास "चाक" में ग्रामीण स्त्री–जीवन और उसके संघर्ष का चित्रण करते हुए यह कहानी स्त्री–मन के विद्रोही स्वर को प्रकट करती है। यहाँ स्त्री के भीतर पनपती असंतुष्टि, विद्रोह और आत्मसम्मान की चेतना स्पष्ट होती है। यह मनोविज्ञान और सामाजिक संदर्भों का सुंदर समाकलन है। कहानी में ग्रामीण जीवन के विविध पहलू दिखाई देते हैं– जाति का भेद, सामाजिक परंपराएँ, और स्त्री की सीमाएँ। फिर भी इन सबके बीच मनुष्यता की गर्माहट बनी रहती है। नायिका का संघर्ष गाँव की स्त्री की चेतना का प्रतीक है। वह समाज से प्रश्न करती है और अपने अस्तित्व के लिए खड़ी होती है। जैसा कि लेखिका कहती हैं, "स्त्री अब चौखट नहीं, चौक पर आ खड़ी हुई है।"[7]

समकालीन मनोविज्ञान और कथा साहित्य के प्रमुख आयाम :

1. **अकेलापन और विस्थापन :**

- महानगरों की भागदौड़, प्रवासन और टूटते परिवारों के कारण व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से अकेला हो गया है।
- 'वापसी' जैसी कहानियाँ इस अकेलेपन को गहराई से व्यक्त करती हैं।

2. **स्त्री-मन का द्वंद्व :**

- स्त्री–कथाकारों ने आत्मखोज, अस्मिता और स्वतंत्रता की आकांक्षा को मनोवैज्ञानिक धरातल पर अभिव्यक्त किया है।
- 'यही सच है' या 'त्रिशंकु' (मन्नू भंडारी) इसके उदाहरण हैं।

3. **उपभोक्तावादी जीवन और मानसिक संकट :**

- साठोत्तरी कथा साहित्य में उपभोक्तावाद के कारण उत्पन्न मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा को दिखाया गया।
- कमलेश्वर और मोहन राकेश की कहानियाँ इस प्रवृत्ति को दर्शाती हैं।

4. **संबंधों की जटिलता :**

- पति–पत्नी, पिता–पुत्र, स्त्री–पुरुष मित्रता या प्रेम– इन सभी रिश्तों के भीतर छिपे मानसिक तनाव को कथाकारों ने विषय बनाया।
- निर्मल वर्मा की कहानियों में संबंधों की यही अस्पष्टता और बेचौनी झलकती है।

5. **आधुनिक तकनीक और डिजिटल मनोविज्ञान :**

- हाल के कथा साहित्य में इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल संस्कृति ने मनुष्य के मनोविज्ञान पर जो असर डाला है, उसका चित्रण मिलने लगा है।
- अब कहानियाँ एवं उपन्यास केवल व्यक्ति और परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक–डिजिटल मानसिकता को भी पकड़ने लगी हैं।

निष्कर्ष :

समकालीन हिंदी साहित्य में मनोविज्ञान का गहरा समावेश है। यहाँ मनुष्य केवल सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक मानसिक संरचना का भी दर्पण है। मन्नू भंडारी ने स्त्री–मन की दुविधा और जटिलता को उजागर किया। उषा प्रियंवदा ने अकेलेपन और परिवारिक विघटन का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया। निर्मल वर्मा ने आधुनिक व्यक्ति की अस्तित्वगत बेचौनी को सामने रखा। मैत्रेयी पुष्पा ने स्त्री की विद्रोही चेतना को मनोवैज्ञानिक धरातल पर उभारा। इन सबके माध्यम से स्पष्ट होता है कि हिंदी कथा साहित्य ने समय–समय पर बदलती मानवीय मानसिकताओं को न केवल चित्रित किया है, बल्कि उन्हें गहराई से समझने का माध्यम भी प्रदान किया है। इस प्रकार, कहा जा सकता है कि समकालीन हिंदी कथा साहित्य मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है, जहाँ व्यक्ति के अंतर्मन की गुत्थियाँ, रिश्तों की जटिलताएँ और सामाजिक तनाव कलात्मक ढंग से उद्घाटित होते हैं।

संदर्भ सूची –

1. https://share.google/J9sPdl7bP8dzBCtHa
2. मन्नू भंडारी, यही सच है, राधाकृष्ण प्रकाशन, पृ. सं. 152
3. नामवर सिंह, नयी कहानी, लोकभरती प्रकाशन, पृ. सं. 143
4. https://share.google/sHnyvkZk7QK6dOrX0
5. निर्मल वर्मा, अन्तर्यात्रा, नंदकिशोर आचार्य– वाणी प्रकाशन, 2003, पृ. सं. 53
6. वही, पृ. सं. 54
7. मैत्रेयी पुष्पा, चाक, राजकमल प्रकाशन, पृ. सं. 149

Address : Dr. Afeefa Fathima Shaik
Assistant Professor, Department of Hindi
Stella Maris College (Autonomous) 17, Cathedral Road, Chennai-600086, Tamil Nadu
Mobile Number : 9710623178
Email: afeefafathima@stellamariscollege.edu.in

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 27-34

असमीया अभिनय कला के गीतों में राग प्रधान गीतों की परंपरा

डॉ. अनिरूद्ध वायन
सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग
मध्यकामरूप कॉलेज।

संगीत गीत, नृत्य, वाद्य का समन्वय है। 'गीतं, वाद्यं नृत्य त्रयं संगीत उच्यते।' अतः गीत नृत्य और वाद्य के अभाव में संगीत नहीं हो सकता है और संगीत के सुर माधुर्य के लिए जरुरी होता है। भारतीय संगीत परंपरा में राग धारणा का स्थान सबसे पहले है। राग का अर्थ है सुर, हवा या स्वरांगम नहीं हो सकता है। भारतीय संगीत धारा के अतिरिक्त अन्य संगीत में राग की प्रति शब्द अभिव्यक्त करने वाला कोई परिभाषा नहीं है। राग का परिभाषा इस प्रकार दिया जा सकता है– 'रंजयति इति राग', अर्थात मन जिसके द्वारा रंजित होता है और मानव ह्रदय में आवेग–वासना और आनंद का भाव जागृत होता है उसका नाम राग है। अनुपूर्वा विशिष्ट सांगितिक स्वर मजंला संरचनात्मक या संयोजनात्मकता का नाम राग है। विशिष्ट पंडित OC गांगुली के अनुसार। 'rugh is a Sonal composition of musical notes having a sequence form or structure of a particular significance"[1]

राग–रागिणी की संख्या के क्षेत्र में पंडितों में मतभेद पायी जाती है। 'गीत–गोविन्द' के अनुसार 'वियाल्लिस ये रागे धरिलेक छत्रदंड।'[2]

कुछ विद्वानों के अनुसार मुल राग की संख्या 6 है और प्रत्येक का पाँच–पाँच रागिणी है। कुल 36 राग–रागिणी है। कोई कोई कहना चाहता है कि राग पुरुष है और स्त्री रागिणी के सहयोग से पुत्र राग की जन्म होता है। ये धारणा तो प्रतिकात्मक है। कारण एक राग से अनेक रागिनी की जन्म होता है। व्यास उजापालि परंपरा में छः राग और छयत्रीस रागिणी की धारणा प्रचलित है।

	राग **(पति)**	**रागिणी** **(पत्नी)**
1.	श्रीराग	मालवी, त्रिवली, गौरी, वावरी, भपाली, कल्याणी।
2.	वसंत	हिंगुली, गुंजरी, माल्लवी, पद्म मंजुरी, सारेरे, कौशिकी।
3.	भैरव	भैरवी, गौरी, रामकिरी, गुनाकिरी, बंगाली, सैंधवी।
4.	पंचम	देवगिरि, ललिता, विभारा, कणीटी, वरहंसिका, अभिरि।
5.	मेघ	मधु–माधुवी, मल्लावी, सौरटी, गांधारी, सारंगी, हरश्रृंगारि।

6. नटनारायन पाहारी, वदसी, केदारी, कामुदी, नर्तिका, हिरम्बी।[3]

असंमीया पंडित और परम्परागत संगीत की प्रत्यक्ष धारणा और वाहक के अनुसार असम के संगीत में पुत्र रागिणी परम्परा अप्रचलित है। दूसरी ओर गीत गोविन्द के कवि राम स्वरस्वती के द्वारा अनुदित ग्रन्थ में पुत्र रागिनी का भी उल्लेख मिलता है–

'माल्लव राग राजार मालसी पाटेश्वरी।
पात्र देहाग मैला कुमार धानश्री।'[4]

वृहद पुराण में वर्णित राग-रागिणी :-

	राग (पति)	**रागिणी (पत्नी)**
1.	कामद–	मायुरी, भोटिका, गौड़ी, वाराड़ी, विलोलिका, धनश्री।
	किन्नर राग	दासी – वागीश्वरी, सारदी, वृंदावनी, श्यामा, जयंती, वैजयंती।
2.	वसन्त राग –	केदारी, कल्याणी, मालिनी, अश्वरुड़ा, कर्णाटी, सहुया।
	किन्नर राग –	हिल्लोल दासी – श्यामकेली, देव केली, मालिनी, कामकेली, सम्भावती, शग्वरी।
3.	मलार –	नटी, सुरद्धट्टा, पाहाड़ी, लीला, जय जयंती, चारु, रूपिनी।
	किन्नर राग –	मधु दासी – चक्रवाकी, चंद्रमुखी, रसिका, विलासिका, यामिनी, श्याम घोटिका।
4.	विभाष राग –	रागिणी, रामकेली, ललिता, कोड़रा, कुमौदी, भैरवी, शर्वरी।
	किन्नर राग –	श्याधोटक– तरंगिणी, नागिनी, किशोरी किल्लोलिनी, हेमभूषणा, भीमनेत्रा।
5.	राग गांधार –	श्री, रुपवती, गौरी, धानसी, मंगल, गंधर्वी।
	किन्नर गौड़राज –	दासी–पट मंजरी, मंजीरा, काल गुजरी, पद्मावती, वेलावती, भूपाली, गंधिनी।
6.	दीपक राग–	उत्तरी, पूर्वि का, गुज्जरि, काल गुज्जरी, गोण्डकरी, माला।

किन्नर राग प्रदीप नाम –दीपहन्ता, दीपवर्णा, दीपकर्णा, प्रदिपिका, दिपाक्षी, दीपरक्ता।[5]

इन राग–रागिनी की स्थिति लोक–संगीत में पायी जाती है। कुछ पण्डितों के अनुसार लोक संगीत में राग–रागिनी की जरूरत नहीं है। शास्त्रीय अथवा मार्गीय संगीत में राग–रागिणी का प्रयोग किया जाता है। इसके हर स्थान में प्रयोग नहीं किया जाता है। कारण विशिष्टता पूर्ण सुर का नाम ही राग है। लोक–संगीत में भी विशिष्ट सुर का उपस्थिति लक्ष्य किया जाता है। मानकर, दुर्गावर, नारायण देव आदि के नाम पर प्रचलित गीत, पद पहले लोकगीत ही था। ये सभी गीत राग–रागिणी से मुक्त था। किंतु धिरे–धिरे राग रागिणी से युक्त होकर लिखित रूप लाभ किया है। पंडितों के अनुसार लोकगीत या आदिवासी गीत से राग–रागिणी युक्त होकर शास्त्रीय धारा में प्रवेश करने के लिय सक्षम हुआ है।

राग रागिनी का प्रति शब्द रूप में दर का ओजापालि में प्रयुक्त ढेक और उत्तर और दक्षिण कामरूप में दिगार पद को प्रयुक्त किया जा सकता है।

आचार्य मनोरंजन शास्त्री के अनुसार –

असमीया ओजापालि संगीत में राग रूप का ही व्यवहार है, रागिनी रूप का प्रचलन नहीं है। असमीया नववैष्णव संगीत के विशिष्ट साधक गोन्धराम वायन के अनुसार नववैष्णव, संगीतों में अनेक राग–रागिनी रूप प्रचलन दिखाई पड़ता है।'[6]

असम के अभिनय कला ओजापालि में पुत्र रागिणी की प्रचलन न रहने पर भी पत्नी रागिणी का प्रचलन है। इस संगीत धारा में – मालव, सारंग, सुखारंग, वावरि, चलन, वसन्त, भैरवी, रामगिरि, गान्धार, गण्डगिरि, पाहारी श्यामगारा, धनश्री, कल्यान, दीपक, अहिर, भाटियाली, मालवि, केदार, मालिनि आदि परम्परागत रूप प्रचलित है।

राग प्रधान संगीत परम्परा का प्रचलन प्राचीन काल से ही असम में प्रचलित है। इसका प्रमाण भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में उल्लेख है। इस ग्रन्थ में भारत में प्रचलित चार प्रकार के नाट्य प्रवृत्ति के सम्वन्ध में उल्लेख है।

'चतुर्विद्या प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता - नाट्य प्रयोगता।
आवस्ती, दक्षिणात्या, पाँचाली, चौड्र, मागधी।'[7]

इसमें प्रयुक्त चौड्र मागधी प्रवृत्ति से– अंग, वंग, मगध, नेपाल, प्रागज्यौतिषपुर आदि को समाहित करते हैं।[8]

चर्यापद का संगीत :-

बौद्ध के सहजयान साखा के चर्यापद को गीत के रूप में राग रागिनी संयोजन करते हुए गाते थे, जिसमें बौद्धों की सहजयानी परम्परा का आदर्श और दर्शन प्रकट हुए थे। इसमें सहजयानी बौद्ध की नीति नियम अभिव्यक्त होते थे। चर्यापद के गीत मूलतः मागधी अपभ्रश के पूर्वी भाषा में रचित हुआ जिसके साथ असमीया, बांग्ला तथा उड़िया आदि भाषा के सामाजंस्य थे। इसलिए असमीया बांला आदि पंडितों ने अपने अपने भाषा को माना है। कुछ चर्यापद के रचियता प्राचीन कामरूप के सिद्धों का नाम सन्निहित है जिनमें से सहरपाद का नाम उल्लेखनीय है। चर्यापद की गीत रागयुक्त,और प्रत्येक पद की राग सुनिश्चि थे।

चर्यापद के परवर्ती काल में मानकर, माधव कन्दली, हरि हर विप्र, हेम स्वरस्वती, कविरत्न सरस्वती आदि कवियों के द्वारा अनुदित महाकाव्य की गीत का राग ताल को संयोजन कर गाते थे।

पाचाली गीत के राग-रागिणी :-

वैष्णव धर्म के आदर्श के प्रभाव से दूर रहकर, मनकर ने मनसा गीत रचना करते हुए असमीया संगीत में एक नई लहर लाये थे। उसने कभी काव्य रचना की बात नहीं किया है बलकि पदुमाई गीत, पाँचाली गीत या शावण का गीत, रचना करने की बात कहते हैं। उनके द्वारा रचित गीत मूलतः लोकगीत की शैली में है। हर गीत के प्रारम्भ में राग रागिणी का उल्लेख नहीं रहने पर भी दिहा का उल्लेख है। पाँचाली गीत में राग उल्लेख रहते हैं। कामाख्या धाम तथा वामुण शुवालकुछि में संरक्षित मनकर की मनसा गीत में राग–रागिणी का उल्लेख है।

मनकर के समसामयिक दुर्गावर की मनसा या पाँचाली गीत में राग–रागिणी का उल्लेख है। दुर्गावर द्वारा रचित गीति रामायण उल्लेखनीय काव्य है। मनकर की तरह दुर्गावर भी सु–गायक थे जिनमें भारतीय शास्त्रीय संगीत में रहने वाला समस्त परंपरा समाहित है। उनके काव्य में षटमंजरी, भौरवी, धनाश्री, वलोयार, वराड़ि, गुंजरी, रामगिरि, भाटियालि आदि राग–रागिणी प्रयुक्त थे।

मानकर, दुर्गावर के उपरान्त पीताम्बर द्विज जी ने हरिवंश के आधार पर पांचाली गीत के शैली में 1533 में उषा–परिणय काव्य की रचना की थी। पाँचाली गीत के शैली में रचना करने के कारण इस काव्य को भी गीत कहा जाता है।

नारायण देव जी ने पाँचाली गीत के आधार पर मनसा पदावली – विषहरि गौरव गरिमा नामक पुराण सदृश काव्य प्रणयन किया। इसको ही बाद में पद्म–पुराण या मनसा काव्य के रूप में आख्या देकर पुराण गीत नाम से अभिहित किया है।

वरगीत :

असम के नव वैष्णव धर्मीय संगीत या सत्रीया संगीत में राग–रूप का प्रचलन का आभास मिलता है। शंकर देव तथा माधव देव द्वारा रचित अंकिया नाटक के गीतों में 30 प्रकार की राग रूप पाया जाता है। अहीर, कानड़, कामोद, केदार, कौ, गौरी, तुड़, तुड़वसंत, धनश्री, नाट, वेलोवार, भाटियाली, भूपाली, मल्लार, माहुर, रामगिरि, ललित, वसंत, धनश्री, गान्धार, श्री गौरी आदि।

शंकरी सत्र में प्रचलित संगीत धार में प्रचलित राग को दो भागों में विभक्त किया जाता है –वन्धा राग और मेला राग। वन्धा राग को पूजा राग के रूप में जाना जाता है।

शंकरी सत्र, कमला बारी सत्र में ओजापालि में वन्धाराग में गीत पद गाते हैं। जबकि आउनी आती तथा दक्षिन पाट आदि दामोदरी सत्र में दोनों में गीत पद गाते है।

पाँचाली संगीत :–

पाँचाली संगीत पद से ही पाचाली संगीत उद्भव हुआ है। पाचाली संगीत का ऐतिह्य असम में प्रचलित ओजापालि अभिनय कला से है। इसका उद्भव पांचाल देश में माना जाता है। इसका मूलतः पाँच अंग है– आरोहण, गुरुवन्दना, दिहा, पद या गीत, अंत।

असमीया ओजापालि यानि जिन लोगों ने मनसा विषयक संगीत पर अभिनय करते है। उस गीत में उल्लेख्य पाँच अंग प्राप्त है।' असम में प्राप्त पाँचाली संगीत को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है–

1. महाकाव्यीय ओजापालि।
2. मनसा विषयक ओजापालि।
3. विविध विषयक ओजापालि।

1. महाकाव्यीय पाँचाली :

महाभारत, रामायण, पुराण आदि के आधार पर रचित पाँचाली संगीत को महाकाव्यीय पाँचाली कहा जाता है। दुर्गावरी गीति रामायण, पीताम्बर द्विज द्वारा रचित ऊषा परिणय आदि।

2. मनसा विषयक पाँचाली :

मनसा देवी या पद्मावती देवी के कथा के आधार पर लिखित कथा को मनसा विषयक पाँचाली कहा जाता है। मनकर, दुर्गावर, नारायण देव रचित मायावती विषहरी देवी के संगीत इस परंपरा में आते है।

3. विविध विषयक पाँचाली :

उक्त दोनों परम्परा से रहित धर्म विषयक संगीत की विविध विषयक पाचाँली के अंतर्गत आते है। ये पाँचाली धर्म, उपासना से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की गीत अकेले या झुंड में गाया जाता है। इसमें श्री सत्यनारायण पाँचाली, श्री शिव पाँचाली, शीतला पाँचाली आदि आते है।

पाँचाली ओजापालि और उन लोगों की गाते हुए गीतों की परिचय इस प्रकार है :–

(1) **मनकरि ओजापालि** – मनकर का मनसा गीत गाते हैं।

(2) **दुर्गावरी ओजापालि** – दुर्गावर का मनसा गीत गाते हैं।

(3) **सुकनानी ओजापालि** – नारायण देव द्वारा रचित पद्मपुराण के गीत पद गाते हैं।

(4) **पद्मपुराण गाण** – वही।

(5) **भाषण गाण** – उल्लेखित सभी पुराण गीत गाते हैं।

(6) **वारी पुराण गाण**– उल्लेखित पुराण गीत गाते हैं।

(7) **मारे गान** – पाति राभा समाज में मौखिक परम्परागत विषहरि कथावृत्त गीत है।

(8) **विषहरि गाण** – मनकर और दुर्गावर द्वारा रचित। मनसा गीत गाते है।

(9) **तुकुरिया ओजा पालि** – मैखिक प्रचलित गीत पद गाते हैं।

नव वैष्णव युग में संत कविगण पाचाली पद से समादृत नहीं थे। जिस कारण इस युग के कविगण इस प्रकार के गीत रचना के लिए आग्रही नहीं हुए। महेश्वर नेओंग ने उषा परिणय काव्य के आमुख में लिखा है– 'विद्याठाकुर रचित चरित में उल्लेख है पद (73–76) शंकर नाति चतुर्भुज ठाकुर विष्णुपुर सत्र में रहते विद्या ओजा के घर में जाते समय पुखिया ओजा आते है कीर्तन करिते।'[9]

वह पाचाली गीत गाने के लिए शुरु करते ही चतुर्भज ठाकुर चले जाते है–

पाचालीर चन्दे गीत गाईवाक लागिला
सुनि आता तेखने संभार उठि गैईला।[10]

मूलतः पाचाली गीत नववैष्णव धर्म के कविगण के समादृत न होते हुए भी महाकाव्य भित्तिक तथा वैष्णव भावापन्न परिवेश्य कला शैली ओजा पालि के द्वारा पाचाली संगीत शैली परितक्त होते हुए भी सर्गदेवी मनसा पूजा के साथ जुरा हुआ होने के कारण ओजापालि रूप में आज भी पाचाली संगीत का परम्परा चले आ रहे है।

ओजापालि मूलतः ओजा पालि से बना है। ओजा का उप संस्कृत के उपाध्याय से तथा पालि आंचलिक शब्द जिसका अर्थ सहायकारी। गीत, पद गाते समय जो व्यक्ति ओजा को सहायता करते है उस पालि कहते है। पालि का कई भेद है – डाईना पालि, गोर पालि और आग पालि। महापुरुष शंकरदेव ने वैष्णव धर्म प्रसार करते समय ओजापालि का सहाय लिया था।

व्यास ओजापालि का ओजा–लम्बा चापकन पहनाव पहनकर सिर में पागरी पहन लेने के साथ साथ पैर मे घुंघरू भी बांध लेते है। पालि सभी ताल बजाकर व्यास ओजा पालि गाते हैं।

ओजापालि गीत–पद और नृत्य, वाद्य का त्रिवेणी संगीत है और ओजापालि गीत–नृत्य में है एक विशेष शेष प्रकार की स्वर, लय जो गन्धर्व संगीत में है। इसलिए ओजापालि को भी गन्धर्व संगीत कहा जा सकता है। ये पंचाग संगीत है जिसमें आलाप, गुरु वन्दना, विष्णुपद, संगीत और झुनागीत है।

परम्परागत शास्त्रीय संगीत का शुभारंभ आप से आलाप से होता है। आलाप या स्वर साधना हा–ता–ना–रि–रिता से होता है जिसक का सांकेतिक अर्थ क्रमानुसार गणपति, सद्शिव, महामाया, कृष्ण गन्धर्व है। जिसका परवर्ती अंग गुरु वंदना है। ओजापालि गुरुमुखी विद्या होने के कारण पहले गुरु को स्मरण किया जाता है। व्यास ओजापालि तीसरी अंग का नाम 'विष्णु पद' है जो नृत्य प्रधान है। जो विष्णु राग में गाया जाता है। विष्णुपद के उपरान्त 'गीत–गोविन्द' में उल्लेखित 'दश अवतार' का गीत गाते थे किन्तु आजकल शंकर देव कृत 'कीर्तन घोषा' का दश अवतार का गीत गाते हैं।

विष्णु पद के परवर्ती अंग 'गाणक राग' या चवरवाना राग है। ये राग दूसरी राग से भिन्न होने के कारण इसे गोर–वान या प्रथम राग भी कहते हैं। चावरवाना राग का शास्त्रीय नाम मालव राग है। इस राग का सात स्तर है। प्रथम चरण से उपर उठकर चौथे चरण में चरम पर पहुंचते है और पंचम से क्रमानुसार उतार की और आकर सप्तम चरण में समाप्ति लाभ करते है। गीतपद और विशेषता के आधार पर ओजापालि के स्वरालाप को पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है– गाथा, राग, वाना, दिहा, पद।

1. गाथा :

गाथा का अर्थ गीत का कहानी, ओजापालि काल में राग–रागिनी जन्म विषयक गीत–पद को गाथा कहा जाता है। संस्कृत परम्परा में इसको राग ध्यान कहा जाता है। सारंग राग के गाथा का एक उदाहरण देखिए–

जगत संहारि प्रभु प्रलय जलत।
ब्रह्माक सजिला प्रभुर नाभि कमलत।।
उपजिया ब्रह्मादेवे चतुर्दिक छाईला।
चाहते ब्रह्मार तवे चारिमुख भैला।।
चित्र सेन गन्धर्वे सेहि राग गाईला।
तुष्ट हुया ब्रह्माई सारंग नाम भैला।।

2. राग :–

गाथा में जिस राग का जन्म कथा कहा जाता है। उसी राग में गीत–पद गाना पड़ता है। प्रत्येक राग, पद छन्द की आश्रय लेकर गाया जाता है। अन्य छंद में उक्त राग गाने की परम्परा व्यास–ओजापालि परम्परा में निषिद्ध है– 1. स्वर–साधना, 2. उपस्थापन, 3. स्वर का आरोह क्रम, 4. गाथा का जन्मालाप, 5. चरन, 6. अवरोह 7. पद आराही और अवरोही स्वर का समन्वय।

3. वाना :–

नाट्यशास्त्र के अनुसार उच्च सर में गाने वाले पद के सुर को वाना कहा जाता है।

दिहा :

वाना के बाद में ही 'दिहा' आते है। स्थायी और दिहा में कोई अन्तर नहीं है। विशेष प्रकार की एक सुर को पुनः पुन आवृत्ति को स्थायी कहते है। दिहा गाकर समाप्त करते ही पद गाया जाता है। पद की अर्थ को कोपकथन के माध्यम से दर्शक को रस रंजित रुप में समझा देता है।

झुना या सुबह की गीत :–

व्यास ओजापालि में अन्तिम चरण में झुना गीत गाते है।

झुना गीत प्रायः शृंगार रस प्रधान होता है। ब्रह्म मुहुर्त में पूर्वी राग में गाये जाने वाले गीत को झुना गीत कहते।

राग-रागिणी :– व्यास ओजापालि परम्परा में राग :

रागिणी की सभी प्रकार के सुर का प्रचलन देखा जाता है। राग का राजा 'मालव' राग के अलावा अन्य राग–रागिणी सारंग, सु–सारंग, वावरि, चालन, वसन्त, भैरवी, रामगीरि आदि का जन्मालाप गाथ पाया जाता है। व्यास ओजापालि परम्परा में सभी राग सभी समय नहीं गाया जाता है। इन सब गाने का निर्दिष्ट समय निश्चित

है। गान्धार, गन्दगिरि, पाहारी, श्याम गरा, धनश्री, दिदागरा, कल्याण, लेली, श्री गान्धार मेघमल्लार, दीपक, अहीर, भाटियाली, केदार, कारुण्य आदि का भी प्रयोग व्यास ओजापालि में परम्परागत रूप में प्रचलित है।

राग ध्यान :– भारतीय संगीत परम्परा में राग–रागीणी :

स्वकीय रूप रहने का विश्वास है जिसको राग ध्यान कहते है या राग लक्षण कहते हैं। इसमें स्थान प्राप्त राग–रागिणी का 'नादमय रूप और 'देवतामय रूप' का अभिव्यक्ति दृश्य मान है। इस प्रकार रागध्यन और राग का परम्परा शुरुआत हुआ है। किन्तु ओजापालि में इसको 'राग–गाथा' शब्द का ही प्रयोग किया है। कवि राम स्वरस्वती ने भी राग–मालिता या राग गाथा को ही स्वीकार किया है।

राग गाथा –

गाथा यानी जन्म सम्बन्धी वर्णना। इसकी सृष्टि मूलतरू मिथ भी कहा जा सकता है। राग–रागिणी की जन्म संबंध को रागमालिता कहा जाता है। व्यास ओजापालि संगीत में प्रत्येक राग–रागिणी की गाथा पाया जाता है। किन्तु मालव राग का गाथा नहीं है क्योंकि इनको राग का राजा माना जाता है।

राग–रागिणी गाने का समय :–

असमीया व्यास ओजा पालि की परम्परा के अनुसार हर राग–रागिणी सब समय में गाया नहीं जाता है। इसके लिए निर्दिष्ट समय निर्धारित किया जाता है। जैसे–

1. प्रभात या भोर में – पूर्वी।
2. दोपहर में – भैरवी, धनाश्री।
3. अपरान्ह में – श्री गान्धार, कल्याण, वावरि।
4. संध्याकाल में – रेलि, चौरथ, वेहाग।
5. रात की पहलार्ध – सारंग, मेध।
6. पिछली रात में – रामगिरी, वसंत, सुहाई।

स्वर साधना – ओजापालि भारतीय शास्त्रीय संगीत परम्परा के आधार पर विकसित है। इसलिए व्यास ओजापालि के संगीत स्वर को–घोर (मध्य), मन्द्र (मन्द्र) और चार (तार) इस तीन भागो में विभक्त किया गया है।

ताल – व्यास ओजापालि संगीत धारा में प्ररम्परागत रूप में पाँच प्रकार की ताल प्रचलित है। चाव ताल, चौताल, जिकरि ताल, लेचेरी ताल, थोकाताल।

नृत्रा – नृत्य के बिना संगीत की पूर्णता नहीं आता (संगीत वाचिक व्यापार और नृत्य गोत का चाक्षुक अभिव्यक्ति)। संगीत का रूप नहीं रहता है, किन्तु इसको रूप प्रदान करते है नृत्य। संगीत की सौन्दर्य और माधुर्यता का प्रकाश नृत्य से ही मिलता है। व्यास ओजापालि गीत, नृत्य और नाट्य का त्रिवेणी है। इसमें पाँच प्रकार की नृत्य की स्थिति प्राप्त है। वह है मयुर नृत्य, हंसिनी नृत्य, धुपुनि, नृत्य, नटी नृत्य और घुरनी नृत्य।

गति – व्यास ओजापालि में गति की परिभाषा चाल चलन, खोज आदि पद से अभिहित है। अभिनय दर्पन के अनुसार गति चार प्रकार के है। मण्डल, उत्प्लावल, भ्रमरी और पदचारी। इसमें चारों गति प्राप्त है।

इस प्रकार असमीया अभिनय कला ओजापालि मूलतः भारतीय कथकीय परम्परा का एक उत्कृष्ट शास्त्रीय संगीत, नृत्य और नाट्य के संयोग से सृष्ट एक अभिनय कला है। जिसमें समस्त शास्त्रीय परम्परा का सुन्दर परिपाक हुआ है।

संदर्भ :

1. Ragas and Raginis Introduction- Page-1 Oc Ganguly.
2. गीत गोविन्द राम सरस्वती – Page–109, संपादक – सत्येन्द्र नाथ शर्मा।
3. मंगलदैर बुरंजी, चंहम– 118–119, दीनेश्वर शर्मा।
4. प्राण्डक्त ग्रन्थ,चंहम–109, सम्पादक–सत्येन्द्र नाथ शर्मा।
5. असमत संगीत चर्चा (रामधेनु), Page–84, आचार्य मनोरंजन शास्त्री।
6. संवाद दाता, गंधराम वायन, शुवालकुछि।
7. नाट्यशास्त्र, श्लोक 13/37, भरतमुणि।
8. नाट्यशास्त्र, श्लोक 14/45, संपादकः मनमोहन घोष।
9. उषा परिणय, Page 38, संपादक : महेश्वर नेओग।
10. वही, संपादक : महेश्वर नेओग।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 35-41

संसदात्मक शासन पद्धति के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री की भूमिका

प्रो. डॉ. मन्जू सोलंकी, निर्देशिका
सुधीर कुमार, शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग, श्री वेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, अमरोहा।

शोध आलेख सार –

सरकार के अगो को पारस्परिक सम्बन्धों के आधार शासन व्यवस्था के दो भाग है। 1. संसदात्मक शासन व्यवस्था, 2. अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था संसदात्मक शासन व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। किन्तु समस्त शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रीमण्डल के साथ करता है। प्रधानमन्त्री समस्त संवैधानिक एवं क्रियाशील शक्तियों का एक मात्र प्रतीक बन जाता है।

मुख्य शब्द – प्रधानमन्त्री, संसदात्मक, सरकार, भारतीय संविधान, भूमिका, संवैधानिक।

भारतीय संविधान, 1950 के अनुसार भारतीय सरकार का संसदीय स्वरूप देश की राजनीतिक संरचना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जो भारतीय लोगों की अनूठी आवश्यकताओं और विविधताओं को सन्तुलित करते हुये ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है।

भारतीय संविधान के भाग 5 में निहित अनु0 74 और 75 राष्ट्रपति, मंत्रीपरिषद और संसद के प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करते है, जो समूहिक रूप से भारत के अन्तर्गत संसदीय प्रणाली को आकार प्रदान करते है। भारतीय संसद प्रणाली के केन्द्र में राष्ट्रपति है, जो राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनु0 52 से लेकर 62 तक संविधान द्वारा निर्धारित कुछ शक्तियाँ और कर्तव्य राष्ट्रपति के पास है। किन्तु वास्तविक कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रिपरिषद के पास है।

”यद्यपि राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति कहा गया है तथापि शक्ति संरचना का मूल–स्रोत ब्रिटेन के समान प्रधानमन्त्री ही है। कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धान्त को छोड़कर ब्रिटेन में संसद की सम्प्रभुता का स्थान आज मन्त्रिमण्डल की सम्प्रभुता ने ले लिया है। यह मन्त्रिमण्डल की सम्प्रभुता अन्ततः प्रधानमन्त्री की सरकार की सम्प्रभुता है।”[1] प्रधानमन्त्री को राज्य रूपी जहाज का पालक कहा गया है। उसे सम्पूर्ण संविधान की आधारशिला कहना उपयुक्त होगा। हम्फ्री बर्फले द्वारा इस अभिमत में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के पद की वस्तुस्थिति प्रकट की गई है। ”वैस्टमिनिस्टर में संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त हो चुका है। ब्रिटिश व्यवस्था का मूल दुर्गुण प्रधानमन्त्री के पास राज्याध्यक्ष से भी अधिक शक्तियों का होना है।”[2] भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा भारत में ब्रिटिश नमूने की संसदात्मक शासन प्रणाली की ही कल्पना की गई थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर आज तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री की महत्वपूर्ण

भूमिका रही है। प्रधानमन्त्री मुख्य प्रशासक, मुख्य नीति–निर्माता, मुख्य विधायक तथा मुख्य राजनयिक के रूप में राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित हुआ है। प्रधानमन्त्री के रूप में पं0 जवाहरलाल नेहरू तथा इन्दिरा गाँधी जैसे कुशल तथा आकर्षक प्रतिभा वाले नेताओं द्वारा क्रियाशील होकर राष्ट्र को स्थायीत्व प्रदान किया गया। निरन्तर होने वाली राजनीतिक घटनाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का नेता है, देश की राष्ट्र, परराष्ट्र, वित्त एवं सुरक्षा नीति के निर्माण में प्रधानमन्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राज्यों का राजनीतिक नेतृत्व अपनी स्वायन्तता के बजाय प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में विश्वास रखता है। राष्ट्रपति के चयन तथा निर्वाचन में प्रधानमन्त्री की पसन्द का ही विशेष महत्व है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का अन्तिम निर्णय उन्हीं का होता है। नीति–आयोग के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय अर्थनीति का निर्धारण प्रधानमन्त्री द्वारा ही होता है।

ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री के समान भारत के प्रधानमन्त्री का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत अत्याधिक महत्व है। ग्रोन्ज कहते है "सरकार राष्ट्र की स्वामी है और वह सरकार का स्वामी है।"[3]

30 जुलाई 1957 को पं0 नेहरू ने प्रधानमन्त्री के दायित्वों के सम्बन्ध में कहा था "मैं जानता हूँ कि प्रधानमन्त्री के क्या कर्तव्य है और संविधान के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री इस कील के सदृश है, जो सरकार रूपी चक्र की धुरी पर लगी है और चक्र को गिरने से रोकते रहती है।"[4] प्रधानमंत्री के कार्य इतने विस्तृत एवं विविध है कि उन्हें सूचीबद्ध करना बड़ा दुष्कर कार्य है। संक्षेप में प्रधानमन्त्री की भूमिका की चर्चा निम्न प्रकार से की जा सकती है।

1. प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल –

संविधान के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के परामर्श से ही अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करेगा। प्रधानमन्त्री को अपने सहयोगियों का चयन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। क्योंकि प्रधानमन्त्री को ही मन्त्रि परिषद के साथ काम करना होता है। वह किसी मन्त्री के आचरण से असन्तुष्ट होने पर त्याग पत्र की मांग कर सकता है। प्रधानमन्त्री को किसी भी मन्त्री की पदोन्नति अथवा पदावनति का भी पूर्ण अधिकार है। मन्त्रियों के बीच विभागों का विवरण भी वहीं करता है। प्रधानमन्त्री ही मन्त्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। यह कहना सत्य प्रतीत होता है कि प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद के निर्माण, जीवन तथा मृत्यु का केन्द्र–बिन्दु है।

2. प्रधानमन्त्री और संसद –

प्रधानमन्त्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमन्त्री द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किये जाते है।

1. शासन सम्बन्धी नीतियों की घोषणा प्रायः लोकसभा के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री द्वारा ही की जाती है।
2. लोकसभा सदस्यों द्वारा गम्भीर मामलों पर पूछे गये प्रश्नों का उत्तर प्रायः प्रधानमन्त्री द्वारा ही दिये जाते है।
3. संसद द्वारा प्रधानमन्त्री को अन्तिम प्रवक्ता और नीति स्रोत के रूप में देखा जाता है।
4. शासकीय विधेयक प्रधानमन्त्री की सलाह से तैयार किये जाते है।
5. देश की वित्त–व्यवस्था तथा वार्षिक बजट को निर्धारित करने में भी प्रधानमन्त्री का हाथ होता है।

3. प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति –

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना को देखते हुये यहीं निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रपति

नाममात्र के औपचारिक प्रधान है तथा वास्तविक कार्य प्रभुत्व प्रधानमन्त्री ही है। डॉ0 अम्बेडकर संविधान सभा में कहा था कि ”हमारे राष्ट्रपति की वहीं स्थिति है जो ब्रिटिश विधान के अन्तर्गत सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है, किन्तु कार्यपालिका नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किन्तु राष्ट्र पर शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है।” पं0 नेहरू ने भी कहा था कि ”हम सरकार की इस मन्त्रि मण्डलीय व्यवस्था पर बल देना चाहते है कि वास्तविक शक्ति मन्त्रिमण्डल और व्यवस्थापिका में निहित है न कि राष्ट्रपति में।”

कुल मिलाकर जिस प्रकार भारत में संविधान का कार्यान्वयन हुआ है, उससे निःसन्देह प्रधानमन्त्री की स्थिति दृढ़ हुई है और राष्ट्रपति ‘स्वर्णिम शून्य’ ही रहे है।

4. प्रधानमन्त्री और दल –

प्रधानमन्त्री अपने दल का नेता होता है। प्रधानमन्त्री से मतभेद होने पर दल के अध्यक्ष को हमेशा से ही मुँह की खानी पड़ी है। उदाहरणार्थ–नेहरू काल में आचार्य कृपलानी तथा पुरूषोत्तम दास टण्डन जैसे शक्तिशाली दल के अध्यक्षों को झुकना पड़ा। इसी प्रकार इन्दिरा गाँधी कांग्रेस पार्टी का करिश्माती सितारा बनकर उभरी और अपनी चतुराई से 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए संजीव रेडी के विरोध में वि0वि0 गिरि को विजयी बनाया।

5. प्रधानमन्त्री और नीति–निर्माण –

भारत की राष्ट्र व परराष्ट्र नीति निर्माता के रूप में प्रधानमन्त्री की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय नेहरू तो स्वयं महत्वपूर्ण नीति की घोषणा कर देते थे। बैंक राष्ट्रीयकरण, संविधान संशोधन आदि जितने भी क्रान्तिकारी निर्णय लिये गये, वे सब प्रधानमन्त्री के ही निर्णय थे। वस्तुतः प्रधानमन्त्री सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण करता है। इन सभी नीतियों में वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है।

6. प्रधानमन्त्री और आपातकाल –

राष्ट्रीय आपातकाल में प्रधानमन्त्री की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। संविधान के अनु0 352 से अनु0 360 तक में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। वास्तव में इन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री द्वारा ही किया जाता है। 1962 में चीनी आक्रमण के समय, 1965 में पाकिस्तानी लड़ाई के समय, सन् 1971 में बांग्लादेश निर्माण के समय क्रमशः पं0 नेहरू लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा इन संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग किया गया। संसद द्वारा भी संकटकाल के समय उनका पूर्ण समर्थन किया गया और तत्कालीन प्रधान मन्त्रियों को ‘राष्ट्र के सर्वोच्च नेता’ की स्थिति प्राप्त हुई।

7. प्रधानमन्त्री और राज्य –

भारत में अमेरिका की भाँति संघात्मक शासन को स्थापित किया गया है, किन्तु वह राज्यों की राजनीति का भी चालक बन गया है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का यथार्थ निर्णय भारत में प्रधानमन्त्री का ही होता है। राष्ट्रपति द्वारा तो उसकी एक औपचारिक घोषणा की जाती है। इन्दिरा तथा राजीव गाँधी के समय में तो मुख्यमन्त्रियों की नियुक्तियों में भी उनकी पसन्द को विशिष्ट महत्व दिया जाने लगा था। जिसके परिणामस्वरूप राज्य मन्त्रि मण्डल निर्माण भी प्रधानमन्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी।

8. प्रधानमन्त्री और नीति–आयोग –

राष्ट्रीय अर्थनीति का निर्धारण नीति–आयोग द्वारा किया जाता है और प्रधानमन्त्री इसके अध्यक्ष है। राज्यों

को दी जाने वाली अनुदान सघमता का निर्णय भी इसी संस्था द्वारा किया जाता है तथा यह संस्था प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में कार्य करती है।

9. प्रधानमन्त्री और अनुग्रह शक्तियाँ –

भारत के समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की सलाह से ही करते है। संविधान द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा के उपलक्ष्य में 'भारत रत्न', पदमविभूषण, पदमभूषण और पद्मश्री इत्यादि सम्मानजनक उपाधियों का वितरण की जो व्यवस्था की गई है, व्यवहार में ये उपाधियाँ प्रधानमन्त्री के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

10. महानिर्वाचन-प्रधानमन्त्री का निर्वाचन –

प्रधानमन्त्री अपने राजनीतिक दल का नेता होता है और महानिर्वाचन उसी के नाम से लड़ा जाता है। पं0 नेहरू काल में सभी महानिर्वाचनों का नारा एक ही था "कांग्रेस को वोट देकर पं0 नेहरू का हाथ मजबूत कीजिए।" 1972 में चुनाव श्रीमती गाँधी के नाम लड़ा गया था। चुनावों में जनता को "इन्दिरा हटाओ" या "इन्दिरा बचाओ" इन घनों में से किसी एक के पक्ष में मतदान करना था। ऐसे निर्वाचन में, जब इस दल को सफलता मिल जाती है, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमन्त्री की प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और वह देश का सर्वप्रमुख शासन बन जाता है। 1971, 1972, 1977, 1980, 1989, 1998 के समस्त चुनाव प्रधानमन्त्री पद पर ही केन्द्रीत थे।

11. प्रधानमन्त्री-देश का सर्वोच्च नेता और शासक –

प्रधानमन्त्री देश का नेता और कुशल शासक होता है। व्यवहार में समस्त नेता और कुशल शासक होता है। व्यवहार में समस्त शासन उसी की इच्छानुसार संचालित होता है। वह व्यवस्थापिका द्वारा अपनी इच्छा से कानून बनवा सकता है, संविधान में आवश्यक संशोधन करवाकर सर्वोच्च न्यायालय को भी बहुत कुछ सीमा तक अपनी इच्छानुसार चलने के लिये बाध्य कर सकता है। मन्त्री परिषद में उसकी स्थिति सर्वोपरि होती है। परिस्थिति वश भले ही कभी–कभी उसे अपने सहयोगियों के समक्ष झुकना पड़े, लेकिन अन्तिम रूप में प्रधानमन्त्री के निर्णय ही मान्य होते है। देश की जनता हो अथवा संसद, राज्य सरकारे हो अथवा प्रधानमन्त्री का अपना राजनीति दल, हर कोई नेतृत्व के लिये प्रधानमन्त्री की ओर हो देखता है।

यह भी सत्य है कि प्रधानमन्त्री की शक्तियाँ चाहे जितनी हो जाये, "संसद वह नींव है, जिस पर प्रजातन्त्र की भव्य इमारत खड़ी है। संसद वह स्रोतस्विनो, जो अपनी अविरल, निर्मल और उन्मुक्त धारा से प्रजातन्त्र के हर क्षेत्र को सींचती है, जिससे राष्ट्र को पोषण मिलता है।"[5] जब–जब सरकार को ऐसे गम्भीर प्रश्नों से जूझना पड़ा, जिनका सम्बन्ध अविरल राष्ट्र के कल्याण अथवा सुरक्षा से हो, तब–तब प्रधानमन्त्री ने विरोधी दल के नेताओं से विचार विमर्श किया तथा सरकारी निर्णयों को सर्वदलीय निर्णयों के स्तर तक उठाया। भारतीय प्रधानमन्त्री की शक्तियों पर कुछ महत्वपूर्ण नियन्त्रण इस प्रकार है।

1. **लिखित संविधान** – प्रधानमन्त्री द्वारा कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग लिखित संविधान की सीमाओं के भीतर ही करना पड़ता है।
2. **संघ व्यवस्था** – भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। प्रधानमन्त्री की कार्यपालिका शक्ति केवल उन्हीं विषयों तक सीमित है, जिन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है।

3. **संसदीय नियन्त्रण** – प्रधानमन्त्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के समर्थन के बिना वह कुछ नहीं कर सकता है। लोकसभा उससे प्रश्न पूछ सकती है, उसके विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती है तथा उसे त्याग पत्र के लिये बाध्य कर सकती है।
4. **दलीय नियन्त्रण** – प्रधानमन्त्री की सारी शक्ति दल के संगठन तथा दल से मिलने वाले समर्थन पर निर्भर करती है।
5. **लोकमत का नियन्त्रण** – प्रधानमन्त्री कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, जो लोकमत को पसन्द न हो। उसे अगले चुनाव का खतरा हमेशा बना रहता है।

हम्फ्री बर्कले ने अपनी पुस्तक 'दि पावर ऑफ दा प्राइम मिनिस्टर' में कहा है कि "संसद की सम्प्रभुता एवं प्रधानमन्त्री शक्तियों पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए प्रधानमन्त्री की शक्तियों में कमी की जानी आवश्यक है।"[6]

सत्य यह है कि भारत का कोई भी प्रधानमन्त्री भले ही कुछ समय तक समकक्षों में प्रथम रहा हो, किन्तु अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वह सूर्य रहा है, जिसके चारों और नक्षत्र घूमते है। भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री जन–जन के 'जवाहर' थे। शास्त्री जी को अपनी अपने सहज स्वभाव के कारण जनता का नेता बनने में देर नहीं लगी। उनके द्वारा आधुनिक भारत के इतिहास में एक स्थायी गौरवमय स्थान प्राप्त किया गया। इन्दिरा गाँधी के बारे में तो यह विश्वास ही करना पड़ेगा कि इन्होंने अपने व्यक्तित्व को उजागर करके इस पद की गरिमा और शक्ति में चार चाँद लगाये।

भारतीय राज व्यवस्था में प्रधानमन्त्री का पद सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पद है। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस पद पर आसीन हो जाता है, तो इसका लगातार महत्व बढ़ता जाता है। जोनिंग्ज ने लिखा है "प्रधानमन्त्री के पद की स्थिति अवश्य ही वह होगी जो उस पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति बनाना चाहेगा और अन्य मन्त्री उसे बनने देंगे।"

भारतीय प्रधानमन्त्री की शक्ति इतनी व्यापक है, जितनी विश्व के किसी शासक, यहाँ तक कि अमरीका के राष्ट्रपति को भी नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि प्रधानमन्त्री का कार्यालय शासन तन्त्र का स्थायी अंग बन गया है। वस्तुतः भारत में प्रधानमन्त्री की विशालतम शक्तियों को देखते हुये उसे प्रेसीडेन्ड प्राइम मिनिस्टर कहा जा सकता है।

भारत के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री की सशक्त भूमिका के कई कारण है।

1. आकर्षक व्यक्तित्व का होना।
2. महत्वपूर्ण निर्णयों का स्रोत 'प्रधानमन्त्री कार्यालय' है।
3. प्रतिपक्ष का असंगठित तथा दुर्बल होना।
4. संविधान के अन्तर्गत उपप्रधानमन्त्री के पद का न होना।

यह स्मरण रहे कि भारतीय संसदात्मक शासन प्रणाली के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री की स्थिति उसके व्यक्तित्व पर ही निर्भर करती है। व्यक्तित्व के अतिरिक्त को प्रधानमन्त्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले कई दूसरे तत्व भी है, जैसे प्रधानमन्त्री को अपने राजनीतिक दल के अन्तर्गत प्राप्त स्थिति, देश की राजनीति में उसके दल की स्थिति तत्कालीन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा व्यावहारिक राजनीति में प्राप्त सफलताएं एवं

असफलताएं।

प्रधानमन्त्री द्वारा तानाशाह पूर्ण ढ़ंग से कार्य करने की सम्भावनाएं पूर्ण रूप से गलत है। पं0 जवाहरलाल नेहरू को उपरोक्त सभी शक्तियाँ प्राप्त की, फिर भी उन्होंने एक तानाशाह के रूप में कभी कार्य नहीं किया। इन्दिरा गाँधी अपने अधिनायक वादी रवैये के परिणाम स्वरूप 1977 का चुनाव हार गई। किसी भी प्रधानमन्त्री की सत्ता का आधार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत सिर्फ नहीं है कि वह जनता की कितनी सेवा कर सकता है। आज तक के संवैधानिक इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत का प्रधानमन्त्री अपनी इतनी विशाल शक्तियों के बाद भी लोकमत के विरूद्ध स्वेच्छाचारी नहीं बन सकता है।

निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकताा है कि सभी प्रधानमन्त्रियों द्वारा अपने प्रधानमन्त्रीत्व काल को मन्त्रि मण्डीय भूमिका से ही प्रारम्भ किया है। धीरे–धीरे राजनीतिक स्थितियों में सुधार, सत्ता के विस्तार एवं पक्ष में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार उनके द्वारा अपनी भूमिका को उत्तरोत्तर विकसित किया गया है। प्रधानमन्त्रिय भूमिका के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री समस्त कार्यों तथा शक्तियों का केन्द्र बिन्दु होता है। सम्पूर्ण संवैधानिक तथा अतिरिक्त संवैधानिक उपसंरचनाएं उसके चारो ओर केन्द्रीत होती है। "कैबीनेट सरकार की भांति, 'प्रधानमन्त्री सरकार' में प्रधानमन्त्री समकक्षों में प्रथम ही नहीं होता, बल्कि वह केबीनेट रूपी मेहराब की आधारशिला होता है।"[7]

प्रधानमन्त्री समस्त संवैधानिक तथा क्रियाशील शक्तियों का एकमात्र प्रतीक एवं प्रतिनिधि बन जाता है। प्रधानमन्त्री की प्रधानमन्त्रीय भूमिका में मन्त्रि परिषद, नौकरशाही एवं केबीनेट सचिवालय का महत्व प्रधानमन्त्री की अपेक्षा कम हो जाता है। सम्पूर्ण मन्त्री परिषद एक व्यक्ति प्रधानमन्त्री में एकाकार हो जाती है। केबीनेट के मृत्यु, जन्म तथा अस्तित्व के लिए वह एकमात्र केन्द्रीय शक्ति का प्रतीक होता है। संसद उसे नियुक्त करने, नियन्त्रित करने या हटाने में अक्षम होती है। प्रधानमन्त्री को प्रधानमन्त्रीय भूमिका में न्यायपालिका की शक्तियाँ सीमित तथा प्रतिबन्धित हो जाती है।

प्रधानमन्त्रीय भूमिका का निर्वाह कौन कर सकता है? इस सन्दर्भ में डा0 शुक्ला ने लिखा है कि "यदि कोई प्रधानमन्त्री अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, निर्विवादीय नेतृत्व तथा राष्ट्रीय स्तर की ख्याति और लोकप्रियता के कारण अपने स्वयं के आधार पर प्रधानमन्त्री का पद प्राप्त करेगा तो निश्चित रूप से उसकी भूमिका प्रधानमन्त्रीय होगी।"[8]

प्रधानमन्त्री की सर्वोच्चता और उसका नेतृत्व संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक प्रभुत्व सिद्धान्त है। भारत में संघ से ही इस सिद्धान्त का पालन किया गया है। 1950–64 के कार्यकाल के अन्तर्गत पं0 नेहरू को मन्त्रिमण्डल पर पूर्ण सर्वोच्चता प्राप्त थी। शास्त्री ने सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कार्य प्रारम्भ किया था, लेकिन 1965 के भारत–पाक युद्ध ने उनके व्यक्तित्व को बहुत अधिक प्रभावशाली बना दिया तथा 1965 के अन्त तक मन्त्रिमण्डल पर प्रधानमन्त्री की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। 1966–69 के कार्यकाल में जो स्थिति थी, इसके सन्दर्भ में दूसरे विचार हो सकते है। 1969 तथा उसके बाद 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद से श्रीमती गाँधी की मन्त्रीमण्डल पर सर्वोच्चता स्थापित हो रही थी। प्रारम्भ से लेकर अन्तर तक प्रधानमन्त्री की सर्वोच्चता का प्रमाण यह है कि कभी किसी मन्त्री के प्रधानमन्त्री से मतभेद हुए तो सम्बन्धित मन्त्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, निभोगी, डा0 जॉन मथाई, डा0 अम्बेडकर, देशमुख, महावीर त्यागी, नन्दा, टी0 टी0 के छागला, अशोक मेहता और 1978 में चौ0 चरण सिंह, राजनारायण, वी0 पी0 सिंह और देवीलाल के

इस्तीफे इसी श्रेणी में देखे जा सकते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. हरीश खरे – भारत में प्रधानमन्त्री का पद–शक्ति, क्षमता एवं सम्भावनाएं, राज्यशास्त्र समीक्षा, पृ0 सं0 35
2. Humphry Berkeley - The Power of the Prime Minister Allen & Urivin, P. 116
3. Administrative Reforms Com, Reports of Government of India and its process work New Delhi, Govt. of India, P. 9
4. पुखराज जैन– भारतीय प्रधानमन्त्री– साहिल भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 1981, पृ0–39
5. डॉ0 ज्ञानवती दरबार– स्वतन्त्र भारत की झलक– अनामिका पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली। पृ0–36
6. हम्फ्री बकर्ले– दि पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर–पृ0 121
7. विमला शुक्ला– भारतीय संविधान में प्रधानमन्त्री की भूमिका–प्रभात प्रकाशन आगरा। पृ0–384
8. माइकेल ब्रेचर– सकसेशन इन इण्डिया, ऑक्सफोर्ड, पृ0 109
9. H.M. Jain. The Union Executive, Chaitanya Publication.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 42-47

हिंदी कहानी और आलोचना और नामवर सिंह

डॉ. हरिकृष्ण आचार
सहायक अध्यापक
दयानंदा सागर बिजनेस अकादमी, उदयपुरा, कनकपूरा मैन रोड, बेंगलूर–560082

शोध सार :

हिंदी साहित्य की आलोचना परंपरा में कहानी को केवल एक रचनात्मक विधा के रूप में नहीं, बल्कि एक वैचारिक और विमर्शशील उपकरण के रूप में भी देखा गया है। विशेष रूप से जब कहानी अपने भीतर सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अंतर्वस्तु को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, तो वह 'आलोचना कहानी' के रूप में विकसित होती है। आलोचना कहानी साहित्य का वह रूप है जिसमें लेखक केवल घटनाओं का चित्रण नहीं करता, बल्कि समाज की गूढ़ परतों, विद्रूपताओं और अंतर्विरोधों की पड़ताल करता है। यह शोध पत्र आलोचना–कहानी की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, साथ ही नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि का विश्लेषण करता है, जिन्होंने हिंदी आलोचना को वैचारिक गहराई और वस्तुनिष्ठता प्रदान की। नामवर सिंह का मानना था कि रचना का मूल्यांकन केवल कलात्मक सौंदर्य के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता और सामाजिक सरोकारों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। उन्होंने 'रचना के प्रति रचना से' की पद्धति द्वारा आलोचना को विशुद्ध साहित्यिक कर्म बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। यह शोध यह भी दर्शाता है कि नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि किस प्रकार से आलोचना कहानी की पाठ्य–व्याख्या में नई दृष्टि जोड़ती है। उन्होंने कहानी को वैचारिक संवाद के माध्यम के रूप में देखा, जिससे साहित्य की सामाजिक भूमिका सशक्त रूप में सामने आती है। इस प्रकार, आलोचना कहानी और नामवर सिंह की दृष्टि दोनों ही हिंदी आलोचना साहित्य में समकालीन संदर्भों में भी अत्यंत प्रासंगिक है।

बीज शब्द : आलोचना–कहानी, सैद्धांतिक आलोचना, नामवर सिंह, विचारधारा, हिंदी साहित्य, प्रगतिशील आलोचना, रचना–केंद्रित दृष्टिकोण।

मूल आलेख :

कहानी की विधा भारत की देन है। यह विधा बहुत पुरानी है, यह कहानी उपनिषदों, पंचतंत्र और हितोपदेशों में भी है। इन्हीं की माध्यम से वह विदेशों में फैली और विकसित होते हुए अलग–अलग रूपों में धरकर लोक मन में बस गई। आधुनिक कहानी को विदेशों से प्राप्त किया है। यह कहानी आगे बढ़ती हुई विविध रूपों में तब्दील होती गई है। ज्यों–ज्यों कहानी आगे बढ़ती गई त्यों–त्यों उस पर चिंतन करना प्रारंभ होता गया है। आधुनिकता मूल्य बोधक होती है आधुनिकता के मूल्यों में विवेक एक है। विवेक एवं संवेदना के योग का नाम

ही आलोचना है। आलोचना का संबंध मूलतः विवेक से होता है। आलोचना में विवेक के आधार पर कृति का मूल्यांकन किया जाता है। आलोचना के विवेक को अर्जित और विकसित करने वाले समर्थ आलोचकों में एक थे आचार्य नामवर सिंह।

आचार्य नामवर सिंह की कहानी आलोचना पर विचार करने से पहले कहानी आलोचना की परंपरा बोध पर विचार एवं विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। यदि बगैर परंपरा बोध के मानने योग्य आलोचना नहीं बन सकती, अगर कही बन भी जाए तो उसमें कहीं न कही गुणवत्ता की कमी दिखाई पड़ती है इससे बचने के लिए परंपरा बोध का होना अनिवार्य है।

हिंदी कहानी आलोचना की परंपरा बोध पर प्रकाश डाला जाए तो जाहिर है कि सन् 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी कृत 'इंदुमति' कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी के रूप में माना जाता है। हिंदी कहानी के प्रथम आलोचना पर कई सारे मतभेद है। जाहिर सी बात है कि कौन से मान एवं प्रतिमान होंगे? इन्हीं करण से ऐसा हुआ है। लेकिन आगे कालांतर में भारतेन्दु काल के प्रसिद्ध आलोचनक बालकृष्ण भट्ट ने सबसे पहले साहित्य की परिभाषा दिया था और उसी परिभाषा के तहत साहित्य का चिंतन भी किया था। उनका मानना था कि 'साहित्य जनसमूह के ह्रदय का विकास है'। उन्हीं मान एवं प्रतिमान के तहत साहित्य का चिंतन भी किया है। यहाँ आधुनिक काल (संवत् 1900) में कई सारे बदलाव हुए है। आधुनिक काल का संपूर्ण साहित्य राजाश्रय से जनाश्रय के साथ जुड़ने के लिए मजबूर होता है। यह आधुनिक साहित्य की देन है। यहाँ स्थिति ऐसी हो गई जो असाधारण पर साधारण की विजय है, और अलौकिकता पर लौकिकता की जीत है।

भट्ट जी ने सही कहा था कि कमल को जिस तरह सूर्य की आवश्यकता होती हैं उसी प्रकार साहित्य के जनसमूह के लिए आधुनिकता की जरूरत होती हैं। भट्टजी आगे लिखते है– "जैसे कमल को अपने विकास के लिए सूर्य की आवश्यकता है, वैसे ही सभ्यता को अपने विकास के लिए साहित्य की आवश्यकता है और सभ्यता का असर जितना अधिक देश के साहित्य पर पड़ता है और चिरस्थाई रहता हैं उतना किसी दूसरी बात पर नहीं। बिना साहित्य के सभ्यता वैसी ही फीकी है जैसे बिना नोन के भोजन।"[1] भट्ट जी का प्रभाव आगे कालांतर में प्रेमचंद के कथा साहित्य में झलकता है। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य एवं कथा आलोचना के माध्यम से जासूसी, ऐयारी एवं कल्पना के स्थान पर सामाजिक यथार्थ के साथ जोड़ देते है। प्रेमचंद ने कथा साहित्य का सृजन करने साथ–साथ कथा साहित्य पर चिंतन भी किया है। आगे वे लिखते हैं कि– "जहाँ आनंद है, वहीं सत्य है। साहित्य काल्पनिक वस्तु है पर उसका प्रधान गुण है आनंद प्रदान करना, और इसलिए वह सत्य है। मनुष्य ने जगत् में जो कुछ सत्य और सुंदर पाया है और पा रहा है, उसी को साहित्य कहते हैं और कहानी भी साहित्य एक भाग है।"[2]

प्रेमचंद सिर्फ कथा साहित्य में नहीं कथा साहित्य के चिंतन में भी यथार्थ को अधिक महत्व दिया है, वे कहानी को जीवन का यथार्थ मानते हुए लिखते है– "मगर यह समझना भूल होगा कि कहानी जीवन का यथार्थ चित्र है। यथार्थ जीवन का चित्र तो मनुष्य स्वयं हो सकता है, मगर कहानी के पात्रों के सुख–दुख से हम जितना प्रभावित होते है उतना यथार्थ जीवन से नहीं होते–जब तक वह निजत्व की परिधि में न आ जाये। कहानियों में पात्रों से हमें एक ही दो मिनट के परिचय में निजत्व हो जाता है और हम उनके साथ हँसने और रोने लगते हैं। उनका हर्ष और विषाद हमारा अपना हर्ष और विषाद हो जाता है।"[3] प्रेमचंद जी मानते हैं कि कहानी की

गतिशीलता को जीवन की घटनाएँ प्रभावित नहीं करती बल्कि पात्र उसको प्रभावित करते हैं। पात्र अगर गतिशील होगा तो कहानी भी खुद–ब–खुद गतिशील होगी। वे कहानी की वास्तविकता की तलाश करते हुए उसके पात्रों के चरित्र को अधिक महत्व देते हैं। इससे झलगता है कि प्रेमचंद की आलोचना में आदार्शोन्मुक यथार्थावाद दृष्टि नजर आती है।

हिंदी कहानी पर चिंतन करने की परंपरा आगे विकसित होते हुए प्रेमचंद से जैनेन्द्र कुमार में तक फैल जाती है। जैनेन्द्र ने भी कथा साहित्य का सृजन करने के साथ–साथ कथा आलोचना पर चिंतन किया है। जैनेन्द्र कुमार ने प्रेमचंद की आलोचना दृष्टि को बरकरार रखते हुए मानते हैं कि कहानी जीवन के आरंभ से आज तक कहानी का एक ही उद्देश्य रहा है, जीवन के उपकरणों द्वारा अपने को व्यक्त करना रहा है। यहाँ अनुभूति की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। वही कहानी अधिक सफल मानी जाती जिसमें जीवन की मार्मिकता को दर्शाते हुए, सत्य एवं यथार्थ का बोध से जुडे हुए है। उसमें भी सबसे ज्यादा कहानी के पात्रों एवं चरित्र का अधिक महत्व है। जैनेन्द्र कुमार लिखते हैं कि– "अपने चुनाव में मेरा मन कहानी पर ही रहा है, उनकी विधाओं और उपकरणों पर नहीं। उपकरणों पर बल देने वाली बोध दे सकती है रस नहीं देती। और रस न दे, उसे कहानी किस हिम्मत से कहा जाये।"[4] अर्थात् जैनेन्द्र कुमार मानते हैं कि कहानी में बोध (समझ) एवं रस दोनों का होनी जरूरी समझा है। यहाँ जैनेन्द्र की आलोचना में प्रेमचंद की दृष्टि से देखा जा सकता। वे बोध को आदर्शवाद और रस को यथार्थवाद से जुड़ते हैं। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जैनेंन्द्र ने प्रेमचंद से सहमत होते हुए उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया है।

दरअसल कहानी आलोचना की परंपरा विकसित होते हुए नई कहानी के दौर में सशक्त एवं सक्रिया होते हुए अनेक विमर्शों को जन्म देती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हिंदी कहानी की आलोचना का सही मानने में इस का नई कहानी के दौर में ही शुरूआत होता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि नई कहानी के दौर में नई कहानी पर चिंतन करने वाले दो सक्रिय आलोचक हुए हैं, उनमें एक डॉ. देवीशंकर अवस्थी दूसरे और दूसरे आचार्य नामवर सिंह है। नामवर जी कहानी समीक्षा को सहयोगी प्रयास के रूप में शुरू करते हुए कहते है कि आज की हिंदी कहानी के रूप में जरूर तब्दील हुई है। जैसे कवियों की तरह कहानीकारों ने भी शिल्प को लेकर नए प्रयोग करने की प्रवृत्ति को अपनाया है। लेकिन नामवर जी ऐसा मानते हैं कि यह प्रवृत्ति सिर्फ प्रयोग करने के लिए लिखी गई है। आगे कहानी एवं नई कहानी में भेद करते हुए लिखते है कि– "जो छोटी–सी बात पुराने कहानीकारों के लिए अपर्याप्त थी, उसी को नये कहानीकारों ने कहानी के लिये पर्याप्त मान लिया है और फिर उसके भीतर से उन्होनें कहानी के कथानक की विभिन्न सिम्तों का विकास किया है। इसी दिशा में नया कहानीकार कभी–कभी इतना अंतर्गूढ होता है कि बातों में से बात का यह निकालते जाना ही इतना मनोरंजक होता है कि एक कहानी बन जाती है। परंतु यह कौशल वही दिखा सकता है, जिसके पास बातचीत करने की उत्कृष्ट कला हो और साथ ही भाषा की बारीकियाँ भी।"[5] यहाँ नामवर जी मानते हैं कि पुराने कहानीकार के लिए जो चीज महत्व नहीं है लेकिन वहीं चीज नये कहानीकार के अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। वे कहानी के लिए कुशलता, बौद्धिकता के साथ भाषा की भी ज्ञान होना जरूरी मानते हैं।

नामवर जी कहानी आलोचना में घटना प्रसंग पर चिंतन करते हुए बहुत खेद प्रकट करते है। वे खास कर कहानीकारों में सामाजिक दृष्टि कमी के कारण ऐसी कृतियाँ खोखले बनते जा रहे हैं। यह कहानीकारों की

कमजोरी समझते है। वे कहानी की सफलता पर विचार करते हुए लिखते हैं कि लोक जीवन का मुग्ध एवं मार्मिक रूप बताना अपने आप में बहुत बड़ा गुण होता है, वह गुण तो मात्र अनुभवी कहानीकारों में उपलब्ध होता है। कहानी के सृजन में सामाजिक दृष्टि के साथा घटना प्रसंग तथा जीवन की वास्तविकता को चित्रण करने की क्षमता होना चाहिए। आगे नामवर जी लिखते हैं कि– "यह साभिप्राय घटना–प्रसंग सर्वथा कल्पित अथवा अविश्वसनीय भी हो सकता है और अत्यंत वास्तविक भी। घटना– प्रसंग जितना ही वास्तविक होगा, कहानी उतनी ही जोरदार होगी।"[6] यहाँ नामवर जी कहानीकार में वास्तविक जीवन की अनुभूति एवं वास्तविक जीवन संघर्ष को ग्रहण करने की क्षमता आवश्यक मानते हैं। यदि मुक्तिबोध की बातों में कहा जाए सही होगा, वे कहते है 'जीवन विवेक ही साहित्य का विवेक हैं।' नामवर जी के विचारों से लगता है कि कौन सी बात पाठको समझ में आ जाएगी है और कौन सी बात पाठकों को समझाना है इसका ध्यान वहीं रखता जिनके पास जीवन के अनुभूतियों गहरा दृष्टि होता है। आगे वही कहानीकार कहानी के सृजन में सफल होते हैं।

नामवर जी कहानी की सफलता और सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए कहते है कि यह कहानी का दुर्भाग्य है कि कहानी को मनोरंजन के रूप में पढ़ी जाती और शिल्प के रुप में आलोचना किया जाता है। नामवर जी लिखते है– "छोटी मँह बड़ी बात कहने वाली कहानी के बारे में प्रायः बड़े मुँह छोटी बात कही जाती है। कहानी का यह दुर्भाग्य है कि वह मनोरंजन के रूप में पढ़ी जाती है और शिल्प के रूप में आलोचना होती है। मनोरंजन उसकी सफलता है तो शिल्प उसकी सार्थकता! कहानी में अनेक आलोचकों को दिलचस्पी इतनी ही है कि वह साहित्य का एक रूप है।"[7] इससे जाहिर होता है कि शास्त्रीय आलोचक कहानी को केवल साहित्य का रूप मानते है तो मूल्यवादी आलोचक जीवन की सार्थकता अनुभूतियों के लिए असमर्थ मानते है। नामवर जी कहते है कि संभव है कि जीवन के लघु प्रसंग को लेकर लिखी जाने वाली कहानियाँ, स्वयं भी लघु समझी जाती है। अंत में वे कहते हैं कि व्यापक जीवन दृष्टि रखने वाले स्वभाव से कहानी जैसे विधा को छोटी चीज समझ कर उन्हें नजरअंदाज किया जाता है।

नामवर जी नई कहानी की सफलता एवं सार्थकत पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि– "कहानी में जब मैं सार्थकता की बात करता हूँ तो इसका यह अर्थ है कि कहानी हमारे जीवन की छोटी–से–छोटी घटना में भी अर्थ खोज लेती है या उसे अर्थ प्रदान कर देती है।"[8] यहाँ नामवर जी नई कहानी की सफलता छोटी घटना से होता मानते है। पुराने कहानीकारों के लिए जो घटना निरार्थ होता है लेकिन वही घटना नई कहानीकारों के लिए सार्थक हो जाता है। वे मानते हैं कि वही कहानीकार सफल एवं सार्थक माना जाता है जो कि जीवन की हर छोटी घटना के भीतर से संपूर्ण जीवन की सार्थकता अनुभव करता है।

दरअसल नामवर जी आज की हिंदी कहानी की भाषा पर प्रकाश डालते हुए कहते है कि– "भाषा इधर की कहानियों की काफी बदली है, यह कह सकते है कि माँजी है। यहाँ तक कि हिंदी गद्य का अत्यंत निखरा हुआ रूप आज की कहानी में ही सबसे अधिक मिलता है। कहानी में एक भी फालतू शब्द न आये, इसके प्रति आज का लेखक बहुत सतर्क है और शुभ लक्षण है।"[9] वे मानते हैं कि आज के कहानीकार के लेखन में हर शब्द किसी न किसी अर्थ को समझाता है और कोई भी शब्द पालतू नहीं है। यह स्थिति आधुनिक के साथ हर व्यक्ति के जीवनशैली की फितरत बन गयी है।

हिंदी कहानी की आलोचना करते समय कला एवं भाषा पर विशेष रूप से ध्यान रहना अत्यंत आवश्यक

हैं। नामवर जी आगे लिखते हैं कि –"नई कहानी को कहानी–कला की अपनी विशेषता के साथ ही संपूर्ण साहित्य के मान और मूल्यों के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है और इसके लिए कहानी समीक्षा की एक व्यापक निश्चित भाषा का भी निर्धारण होना चाहिए। मेरी अपनी सीमा यह है कि मैं अब तक मुख्यताः काव्य का पाठ रहा हूँ। कहानियाँ मैंने कम पढ़ी हैं और उनमें अंतर्निहित सत्य को समझने और व्यक्त करने की भाषा भी अब तक नहीं तय कर पाया हूँ।"[10] इससे झलकता है कि नामवर जी कहानी की कला में मूल्यों एवं भाषा पर अधिक बल देते हैं।

आचार्य नामवर सिंह की कहानी की दृष्टि पर चिंतन किया जाए तो मुझे हिंदी के युवा आलोचक डॉ. अभिषेक रौशन की पंक्तियाँ याद आती है। आगे वे लिखते हैं कि–"किसी रचना का सामाजिक आधार क्या है, उसकी सृजन के स्त्रोत क्या हैं, उसमें कौन–सी जीवन–दृष्टि निहित है, उसकी भाषा कैसी है, इन प्रश्नों से टकराकर ही आलोचना सही मायने में रचना में अर्थ का संधान कर सकता है। और आलोचना का दायित्व है कि रचना घटनाओं, चरित्रों के माध्यम से व्यक्त विचारधारा को व्याख्यायित करे।"[11] इस दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य नामवर सिंह ने कहानी की आलोचना करते हुए उपर्युक्त दर्शाए गये सारे पहुलुओं पर विचार विश्लेषण करते है। अगर गहराई से देखा जाए तो उन्में मार्क्सवादी विचारधारा दिखाई पड़ती है। नामवर जी ने अपने आलोचनात्मक विवेक से हिंदी कहानी आलोचना को मजबूत आधार प्रदान किया है जो कहानी आलोचना के इतिहास में नए और अर्थवान अध्याय को जोड़ते है। अतः लेखक एवं आलोचक के बीच के संबंध को एक अन्य कवि के शब्दों में कहा जाए तो बहुत सही होगा– When me they fly, I am their Wings.

उपसंहार :

हिंदी साहित्य में आलोचना कहानी एक ऐसी विधा के रूप में उभरकर सामने आती है, जो केवल कथा कहने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज के भीतर सक्रिय विचारधाराओं, संघर्षों और विरोधाभासों को उजागर करने का कार्य करती है। यह कहानी की उस प्रवृत्ति को दर्शाती है, जो पाठक को केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि बौद्धिक स्तर पर भी झकझोरने की क्षमता रखती है। आलोचना कहानी सामाजिक यथार्थ, सत्ता–व्यवस्था, वर्ग–संघर्ष, लैंगिक विमर्श जैसे अनेक जटिल प्रश्नों पर संवाद स्थापित करती है। नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि इस सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को और भी अधिक स्पष्ट करती है। उन्होंने साहित्य को केवल सौंदर्य के उपासक रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम माना। उनका 'रचना के प्रति रचना से' दृष्टिकोण आलोचना को किसी बाहरी मानदंड पर आधारित करने के स्थान पर स्वयं रचना की अंतर्वस्तु, संरचना और संवेदना से जुड़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने यह स्थापित किया कि आलोचना केवल टिप्पणी नहीं, बल्कि साहित्यिक विकास की प्रेरक शक्ति है। समकालीन संदर्भ में जब साहित्य का सामाजिक उत्तरदायित्व फिर से चर्चा में है, आलोचना कहानी और नामवर सिंह की दृष्टि हमें एक वैचारिक एवं मूल्यपरक आलोचना की दिशा दिखाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि आलोचना कहानी और नामवर सिंह का योगदान आज भी हिंदी साहित्य में प्रासंगिक, प्रेरणादायक और बौद्धिक विमर्श को समृद्ध करने वाला है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. बालकृष्ण भट्ट – हिंदी प्रदीप पत्रिका, नवंबर–दिसंबर, 1900, पृ सं–18

2. संपादक सत्यप्रकाश मिश्र – प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध, पृ. सं–102
3. संपादक सत्यप्रकाश मिश्र – प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध, पृ. सं–103
4. संपादित जैनेद्र कुमार– हिंदी 23 कहानियाँ, भूमिका (साहित्य अकादमी की ओर से), पृ. सं–10
5. नामवर सिंह– कहानी नई कहानी, पृ. सं–14
6. नामवर सिंह– कहानी नई कहानी, पृ. सं–15
7. नामवर सिंह– कहानी नई कहानी, पृ. सं–18
8. नामवर सिंह– कहानी नई कहानी, पृ. सं–26
9. नामवर सिंह– कहानी नई कहानी, पृ. सं–16
10. प्रो. नामवर सिंह– पहल पत्रिका, कहानी –नववर्षांक1958 – पृ. सं–36
11. डॉ. अभिषेक रौशन– बालकृष्ण भट्ट और आधुनिक हिंदी आलोचना का आरांभ, पृ. सं–22, 24

दूरभाष – 9611973301

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 48-58
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

Assessing the Role of Uttar Pradesh Government Poised to Become a US$1 Trillion Economy : A Qualitative Analysis

Dr. Prashant Singh, Assistant Professor,
Sejal Jaiswal, Research Scholar,
Department of Commerce, University of Lucknow, Lucknow, 226007, U.P.

Abstract :

The economy is the most crucial element of a country, as a strong economy provides prosperity, opportunities, and a better life for its citizens. India is on the path of becoming the world's third largest economy to serve its citizens better standard of living and increase its influence at the global level. Uttar Pradesh, being the third-largest economy among the states, has great potential to contribute to becoming the third-largest economy. To achieve India's goal of becoming US$ 5 trillion economy, the Government of Uttar Pradesh has set an ambitious target of transforming the state into US$ 1 trillion economy. The study uses secondary data and is a descriptive study that mentions the potential sectors in the state and examines key policy interventions, infrastructural developments, and sectoral initiatives driving growth across various sectors, investment in which is profitable for both investors as well as the state, and helps in achieving the state's target of becoming $1 trillion economy by 2029. The findings of the study highlight that to make use of the vast workforce available in developing Uttar Pradesh, it is necessary to provide them with skills for the emerging sectors like robotics, AI, health tech, etc. The government should focus on eco-friendly practices across sectors, infrastructure development in tier 2 and tier 3 cities, and accelerate digital infrastructure development to get holistic development of the state. Finally, the study concludes that with sustained efforts to strengthen infrastructure, ease of doing business, and innovation will accelerate Uttar Pradesh's journey toward becoming an industrial and investment powerhouse and help in achieving its aspirational target of $ 1 trillion economy.

Keywords : Uttar Pradesh, Economy, Government initiatives, $1 trillion, Investment, and Sectors.

1. Introduction

As an individual manages his limited resources to meet personal and familial needs while striving for a balanced and socially respectable standard of living, so does a country or region manage the scarce resources available to fulfil the needs and wants of its citizens. Apart from providing its citizens, a country aspires to raise the general standard of living by producing, distributing, and consuming goods and services efficiently. This complex system of economic activity and resource allocation serves as the basis for what is known as a country's economy, which results in the country's growth and development. Along with accelerating national growth and development, a strong and dynamic economy raises a nation's standing, influence, and longevity internationally.

India, the world's fifth-largest economy with an estimated GDP of $3.7 trillion in FY 2023–2024 and the third-largest in terms of purchasing power parity (PPP), is the best example of this vibrant economy. Over the past ten years, the Indian economy has maintained a robust average yearly growth rate of 6–7%, which has contributed to its growing global influence and led to both domestic and foreign investment, infrastructure development, innovation, technological advancement across industries, and the creation of job opportunities. Building on this success, Prime Minister Narendra Modi mentioned at the 2018 World Economic Forum that India will become a $5 trillion economy. A new period of economic proficiency, international power, and a higher standard of living for its citizens will arise from this. However, without significant contributions from its member states, this vision cannot be achieved.

Uttar Pradesh, India's most populated state and the third-largest economy in the country, with a wide range of economic factors, including agriculture, industry, services, and tourism, by recognizing its potential, set an ambitious goal: to transform the state into a $1 trillion economy by 2029. By making strategic investments in important industries and utilizing the state's sizable consumer base, well-connected infrastructure, such as highways and airports, and a growing industrial ecosystem, this vision seeks to promote inclusive development.

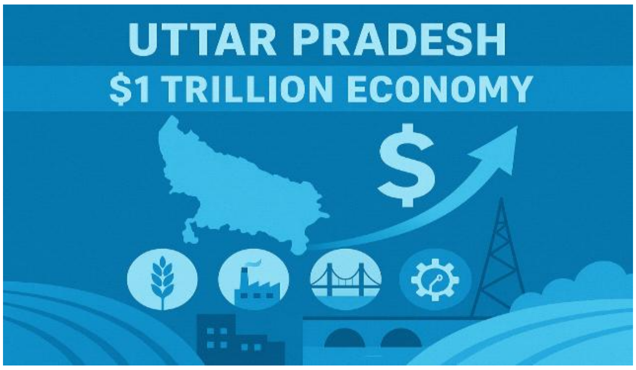

Source : Created by the author

Chief Minister Yogi Adityanath has ordered the creation of a thorough roadmap focused on ten priority sectors, such as infrastructure, education, tourism, law and order, and renewable energy, in order to operationalize this vision. Ensuring interdepartmental coordination and successful implementation in these crucial areas is the ultimate objective. The results of this kind of strategic planning are already apparent. With an impressive growth rate of 8%, Uttar Pradesh's Gross State Domestic Product (GSDP) increased from ?22.58 lakh crore in 2022–2023 to ?25.48 lakh crore in 2023–2024. The state is the 11th most attractive state for FDI inflows, with a total inflow of $1.7 Bn from October 2019 to September 2024, and $18.58 Bn Total merchandise exports of India in FY 2023-24**.** The state is well-positioned to quicken this trajectory in the upcoming years with sustained policy attention, institutional strengthening, and focused investments, making steady progress toward its $1 trillion economy target and making a substantial contribution to India's larger economic goals.

2. Literature Review

Naveen, Sivakumar, and Karthikeyan (2024), in "Indian states and their contribution towards India's 5 trillion dollar economy mission," examine the contributions of Indian states to India's $5 trillion economy mission, highlighting their unique approaches to economic growth based on their industries, strengths, and limitations, thereby assisting India in achieving its goal.

Shoaib, Sharma, and Padasalagi (2024), in "India's $5 trillion economy - the vision, challenges and road map," outline India's plan to boost its GDP to $5 trillion by 2027-2028, leveraging its diverse domestic market, robust IT sector, strategic location, policy opportunities, infrastructure, and demographic dividend. make it a viable investment location, despite challenges like bureaucracy and talent shortages.

Lakshmi and Gayathri (2024), in "Billion Dreams, Trillion Economy: India's ascent to economic eminence", highlight how economic growth is fuelled by elements including demand, exports, investments, job creation, and productivity. Despite challenges like skill shortages, acquisition policies, labor laws, bureaucratic red tape, and infrastructure deficiencies, India can achieve 8-9% yearly GDP growth over the next ten years.

Karthick and Prabhakaran (2024), in the research paper "India's $5 trillion economy: the vision, challenges, and roadmap," stress the importance of technology, infrastructure development, skill improvement, legislative measures, and foreign collaborations for the growth of India's economy. The strategy aims to achieve inclusiveness, transformative growth, and global leadership, leveraging India's growing services sector and demographic dividend.

Rao and Ramakrishna (2024), in the research paper "Agriculture's place in India's aim for a $5 Trillion Economy," analyze how India's goal of a $5 trillion GDP is affected by recent agricultural reforms. According to the study, India's economy depends on agriculture for around $400 billion and 14–16% of its GDP. To achieve the idealistic aim of India, the agricultural sector should contribute $1 trillion to India's GDP by 2025, aided by labor and agricultural reforms, increased productivity, and increased agricultural exports.

Dhanalakshmi, Keerthana and Haritha (2024) in the research paper, "Economic benefits of five trillion dollar economy" The research paper by Dhanalakshmi, Keerthana, and Haritha (2024) highlights the economic benefits of a five trillion dollar economy, including job creation, poverty alleviation, infrastructure development, and technological innovation, emphasizing the need for government policy, international collaboration, and innovation.

Gulabsing, Balaji, and Arab (2024), in the research paper, "Empowering the Future: a study on India's economic strategies for a five trillion dollar milestone," explore India's tourism industry and government strategies for economic growth, suggesting a comprehensive approach to empower local populations, improve ecotourism policies, and encourage responsible projects across India.

Maurya (2024), in the research paper, "Uttar Pradesh US$ One Trillion Economy – How Realistic is it?" uses EPWRF India Time Series sectoral growth performance data to show that achieving the US$ 1 Trillion economy target by 2027 requires annual growth of at least 27.80%

Kumar (2024), in the research paper, "Achieving a $1 Trillion Economy in Uttar Pradesh: Strategies for environmental Sustainable and Inclusive Growth" suggests a coordinated approach from public, business, and civil society to improve the economy and raise living standards in areas like agriculture, industry, services, urban development, infrastructure, skill development, innovation, and governance.

PHDCCI (2025), in the report, "Uttar Pradesh poised to become USD 1 trillion economy," predicts Uttar Pradesh will become an important economic centre for both domestic and foreign investors by 2047 due to its growing significance in India's Viksit Bharat journey. The state's thriving economy, bolstered by smart investments, industrial expansion, and agricultural reforms, is well-positioned to contribute significantly to India's progress. High-growth industries like energy, agriculture, infrastructure, tourism, IT, electronics manufacturing, and textiles are also attractive.

3. Research Gap

After reviewing a number of publications and research articles, the researcher concluded that although the Government of Uttar Pradesh set an aspirational target of making Uttar Pradesh $1 trillion economy by 2029, there is little research evaluating potential sectors' investment in helping achieve the ambitious target of the Uttar Pradesh government. That's why this study aims to address these gaps by mentioning the potential sectors to drive investment in Uttar Pradesh.

4. Research Questions

- What are the potential sectors that can drive investment and economic contribution toward the vision of becoming US$ 1 trillion economy?
- What are the investment opportunities available in those sectors?

5. Research Methodology

This study is descriptive in nature and mainly uses secondary data from sources like RBI reports, numerous government websites, like invest. up, newspapers, and many more. Data from such sources have been carefully collected and analysed according to the needs of the study.

6. Data collection & analysis

As Uttar Pradesh desires to become $1 trillion economy, various key sectors are contributing significantly to developing the state's social and economic landscape. Some of these are :

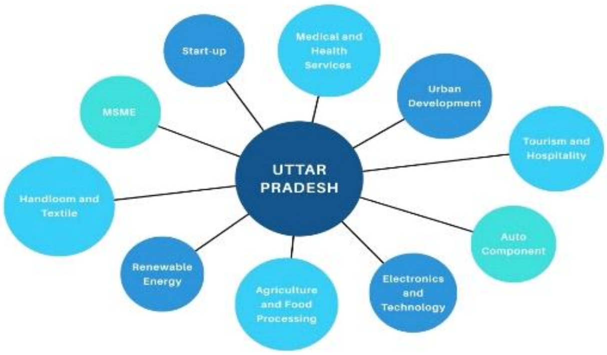

Source : Created by the author

- ***Renewable Energy –*** As energy is one of the important components of today's economy, Uttar Pradesh is focusing on cleaner energy sources and sustainable energy sources for developing its economy, with 49,987 Rs crore allocated in the 2025-26 budget. The state has a total power generation capacity of 5,347.16 MUs (Mn Units), which includes 2,966.98 MU from solar, 24.39 MU from biomass, 1,486.24 MU from bagasse, 126.03 MU from small hydro, 666.83 MU from large hydro (excluding imports from Bhutan), and 76.69 MU from others. With 30,003 MW in service and 14 GW of utility-scale solar projects planned, Uttar Pradesh aims to generate 40,191 MW of power by FY 2028. Over INR 17,965 crore has been set aside under Green Energy Corridor Phase II, and the state has installed 624 substations and over 50,000 km of transmission lines. Investment opportunities include pumped storage facilities, rooftop solar arrays, solar cities, green hydrogen units, and bioenergy initiatives.
- ***Urban Development –*** Cities are the major growth engines for any state's development. Uttar Pradesh has developed 10 cities and upgraded 7 under the Smart Cities mission, improving public transportation infrastructure in 3 operational and 5 underway metro projects. The state has focused

on environmental sustainability through sewage treatment plants, tree plantation drives, green building practices, and renewable energy use. The 2025-26 budget allocates ?25,946 crore for urban development, with major investment opportunities including Trans Ganga City, Saraswati Hi-Tech City, Moradabad Special Economic Zone, integrated industrial townships, Mega Leather Cluster, Film City, Financial City, and Ayodhya transformation.

- ***Tourism and Hospitality*** – Uttar Pradesh's economy is heavily reliant on tourism and hospitality, with the state renowned for its rich heritage, cultural tourism, and religious destinations. The sector aims to attract investments worth ?5,000 crore annually and create employment for 5 lakh people. The investment opportunities available in the state are developing various types of accommodation, including hotels, wellness centers, sports resorts, eco-tourism resorts, heritage hotels, homestays, flotels, and Swiss cottages. It is also enhancing infrastructure at international religious and cultural sites through public-private partnerships.
- ***Agriculture and Food Processing*** **-** Uttar Pradesh's agriculture and food processing sector is crucial for the country's economy, with the state leading in milk, grains, sugarcane, mangoes, and Indian gooseberries. The state has established 15 Agro and Food Processing Parks in cities like Varanasi, Barabanki, Saharanpur, and Gorakhpur, and has a robust market network with 250 regulated markets, 225 rural markets, 100 e-NAM mandis, 4 Agriculture Export Zones, 10 Inland Container Depots, 1909 cold chains, and 35 Farmer-Producer Organizations. Premier institutions like Kanpur University, Ayodhya University, SHUATS Prayagraj, SVPUAT Meerut, and the Indian Veterinary Institute are providing academic and research support to boost the sector. Key agricultural export markets include South Africa, the USA, Australia, and Canada. Investment opportunities include processing food products, manufacturing and supplying fertilizers, seeds, agro-chemicals, farm equipment, and irrigation systems.
- ***MSME*** **-** Uttar Pradesh's MSME sector is the backbone of the state's manufacturing industry, with 90 lakh units, contributing 14% to India's total. Micro industries dominate, with 89.64 lakh units and 0.36 lakh units. The sector employs over 14 million people and has significantly boosted Uttar Pradesh's foreign exchange earnings, with MSME exports valued at $16 billion in 2022. Investment opportunities are abundant in handicrafts, processed food, engineering goods, carpets, readymade garments, and leather products. The state's rich manufacturing tradition offers potential for job creation and economic growth. Large players find opportunities to collaborate with MSME vendors for indigenization and import substitution efforts. A favourable procurement policy mandates 25% of government and PSU procurement from MSMEs. The Uttar Pradesh government has launched initiatives to promote indigenous and specialized products, strengthening the MSME ecosystem and

driving economic growth.

- ***Startup –*** Uttar Pradesh is transforming into a hub for startups due to government policies, investments, and a diverse talent base. With over 14,200 startups recognized by DPIIT, the state has created over 1 lakh jobs and is the 4th largest startup ecosystem in India. The government has established an Innovation Hub at AKTU and approved 63 incubators to support young entrepreneurs. Startups are flourishing in sectors like Information Technology, e-Commerce, Agritech, Healthtech, and Fintech. The state's strong agricultural base has fueled innovation in Agritech solutions. Angel investors and venture capitalists are also attracting investment in sectors like Fintech, Edtech, E-commerce, Social Networking, FoodTech, Logistics, and HealthTech.
- ***Medical and Health services* -** Uttar Pradesh's healthcare sector is rapidly expanding, with a market worth over $100 million in healthcare and medical device exports. The state boasts 18 world-class pharmaceutical research institutes and 208 medical, biotechnology, and pharmacy colleges, fostering a skilled workforce. The government has also strengthened rural healthcare services by deploying doctors and professionals in rural areas. The state has a network of over 30,000 Sub Centers, Primary Health Centers, Community Health Centers, and sub-district hospitals. Programs like Janani Suraksha Yojana and Mission Indradhanush enhance maternal and child health, while initiatives like Jan Aushadhi Pariyojana have fuelled the expansion of affordable medicine centres. E-health initiatives are streamlining healthcare delivery, and investment opportunities include establishing telemedicine hubs, developing nursing and paramedical colleges, strengthening the trauma care network, and expanding clinical trials using artificial intelligence and machine learning technologies.
- ***Auto Component* -** Uttar Pradesh is transforming into a major auto component manufacturing hub due to its strategic location, skilled workforce, and robust industrial infrastructure. Investments in electric vehicle components are being drawn to important industrial clusters like Ghaziabad, Greater Noida, and Kanpur. Significant investments in EV components have been made in the Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) area. Investments in EVs have increased due to the Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing Policy 2022, especially in the production of batteries and charging infrastructure. The state promotes cooperation with OEMs to fortify regional supply chains and provides a range of investment options in both traditional auto components and cutting-edge EV technology.
- ***Electronics and Technology* -** Uttar Pradesh, India's largest electronics and technology hub, is home to 45% of smartphone manufacturing and 55% of mobile component production. It is primarily concentrated in Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) clusters, with global brands like OPPO, VIVO, and Samsung contributing to 40% of India's total mobile production. The government

is establishing three major ESDM clusters to strengthen the sector, focusing on mobile devices, consumer durables, IT hardware, defense electronics, drones, robotics, IoT, and more. ESDM parks are being developed in collaboration with government and private players, with plans to establish Centers of Excellence. Uttar Pradesh presents vast investment opportunities across the value chain, including smartphones, laptops, televisions, infotainment systems, and automobile communication devices. The electronics industry has significant export potential, particularly in ASEAN countries, Japan, South Korea, the USA, Germany, and the UK.

- ***Handloom and Textile –*** Uttar Pradesh is India's 3rd largest textile and 5th largest apparel producer, with a strong presence in traditional textile clusters like Agra, Mirzapur, Lucknow, and Bhadohi. The state employs 1.5 million people and accounts for 90% of India's carpet production. Premier institutions like NIFT Raebareli, Uttar Pradesh Textile Technology Institute, and Indian Institute of Apparel Technology support the industry. The government plans the PM MITRA Park in Lucknow and Hardoi, offering an integrated textile value chain from spinning to garment manufacturing. Investment opportunities include man-made fiber production, technical textiles, home textiles, and research institutes for silk production. Private textile parks, garment manufacturing units, design studios, and textile R&D centers further attract domestic and global investors.

7. Finding, Conclusion, and Suggestion

With India's economy growing to become the third largest in the world, Uttar Pradesh, which is the fourth largest state in terms of area and the first in terms of population serving as largest consumer base in which approximately 53.9% comprises working age group as per 2022-23 and being the second largest economy among states after Maharashtra contributing approximately 9.2% share in the India's GDP as per 2023-24 all of these are the key driver for future growth. Uttar Pradesh is a leader in infrastructure development in India, with the greatest highway network and the longest railway network, with over 16,000 kilometers of track. The state is the nation's first to create a Regional Rapid Transit System (RRTS) line that connects Meerut and Delhi. Furthermore, Uttar Pradesh has five international airports, with four operating and one planned. It also has the second-largest road network in India, with more than 4 lakh kilometers. Additionally, the state is home to the nation's first inland waterway and first multimodal terminal. The state has one of the two defence corridors in the country and has $6.11 Bn of investment potential. The state is also seeking various investments with more than 50% pledged investment translated into proposals and lakhs of jobs created since the 2018 Investors Summit.

Uttar Pradesh, with its vast geographical expanse, diverse resources, and progressive policy ecosystem, has emerged as one of India's most promising destinations for investment across multiple sectors. Uttar Pradesh has various potential sectors for investment in which would be beneficial for both investors in terms of profit, as the state has resources necessary for the accomplishment of any project, from Raw materials to Human Resources, in addition to the state regarding growth and development. The state's robust infrastructure, skilled workforce, and proactive governance have opened up substantial investment opportunities available in agriculture and food processing, MSMEs, startups, electronics, textiles, dairy, healthcare, auto components, and the defense manufacturing corridor. Uttar Pradesh, India's largest milk-producing state, also offers numerous investment opportunities in civil aviation, the dairy sector, defence and aerospace, EV manufacturing, film, and other sectors. The state has seven airports, six under progress projects under the Regional Connectivity Scheme (RCS) phase 1&2, and five new projects identified under RCS phase 3. The state also aims to establish six integrated dairy complexes to increase commercial milk production and supply chain, empowering farmers and boosting the dairy sector. The Bundelkhand region hosts one of India's two Defence Industrial Corridors, attracting ?50,000 crore in investments. Uttar Pradesh also accounts for the bulk of EVs registered in India, having a market share of over 14% in 2023. The state has received the most film-friendly state award in 2015 and 2016. The state is the emerging hub of fintech start-ups, as approximately 239 start-ups mainly operating in the Noida region. The state is also now the leading exporter of consumer electronics in India and is regarded as a prospective hub for semiconductor design and research and development offices.

While Uttar Pradesh is the home of a working-age group that comprises more than 50% of the total population, it is still necessary to teach them particular skills for the emerging sectors like robotics, AI, health tech, etc., to make use of the workforce in developing Uttar Pradesh. To ensure that more and more individuals can take advantage of government programs, raising awareness about them is needed. The government should focus on eco-friendly practices across sectors, infrastructure development in tier 2 and tier 3 cities, and accelerate digital infrastructure development to get holistic development of the state.

With a clear focus on inclusive growth, employment generation, and sustainable development, Uttar Pradesh is poised to become a key contributor to India's economic transformation, as is clear from the rising GSDP of Uttar Pradesh. Continued efforts to strengthen infrastructure, ease of doing business, and innovation will further accelerate its journey toward becoming an industrial and investment powerhouse, helping to achieve its aspirational target of a $ 1 trillion economy.

Disclaimer :

The views mentioned in the study are solely those of the authors and do not represent the official position of any institution or government. The study is based on the secondary data collected from reliable and publicly accessible sources that are thought to be trustworthy. However, the authors make no claims about the completeness of the results and are not liable for any errors and misinterpretations resulting from limited data. The study is purely academic and aims to facilitate conversations about Uttar Pradesh's efforts to promote economic growth.

References :

1. Naveen, R., Sivakumar, M., & Karthikeyan, P. (2023). INDIAN STATES AND THEIR CONTRIBUTION TOWARDS INDIA'S 5 TRILLION DOLLAR ECONOMY MISSION. *INDIA'S $5 TRILLION ECONOMY: THE VISION, CHALLENGES, AND ROADMAP*, *1*. https://doi.org/10.34293/India-5TE-2024
2. Shoaib, M., Sharma, A. M., & Padasalagi, S. M. INDIA'S $5 TRILLION ECONOMY-THE VISION, CHALLENGES AND ROAD MAP. *INDIA'S $5 TRILLION ECONOMY: THE VISION, CHALLENGES, AND ROADMAP*, 44. https://doi.org/10.34293/India-5TE-2024
3. Lakshmi, A. S., & Gayathri, M. J. BILLION DREAMS, TRILLION ECONOMY: INDIA'S ASCENT TO ECONOMIC EMINENCE. *INDIA'S $5 TRILLION ECONOMY: THE VISION, CHALLENGES, AND ROADMAP*, 65. https://doi.org/10.34293/India-5TE-2024
4. Karthick, M. V., & Prabhakaran, J. India's $5 Trillion Economy: The Vision, Challenges, and Roadmap. *India's $5 Trillion Economy: The Vision, Challenges, and Roadmap*, *79*. https://doi.org/10.34293/India-5TE-2024
5. Rao, P. N., & Ramakrishna, G. N. (2025). AGRICULTURE'S PLACE IN INDIA'S AIM FOR A $5 TRILLION ECONOMY. *INDIA'S $5 TRILLION ECONOMY: THE VISION, CHALLENGES, AND ROADMAP*, 104. https://doi.org/10.34293/India-5TE-2024
6. Dhanalakshmi, M., Keerthana, M. K., & Haritha, M. Economic benefits of five trillion dollar economy. *INDIA'S $5 TRILLION ECONOMY: THE VISION, CHALLENGES, AND ROADMAP*, 134. https://doi.org/10.34293/India-5TE-2024
7. Gulabsing, M. R. K., Balaji, M. M., & Arab, A. A. EMPOWERING THE FUTURE: A STUDY ON INDIA'S ECONOMIC STRATEGIES FOR A FIVE TRILLION DOLLAR MILESTONE. *INDIA'S $5 TRILLION ECONOMY: THE VISION, CHALLENGES, AND ROADMAP*, 137. https://doi.org/10.34293/India-5TE-2024
8. Maurya, N. K. (2024). Uttar Pradesh US$ One Trillion Economy-How Realistic Is It?. *IASSI Quarterly*, *43*(2). https://www.researchgate.net/publication/381457987
9. Kumar, Y. (2024). Achieving a $1 Trillion Economy in Uttar Pradesh: Strategies for Environmental, Sustainable, and Inclusive Growth. *Idealistic Journal of Advanced Research*

in Progressive Spectrums (IJARPS) eISSN–2583-6986, *3*(10), 31-35. https://journal.ijarps.org/index.php/IJARPS/article/view/414

10. Uttar Pradesh poised to become a USD 1 trillion economy: PHDCCI. (2025). In *https://www.phdcci.in/2025/02/11/phdccis-7th-global-film-tourism-conclave-to-spotlight-the-power-of-cinema-in-boosting-tourism/*, PHD Chamber of Commerce and Industry.
11. https://www.investindia.gov.in/state/uttar-pradesh
12. https://m.economictimes.com/news/india/up-to-become-usd-1-trillion-economy-in-four-years-moving-towards-zero-poverty-cm-adityanath/articleshow/117527570.cms
13. https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/uttar-pradeshs-path-to-a-usd-1-trillion-economy-yogi-adityanaths-vision-and-strategies/articleshow/114360257.cms
14. https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/12/With-92-share_181223.pdf
15. https://m.economictimes.com/news/economy/finance/five-years-since-2018-up-investors-summit-half-of-investment-pledged-translated-into-proposals-3-24-lakh-jobs-created/articleshow/105649143.cms
16. https://invest.up.gov.in/renewable-energy-sector/
17. https://invest.up.gov.in/urban-development/
18. https://invest.up.gov.in/tourism-hospitality/
19. https://invest.up.gov.in/agriculture-food-processing/
20. https://invest.up.gov.in/msme-sector/
21. https://invest.up.gov.in/startup-sector/
22. https://invest.up.gov.in/medical-device-and-pharma/
23. https://invest.up.gov.in/auto-components-sector/
24. https://invest.up.gov.in/electronics-technology/
25. https://invest.up.gov.in/handloom-and-textile-sector/
26. https://invest.up.gov.in/sectors-in-uttar-pradesh/

E-mail: sejaljaiswal202@gmail.com
Mob. No.: +91 9305382351

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 59-63

पंजाब के साहित्यकारों द्वारा रचित आदिवासी लेखन में समाज

अनीता रानी
शोधार्थी, केंन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, अजमेर।

शोध सार :-

किसी समुदाय विशेष जिसके पास अपने निर्धारित नियम, आपसी सहयोग की भावना, विशेष सभ्यता–संस्कृति, रहन–सहन, रीति–रिवाज, पहरावा, खान–पान आदि हैं एक विशेष प्रकार के समाज को परिभाषित करते हैं। इन्हीं सब मानदंडों की पूर्ति करता है आदिवासी समाज जिसे जंगलों में निवास करने वाला समाज के नाम से भी पहचाना जाता है। चूँकि हर समाज के अपने विशेष तौर तरीके होते हैं इसलिए उस समाज का साहित्य भी निश्चित रूप में उस समाज के आंतरिक और बाह्य प्रवृतियों को दर्शाने का कार्य करता है। जैसे–जैसे समाज में बदलाव होते रहते हैं साथ–साथ साहित्य लेखन की प्रवृतियाँ भी बदलती रहती हैं। साहित्य और समाज के बीच जो अटूट संबंध है को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल परिभाषित करते हुए लिखतें हैं :– "प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृति के परिवर्तन के साथ–साथ साहित्य के स्वरुप में भी परिवर्तन होता चला जाता है।"[1] साहित्य को समाज का दर्पण या प्रतिबिंब इसलिए ही स्वीकृत किया जाता है चूँकि साहित्यकार अपने आस–पास की घटनाओं का आँखों देखा यथार्थ अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। साहित्य लेखन का आधार समाज को स्वीकृत किया जाता है। दूसरे शब्दों यदि कहा जाए कि साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं तो इस बात में कोई अतिकथनी नहीं होगी।

समय के साथ साहित्य लेखन तथा लेखन की प्रवृतियों में भी परिवर्तन होते रहे हैं और वर्तमानकालीन साहित्य किसी एक विशेष धारा को आधार बना कर नहीं लिखा जा रहा, अपितु वर्तमान साहित्य में विभिन्न विमर्शों को आधार बना कर लेखन किया जा रहा है। अब साहित्य लेखन केवल मुख्यधारा पर आधारित नहीं है बल्कि सदियों से दबे कुचले, सत्ताविहीन, हाशिए पर अनदेखे किए जाने वाले समुदायों के संघर्ष और पीड़ा को दर्शाने वाला सशक्त साधन है। वैश्वीकरण के इस दौर ने जहाँ एक तरफ मानवता और नैतिक मूल्यों का पतन करते हुए सामाजिक मान्यताओं का ह्रास किया है वहीं दूसरी और दलित, किसान, स्त्री, वृद्ध, किन्नर, आदिवासी अनेकों समुदायों को अपनी पहचान बनाने के लिए मंच प्रदान किया है। पिछले लंबे अरसे से यह सभी समुदाय उपेक्षा का शिकार होते आएं हैं लेकिन अब इनके पास अपने दुःख, कष्ट, पीड़ा, संघर्ष को प्रस्तुत करने का उचित माध्यम है। साहित्य लेखन जिसके द्वारा न केवल इन समुदायों से संबंध रखने वाले साहित्यकार अपितु

गैर–संबंधित साहित्यकारों द्वारा भी इन समुदायों के लिए लेखन कार्य पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है।

बीज शब्द :– आदिवासी, साहित्य, समाज, संघर्ष, साहित्यकार।

प्रस्तावना :–

आदिवासी समाज जिसके रहन–सहन में लोगों में समानता होती है पर आधारित साहित्य लेखन को आदिवासी साहित्य के नाम से सम्बोधित किया जाता है। आदिवासी समाज जिसकी अपनी मान्यताएं, अपने निर्धारित मूल्य हैं। मानव वैज्ञानिक गिलीन आदिवासी समाज को अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए लिखते हैं :– "किसी विशिष्ट भू–प्रदेश पर रहने वाले, समान बोली भाषा बोलने तथा समान संस्कृति का जीवन जीने वाले स्थानीय जत्था को आदिवासी समाज कहते हैं।"[2] जिसमें आदिवासी लोगों का रहन–सहन, रीति–रिवाज, भाषा, त्योहार, पहरावा, संस्कृति सम्मलित होती है जो आदिवासी समाज को अपनी अलग पहचान प्रदान करने वाले कारक हैं, इन्हीं को आधार बना कर किया जाने वाला साहित्य लेखन आदिवासी साहित्य कहलाता है। वर्तमान दौर में आदिवासी और गैर–आदिवासी समाज के साहित्यकारों द्वारा आदिवासी लेखन कार्य किया जा रहा है। आदिवासी जिन्हें किसी प्रदेश या राज्य के मूल निवासी स्वीकृत किया जाता है। आमतौर पर आदिवासी शब्द आते ही जंगलों, पहाड़ों में निवास करने वाले मनुष्यों का ध्यान आता है जिनका जीवन जंगलो, नदियों, पहाड़ों में शुरू होकर वही खत्म हो जाता है, किंतु अब आदिवासी समाज शिक्षा की ओर अग्रसर होते हुए अपने जीवन–आयामों को परिवर्तित करता दीख पड़ता है। आदिवासी समाज को परिभाषित करते हुए डॉ. विवेकीराय लिखते हैं :– "पिछड़े अंचलों, पहाड़ों, वनों के निवासियों को आदिम–आदिवासी माना जाता है।"[3] भारत एक ऐसा देश है जो अनेकताओं में एकता समाहित किए हुए विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों की विलक्षण प्रवृतियों का प्रस्तोता है। आदिवासी समाज भी जोकि भारत के विभिन्न राज्यों जैसे झारखंड, बिहार, तमिलनाडू, केरल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आदि में निवास करता है। इन विभिन्न राज्यों के आदिवासी समाज की जीवन–शैली को आधार बनाकर वहां के साहित्यकारों अथवा अब तो खुद आदिवासी साहित्यकारों द्वारा साहित्य लेखन किया जा रहा है। वैश्वीकरण के दौर में जब पूरा विश्व सिमट कर एक गाँव बन चुका है तो भारत के गैर–आदिवासी राज्यों के साहित्यकारों द्वारा आदिवासी समाज को आधार बनाकर साहित्य लेखन करना आश्चर्यजनक प्रतीत नहीं होता है।

पंजाब एक ऐसा ही राज्य है जोकि गैर–आदिवासी राज्य है लेकिन यहां के साहित्यकारों द्वारा भी आदिवासी समाज पर लेखन कार्य हो रहा है। पंजाब के साहित्यकारों में आदिवासी समाज का लेखन करने वाले साहित्यकारों में विशेष रूप से रमणिका गुप्ता का नाम लिया जाता है इनके अतिरिक्त मनमोहन बावा, स्वराज बीर और भगवंत रसूलपुरी आदि साहित्यकारों का नाम लिया जा सकता है। आदिवासी समाज का साहित्य आदिवासी साहित्य को अधिक गहनता से समझने के लिए उपर्युक्त हो सकता है। आदिवासी समाज का साहित्य डॉ. रा. चिंढेरे के शब्दों में :– "आदिवासी साहित्य में आदिम मानव की अभिव्यक्ति होती है। आज का आदमी समाज विकासशील दिखता है, फिर भी उसकी अलग–अलग अभिव्यक्ति में इसी आदिम–अभिव्यक्ति का अवशेष रहा है।"[4] पूरी दुनिया में जितने भी समाज हैं सब अपनी आदिकालीन अवस्था में आदिवासी ही रहे। प्रकृति के निरतंर होने वाले परिवर्तन के नियम के अनुसार बाद में सभी समाज विकास की ओर अग्रसर होते हुए सभ्य होते गए। विभिन्न आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन–यापन को सुखद बनाने में योगदान दिया। जो मनुष्य प्रकृति प्रेमी थे, उन्होंने

जंगलों, नदियों, पहाड़ों को ही अपना जीवन जीने का उत्तम साधन स्वीकृत किया और प्रकृति की गोद में ही बसे रहे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट रेडफिल्ड के अनुसार :–"हम सभी पहले आदिवासी थे, आगे चलकर ग्राम्य समाज बना, बाद में राज्य–केंद्र संस्था आने के बाद राजधानी तथा बेपार केंद्र बाजारों के कारण नगरीय, महानगरीय जीवन का प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद समग्र शहरों के विकास की रफ्तार बढ़ गयी।"[5] प्रत्येक समाज के विकास की कथा–कहानी को साहित्य में स्थान दिया जाता रहा है और आज भी समाज की प्रत्येक घटना को साहित्यकार यथासंभव अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो आदिवासी समाज का लेखन कार्य भी उतना ही आवश्यक है जिनता अन्य समाजों का। बल्कि आदिवासी समाज का लेखन अन्य समाजों से अधिक होना चाहिए चूँकि आदिवासी समाज पर्यावरण की रक्षा हेतु सदियों से सहयोग करता रहा है। ऐसा भी नहीं है पर्यावरण की रक्षा का दायित्व केवल आदिवासी समाज का ही है या फिर इससे केवल उनका ही कोई फायदा होना है। जब–जब जंगलों की कटाई की जाती है आदिवासी लोग उसका विरोध करने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनके जीवन के निर्बाह का आधार ही जंगल हैं। तो वो लोग सब के हित में ही तो कार्य करते है, पर्यावरण की सुरक्षा में पूरे जीव–जन्तुओं का जीवन निर्भर करता है। इसलिए आदिवासी और गैर–आदिवासी साहित्यकारों का दायित्व है कि वो आदिवासी समाज को आधार बनाकर लेखन कार्य कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाते रहें।

पंजाब के साहित्यकारों में आदिवासी समाज के हितों के लिए आंदोलन करने की बात हो अथवा साहित्य लेखन करने की बात हो रमणिका गुप्ता का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने पद्यात्मक व गद्यात्मक दोनों प्रकार का लेखन कार्य कर साहित्य में अपना योगदान दिया है। और साथ ही व आदिवासी समाज का यथार्थ चित्रण भी अपने गद्य व पद्य साहित्य लेखन में करती हैं। उन्होंने आदिवासियों की पीड़ा, दु:ख, संघर्ष आदि को नजदीक से देखने के लिए उनका सा जीवन जिया उपरांत अपने लेखन में आदिवासी समाज की व्यथा का चित्रण करती हैं। साहित्य लेखन में काव्य को भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति स्वीकृत किया जाता है। रमणिका गुप्ता के काव्य लेखन का आधार सामाजिक, राजनीतिक, मजदूर वर्ग, आदिवासी, आदिवासी मजदूर आदि विषय रहे हैं। विकास के नाम पर जो छलावा किया जा रहा पूरी दुनिया के निम्न वर्गो के साथ उस का संताप आदिवासी समाज को भी भुगतना पड़ रहा है। उनके निवास स्थानों का विकास के नाम पर हनन किया जा रहा है जंगलों को काटा जा रहा जिसके कारण ये लोग पलायन करने को विवश हैं और अपने आप को सभ्य कहलाने वाला समाज इनके आशियाने उजाड़ कर खुद सकूं की जिंदगी जीने की आस में रहता है। वर्तमानकालीन आदिवासी समाज अपने अतीत की स्मृतियों को देखता है तो वो अपनी पहचान खो जाने के डर में चिंतित नजर आता है। आदिवासी समाज अपने इतिहास, अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु संघर्षरत है। इस बात की झलक रमणिका गुप्ता द्वारा रचित उनके कविता संग्रह 'अब और तब' में इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्टतः देखी जा सकती है :–

'राम ने भिलनी के घर बेर खाये
आज के दृष्टिकोण से
ये राम की महत्ता भी
और भिलनी का सौभाग्य !
में नहीं कहती – में सपना देखती हूँ

उस दिन का
जब लोक कहें ये कि
ये भिलनी का बडप्पन था
और राम का गौरव

...

राम का भिलनी के घर बेर खाना
चर्चा का विषय ही ना समझा जाए।'6

वर्चस्वशाली समाज जो सत्ता पर काब्ज होने के बाद सत्ता पर अपना आधिपत्य समझता है के नजरिए आमजन सदियों से उपेक्षित ही रहा है। फिर आदिवासी समाज को जंगलों के वासी मानते हुए उपेक्षित करना कौन–सी बड़ी बात होती है। उपेक्षा तक तो रुकते तो बात शायद अलग होती किंतु इस सत्ताधारी तबके ने तो विकास के नाम पर जंगली जमीनों पर कब्जा कर आदिवासियों को वहां से पलायन करने पर विवश कर दिया। प्रकृति के परिवर्तन के नियम का अनुसरण करते हुए आदिवासी समाज जब से शिक्षा की ओर अग्रसर हुआ है तब से अपने हितों की रक्षा हेतु भी सामने आना लगा है। अब यह समाज अपने साहित्य के माध्यम से अपनी व्यथा को प्रस्तुत करने में सक्षम हो रहा है। किंतु वैश्वीकरण के इस युग में बदलते हुए तेज गति के समय और परस्थितियों में भी इस समाज को छला ही जा रहा है जिसकी अभिव्यक्ति लेखिका की इन पंक्तियों में देखी जा सकती है :–

'जो हारे थे
जो हरा दिये गये थे
एक साजिश के तहत।'[7]

उनके काव्य लेखन में विभिन्न विषयों की झलक देखी जा सकती है, उनका काव्य संग्रह 'अब और तब' में स्त्री को शोषण से मुक्त होते दिखाया गया है इसके अलावा मजदूरों का जीवन, निम्नवर्ग, आदिवासियों के सुविधाविहीन जीवन का प्रस्तुतिकरण भी कवित्रयी ने किया है।

अपने दो उपन्यासों जो कि 'सीता' और 'मौसी' के नाम से रचित हैं में लेखिका ने आदिवासी समाज का यथार्थ चित्रण किया है उनकी दिनचर्या, पुरुष प्रवृति और स्त्री की दशा आदि का बारीकी से वर्णन किया है। "इन लोगों की दिनचर्या बड़ी ही सीमित होती है मुँह अँधेरे जंगल जाना। दिन भर शहर में लकड़ी बेचना या मजदूरी करना, साँझ को बस से लौट जाना, रांधना–पकाना, हंडियाँ या महुआ चुआना, पीना–खाना, घर के बाहर बने मिट्टी के ही बेंचनुमा चबूतरे या गाछ के तने पर, जिसे घर के बाहर बैठने के लिए रख दिया जाता है––– बैठकर 'बतियाना' गाँव घर का झगड़ा हो तो मिल–जुलकर मिटाना–निपटाना। पर्व हो या हफ्ते का पैसा मिला हो, तो नाचना–गाना। कोई शिकार मार कर लाया हो हो, तो मिलजुल कर खाना, नाचना। फिर सो जाना।"[8] आदिवासियों की साधारण सी जीवन–शैली में अब शहरीकरण की छवि भी दिखने लगी है। "लड़के का नाम रखा सुनील। शहरी नाम चुन रखा था सीता ने। उसने आदिवासी नाम नहीं रखा, जो वर्ष, दिन या महीने के नाम पर होते हैं।"[9] रमणिका गुप्ता अपने साहित्य लेखन में आदिवासियों का कोयिला खदानों में कार्य करने और वहाँ उन पर होने वाले अत्याचारों का यथार्थ चित्रण करती हैं। आदिवासियों में स्त्री और पुरष में भेदभाव नहीं था स्त्री को

पुरुष के सामान अधिकार थे किंतु अब धीरे–धीरे सभ्य समाज की तरह स्त्री के प्रति बदलते रवैया दिखाया गया है। यदि यह कहा जाए के वैश्वीकरण की आंधी ने आदिवासी समाज में मूल्यों–मान्यताओं का ह्रास करना प्रारंभ कर दिया है तो इस बात में कोई दोराय नहीं होगी।

निष्कर्ष :–

प्रकृति की गोद में जन्म लेकर प्रकृति की पूजा करते हुए बड़े होने से प्रकृति की गोद में समा जाने की ख्वाहिश रखने वाले आदिवासी समाज को विलुप्त होने से बचाना आवश्कयता है। वैश्वीकरण ने मानव का यंत्रीकरण करने में कोई कसर बाकि नहीं छोड़ी है आदिवासियों में आज भी वो मानवता बची है जो प्रकृति को अपना सब कुछ मानते हैं। इनके सादगी भरे जीवन का असितत्व बचाए रखने का जिम्मा न केवल आदिवासी समाज के साहित्यकारों का है अपितु सभी का बन जाता है। ''दीवारों पर रंग–बिरंगे चित्र। फूस या खपरे की छत। गर्मी में गरम घर। घर के भीतर हंडिया, महुआ चुहाने का जुगाड़। बाहरबाड़ी, जिसमें उगी कद्दू, लौकी या नितुए की लतर पेड़ या घर की छत पर चढ़ी रहती है। ये लोग 'किसिम–किसिम' का साग बाड़ी में जरूर उगाते हैं। धान, मक्का और रहर (अरहर) तीनों की खेती करते हैं।''[10] आदिवासी साहित्य लेखन कितना आवश्यक है इस बात की पैरवी करने का कार्य करता है रमणिका गुप्ता के उपन्यासों में कविताओं वर्णित आदिवासी समाज का प्रकृति के साथ कितने निश्छल भाव के संबंध है। आदिवासी लेखन कार्य आदिवासी समाज के साहित्यकारों द्वारा किया जाए अथवा गैर–आदिवासी समाज के साहित्यकारों द्वारा अहम बात आदिवासी समाज की सुरक्षा के साथ–साथ प्राकृतिक सौन्दर्य की सुरक्षा भी साहित्यकारों का दायित्त्व बन जाता है।

संदर्भ सूची :–

1. हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, पृष्ठ सं – 21
2. आदिवासी साहित्य और विधा : शास्त्र और इतिहास, डॉ. बापुराव देसाई, गरिमा प्रकाशन, कानपुर पृष्ठ सं– 20
3. आदिवासी साहित्य विविध आयाम, डॉ. रमेश सम्भाजी कुरे, डॉ. मालती धोंडोपंत शिंदे, प्राचार्य प्रवीण अनंतराव शिंदे, विकास प्रकाशन कानपूर, भूमिका से।
4. आदिवासी साहित्य और विधा : शास्त्र और इतिहास, डॉ. बापुराव देसाई, गरिमा प्रकाशन, कानपुर पृष्ठ सं– 21–22
5. वही, पृष्ठ सं– 65
6. अब और तब, रमणिका गुप्ता, युगवाणी प्रकाशन कानपुर, पृष्ठ सं– 147
7. अब मूरख नहीं बनेगे हम, रमणिका गुप्ता, नवलेखन प्रकाशन, हजारी बाग, पृष्ठ सं– 5
8. सीता–मौसी, रमणिका गुप्ता, ज्योतिलोक प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ सं. 104
9. वही, पृष्ठ सं. 105
10. वही, पृष्ठ सं. 56

M. No. 8569912990
neetuanita39@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 64–67

दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक दर्शन का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में योगदान

डॉ सुनीता शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग)
श्री भवानी निकेतन महिला पी जी महाविद्यालय, सीकर रोड, जयपुर।

सारांश (Abstract)

भारतीय शिक्षा परंपरागत रूप से केवल ज्ञानार्जन का साधन नहीं रही, बल्कि यह समाज, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण का आधार रही है। आधुनिक समय में शिक्षा अधिकतर रोजगार–केंद्रित और बाजारवादी प्रवृत्तियों की ओर झुक गई है, जिससे नैतिकता, मूल्य–शिक्षा और सांस्कृतिक चेतना हाशिये पर चली गई है। दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानववाद दर्शन के माध्यम से शिक्षा को समग्र विकास का साधन माना और इसे शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा के संतुलित निर्माण का माध्यम बताया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की पहल है। इसमें मातृभाषा–आधारित शिक्षा, मूल्य–आधारित पाठ्यक्रम, कौशल विकास, समावेशी शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया गया है। प्रस्तुत शोध–पत्र में यह विश्लेषण किया गया है कि NEP 2020 किस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक दर्शन के अनुरूप है और किस प्रकार उनके विचार इसमें परिलक्षित होते हैं।

प्रमुख शब्द (Keywords) : दीनदयाल उपाध्याय, शिक्षा दर्शन, एकात्म मानववाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मूल्य–आधारित शिक्षा, आत्मनिर्भरता।

1. भूमिका (Introduction) :

भारत की शिक्षा प्रणाली सदैव मूल्य–आधारित और जीवनोपयोगी रही है। प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने केवल ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने की कला, राष्ट्र और समाज की सेवा का भाव भी सिखाया। परंतु उपनिवेशवाद के दौर में शिक्षा का उद्देश्य संकुचित होकर रोजगार और प्रशासनिक कार्यों तक सीमित कर दिया गया।

आज भी शिक्षा पर बाजारवादी दबाव है। विद्यार्थी केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। परिणामस्वरूप नैतिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक चेतना का लोप होता जा रहा है। ऐसे समय में दीनदयाल उपाध्याय का शैक्षिक दर्शन हमें दिशा दिखाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय शिक्षा के पुनर्निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। इसमें भारतीय परंपरा

और आधुनिकता का संतुलन है। इस नीति के अनेक बिंदु दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से मेल खाते हैं।

2. शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study) :

1. दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक दर्शन का गहन अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करना।
3. यह समझना कि NEP 2020 में उपाध्याय के शैक्षिक विचारों का किस प्रकार योगदान है।
4. भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए इन विचारों की उपयोगिता और चुनौतियों को रेखांकित करना।

3. साहित्य समीक्षा (Literature Review) :

- **उपाध्याय (1965) :** अपने एकात्म मानववाद दर्शन में उन्होंने शिक्षा को समाज और राष्ट्र निर्माण का साधन बताया।
- **जोशी (2002) :** दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जोड़ा।
- **शर्मा (2010) :** भारतीय शिक्षा में नैतिकता और मूल्यों की कमी पर चर्चा करते हुए उपाध्याय के दृष्टिकोण को प्रासंगिक बताया।
- **Government of India (2020) :** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय ज्ञान परंपरा और मूल्य शिक्षा पर बल दिया।
- **मिश्रा (2018) :** आधुनिक शिक्षा में उपाध्याय के विचारों की उपयोगिता और उनकी समयानुकूल प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।

4. दीनदयाल उपाध्याय का शैक्षिक दर्शन (Educational Philosophy)

4.1 एकात्म मानववाद और शिक्षा :

दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार मनुष्य केवल शरीर मात्र नहीं है। उसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वय है। शिक्षा का लक्ष्य इन चारों का समुचित और संतुलित विकास होना चाहिए।

4.2 शैक्षिक मूल्य :

1. **आत्मनिर्भरता (Self-Reliance) :** शिक्षा व्यक्ति को आर्थिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए।
2. **नैतिकता (Morality) :** शिक्षा में चरित्र निर्माण और सदाचार का बोध कराना अनिवार्य है।
3. **सांस्कृतिक चेतना (Cultural Awareness) :** भारतीय परंपरा और संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन शिक्षा के माध्यम से हो।
4. **सामाजिक समरसता (Social Harmony) :** शिक्षा से जाति, वर्ग, लिंग और धर्म आधारित भेदभाव समाप्त हों।
5. **राष्ट्र निर्माण (Nation-Building) :** शिक्षा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाले नागरिक तैयार करे।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020)

5.1 प्रमुख विशेषताएँ :

- **मातृभाषा पर बल :** प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा।

- **भारतीय ज्ञान परंपरा :** वैदिक गणित, आयुर्वेद, योग, दर्शन आदि का समावेश।
- **कौशल विकास :** व्यावसायिक शिक्षा और रोजगारपरक पाठ्यक्रम।
- **मूल्य शिक्षा :** नैतिकता, पर्यावरण चेतना और संवेदनशीलता का विकास।
- **समावेशी शिक्षा :** सभी वर्गों और लिंगों के लिए समान अवसर।
- **समग्र शिक्षा :** बहुविषयक और शोध–आधारित दृष्टिकोण।

5.2 नीति का उद्देश्य :

- विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन और नवाचार की क्षमता विकसित करना।
- शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, परंतु भारतीय संस्कृति से जोड़े रखना।

6. दीनदयाल उपाध्याय और NEP 2020 का सामंजस्य (Integration)

6.1 आत्मनिर्भरता और कौशल विकास :

NEP 2020 कौशल विकास पर बल देती है। यह उपाध्याय के आत्मनिर्भरता सिद्धांत से जुड़ा है।

6.2 नैतिकता और मूल्य शिक्षा :

NEP 2020 में नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल और चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया है। यह उपाध्याय की शिक्षा दृष्टि से मेल खाता है।

6.3 सांस्कृतिक चेतना :

NEP 2020 में भारतीय भाषाओं और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। उपाध्याय भी शिक्षा में भारतीय संस्कृति के संरक्षण के पक्षधर थे।

6.4 सामाजिक समरसता :

NEP 2020 समान अवसर और समावेशी शिक्षा की बात करती है। उपाध्याय भी समरस समाज की स्थापना चाहते थे।

6.5 राष्ट्र निर्माण :

नीति का लक्ष्य "वैश्विक नागरिक" के साथ "भारतीय मूल्य–आधारित नागरिक" तैयार करना है। यह उपाध्याय की राष्ट्रवादी शिक्षा दृष्टि के अनुरूप है।

8. निष्कर्ष (Conclusion) :

दीनदयाल उपाध्याय ने शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन का साधन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण का माध्यम माना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आत्मनिर्भरता, मूल्य शिक्षा, सांस्कृतिक चेतना और समरसता जैसे उनके विचार स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं।

यदि इस नीति को पूरी निष्ठा और गंभीरता से लागू किया गया, तो यह भारत को न केवल ज्ञान आधारित बल्कि मूल्य आधारित समाज बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

संदर्भ References :

1. Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education.
2. उपाध्याय, दीनदयाल. (1965). एकात्म मानववाद. नई दिल्ली : भारतीय जनसंघ प्रकाशन।

3. जोशी, रामबहादुर. (2002). दीनदयाल उपाध्याय : दर्शन और विचार. जयपुर : राजस्थान प्रकाशन।
4. शर्मा, रमेश. (2010). भारतीय शिक्षा और मूल्य. वाराणसी : सरस्वती प्रकाशन।
5. Mishra, R. (2018). Value-based Education in India : Relevance of Deendayal Upadhyaya's Philosophy. New Delhi : Concept Publishing.
6. Singh, P. (2015). Integral Humanism and Indian Education. Journal of Indian Philosophy, 42(3), 211–230.

Email Sunita.prince26@gmail.com
Mobile 7878216220

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 68–70

प्रवासी हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श

अलका शर्मा
के. एल. पी. कॉलेज, रेवाड़ी।

प्रस्तुत शोध पत्र में प्रवासी साहित्यकारों के हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श पर विचार किया गया है। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में, चाहे वह कविता है, कहानी है या निबंध है सभी में स्त्री की समस्या को उठाया है।

साहित्य को समाज का प्रतिबिंब कहा जाता है क्योंकि जैसा समाज होता है साहित्य में भी वही नजर आता है। प्रवासी भारतीय साहित्यकार भारत में हो रही गतिविधियों से प्रभावित हैं। यह प्रभाव उनके लेखन में बखूबी दिखाई भी देता है, यह लेखन चाहे कोई भी विधा हो, कविता हो, कहानी हो, निबंध हो। प्रवासी साहित्य में साहित्यकारों ने जो विषय उठाए हैं, वह समाज की ठोस समस्याओं से जुड़े हैं। प्रवासी साहित्यकारों में ऐसे बहुत से नाम है जिनकी रचनाओं को पढ़कर यह जाना जा सकता है कि यह लोग विदेश में रहने के बावजूद दुनिया को भारतीय चश्मे से देखते हैं। इसीलिए उनका साहित्य नएपन के बावजूद पाठक के मन को छूता है। सभी देशों में और सभी धर्मों में स्त्री का हमेशा से ही पुरुष समाज द्वारा शोषण किया जाता रहा है।

प्रवासी कवियों ने इसी समस्या को अपनी कविताओं में दिखाया है। प्रवासी कवियों में शरद आलोक ने अपनी कविताओं में उन नाबालिग मांओं के जीवन की त्रासदी को कविता का विषय बनाया है जो बचपन से ही किसी हैवान की हवस का शिकार हुई और उस नाजायज बच्चे का पालन पोषण कर रही है।

'जूठन' कविता एक नाबालिक मां के दर्द को बड़ी ही मार्मिकता से उजागर करती है–

मैं तुम्हारे बच्चों की नाबालिक आया मां
तुम मेरे बाप तो ना बन सके पर तुम्हारी हवस ने
मुझे नाबालिक मां बना दिया।

इसी प्रकार तेजेंद्र शर्मा ने भी नारी जीवन की त्रासदी को बड़े ही मार्मिक ढंग से अपनी कविता 'औरत को जमाने ने बस जिस्म ही माना है' में प्रस्तुत किया है। कवि का मानना है कि औरत के दिल के दर्द को कोई जानना नहीं चाहता। वह पुरुष के लिए केवल एक उपयोगी वस्तु है। वह कभी बाजार में बिकती है, कभी घरबार के कामों में पिसती है। पति के अन्याय और अत्याचार को वह केवल इसलिए सहती है कि वह मानती है कि पति के अन्याय का विरोध करने का कोई फायदा नही, उसे जिंदगी उसे के साथ में बितानी है –

बाजार में बिकती है, घरबार में पिसती है
दिन में उसे दुत्कारे बस रात को पाना है

इक उम्र गुजर जाती संग उसके जो शौहर है
सहने है जो जुल्म उसके, जीवन जो बिताना है।

इसी प्रकार प्रवासी कथाकारों में से अनेक की कहानियों में स्त्री समस्या को उठाया गया है और उसका समाधान तलाशने की कोशिश की गई है। पति कहीं पत्नी को बेवकूफ कहता है, कहीं उसे छलता है और कहीं दहेज के लिए उस पर अत्याचार करता है।

अमेरिका में पिछले 25 वर्षों से रह रही कथाकार सुधा ओम ढींगरा जी के कहानी संग्रह 'कौन सी जमीन अपनी' में कहानी 'कौन सी जमीन अपनी' सोचने पर मजबूर कर देती है कि स्त्री ही क्यों हमेशा त्याग की मूर्ति बनी रहे और पति के अन्याय को सहती रहे। कहानी की नायिका सारंगी जो दसवीं पास है, 17 साल की आयु में पति सुलभ के साथ अमेरिका पहुंचती है। तब पहले ही दिन पति उसे बेवकूफ कहकर पुकारता है। उसके बाद 40 साल तक उसका पति उसे बेवकूफ का संबोधन देता रहा और वह त्याग और सहनशीलता की मूर्ति बनी, अपने सारे कर्तव्य निभाती रही और अंत में वह निश्चय करती है कि उसे अपने पति को तलाक देना होगा जो अभी भी 40 साल पहले की मानसिकता में जी रहा है। उसे उससे अलग होना ही होगा और अपने आसमान की तलाश करनी ही होगी।

इसी प्रकार अमेरिका की प्रसिद्ध लेखिका रचना श्रीवास्तव जी की कहानी 'पार्किंग' में लेखिका ने पुरुष की स्वार्थी मानसिकता को दिखाया है। कहानी की नायिका जूलिया स्नेह को अपनी आपबीती सुनाती है कि किस प्रकार उसके पति ने उसे छला है। बेटे का एक्सीडेंट उसे तोड़ देता है पर फिर भी बेटे की खातिर जीती है। परिवेश कोई भी हो आज की नारी बच्चों और परिवार की खातिर सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। समाज चाहे भारतीय हो या विदेशी पुरुष सिर्फ अपने लिए जीता है।

अनिल प्रभा कुमार की कहानी 'बस पांच मिनट' की नायिका सोना अपने मामा के सुझाव से स्टूडेंट वीजा की आड़ लेकर विवाह करने के लिए अमेरिका आती है लेकिन जिस युवक से उसका विवाह होता है वह भी उसे एक दिन वापिस जाने के लिए कहता है। पूछने पर पता चलता है कि सोना के पिता ने दहेज के 10 लाख रुपए उसके पिता को भारत में नहीं दिए। शादी के समय शर्त यह थी कि शादी अमेरिका में होगी और बदले में सोना के पिता दहेज के 10 लाख रुपए भारत में वर के पिता को देंगे जो उन्होंने नहीं दिए। सोना के यह कहने पर कि वह उससे किस बात में कम है, उसके पिता क्यों दे 10 लाख रुपए? उसका पति उसे धमकी देकर चला जाता है कि वह किसी न किसी तरह पैसे वसूल ही लेगा। बाद में एक षड्यंत्र के तहत घर में आग लग जाती है और सोना उस आग में जल जाती है लेकिन 6 महीने कोमा में रहने के बाद वह बच जाती है। वह अपने पैरों पर खड़ी होती है और अपनी जैसी अन्य दुखी स्त्रियों की मदद करती है।

इसी प्रकार अमेरिका की कहानीकार पुष्पा सक्सेना की कहानी 'विकल्प कोई नहीं' में बेटे के मर जाने के बाद सास द्वारा बहू का बेटी के समान कन्यादान करना नारी के अंतर्मन की महानता को दर्शाता है। इस प्रकार प्रवासी कथाकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से स्त्री के प्रत्येक रूप को बारीकी से दर्शाने में ईमानदारी से कोशिश की है।

वर्तमान समय में देश हो या विदेश प्रत्येक स्थान पर नारी घर व नौकरी दोनों के बीच तालमेल बिठाकर चल रही है। उसका जीवन आज पहले से ज्यादा व्यस्तता से भरा हो गया है। बेशक वह आर्थिक स्तर पर

आत्मनिर्भर हो गई है परंतु आज भी वह स्वयं की सुरक्षा के लिए पुरुष का साथ आवश्यक समझती हैं।

इस संबंध में सुषम बेदी कहती हैं 'आधुनिकता के इस मोड़ पर जबकि औरत ने बहुत कुछ बाहर का भी संभाल लिया है, उसके प्रति पुरुष की मूल वृत्ति में कोई फर्क नहीं आया। वह कितना भी बाहर काम कर ले घर में खाना वही बनाएगी। सभी बाहर के काम निपुणता से निभा लेती है फिर भी पुरुष के कंधे के बगैर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। यह सुरक्षा की जरूरत ही उसे पुरुष द्वारा प्रताड़ित भी करवाती हैं इसलिए वह पिट कर भी उसका घर नहीं छोड़ती क्योंकि बाहर खतरा और भी ज्यादा है।'

एक स्त्री समाज में केवल पुरुष के साए में ही स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। शादी से पहले वह पिता व भाई पर निर्भर रहती है तो शादी के बाद पति के साथ स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं।

कहानी के समान निबंधों में भी प्रवासी साहित्यकारों ने स्त्री संबंधी समस्याओं को उठाया है। स्नेहा ठाकुर ने अपने निबंधों में घरेलू हिंसा से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार भारतीय परिवारों में चाहे देश में हो या विदेश में घरेलू हिंसा देखने को मिल जाती है। स्नेहा ठाकुर के निबंध 'पत्नी प्रताड़ना' में घरेलू हिंसा की समस्या को लेखिका ने बहुत ही गंभीरता से उठाया है। दो अलग–अलग नारी पात्र घरेलू हिंसा का शिकार होती है। एक शमा किसी के पूछने पर हल्के से कहती है गिर गई थी तो दूसरी सुरिंदर डॉक्टर द्वारा लगाए गए टांकों को भी यह कहकर कि बाथरूम में फिसल गई थी पति की हिंसा को झुठलाने का प्रयास करती हैं। शमा व सुरिंदर जैसी अनेक भारतीय महिलाएं आज भी शारीरिक और मानसिक अत्याचारों को सहन कर रही हैं। इस प्रकार प्रवासी हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श दिखाई देता है। हिंदी के प्रवासी साहित्यकारों ने स्त्री के संघर्ष, त्याग, साहस और बुद्धिमत्ता का अपनी पैनी कलम से बहुत ही सुंदर चित्रण किया है।

M. 89013 66266
parkash.om2007@rediffmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 71-76
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

राजनीति का दलित पक्ष और शिवमूर्ति : संदर्भ बनाना रिपब्लिक

प्रियंका श्रीवास्तव
पता : आनंद भवन, राजबाड़ी पारा, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल। पिन–735101

शोध सार :

राज्य के लिए बनाई गई नीति के संदर्भ में राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ और जैसे–जैसे इसका विकास हुआ इसके मूल में स्थित राज्य का अर्थ ही धूमिल होता चला गया। राज्य यानि राज्य के कल्याण के लिए भावना पीछे छुटती चली गई और राज करने की नीति ही मुख्य ही गई। राजनीति का सवाल सत्ता के सवाल से जुड़ा है और जहाँ सत्ता है वहीं शासन के साथ शोषण की स्ट्रेटजी भी। समाज की मुख्यधारा में प्रारंभ से ही उच्च वर्ग अर्थात् ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा और दलितों को हाशियाकृत किया गया। इनकी समस्याओं को राजनीति के सवाल से न जोड़कर धर्म और समाज से जोड़ा जाता रहा, ताकि मुख्यधारा से अलग उपेक्षित, अवहेलित कर इन्हें प्रताड़ित किया जा सके। राजनीति में इनकी उपयोगिता केवल इतनी रही कि मंत्रिमंडल बनाने के लिए इनके वोट का उपयोग किया जाता रहा, तो वहीं सामाजिक संरचना में यह वर्ग बहुत ही अधिक उपेक्षित रहा। स्वतंत्रता संग्राम में अन्य सभी वर्ग औपनिवेशिक सत्ता से लड़ता नजर आया, लेनिन के मार्क्सवाद, समाजवाद की लड़ाई आर्थिक विषमता और पूंजी के एकाधिकरण के में विरोध रहा, वहीं दलित का संघर्ष बहुत ही व्यापक रहा।

औपनिवेशिक सत्ता के साथ आंतरिक उपनिवेश अर्थात वर्ण व्यवस्था से उसे लड़ना पड़ा, जो औपनिवेशिक सत्ता से भी अधिक घातक रहा, तो दूसरी ओर आर्थिक विषमता के साथ सामाजिक, धार्मिक विषमता का भी सामना इस वर्ग को निरंतर करते रहना पड़ा। ऐसे में राजनीति ही एक ऐसा मार्ग नजर आ रहा था जहाँ सत्ता परिवर्तन के साथ इस वर्ग के प्रति जो सामाजिक सोच रही उसमें परिवर्तन लाया जा सकता था और इसीलिए अंबेडकर ने राजनीति में दलितों के आगमन को जरूरी बताकर दलित आरक्षण की मांग की। जब दलित आरक्षण के तहत दलितों को राजनैतिक अधिकार प्राप्त हुए ताकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास हो सके, राजनैतिक कुर्सी के सहारे इनकी सामाजिक स्थति में सुधार हो, तब भी यह वर्ग मुख्यधारा के सवर्णों की गंदी राजनीति से मुक्त नहीं हो पाया। जिसके तहत कुर्सियाँ तो जरूर बदल गई, इनकी हो गई पर टोपियाँ सवर्णों की ही रही अर्थात् राजनैतिक चेतना शून्य यह वर्ग सवर्णों के हाथों की कठपुतली ही बना रह गया। शिवमूर्ति की 'बनाना रिपब्लिक' दलित राजनीति के ऐसे ही एक पक्ष को सामने रखती है। जहाँ सत्ता में जाति से दलित तो है, पर अर्थसत्ता इस हिसाब से उसके अंदर काबिज है कि दलित ही गायब है। राजनीति के इसी कुरूप विद्रूपत्ता का पर्दाफाश इस शोध–आलेख में किया गया है।

बीज शब्द : सत्ता, शासन, शोषण, मुख्यधारा, दलित, हाशियाकृत, स्वतंत्रता संग्राम, औपनिवेशिक सत्ता, मार्क्सवाद,

समाजवाद, अंबेडकर, दलित आरक्षण, सवर्णों, राजनीति।

डॉ. अंबेडकर लिखते हैं–" हिन्दू समाज एक मीनार की भाँति है और एक–एक जाति मीनार का एक तल है। ध्यान देने की बात यह है कि इस मीनार में सीढ़ियाँ नहीं है। एक तल से दूसरे तल में आने–जाने का कोई मार्ग नहीं है। जो जिस तल (जाति) में जन्म लेता है वह उसी तल में मरता है। नीचे के तल का व्यक्ति कितना भी लायक क्यों हो पर ऊपर के तल में उसका प्रवेश संभव नहीं। इसके विपरीत ऊपर के तल का मनुष्य चाहे कितना भी नालायक हो उसे नीचे के तल में धकेल देने की हिम्मत किसी में नहीं हैं।"[1] ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत दलितों को न्याय मिलने, स्वतंत्रता और समता के साथ अपना जीवन यापन करने का अधिकार मिल पाना संभव ही नहीं रहा। इस वर्ग को न्याय मिल सके इसके लिए सामाजिक व्यवस्था में काबिज जाति व्यवस्था के जंजीर का टूटना जरूरी है और हृदय परिवर्तन द्वारा ऐसा हो पाना संभव नहीं रहा। फलस्वरूप राजनीति के आँगन में आरक्षण नीति के तहत इनका आगमन हुआ। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जाति व्यवस्था के मीनार के एक तल से दूसरे तल में प्रवेश जहाँ असंभव रहा, वहीं राजनीति में दलित आरक्षण के तहत हरिजनों को सत्ता में काबिज होने का मौका मिला। 'बनाना रिपब्लिक' में भी दलित आरक्षण के तहत चुनाव लड़ने का अधिकार गाँव में दलित कोटे में आ जाता है। ऐसे में गाँव में ब्राह्मण, ठाकुर कानून के आगे मजबूर हो जाते है और दलितों के लेकर एक नई तरह की राजनीति शुरू कर देते है।

शिवमूर्ति ठाकुर के मुँह से कहलवाते है–" मैं नहीं बन सकता तो मेरा आदमी बने। लाखों की कुर्सी दूसरे के पास क्यों जाए।"[2] दलित आरक्षण के तहत ठाकुर–वाभन विवश है। चाह कर भी खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। सरकारी नीति का विरोध कर पान उनके द्वारा संभव नहीं है पर अब भी हार नहीं मानते इसलिए लाखों की कुर्सी पर किसी और को काबिज नहीं होने देंगे। खुद नहीं बन सकते तो ऐसे आदमी को सत्ता पर काबिज करेंगे, जो कागज पर तो दलित हो पर दिल और दिमाग से ब्राह्मण या कहा जाए ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोषक। इसी सोच के तहत ठाकुर साहब और पदारथ दूबे जैसे ब्राह्मण जग्गू और मुंदर जैसे दलितों को अपनी ओर से दलितों का प्रतिनिधित्व बनाकर दलित कोटे पर चुनाव लड़ना चाहते है। सत्ता में दलितों के आगमन को अम्बेडकर इसलिए चाहते थे ताकि जब यह वर्ग स्वयं सामने आएगा, सत्तासीन होगा तो अपने वर्ग की समस्याओं का समाधान कर पाएगा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की नींव रख पाएगा परंतु गाँव में देखे, तो कुर्सी भले दलितों के पास जा रही है फलस्वरूप कुर्सी पर बैठेगा तो दलित पर शासन ब्राह्मणों का ही रहेगा अर्थात् नाम और सरनेम से दलित पर दिल और दिमाग से ठाकुर। गर्व से ठाकुरों का उद्‌घोष है–"सरकार बुजरी करती रहे वहां बैठकर रिजरवेशन। यहां उनकी इस्कीम में पतिला लगाने वाले हम कम है क्या?"[3] वर्तमान में दलित आरक्षण के तहत दलितों को इतना तो पता है कि चुनाव लड़ना उसे है पर कैसे? इसके लिए आज भी ब्राह्मणों पर निर्भर है। जग्गू चुनाव में खड़े होने से लेकर जीतने की प्रक्रिया में ठाकुर साहब के इशारों पर चलते दिखाई पड़ता है और दलितों की इसी निर्भरता के कारण ही ठाकुर, ब्राह्मण भी सरकारी नीति का फायदा उठाने को मुक्त हो जाते है। जग्गु के विजयी होने पर सवर्ण समाज सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता कि 'पावर ऑफ एटार्नी' की तरह परधानी भी अपने नाम लिखा ली जाए। अर्थात कुर्सी किसी की भी हो, सत्ता ठाकुर, वाभन के हाथ में रहे।

इससे भी बिडम्बनात्मक स्थिति यह है कि ठाकुर सोचते है –"ठाकुर होकर बेची खरीदी क्यों करेंगे? दो लाठी मार कर छीन नहीं लेंगे?"[4] डॉ. वीरेंद्र सिंह यादव लिखते हैं–"संसार में ऐसा कोई देश नहीं होगा जो

मानव–मानव में इतना भेद रखता हो। परंतु भारत का दलित, वह शोषित मानव है जो पैदा हुआ तब भी दलित था, जिंदा रहेगा तब भी दलित है और मरेगा तब भी दलित है।"[5] दलित समाज के बारे में जब ऐसी सोच का बदलाव हो पाना संभव नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में दलितों की हित रक्षा को कौन देखेगा।

माना जाता है भारत गाँव में निवास करता है और ग्रामीण व्यवस्था के तह में देखेंगे तो पाएँगे गाँव में हमेशा से सवर्णों का ही अधिकार रहा है। ठाकुर, वाभन, जमींदार, महाजन के बनाए नियमानुसार ही गाँव संचालित होता रहा है। प्रेमचंद के कहानी और उपन्यास पर अगर नजर दौराए तो पाएँगे ग्रामीण व्यवस्था के कर्ता–धर्ता सवर्ण वर्ग ही रहा है। दलितों की गाढ़े –पानी की कमाई को लूटकर ही, उन्हें शोषित करके ही यह वर्ग ऐशों–आराम का जीवन जीता है और हाशिए पर खड़ा दलितों का पूरा समाज इनके अत्याचार को सह कर सिर झुकाकर, अपमानित होकर जीने को बाध्य है। कभी–कभी तो बेगारी करने को भी मजबूर है और अगर बेगारी न भी करे तो उचित मूल्य मिल पाने की स्थति में तो कम से कम नहीं है। ऐसे में दलित युवक जग्गू को चुनाव में खड़ा करने की ठाकुर की सोच दलित परिवार के लिए न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि उतना ही किसी अनहोनी के डर से सहमा देने वाला भी। तभी घर आ कर चुनाव लड़ने की बात जब जग्गू अपने पिता से कहता है वह चुनाव लड़ने वाला है तो जग्गू के पिता कह उठते है– "कहा नहीं कि मुझे पागल कुत्ते ने कांटा है, जो ठाकुरों–बाभनों के गांव में परधानी लरुगा। लर कर उनकी आंख का कांटा बनना है क्या?"[6] यह कथन बतलाता है कि गांव में दलितो की स्थिति गुलाम की है क्योंकि गाँव ही ठाकुर–वाभन का माना जा रहा है। ऐसे में सीट के आरक्षित होने पर चुनाव कोई लड़ सकता है तो दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि ठाकुर का आदमी ही। और अगर तीसरा कोई अपनी नीति को लेकर लड़ने के लिए खड़ा होता है तो ठाकुर–वाभन के विरोध में होने के कारण उसे फुलझरिया जैसा परिणाम भोगना पड़ता है।

अम्बेडकर लिखते हैं–" बहुतों ने ग्राम पंचायत की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। कुछ लोग ने उन्हें ग्रामीण प्रजातन्त्र कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजानिक जीवन के लिए अभिशाप है। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तू इसका मुख्य कारण मेरी समझ से ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। इससे हमारे लोगों में विशिष्ट स्थानीयता की भावना भर गई उससे बड़ी नागरिक भावना के लिए थोड़ी भी जगह ना रही। प्राचीन ग्राम पंचायतों की व्यवस्था के अंतर्गत एकताबद्ध जनता के देश के बदले भारत ग्राम पंचायतों का ढीला ढाला समुदाय बन गया। वे सब एक ही राजा की प्रजा है, इसके सिवा उनके बीच और कोई बंधन नहीं था।"[7] भारतीय गांव व्यवस्था को शोषण का धारदार हथियार माना जाता है तो इसके पीछे की क्रूर सच्चाई यही है।

अम्बेडकर ने कहा हैं–" मेरे विचार से इस देश के दो दुश्मनों से कमगारों को निपटना होगा। ये दो दुश्मन हैं, ब्राह्मण्वाद और पूंजीवाद.....। ब्राह्मण्वाद से मेरा आशय स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की भावना के निषेध से है। यद्दपि ब्राह्मण्वाद इसके जनक है लेकिन यह ब्राह्मण तक सीमित नहीं होकर सभी जातियों में घुसा हुआ है।"[8] अंबेडकर के अनुसार दलितों के दो दुश्मन ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद रहे, जिनके विरुद्ध उन्हें लड़ना था पर आज सत्ता में आने के बाद दलित भी पूंजीवाद का ही पोषक बना नजर आ रहा है। एक दलित भी अपने निजी लाभ /हित्त के आगे कुछ नहीं देखता। अंबेडकर का मानना था दलित जब मुख्यधारा में आएँगे तो स्वतंत्रता, समानता,

बंधुत्व की भावना से समृद्ध हो अपने पूरे समुदाय का हित्त करेंगे। सदियों के शोषण से उसे मुक्त करेंगे, वहीं दूसरी ओर हकीकत देखे तो स्थिति बिल्कुल भिन्न है अर्थात पहले से भी भयानक है। जग्गु राजनीति में अपने समूह, जाति के उत्थान के लिए नहीं उतरता, बल्कि अर्थ–लाभ के लिए उतरता है। ठाकुर समझाता है– "सालाना पंद्रह बीस लाख तक खर्च करने का चांस रहता है। मनरेगा की मद से तो चाहे जितना निकालो। बस कागज की पेटा पूरा करते रहो. . .पांच साल में पच्चीस लांख की बचत।....बेटे की शादी में मोटरसाईकिल मिलती है। बेटी की शादी में हजारों रुपए न्योता मिलता है।......वृधावस्था पेंशन, विधवा पेंशन.... । पांच साल में कितनी कमाई होगी उसका हिसाब लगा सकता है।"[9] जग्गुआ की भी यहीं सोच है। उसे चाहिए तो रामसिंह की तरह मोटर साइकिल, अच्छा नाम, मान–सम्मान अधिकार चाहिए, लाभ चाहिए जग्गु से जे.एन. टाईगर बनना है लेकिन अपने ही दलित भाइयों के प्रति दायित्व और कर्तव्य की भावना गौण है। दलित राजनेता की यह भावना दलितो के शोषण की दोहरी पृष्टभूमि का निर्माण कर रही है। जिस प्रकार ब्रिटिश काल में अंग्रेज और उनके द्वारा तैयार मध्यस्त 'जमींदार' शोषण करते रहे, वैसे ही राजनीति में दलितों के आगमन के बाद ब्राह्मण, ठाकुर और उनके द्वारा तैयार जग्गु जैसे दलित ब्राह्मण, दलितों का शोषण करेंगे। पहले सवर्ण और दलित के बीच की समस्या थी, आज दलित और महादलित के बीच भी वही समस्या है। यहाँ विकास या कल्याण की योजना नहीं है बल्कि सता हथियाना है। ज्यादा से ज्यादा कुछ करना है तो राष्ट्रवादी नेता नेहरू, गांधी या दलित मसीहा प्रेमचंद की तरह सहानुभूति की राजनीति पर व्यावहारिक धरातल पर कुछ भी नहीं।

वर्तमान संदर्भ में देखे तो दलित आंदोलन, दलित आरक्षण जिस ब्राह्मणवाद के विरोध में है, आज वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कुसंस्कारों का पोषक बन गया है। जाति भेद जिसने दलितों का सबसे अधिक शोषण किया और जिसके दंश को आज भी ऊँचे से ऊँचे पद पर आसीन दलित भोग रहा है उसी जातिगत अस्पृश्यता का पोषक आज का दलित बन गया है। वास्तव में हर जाति अपने से छोटी जाति को शोषित करने के लिए खोज ही लेती है और दलितों के संदर्भ में स्थति तो यह है कि अपनी ही जाति में जो उनसे छोटे है उससे अस्पृश्य व्यवहार करने, उसका शोषण करने से भी वो पीछे नहीं हटते। शिवमूर्ति दलितों के इस कटु सत्य को भी उभारकर 'बनाना रिपब्लिक' में रखते है। जब मास्टर के यहाँ युनिवर्सिटी के छात्र परधानी के चुनाव में दलित फैक्टर पर स्टडी करने आते है, तो मुंदर और जग्गु जैसे दलित इसलिये वहाँ नहीं जाना चाहते है क्योंकि वह उनसे छोटे दलित है–"वह स्कूली लौंडों के आगे हाजिरी बजाने जाएगा? वह भी अपने से छोटे दलित के दरवाजे पर? हरगिज नहीं।"[10] जग्गु और मुंदर जैसे दलितों की यह सोच एक चिंता छोड़ जाती है कि ब्राह्मणवाद के जिस कुसंस्कार से लड़ने के लिए इन्हे आरक्षण मिला, सत्तासीन होने के बाद क्या वही संस्कारों को पोषित नहीं करेंगे। सवर्ण जो नजरिया इनके प्रति रखता है, इनका नजारियाँ भी अपने से छोटे दलितों के प्रति वैसा ही है। ऐसे में दलितों की छोटी जाति की समस्या का समाधान होना नजर नहीं आता। ऐसे में संभव है कि उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की मांग हो और दूसरी स्थिति यह भी संभव है कि वो भी सत्तासीन होकर अपने से छोटे का शोषण करें। दलितों ने जहाँ से लड़ना शुरू करते है फिर वहीं आ पहुँचते है।

सत्ता के मद में दलित जहां ब्राह्मणवादी कुसंस्कारों को पाल रहा है वहीं अपना दूसरा दुश्मन पूंजीवाद भी उस पर इस कदर हावी है कि उसकी आंधी में दलित अखण्डता टूटती है। शिवमूर्ति जिक्र करते है–"पांच जातियों में बंटे चालिस घर दलितों के बीच से जग्गु को लेकर तेरह उम्मीदवारों ने पर्चा भरा।"[11] दलित जाति

को सवर्णों के शोषण के विरोध में अपनी लड़ाई लड़ना था। यह लड़ाई अपने सही अंजाम तक पहुँच पाएं इसलिए एकजुट रहना था लेकिन आज वहीं आपस में ही उपजातियों में बँट गए है। उनमें फूट पर गई है। ऐसे में सत्ता लाभ के लिए जिन दलितों को सवर्णों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी थी, वह खुद उन्हीं सवर्णों जा मिलता है। जग्गू और मुंदर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अम्बेडकर जिन दो दुश्मनों से दलितों को निपटने की बात करते है आज दलित उन्हीं दो दुश्मन से जा मिले है। जग्गु ब्राह्मण से मिलता है तो मुंदर पदारथ दूबे से, पूंजी प्राप्ति के लिए।

यहां राजनीति में सत्ता लाभ के लिए दलित और ब्राह्मण एक होते नजर आते है पर सामाजिक व्यवस्था में ऐसा होता नहीं दिखता क्योंकि जब चुनाव में दलित जग्गू जीतता है और ठाकुर उसके स्वागत के लिए ठकुराइन को माला बनाने कहते है, तो वह मना कर देती है और जो कहती है वह विचारणीय है। "राजगढ स्टेट की राजकुमारी ठकुराईन, शिवराज कुवंरि आंखे तरेरकर देखती है। यानी की मैं माला गूंथूंगी। जगुआ के लिए?"[12] ठाकुर की बीबी ही नहीं, बल्कि गाँव के सभी सवर्ण औरतों का मानना है–"सवर्णों के गांव में दलित को परधानी की कुर्सी पर बैठाना सवर्णों के सिर पर बैठाना हुआ। लोहिया तो समाजवाद नहीं ला पाए लेकिन आज की सरकारे लगता है ला के रहेगी। किसी आदमी ने ऐसा किया होता तो उसका मूंह फोंर देते।"[13] दया पवार कहती भी है, दलित के शत्रु अदृश्य है। वह पुस्तक में, भाषा में, विचारों में, लोगो के दिमाग में है। तभी तो जगुआ से जे. एन. टाइगर बनने के सफर को तय करने के बाद भी, सत्ता हासिल करने के बाद भी समाज की नजर में वह हेय हीं, घृणा का पात्र ही रह जाता है। ठाकुर भी दलित की आड़ में सत्ता हथियाना चाहते है पर सामाजिक दृष्टि से इतना अस्पृश्य मानते है कि उन जैसों के हाथ का पानी तक नहीं पीना चाहते और अंततः पानी पीते और कमर लचकाते भी है जो व्यवस्थागत मजबूरी के आगे जहां काम आने पर बंदर को भी बाप बना लेना पड़ता है का नियम लागू होता है। ठकुराइन को वह समझाते है– "गूंथना परेगा रानी।....जमाने के साथ चलना परेगा। समझों वह नहीं, मै जीता हूं। असल में तो परधानी मुझे ही करनी है। वह ससुरा तो चिरी का गुलाम है।"[14] ठाकुर और जग्गू राजनीति में वोट प्राप्त करने के लिए तरह–तरह के लालच देते है। मुसलिम वोटो की अलग से राजनीति की जाती है लेकिन इस के ऊपर निजी हित्त की राजनीति प्रारंभ हो जाती है और दलित हित्त की राजनीति खत्म।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिवमूर्ति की 'बनाना रिपब्लिक' राजनीति के दलित पक्ष के विभिन्न रूप को बखूबी उजागर करती है। जान हालवे का कहना है– "सैद्धांतिक धरातल पर सत्ता और शक्ति की केंद्रितता को घातक माना गया है, उनके अनुसार केंद्रिकरण तो सत्ता की प्रकृति में निहित है, उसकी गतिकी की उसी ओर ले जाती है और यही इतिहास में प्रमाणित हुआ है।"[15] जग्गु भी सत्ता पाकर केंद्रिकरण की ओर ही बढ़ता है। जीत कर जग्गू का ठाकुर के दरवाजे पर न जाना, ठाकुर के उसके दरवाजे पर आने पर जग्गु का उनसे बात न करना, उनकी पहनाई माला को निकाल कर उन्हें ही वापस करना और वहाँ मौजूद दलित लड़के का कहना –" जरा कमरिया लचकाइए ठाकुर।"[16] एक तथ्य तो सामने जरूर रखता है कि जग्गू ठाकुर के हाथ की कठपुतली बनने को तैयार नहीं है लेकिन एक सत्य यह भी है अपने दलित भाइयों के लिए भी वह कुछ नहीं करने वाला क्योंकि उसे तो पैसा कमाना है, जे. एन. टाइगर बनकर दलित सरनेम से मुक्त होना है। दलित सरोकार से उसका कोई लेना देना नहीं। डॉ. वीरेंद्र सिंह यादव लिखते हैं–"वर्तमान समय में दलितों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती उनकी जातीय अस्मिता और आर्थिक उन्नति को लेकर है।"[17] दलित भाईयों के लिए आज

सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि आज जहाँ इन्हे अपने जातीय उत्थान के बारे में सोचना था वहीं जग्गू जैसा दलित केवल निजी हित्त तक ही सीमित रह जा रहा है। ऐसे में वह दलितों के भीतर दलित ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व ही बनेगा और इस नियति के आगे दलितों की मजबूरी अब आगे से भी वीभत्स है क्योंकि मौजूदा हालात में जब दलित ही दलित का शोषक बनकर उभरेगा तब वह अपनी शिकायत किस्से करेगा, किसे कोसेगा। धूमिल ने कहा है–"जिसके पास थाली है, हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है।"[18] जग्गुआ उसी दिशा को अग्रसर है। दलित आरक्षण जो दलितों की हित रक्षा के लिए किया गया, वह 'बनाना रिपब्लिक' बनती जाती है।

संदर्भ सूची :-

1. मूकनायक –डॉ. बी. आर. अंबेडकर, संपादकीय।
2. कहानी : बनाना रिपब्लिक–शिवमूर्ति hindisamay.com
3. वही।
4. वही।
5. डॉ भीमराव अंबेडकर और दलित चिंतन की प्रतिबद्धता : परिवर्ती अम्बेडकरवाद या दलित नवजागरण युग – डॉ वीरेंद्र सिंह यादव, जनकृति पत्रिका, Vol. 2, issue -14, April 2016.
6. कहानी : बनाना रिपब्लिक–शिवमूर्ति hindisamay.com
7. अंबेडकर बी. आर. राइटिंग्स एंड स्पीचेशय खंड–७, पृष्ठ 300
8. 'दलित राजनीति की समस्या', प्रफुल्ल कोलख्यान, पृष्ट ५, ६
9. कहानी : बनाना रिपब्लिक–शिवमूर्ति hindisamay.com
10. वही।
11. वही।
12. वही।
13. वही।
14. वही।
15. 'चीख', जान हालवे, 'आज की क्रांतियों का अर्थ' अनुवाद लाल बहादुर शर्मा, प्रकाशक– संवाद प्रकाशन, पहला संस्करण दिसम्बर २००६
16. कहानी : बनाना रिपब्लिक–शिवमूर्ति hindisamay.com
17. ग्रीन 3. डॉ भीमराव अंबेडकर और दलित चिंतन की प्रतिबद्धता : परिवर्ती अम्बेडकरवाद या दलित नवजागरण युग –डॉ वीरेंद्र सिंह यादव, जनकृति पत्रिका, Vol. 2, Issue 14, April 2016, Page 114
18. पटकथा –धूमिल।

Address : Anand Bhawan, Rajbari Para, Po+ Dist Jalpaiguri, State : West Bengal
Email : shrivastava123priyanka@gmail.com, Mobile No. : 8927595844

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 77-83

Regional Political Parties in India : Balancing Local Interests and National Integration

Mamta Goutam
Assistant Professor, Government P. G. College, Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P.

Abstract :

India's federal democracy is shaped not only by national parties but also by the strong presence of regional political forces that articulate local aspirations and influence national policymaking. Emerging from linguistic, cultural, and socio-economic identities, regional parties have played a decisive role in India's politics since the reorganization of states in 1956 and the decline of Congress dominance after 1967. Their prominence grew further in the coalition era of the 1990s, when they became crucial power brokers at the Centre. Even in the context of single-party dominance since 2014, regional parties have maintained their relevance due to their strong electoral bases in states, their bargaining power in federal institutions, and their capacity to shape coalition arithmetic, as seen in the 2024 general elections. These parties address issues ranging from social justice, welfare policies, and caste-based reservations to regional development, fiscal devolution, and state autonomy. While they strengthen India's federal balance by voicing subnational concerns, they also pose challenges such as policy fragmentation, leadership concentration, and tensions between local and national priorities. This paper analyses the historical evolution, socio-economic basis, and policy impact of regional parties in India, highlighting their enduring role in balancing local interests with the imperatives of national integration.

Keywords : Regional Parties; Federalism; Indian Politics; Coalition Governments; Social Justice; State Autonomy; Electoral Politics; Party System; Regionalism; Policy Impact

Introduction :

India's multi-layered democracy is unique because of its diverse linguistic, cultural, religious and regional identities. This diversity has given rise to parties focused on national as well as regional issues, commonly called regional or state level parties. These parties are often labelled as "state parties" in the Election Commission's recognition system and their influence is concentrated in only one or a few states—but in an era of fragmented parliamentary majorities, their influence extends to the national power structure and policy-making. In the 2024 Lok Sabha elections too, the seat count of parties like Samajwadi Party, Trinamool Congress, DMK, Telugu Desam, JD(U) had a concrete impact on the power mathematics and policy agenda of the Centre, which has become a central feature of today's Indian party system.

The aim of this paper is to analyse the emergence of major parties formed on regional issues, their socio-economic base, their agenda, and their role in Indian politics—particularly in the federal system, coalition governments, and policy-making.

1- Regional Political Parties: Definition, Evolution and Growth :

The Election Commission of India (ECI) divides political parties into national and state parties, determined by criteria such as vote-share and seat performance. Thus, "Pradeshik" or "regional" parties are those that are organised in a specific state/region and have a decisive political presence there; the ECI's updated list and the 2024 election data confirm this classification and their spread-out network.

Historical Evolution :

The 1956 linguistic reorganisation led to the institutionalisation of identity politics at the state level; the 1967 general election saw the first widespread challenge to Congress supremacy in the states, and the coalition era at the national level emerged permanently after 1989—with regional parties becoming kingmakers. Economic liberalisation after 1991 encouraged competitive federalism and state-centred development agendas, which also enhanced the policy-bargaining capacity of regional parties.

Contemporary scenario :

Along with the trend of "national party dominance" in the Indian party system after 2014, regional parties have retained strong roots in many states—and their parliamentary weight is again seen to be decisive in 2024 (e.g. SP, TMC, DMK, TDP, JD[U] etc.). This leads to the conclusion that despite claims of "renationalization" of national politics, the relevance of regional parties in the states is structural.

2- Regional issues: socio-economic basis and agenda :

The rise of regional parties is not just a result of linguistic/cultural identity; it is also rooted in concrete policy issues such as development inequalities, resource-distribution, reservation/social justice, state autonomy, agriculture/employment/local industry, disaster management, and state-specific infrastructure needs.

In Tamil Nadu, the long-term agenda of language-based identity and social justice (reservations, welfare schemes) by the DMK/AIADMK; as well as demands for centre-state financial sharing and "true federalism", remains central to political discourse.

In West Bengal, land-reform (Left Front era) followed by welfare transfers and rural-urban safety nets (TMC) set the state-level agenda.

The party that emerged from the Telangana statehood movement (BRS) prioritised water-irrigation, income-support for farmers, and urban-hub policy.

TDP–YSRCP competitive politics on the question of special category status and capital/infrastructure after bifurcation (2014) in Andhra Pradesh.

BJD's emphasis on disaster-management and health/nutrition in Odisha.

Caste-based social justice, reservation expansion, and recent caste survey and emphasis on jobs/local welfare in Bihar/UP.

Coordination of cooperative-agriculture, urban development and Marathi identity through regional parties (both Shiv Sena factions, NCP [Sharad Pawar] etc.) in Maharashtra.

These priorities have consistently kept the state voice strong in centre-state fiscal federalism (tax-distribution, grants, revenue-sharing).

3- Regional parties and federalism: impact on centre-state relations :

Indian federalism has oscillated between cooperative and sometimes competitive federalism. Regional parties—whether in power or in opposition—have shaped centre-state equations in the following ways :

Indian federalism has oscillated between cooperative and sometimes competitive federalism. Regional parties—whether in power or in opposition—shaped the Centre-State equations in the following ways :

Political bargaining power : In exchange for support in coalition governments, they secured states' financial/policy demands—new institutions, special packages, projects, etc. This was seen during both the UPA/NDA phases in the 1990s and 2000s.

Pressures in fiscal federalism : Strong advocacy of state interests in the FC-due share, the GST Council, and the alignment of centrally sponsored schemes. (Demands for "revenue sharing" and "state autonomy" have resurfaced in recent discussions.)

Policy pluralism : Innovation and competition among states in education, health, social security, liquor policy, local taxes/industries, agricultural markets, etc.—leading to the diffusion of best practices.

Subnational diplomacy : Some states have become active in investment attraction/diaspora connectivity/border commerce; this is referred to in the scholarly literature as "subnational diplomacy".

4. The Role of Regional Parties in Coalition Politics :

(a) 1989–2004: "Coalition Mantra" and Kingmaker : Regional parties were crucial components/supporters in the National Front (1989), the United Front (1996–98), and then the NDA-I (1998–2004) and UPA-I/II (2004–14). Literature suggests that parties often form coalitions to pursue three interests—power, policymaking, and organizational expansion. Regional parties left a strong imprint on central policies by balancing these three objectives.

(b) After 2014 : Dominance and Counter-Dominance : Despite single-party majorities in 2014 and 2019, regional parties remained indispensable in parliamentary arithmetic due to heterogeneity across states—especially in the Upper House, inter-state coordination, and the need for multi-party support at the center in 2024. In the 2024 election results, the performance of SP (37), TMC (29), DMK (22), TDP (16), JD(U) (12), Shiv Sena [UBT] (9), NCP [Sharad Pawar] (8) and others directly affected the power equation.

(c) Policy Outcomes : In coalition phases—whether the rise of rural employment/rights-based welfare under the UPA or the acceleration of infrastructure/telecom liberalization during the NDA-I—the approval of regional parties was a practical prerequisite. Scholars argue that competitive politics often advances economic reforms because it creates multi-level consensus and checks and balances on policy decisions.

5. Major Categories and Examples of Regional Parties :

1. Identity-Anchored (Language/Culture/Regional Identity) :

- Dravidian Parties (DMK/AIADMK)—Tamil identity + social justice.
- Shiv Sena (both factions)—Marathi identity and urban-based interests.
- Asom Gana Parishad (AGP)—Assamese identity/immigration issue.
- National Conference/PDP (J&K)—Regional autonomy/specific constitutional issues.

2. Class/Caste-Justice/Welfare Oriented :

- Samajwadi Party (SP), Rashtriya Janata Dal (RJD)—Social justice and reservation politics in North India; leading in recent caste survey debates.
- Trinamool Congress (TMC)—Welfare-oriented model, especially schemes for women/rural poor.
- JD(U)—Social justice + development combination in Bihar.

3. Development-oriented/state-building agenda :

- Telugu Desam Party (TDP), YSR Congress (YSRCP)—Andhra Pradesh Public Sector Undertakings (PSSs), capital projects, Special Category Status (SCS)/Capital debate.
- BJD (Odisha)—Disaster management, nutrition, primary health; long-term governance stability.

- BRS (Telangana)—State-building, water and irrigation, and income support for farmers.

4. Emerging/Hybrid Models :

- Aam Aadmi Party (AAP)—Urban governance/service delivery, but with state-based expansion.
- NPP, MNF, IPFT, etc. (Northeast)—Regional identity + development-connectivity agenda.

6. Concrete Dimensions of Policy Impact :

(a) Social Justice and Welfare :

Dravidian politics institutionalized programs such as reservation expansion, scholarships, nutrition, and gender equality; the social justice paradigm in North Indian states promoted representation in education and employment and welfare schemes. Contemporary discourses in Tamil Nadu—center-state finance, "strong states lead to a strong India"—remain central to the federal debate today.

(b) Economic Liberalization and Competitive Federalism :

After 1991, states played an active role in attracting investment, creating manufacturing/service hubs, and the infrastructure race. Several studies argue that competitive/coalitional politics often made reforms possible by securing buy-in from state interests and creating space for policy adaptation.

(c) Centre-State Financial Issues :

Regional parties, through their governments/organizations, negotiate with the Centre on issues such as the Finance Commission's recommendations, centrally sponsored schemes, and states' share in the GST Council. Recent statements and political initiatives have repeatedly emphasized "equitable revenue distribution."

(d) Pluralization of National Policy Debate :

State-level experiments on food security, rural employment, the right to education and health, land acquisition, cooperative farming, liquor policy, urban governance, police reforms, and disaster management have energized national-level debate and policy innovation. This pluralization would not have been possible without regional parties.

7. Challenges and Criticisms :

1. Policy Fragmentation :

Multi-national priorities and short-term bargaining can sometimes disrupt national policy coherence (e.g., constant tussle over tax structures/subsidies). However, higher-level collaborative forums—such as the GST Council—have sometimes facilitated coordination.

2. Instability and Coalition Management :

The short-lived nature of governments and episodes of "withdrawal of support" in the 1990s underscore this concern; yet, examples like the NDA-I/UPA-I/II also demonstrate relative stability and policymaking capabilities.

3. Local versus National Priorities :

State-specific benefits sometimes demand difficult compromises from a national perspective—this is an inherent conflict of federal politics.

4. Internal Democracy and Leadership Concentration :

Many regional parties have been highly leadership-centric; Succession/splits (such as in some Maharashtra/Andhra/Telangana parties) may raise questions about their sustainability.

5. From cadre to "network" party :

Parties born out of student/worker/social movements are bound to become electoral machines over time; but this can also lead to a shrinking of ideological debate—a broader trend highlighted by contemporary analysis.

8. The Post-2024 Picture: A "Hybrid" Party System :

The 2024 Lok Sabha elections demonstrate that while a dominant party remains dominant at the national level, regional parties continue to wield decisive weight in power formation and policymaking. Parliamentary support, the composition of the Upper House, state election cycles, and fiscal federalism all combine to create a "hybrid" party system in which national and regional power centers coexist. The foundation of this coexistence—India's multi-layered, multilingual, and multi-ethnic society—is likely to persist in the future.

9. Conclusion :

A major reason for the success of Indian democracy is its ability to incorporate regional aspirations within the party system and institutional federalism. Regional parties—whether identity-based, focused on social justice, or development-oriented—translate state-level priorities into the national discourse. Between the coalition era after 1989, liberalization after 1991, and national dominance/opposition after 2014, these parties have deepened policy outcomes, fiscal federalism, and democratic representation.

Going forward—in areas such as the GST Council, the Finance Commission, the design of centrally sponsored schemes, internal migration/urbanization, water-climate-disaster, agricultural markets, education-healthcare, and digital/green transition—the bargaining power and innovation-competitiveness of regional parties will continue to shape India's policy economy. This is not just a story of kingmakers, but the ongoing politics of the Republic of States, in which the voices of states—in partisan form—shape the policy direction of the nation.

Bibliography :

1. H. Schakel. "India after the 2014 General Elections: BJP Dominance and the

Renationalisation Debate." Published 2019.

2. C. K. Sharma. "Partisan Federalism and Subnational Governments' International Engagements." Publius: The Journal of Federalism, 2020.
3. ECI. Recognition/De-recognition and Symbols—Guidelines & Compendium.
4. Election Commission of India (ECI). General Election to Lok Sabha 2024—Statistical Reports (Highlights, Parties Participated, Successful Candidates).
5. Election Commission of India (ECI). General Election to Parliamentary Constituencies: Trends & Results June-2024 (Party-wise performance). Accessed 2024.
6. Election Commission of India (ECI). List of Political Parties (National/State), 2024 updates.
7. Election Commission of India (ECI). List of Political Parties—(detailed PDF extracts).
8. FNF (India). "Politics of Economic Reforms: Real Lessons from 1991." 23 July 2021.
9. M. P. Singh. "India's National Front and United Front Governments: Coalition Politics in the 1990s." Friedrich-Ebert-Stiftung Paper (JSTOR archived).
10. Milan Vaishnav & Caroline Mallory. The Resilience of India's Fourth Party System. Carnegie Endowment, 26 Sept 2024.
11. Sanjay Ruparelia. "Assessing the Efficacy of Coalition Governments: UPA and NDA." EPW Engage.
12. The Academic (Journal article, 2024). "The Role of Regional Parties in Coalition Politics in India."
13. Times of India (Campus politics trend note). "Shift from campus-born parties to national affiliates in PU elections," Aug 2025.
14. Times of India (News Report). "Centre–State fiscal devolution debate; Tamil Nadu CM's remarks on true federalism," Aug 2025.

09455883002 (M)

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 84–90
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

A Socio-Legal Analysis of Female Foeticide in India : Unraveling the Roots, Re-evaluating the Laws, and Re-imagining the Future

Dr. Kamal
Department of law, Assistant professor, SKD University, Hanumangarh.

Abstract :

Female foeticide, the gender-selective abortion of female fetuses, represents a critical demographic and social crisis in modern India. Despite rapid economic development and a robust legal framework specifically designed to prevent it, the practice persists, leading to a dangerously skewed Child Sex Ratio (CSR). This paper argues that the persistence of female foeticide is not a failure of law alone but a symptom of a deep-seated socio-cultural pathology that the legal system has been unable to address effectively. Through a socio-legal analysis, this paper deconstructs the patriarchal and economic underpinnings of son preference, which creates the "demand" for sex selection. It then critically evaluates the premier legislative response—the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act, 1994—highlighting the chasm between its legislative intent and its pathetic implementation, marked by low convictions and regulatory capture. The paper further examines the complicit role of medical technology and ethics, and the consequent societal fallout of declining sex ratios. Concluding that a purely punitive legal approach is insufficient, the paper advocates for a paradigm shift towards a holistic strategy that synergizes stringent legal enforcement with transformative social policies aimed at dismantling patriarchy and empowering the girl child, thereby addressing the "demand" at its source.

1. Introduction: The Paradox of the "Missing Girls"

India stands at a perplexing crossroads. It is a nation that venerates the feminine divine in its mythology, yet systematically eliminates its daughters in reality. This paradox is starkly quantified in the decennial census data, which reveals a Child Sex Ratio (CSR, defined as the number of girls per 1000 boys aged 0-6 years) that has shown a consistently alarming decline: from 945 in 1991, to 927 in 2001, to a historic low of 918 in 2011. While the latest National Family Health Survey-5 (2019-21) indicates a marginal improvement to 929, this figure remains deeply pathological and masks severe regional disparities, with states like Haryana (894), Punjab (938), and Gujarat (954) continuing to reflect a profound son preference.

Female foeticide is the deliberate abortion of a fetus because it is female. It is the most potent manifestation of son preference, facilitated by modern medical technology. A socio-legal analysis of this phenomenon is imperative, as it moves beyond a siloed examination of either the law or the society, and instead investigates their dynamic interplay. It probes how social norms shape the efficacy of laws and how laws, in turn, can attempt to reshape social norms.

The central thesis of this paper is that despite a comprehensive legislative framework in the form of the PCPNDT Act, female foeticide persists in India due to a complex interplay of deep-seated socio-cultural norms, systemic failures in legal implementation, and medical complicity. The law, focused predominantly on punishing the "supply" side, has failed to dismantle the "demand" side rooted in patriarchal structures. Consequently, a sustainable solution necessitates a paradigm shift from a predominantly punitive approach to a holistic strategy centered on female empowerment and social engineering.

2. The Socio-Cultural Crucible: Deconstructing the Demand for Sons

The practice of female foeticide cannot be understood without first deconstructing the powerful socio-cultural engine that drives the demand for sons. This demand is not monolithic but a complex web of religious, economic, and social imperatives.

Patriarchy, Lineage, and Ritualistic Imperatives: At its core, Indian society is predominantly patrilineal (descent traced through the male line) and patrilocal (a wife resides with her husband's family). This system places an immense premium on the son as the carrier of the family name and lineage. A daughter, in contrast, is often perceived as paraya dhan (someone else's wealth), who will eventually belong to her husband's family. Religious rituals further entrench this bias. In Hindu traditions, the performance of the father's last rites (shraddha) by a son is considered essential for the salvation of his soul. The ritual of kanyadaan (the giving away of the daughter) is seen as the ultimate pious act for a father, but it also symbolically reinforces the notion that a daughter's primary affiliation is transitory.

The Economic Disincentive of Dowry : The dowry system, though illegal under the Dowry Prohibition Act, 1961, remains virulently prevalent. It transforms a daughter from a member of the family into a financial liability. The prospect of financing a substantial dowry at the time of her marriage often leads families to view a daughter's birth as an economic burden. A son, conversely, is seen as an economic asset who will bring dowry into the family and provide old-age security for his parents. This economic calculus becomes particularly acute in the context of the idealized small family norm promoted by family planning programs. When parents decide to have only one or two children, the pressure to ensure that at least one is a male becomes overwhelming, directly leading to sex-selective practices.

Social Status and Security : Beyond economics, sons confer social status and a sense of security. They are expected to support parents in their old age and protect the family. Daughters, after marriage, are often unable to provide the same level of day-to-day support or physical security to their natal families. This perception, while changing in urban, educated contexts, remains a powerful force in large parts of the country. The regional clustering of the most skewed sex ratios in the northern "patriarchal belt" of India (Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh) is a direct testament to the strength of these interlinked socio-cultural factors.

3. The Legal Architecture: A Fortress with Weak Foundations

Recognizing the crisis, the Indian state responded with one of the world's most specific and stringent laws against sex selection: The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (amended in 2003).

The PCPNDT Act: A Critical Analysis : The Act is comprehensive on paper. It prohibits sex selection both before and after conception. It regulates the use of prenatal diagnostic techniques (like ultrasound and amniocentesis) strictly to detect genetic abnormalities, and explicitly bans their use for determining the sex of the fetus. Key provisions include :

1. **Registration and Regulation :** Mandatory registration of all clinics and equipment.
2. **Prohibition on Disclosure :** A strict ban on communicating the sex of the fetus to the pregnant woman or her relatives.
3. **Record Keeping :** compulsory maintenance of detailed records (Form F) for every scan or procedure.
4. **Stringent Penalties :** Violations can lead to imprisonment and hefty fines, with the possibility of license cancellation for medical professionals.

The Implementation Gap : Despite its robust design, the Act has been a spectacular failure in implementation. The most glaring indicator is the abysmally low conviction rate. As of 2021, over 4,000 cases have been filed under the Act across India, but convictions have been secured in only a handful. This failure stems from several factors:

Procedural and Evidentiary Hurdles : Proving that a doctor disclosed the sex of the fetus is extremely difficult. It often requires sting operations by NGOs or decoy patients, evidence which is sometimes challenged in court. The lengthy and complex legal process discourages witnesses and dilutes cases over time.

Inadequate Enforcement Machinery : The regulatory bodies established under the Act—Appropriate Authorities, Advisory Committees, and Supervisory Boards—are chronically understaffed, underfunded, and lack technical expertise. They often function as peripheral government departments without the teeth or the motivation for proactive, surprise inspections.

Medical Complicity and Collusion : The medical community, which should be at the forefront of implementing the law, is often the primary violator. A powerful nexus of doctors, clinic owners, and middlemen has developed sophisticated methods to circumvent the law, using coded language or operating through clandestine networks.

The MTP Act Loophole : The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, allows abortion on a range of grounds, including the "mental health" of the mother. This creates a significant loophole. A family can legally determine the sex of the fetus illegally, and then procure an abortion by claiming the pregnancy is causing mental stress, effectively bypassing the PCPNDT Act.

Judicial Activism and Its Limits : The Indian judiciary, particularly the Supreme Court, has repeatedly intervened to shore up the Act. In landmark judgments like CEHAT vs. Union of India (2001), the Supreme Court issued detailed directives to central and state governments to ensure effective implementation, including the sealing of unregistered machines and the creation of dedicated supervisory bodies. However, these directives have often been met with bureaucratic inertia and a lack of political will, revealing the limits of judicial power in the face of executive apathy.

4. The Nexus of Technology and Ethics: The Medical Complicity

The advent of accessible prenatal diagnostic technology was the catalyst that transformed the traditional practice of female infanticide into the more modern, clinical, and hidden practice of female foeticide.

The Double-Edged Sword : Technologies like ultrasonography, developed for monitoring fetal health and detecting abnormalities, became the primary tool for sex determination due to their non-invasive nature and widespread availability. The very medical progress that was meant to save lives was perverted to eliminate them based on gender.

Erosion of Medical Ethics : The active participation of qualified medical professionals in this illegal trade represents a profound ethical crisis. Driven by lucrative financial incentives—sex determination and subsequent abortion can be a highly profitable package—a section of the medical community has prioritized profit over the Hippocratic Oath and their role as guardians of public health. This complicity makes enforcement incredibly difficult, as it involves prosecuting a powerful and respected professional class.

The New Frontier : NIPT and ARTs: The regulatory challenge is evolving. Newer technologies like Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT), which can detect fetal DNA in the mother's blood as early as 7-9 weeks, pose a significant threat. While a boon for detecting chromosomal disorders, these tests can also reveal the fetal sex with high accuracy. Regulating the misuse of such tests, which can be conducted with a simple blood draw and the samples sent to labs abroad, is a monumental task for the existing PCPNDT machinery. Similarly, Assisted Reproductive Technologies (ARTs) like pre-implantation genetic diagnosis (PGD), used for selecting embryos free of genetic disorders, can be misused for sex selection.

5. The Fallout: Demographic Imbalances and Social Consequences

The cumulative effect of decades of female foeticide is a demographic disaster with far-reaching social consequences.

The "Missing Women" Phenomenon : Nobel Laureate Amartya Sen first coined this term in 1990, estimating over 100 million women "missing" across Asia due to gender discrimination. In India, millions of girls have been statistically eliminated from the population before birth, creating a profound demographic deficit.

Marriage Squeeze and Trafficking : A direct consequence of a surplus of young men is the "marriage squeeze." In regions with highly skewed sex ratios, a significant proportion of men will be unable to find brides. This has already led to the phenomenon of "bride buying," where women are trafficked from poorer regions like Assam, West Bengal, and Odisha to states like Haryana and Punjab. These women often live in conditions of servitude and exploitation.

Rise in Crime and Social Instability : Sociological studies have linked skewed sex ratios to an increase in anti-social behavior, including violence, crime, and substance abuse among the surplus male population. A society with a large number of young, unmarried, and frustrated men is inherently less stable.

A Perverse Cycle of Victimization : Ironically, the very women the practice seeks to eliminate face increased risks. The shortage of women can lead to their commodification, but also to increased control over their sexuality and mobility, potentially exacerbating practices like honor killings and domestic violence.

6. Beyond the Law: The Imperative for a Holistic Solution :

The analysis makes it clear that a law-centric approach has reached its limits. A sustainable solution requires a multi-pronged strategy that attacks the problem at its roots—the social devaluation of the girl child.

Strengthening the Legal Framework (Addressing Supply) : The PCPNDT Act must be implemented with renewed vigor. This requires political will, adequate funding for enforcement bodies, the creation of fast-track courts for speedy trials, and leveraging technology for better monitoring of clinics. Punishing the clients (the families) along with the doctors could act as a stronger deterrent.

Dismantling the Demand-Side Drivers (Socio-Economic Reforms) :

Empowerment through Education and Economics : Schemes that provide long-term financial incentives for girls, such as the Sukanya Samriddhi Yojana (a savings scheme), are steps in the right direction but need to be scaled up. Scholarships for higher education and skill development are crucial to enhance the perceived economic value of a daughter.

Effective Dowry Prohibition : The dowry law must be enforced with the same seriousness as the PCPNDT Act. Social campaigns that promote "dowry-free" marriages and celebrate families that give daughters equal inheritance rights (as mandated by the Hindu Succession Act) are essential.

Changing the Narrative : Mass media campaigns must move beyond slogans to actively challenge patriarchal norms. Celebrating successful women, promoting shared parental property rights, and portraying the father-daughter bond as a source of strength and pride can help reshape social attitudes.

Re-evaluating Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP) : The flagship BBBP scheme has succeeded in raising awareness, but critics argue it has been heavy on publicity and light on substantive, ground-level implementation. The scheme's funds have been disproportionately spent on advertising rather than on building infrastructure like toilets for girls in schools or funding vocational training. A restructured BBBP, with a focus on outcomes and local community ownership, is needed.

Community Engagement : Empowering local self-government institutions (Panchayats) to take ownership of the CSR in their villages can be highly effective. Incentivizing villages that show improvement in their sex ratios and promoting women's leadership in these bodies can create a bottom-up pressure for change.

7. Conclusion :

Female foeticide in India is a stark reminder that technological and legal progress can be nullified by resilient social prejudices. The PCPNDT Act, though well-intentioned, has functioned as a blunt instrument, unable to penetrate the hard shell of patriarchy, son preference, and economic calculus that protects the practice. The law has failed because it was designed to fight a symptom—the act of sex selection—while the disease, the devaluation of females, continues to flourish.

The path forward requires a fundamental re-imagination of the solution. It demands a synergistic model where a strictly enforced legal framework creates a credible deterrent, while simultaneously, a powerful social movement works to dismantle the very foundations of son preference. This involves empowering the girl child through education, economic opportunities, and legal rights, and engaging communities to redefine honor and status. The goal must be to create a society where a daughter's birth is met with the same joy, hope, and investment as a son's, not because the law commands it, but because society genuinely values her. The future of India's social fabric depends on this critical transition from merely saving the daughter to truly celebrating her.

References :

1. Census of India. (2001, 2011). Primary Census Abstract. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.
2. International Institute for Population Sciences (IIPS) and ICF. (2021). National Family Health Survey (NFHS-5), 2019-21. IIPS.
3. Sen, A. (1990). More than 100 million women are missing. The New York Review of Books, 37(20).
4. CEHAT & Others v. Union of India (2001) 5 SCC 577.
5. The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (as amended in 2003).
6. The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (as amended in 2021).
7. Guilmoto, C. Z. (2009). The sex ratio transition in Asia. Population and Development Review, 35(3), 519-549.
8. Nanda, A. (2014). The PCPNDT Act: A Review of the Implementation and Effectiveness. Centre for Women's Development Studies.
9. Purewal, N. K. (2010). Son Preference: Sex Selection, Gender and Culture in South Asia. Berg Publishers.
10. Unnithan, M. (2010). Infertility and assisted reproductive technologies in India: The legal, social and feminist responses. In M. Unnithan & S. K. Das (Eds.), Global Health and the New World Order. Routledge.

Email- kamalguptaadvocate041@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 91-101

डॉ. सुशील कुमार फुल्ल के उपन्यासों में नारी विमर्श के आयाम

परमजीत सिंह, शोधार्थी
डॉ. अजयपाल सिंह, निर्देशक एवं अध्यक्ष
हिंदी विभाग, देश भगत विश्वविद्यालय मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब।

शोषण :–

दुनिया में मौजूद लगभग सभी विचारधाराओं को मानने वाले लोगों ने नारी की स्थितियों की अलग–अलग ढंग से व्याख्या की है नारी मानवता समाज का वह अभिन्न हिस्सा है जिससे सभ्य समाज की संरचना पूर्ण होती है। नारी सिर्फ मादा जीव प्राणी नहीं है, बल्कि नारी मादा से भिन्न अर्थों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्ताओं को अपने आप में समेटे हुए है। जब हम नारी या महिला कहते हैं तो इससे केवल गर्भ धारण करने वाली श्मादाश जीव प्राणी का संबोधन नहीं होता बल्कि पुरुषों के कई माइनों में अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अस्तित्व रखने वाली प्राणी का बोध होता है। यह अलग बात है कि पुरुष प्रधान अर्थव्यवस्था वाले समाज में स्त्री पुरुषों के साथ अन्य प्रक्रियाओं में हिस्सा लेती है लेकिन उसके सभी अधिकार पुरुषों के अधीन होते हैं। नारी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी पुरुषों के अस्तित्व में समाहित हो जाता है हालांकि वर्तमान समय में उत्पादन के बदलते साधनों ने समाज में नारी की भूमिका को बदल कर रख दिया है। वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति ने विश्व भर में श्रम के तरीकों को शारीरिक कम बौद्धिक ज्यादा बना दिया है। फलतरू उत्पादन की क्षमता में नारी की प्रत्यक्ष भूमिका बढ़ी है और इस आधार पर अन्य संबंधों में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। आज की नारी समाज में केवल जननी या कुछ खास कार्यों के लिए आरक्षित नहीं रह गई है। स्वाभाविक तौर पर इस बदलाव और समाज को नारी की बदलती भूमिका के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव उत्पन्न हुए हैं।

भारतीय समाज के परिपेक्ष्य में यदि बात की जाए तो उत्पादन के बहलते साधनों के साथ ऐतिहासिक रूप से तकनीकी क्रांति तक के सफर में नारी की भूमिका को लेकर कई उतार–चढ़ाव हुए हैं। 'एंगल्स' ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'परिवार नीति संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति' मैं बताया है कि औरत का इतिहास तकनीक के इतिहास से जुड़ा होता है। आदिम समाज में पहला क्षम विभाजन स्त्री और पुरुष के बीच हुआ था : पुरुष मुख्यता अधिक क्षम की आवश्यकता वाला कार्य करते थे और महिलाएं अपनी विशिष्ट शारीरिक बनावट के चलते पुरुषों की तुलना में कम शारीरिक क्षम वाले कार्य करती थी। शारीरिक और आर्थिक चक्र में यह दोनों ही प्रकार के कार्य महत्वपूर्ण थे। और इनके परस्पर सहयोग से ही समाज में सभी कार्य फलीभूत होते थे।

इस अवस्था में पुरुष द्वारा नारी के शोषण जैसी कोई बात मौजूद नहीं थी इस आदिम समाज सभ्यता की भ्रुण अवस्था में स्त्री और पुरुष के बीच अंतर केवल जैविक था। तकनीक विकास ने उत्पादन के बदलते साधनों के साथ स्त्री पुरुष के प्राकृतिक अंतर को और अधिक गहरा करते हुए अन्य भिन्नताओं को जन्म दिया और श्रम विभाजन को जटिल बना दिया। योग्यता अनुसार या जरूरत के लिए जिन कार्यों को नारी और पुरुष आपसी सहयोग से किया करते थे वे अनिवार्य बन गए। एक तरफ उत्पादन के साधनों पर से महिलाओं का अधिकार जाता रहा और दूसरी तरफ पुरुषों की एकाधिकार सत्ता स्थापित होती चली गई।

यदि जो गुण महिलाओं को समाज में विशिष्ट स्थान देता था वही उसकी गुलामी का कारण बन गया। आदिम साम्यवाही व्यवस्था के बाद प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में नारी को नींद बनाकर उसी की गुलामी की इमारत खड़ी की गई। दास व्यवस्था और सामंतवाद को औरतों के इतिहास का काला युग कहा जा सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में नारियों की स्थिति में व्यापक बदलाव आया। वैज्ञानिक विकास और तकनीकी नारी शिक्षा से भी वंचित रखी गई। आज के नव उदारवादी समय में समाज में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव व उपयोग की वस्तु मानी जाने वाली नारियों में रास्सा–कस्सी का दौर है। आज भारत में मनुस्मृति को करने और समाज में लागू करने की इच्छा रखने वाले लोग सत्ता पर काबिज है। जो समाज में नारी के अस्तित्व को धीरे–धीरे अंधकार की ओर ले जा सकते हैं। आज कई मायनों में नारी समाज में अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने में कामयाब हो चुकी है लेकिन लगातार बढ़ती महिला असुरक्षा के मायने से देखा जाए तो ये कामयाबी अधूरी सी मालूम होती है आज नव उदारवादी समाज में महिला अस्तित्व के संघर्ष के साथ महिला शोषण की दास्तां लिखी जा रही है।

दैहिक शोषण :

महिलाओं के दैहिक शोषण पर कई शोध पत्र लिखे गए हैं इन शोध पत्रों में महिलाओं के शोषण के कारण इसके निवारण के उपाय और महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा की गई है। मैंने महिला विकास पर अंतर पारिवारिक यौन शोषण के प्रभाव के 23 वर्षीय अनुदैर्ध्य अध्ययन के शोध डिजाइन और निष्कर्षों को पढ़ा और समझा। वैचारिक ढांचे में मनोवैज्ञानिक समय की अवधारणाओं को इस सिद्धांत के साथ एकीकृत किया की मनोवैज्ञानिक कारण किस तरह से विकास को प्रभावित कर सकते हैं। प्रतिभामियों में 6 से 16 वर्ष की आयु की महिलाएं शामिल थी। जिनके साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई थी और एक जनसंख्या रूप से सामान तुल्यात्मक समूह था। एक क्रॉस सीक्वेंशियल डिजाइन का उपयोग किया गया था। और छः मूल्यांकन हुए थे। जिसमें पहले समूह में मूल्यांकन में प्रतिभागियों की औरत आयु 11 वर्ष और छठे मूल्यांकन शुरू में 25 वर्ष थी। प्रतिभागियों की माता ने शुरुआती मूल्यांकन में भाग लिया और संतानों ने छठे मूल्यांकन में भाग लिया।

कई विश्लेषणों के परिणाम दोनों ही परिसीमित विकासात्मक चरणों के भीतर और विकास के दौरान संकेत देते हैं कि यौन रूप से दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाओं (औसतन) ने कई जैव मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में हानिकारक परिणाम दिखाएं जिसमें शामिल है यौवन के समय से पहले शुरू होना, संज्ञानात्मक कमी, अवसाद विहारनकाती लक्षण, अनुयुक्त यौन विकास हारपोथेलेमिक– पिट्यूटरी– एड्रिनल क्षीणन, विषय तनाव प्रक्रियाएं, मोटापे की उच्च दर, अधिक गंभीर बीमारियों और स्वास्थ्य सेवा का उपयोग हाई स्कूल से बाहर होना, लगातार पोस्ट्रामेटिक तनाव विकार, आत्मक्षति, मानसिक विकारों के निदान और सोसाइटी मैन्युअल, शारीरिक और यौन उत्पोड़न, समय से

पहले प्रसव किशोरावस्था में मां बनना नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग यह तो मात्र सांकेत थे।

मानसिक शोषण :

साहित्य लिखने वाली महिला व्यंग्यकार और कवित्री मीना अरोड़ा ने अपने उपन्यास 'एक ऐसी भी निर्भया' में नारी जीवन के दर्दनाक चित्र का अक्षरमह वर्णन किया है। लेखिका अपने सहज रूप में सामाजिक विसंगतियों के प्रति आक्रोश जाहिर करने वाली और पीड़ित शोषित नारी के प्रति संवेदनशील एवं मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा रखने वाली है। इसलिए अपनी आंखों के सामने घटी घटना से क्षुब्ध होकर नारी जीवन की सुरक्षा की राहों की तलाश करते हुए छोटी उम्र की लड़कियों को अपनी काम पिपासा की शिकार बनाने वाले कामी पुरुष वर्ग को चेतावनी देते हुए 'एक ऐसी भी निर्भय' तीसरा उपन्यास का लेखन किया। उनके द्वारा नारी शोषण पर आधारित उपन्यास लिखने का बड़ा कारण है समाज से इस उत्पीड़न को समाप्त करना। इसे लिखने की प्रेरणा उन्हें निर्भया से मिली। जिसको उसके पिता ने शराब के लिए भेज दिया था। कहानी सौ फीसदी सच्ची है।

उनके इस कथन में देश में लड़कियों के साथ होने वाले अत्याचार के लिए कौन जिम्मेदार है इस बात पर प्रकाश डाला है। तात्कालिक खुशियों के लिए लड़कियों की जिंदगियों से खेलने वाले अभिभावक और लोग आज भी नहीं पहले भी थे। सामाजिक नियमों व मर्मदाओं की आड़ में बाल विवाह, विधवा का शोषण आदि घर की चार दिवारी के अंदर घटते हुए साहित्य में चित्रित किए गए है। वहीं अब आज लड़की घर से बाहर आने लगी, तो अब समाज में सामूहिक रूप से उसका शोषण हो रहा है। एसिड अटैक और बलात्कार से पीड़ित लड़कियां किस तरह की मानसिक पीड़ा से गुजरती है और फूटा जीवन किस तरह की यातना रहती है। नारी के दुश्मन चाहे कोई भी हो लेकिन उनके अत्याचारों की शिकार बनाकर वह आजीवन रोते हुए जीवन बिताने के लिए विवश हो रही है। नयी सदी के इस दौर में देश एक तरफ तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है तो इसी और भ्रष्टाचार, अत्याचार, अमानवीय व्यवहार जैसी विसंगतियों से व्यक्ति और समाज झुलस रहा है।

एस डी मठपाल जी की कविता 'गगन सा तुम्हारा हृदय है' औरत की मानसिक पीड़ा को व्यक्त करती एक एस डी मठपाल की में पंक्तियां पढ़कर अवश्य ही हम स्त्री की दशा को समझ सकते हैं। इतिहास से ही स्त्री का हमेशा भोग्या ही माना गया है यह बात बात निम्न पंक्तियों से भी स्पष्ट होती है :

गगन सा तुम्हारा हृदय है
सब रोगा की तुम में लय है
तुमको सिर्फ भोग्या माना
देखो अब कितना प्रलय है।

पुरुषों द्वारा औरत के जिस्म की किस तरह से नीलामी की गई है या चौराहों पर उसकी इज्जत का तमाशा बनाया है यह बात निम्न पंक्तियों से पता चलती है :

जिस्म का बाजार सजाया
हवस का शिकार बनाया
हृदय विदारक चीत्कारें हैं
किसने ये अधिकार जताया।

स्त्री की बरबर स्थिति को प्रकट करने में पंक्तियां भी आवश्यक पढ़िए ताकि वास्तविक स्थिति का पता

चल सके :

कुछ औरतों ने
अपनी इच्छा से
कुएं में कूद कर जान दी थी
ऐसा पुलिस के रिकॉर्डों में दर्ज हैं
और कुछ औरतें
चिंता में जल कर मारी थी
ऐसा धर्म की किताबों में लिखा था।

मैं आज अखबार पढ़ रहा था तभी मेरी नजर आज के पढ़े लिखे युग में फैली एक जटिल समस्या पर पड़ी जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के छोटे–छोटे टुकड़े कर कर उसे तीन दिनों तक कुकर में पकाया। और उसकी बच्ची हड्डियों को भी पीसकर बाद में झील में फेंक दिया। आज के युग में जहां स्त्री स्वतंत्रता हो चुकी है वह अपने निर्णय लेना जानती है।

वह अपना अच्छा बुरा सब जानती है वही समाज में हो रहे ऐसे कृत्य औरत को कहीं न कहीं कमजोर साबित करते हैं। नारी की आंतरिक वेदना को प्रकट करती निर्मला पुतुल की यह पंक्तियां :

बाबा!
मुझे उतनी दूर मत ब्याहना
जहां मुझसे मिलने जाने खातिर
घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें मत बयान उसे देश में
जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हो।

नारी की पीड़ा इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाती है। कवि ने हर भाव में नारी की मनोदशा का वर्णन किया यह निबंध पंक्तियों से स्पष्ट होता है :

कितने बूढ़े रोए तो
बने उपन्यास :
कितने बच्चे दिलखे
तो कहानीयां,
कितनी औरतें रोई
तो उल्टी कविता
वह सिसकती रही
मैं कुछ कर नहीं सका।

मैं आज अखबार पढ़ रहा था तभी मेरी नजर आज के पढ़े लिखे युग में फैली एक जटिल समस्या पर पड़ी जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के छोटे–छोटे टुकड़े कर कर उसे तीन दिनों तक कुकर में पकाया। और उसकी बच्ची हड्डियों को भी पीसकर बाद में झील में फेंक दिया। आज के युग में जहां स्त्री स्वतंत्रता हो चुकी है वह अपने निर्णय लेना जानती है वह अपना अच्छा बुरा सब जानती है वही समाज में हो रहे ऐसे कृत्य

औरत को कहीं न कहीं कमजोर साबित करते हैं। नारी की आंतरिक वेदना को प्रकट करती निर्मला पुतुल की यह पंक्तियां :

बाबा!
मुझे उतनी दूर मत ब्याहना
जहां मुझसे मिलने जाने खातिर
घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें मत बयान उसे देश में
जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हो।

नारी की पीड़ा इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाती है। कवि ने हर भाव में नारी की मनोदशा का वर्णन किया यह निबंध पंक्तियों से स्पष्ट होता है :

कितने बूढ़े रोए तो
बने उपन्यास :
कितने बच्चे दिलखे
तो कहानीयां,
कितनी औरतें रोई
तो उल्टी कविता
वह सिसकती रही
मैं कुछ कर नहीं सका।

आर्थिक शोषण :

आर्थिक शोषण भी शारीरिक उत्पीड़न एवं भावात्मक उत्पीड़न का गहनता से संबंध है। आर्थिक उत्पीड़न में सबसे ज्यादा वर्गीकरण इस प्रकार से है। महिलाओं पर रूपए पैसे के मामले में भरोसा नहीं करना, उन्हें बाहर कार्य करने की अनुमति नहीं देना और उन्हें घर खर्च के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध न करवाना।

घरेलू हिंसा के बारे में आम समझ यह है कि यह स्त्रियों के विरुद्ध शारीरिक एवं यौन प्रकृति की हिंसा है जो प्राय उनके अंतर्गत साथी द्वारा की जाती है। क्योंकि दहेज प्रथा भी मानव के आर्थिक स्वरूप से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए यह भी घरेलू हिसा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। भारतीय समाज में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप रहा है हालांकि वक्त के साथ आज इस प्रथा में काफी हद तक सुधार आया है। लोग काफी जागरूक और समझदार भी हो गए हैं परंतु अभी भी भारत के बड़े तबके में इसका प्रचलन है और आज भी दहेज के लिए ससुराल पक्ष द्वारा लड़की को ताने सुने जाते हैं उसे मानसिक और शारीरिक रूप से दंड दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश की एक पढ़ी–लिखे परिवार की औरत से मेरी बात हुई उसने बताया कि वह अपने बेटे के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है परंतु जो अच्छे रिश्ते मिल भी रहे हैं दहेज में धान की ज्यादा मांग कर रहे हैं। इसलिए वह ऐसे परिवार में रिश्ता नहीं करना चाहती। वर्तमान युग में भी भारत में यह चलन है मैं इस बात से आश्चर्यचकित हुआ हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या नहीं है या है भी तो बिल्कुल कम है। आर्थिक उत्पीड़न पर सामान का अधिक ध्यान नहीं पडना आश्चर्य जनक है जहां मुख्य धारा समाज में महिलाओं बच्चों

के विरुद्ध हिंसा की सबसे आम धारणा शारीरिक या यौन संदर्भ में प्रचलित है। जबकि भारतीय कानून में घरेलू हिंसा के विरुद्ध विशेष कारण 'घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005' (PWD act) के अंतर्गत आर्थिक उत्पीड़न को चिन्हित किया गया है। आर्थिक संदर्भ में हिंसा का उत्पीड़न सार्वजनिक चेतना का अंग उस तरह नहीं बन सका है जैसे अंतरंग साथी द्वारा यौन एवं शारीरिक प्रकृति की हिंसा को देखा जाता है।

PWD अधिनियम के तहद आर्थिक उत्पीड़न को ऐसे सभी या किसी भी आर्थिक या द्वितीय संसाधनों से वंचित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। जिसके लिए पीड़ित महिला किसी भी कानून के तहत हकदार है।

कानून के अनुसार पीड़ित महिला जीन संसाधनों या सुविधाओं का उपयोग करने की हकदार है। उन तक उनकी निरंतर पहुंच पर रोक या प्रबंध को भी आर्थिक उत्पीड़न माना गया है।

इसके अलावा गृहस्थी की चल अचल संपत्ति जिसमें पीड़ित महिला का हित शामिल है आदि को भी अधिनियम में शामिल किया गया है। विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में आर्थिक उत्पीड़न दहेज और स्त्री धन हमें जैसे संबंधित विषयों को भी अपने दायरे में लेता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि पीड़ित महिला के पक्ष में एक संरक्षक आदेश पारित किया जा सकता है। इसमें पीड़ित महिला का स्त्री धन दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से एकल रूप से चरित कोई अन्य संपत्ति भी शामिल है। आर्थिक हिंसा महिला को वास्तविक रूप से स्वतंत्र होने से रुकती है। अपने जीवन के संबंध में निर्णय लेने की उनकी क्षमता को बाधित करती है और प्रायः अपमानजनक स्थितियों से बाहर निकल रुकने या उत्पीड़न कर्ता से अलग हो रुकने की उनकी अक्षमत्म मैं एक प्रमुख योगदान कर्ता है।

महिलाओं की वेदना को प्रकट करती बहुत सारी कविताएं साहित्य जगत में देखी पढ़ी जा सकती है। यह कविताएं महिलाओं को आर्थिक स्थिति को भली–भांति प्रकट करती हैं। इन कविताओं में समय–समय पर साहित्यकारों व कविताओं ने अपना मन प्रस्तुत किया है। एक मजदूर औरत की दशा को व्यक्त करती ऐसी ही एक रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस लिखी गई रचना 'तोड़ती पत्थर तोड़ती पत्थर' कविता महाव्यादि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। यह कविता मजदूर वर्ग की दयनीय स्थिति को दर्शाती है। इस कविता में कवि ने सड़क किनारे पत्थर तोड़ने वाली एक मजदूर महिला की दुर्दशा का वर्णन किया है। 'वह तोड़ती पत्थर' कविता में सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा मजदूरी की आर्थिक व्यवस्था व दुख का वर्णन किया है। स्त्री की दाहिनी दिशा का अवलोकन हम कविता की विभिन्न पंक्तियां पढ़कर लगा सकते हैं।

कोई न छाया दार
पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार
श्याम तन, भर बंधा यौवन
मत नयन, प्रिय-कर्म रत मन,
गुरु हथोड़ा हाथ,
करती बार-बार प्रहार
सामने तरु मालिका अट्टालिका, प्राकार।

सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उपरोक्त पंक्तियों से पता चलता है कि मजदूर औरत अपने काम में पूरी कर्मठता से रत रहती है। हालांकि वह सुंदर भी है लेकिन जैसा कि मिच्चा औरतों के बारे में भ्रम फैला हुआ है कि औरतें शारीरिक रूप से निर्बल होती है यह बिल्कुल ही गलत है।

कविता में स्पष्ट वर्णन है की नई अपने काम को बहुत मेहनत से पूरा करती है। वह भी गर्मियों की कड़कती धूप की पर वह किसी दिन तपती दोपहर में भी पूरी लगन से अपना काम पर ध्यान देती है। कविता के निबंध पंक्तियों से यह बात स्पष्ट होती है :–

चढ़ रही थी धूप
गर्मियों के दिन
दिवा का तम तमाता रूप
उठी झुलस्मही हुई लू
रूई क्यूं जलती हुई भू
गर्द चिनगी छा गई।

उपरोक्त कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने निवर्तदान युग की समस्या को उजागर करने का प्रयास किया है। स्त्री के हाथ में एक भारी हथोड़ा है जिससे वह बार–बार पत्थर पर प्रहार कर रही है। जिस पेड़ के नीचे बैठकर वह पत्थर तोड़ रही है वह पेड़ छाया दार भी है फिर भी वह पूरी मेहनत से कड़कती धूप में बैठकर पत्थर तोड़ रही है। कवि ने कविता के माध्यम से पूरी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे–जैसे धूप चढ़ती जा रही है उसी रूप में गर्मी बढ़ती जा रही है। समूचे शरीर को झुलसा देने वाली लू चल रही थी ऐसे में जब उसने मुझे उसकी ओर देखते हुए देखा तो एक बार तो उसे बनते हुए भरन को उसने देखा फिर लक्षण करके कि मैं अकेला दिया उसने अपने तार तार होकर फटे कपड़ों की ओर देखा। ऐसे लगा जैसे अपनी उसे स्थिति द्वारा कि उसने मुझको अपनी दीन अवस्था की पूरी करुणा माया उसी तरह सुना दी जिस प्रकार कोई सीतार पर सहज भाव उंगलियां चलाकर झंकार उत्पन्न कर देता है। एक क्षण तक कवि की और देखने के पश्चात वह श्रमिक युवती कांप उठी उसने मस्तिष्क से पसीने के करण छलक तत्पश्चात वह फिर कर्म पत्थर तोड़ने लगती है।

यौन इच्छा की पराकाष्ठा :–

चाणक्य नीति में वर्णित है कि औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा समय–समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता,सोम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन या यौन इच्छा की प्रकाष्ठा रखने वाली उपन्यास महिलाओं का वर्णन किया है। डॉक्टर सुशील कुमार फुल ने भी अपने उपन्यासों में कुछ ऐसी ही दृश्य का जीवान चित्रण किया है। इसके बारे में कई ऐसी बातें बताई है जो नारी की यौन इच्छा की प्रकाष्ठा का जीता जागता उदाहरण है। चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई है जिन पर विचार और उन बातों पर अनुसरण वाले लोगों के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसी ही कुछ बातें जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता

है जब कोई स्त्री किसी को अपनी सुंदरता के जाल में फसाना चाहे तब उससे बचना भी एक कला है। ऐसी महिलाएं काफी खुले स्वभाव की होती है। यह अपने दिल और जुबान का तालमेल नहीं दिखा पाती यह हमेशा किसी पुरुष की सुंदरता और सुडौल शरीर को देखकर मोहित हो जाती है। इनमें बहुत ज्यादा उतावलापन होता है।

यह हमेशा ही किसी पुरुष को अपनी यौन इच्छा की पूर्ति के लिए फसाने के जुगाड़ में लगी रहती है। यह कायुक्त उनमें कई बार अपने ही पति की वजह से होती है। क्योंकि वह या नशे की हालत में घर लौटते हैं या नपुंसकता को देश झेल रहा होता है। ऐसे में वह अपनी स्त्री की योनि इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाता। परिणामस्वरुप ऐसी महिलाएं यह सुख बाहर की किसी पुरुष से हासिल करने का प्रयास करती है और धीरे–धीरे यह उसकी आदत बन जाती है। जो वेश्यावृत्ति को जन्म देती है। वास्तव में पुरुष स्वयं स्त्री को ऐसा बनने के लिए मजबूर होने का मौका देता है। आज भी जिस समाज में पुरुषों का इधर–उधर मुंह मारना उनकी पुरुषपीड़ काबिलियत माना जाता है। और औरत के इंसान होने के हक की बात करना भी उसके चरित्रहीन होने का प्रमाण घोषित हो जाता है।

ऐसे ही कुछ उपन्यास डॉक्टर सुशील कुमार फुल जी द्वारा लिखे गए जिनका समाज में जमकर विरोध भी हुआ। कई साहित्यकारों ने उनके स्त्री के खुले यौन निमंत्रण को आलोचना की दृष्टि से देखा और जमकर भड़ास निकाली। जबकि मैं फूल जी के उपन्यासों में किए गए नारी के वृतांत से शत प्रतिशत सहमत हूं। हालांकि संपूर्ण नारी जाति को इसके लिए भागीदार नहीं स्वीकारा जा सकता फिर भी नारी जाति का कुछ हिस्सा ऐसा जरूर है जो नौकरी पेशा और स्वतंत्रता व खुले विचारों की आड़ में कहीं–कहीं अपने पुराने प्रणय संबंधों को अपनी यौन इच्छा की पूर्ति के लिए कोसती और उकसाती नजर आती है।

कहीं ना कहीं नारी की तडप और पीड़ा में पुरुष बराबर का भागीदार है। मेरा मानना ऐसा है कि प्रेम सेक्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर औरत और हर पुरुष के विघमान होती है। कुछ लोग इसका इजहार कर देते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। हालांकि पतिव्रता नारी के लिए किसी पराए मर्द से यौन इच्छा की पूर्ति करवाना एक अपराध है। परंतु यही बात पुरुष समाज पर भी लागू होती है। जैसा कि मैं पहले ही कह लिख चुका हूं कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तथा इस प्राकृतिक प्रक्रिया में पति को पूर्णतया सहयोग करना चाहिए और यथा संभव प्रथम करना चाहिए कि स्त्री की योनि इच्छा पूर्ण हो। यदि पुरुष इस कर्तव्य निवेदन में जरा भी चूक करता है तो नारी का कामुकता वश इतिहास इस बात का साक्षी है नारी में स्वयं को हमेशा सीमाओं में संक्षिप्त रखा है। लेकिन जिस भी स्त्री के बारे में आप नाजायज संबंधों की बात सुनेंगे उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर मिलेगा।

बिखरते संबंध :–

सामाजिक व्यवस्था का बहुत कुछ लोगों की आर्थिक दशा पर निर्भर करती है। कुछ परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं और उन परिवारों की महिलाएं दिखावा करने के लिए व्यर्थ के शौक पालती है जैसे क्लब में जाना या पार्टियों में जाना और वहां महंगे नशों का सेवन करना फिर अनजान व्यक्तियों के साथ गलत तरीके से पेश आना या फिर नशे की हालत में अपने ऊपर काबू न रख पाना फिर उसका गलत ही परिणाम होता है और इससे परिवार बिखरव की तरफ बढ़ जाते है।

समाज में बहुत सारे ऐसे अमीर घराने हैं जिनके पास दौलत की कमी नहीं है परंतु वह अपने घर को समय भी नहीं दे पाते इस कारण भी कुछ महिलाएं अकेले घुटन महसूस करती है और अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ ऐसा साथी ढूंढती है जो उनकी शारीरिक इच्छाएं पूरी कर सके। व्यक्ति की परिवार और पत्नी के प्रति उदासीनता पत्नी को अन्य जगह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मजबूरन कदम बढ़ाने पड़ते हैं। भारतीय समाज में ऐसी औरतों को सही नहीं समझा जाता। और धीरे–धीरे कभी ना कभी वह बातें सामने आने लगती है। जो पर्दे के पीछे होती है जो पारिवारिक संबंधों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देती है। विदेश में यह बात बिल्कुल आम है डॉक्टर सुशील कुमार फुल ने ऐसे ही पारिवारिक बिखराव की बात अपने उपन्यासों में की है जिसमें कामकाजी महिलाएं अपने परिवेश में भटकती हुई नजर आती है।

महिलाओं का कामकाजी होना भी एक क्रांति की बुनियाद है परंतु कुछ महिलाएं नौकरी के चक्कर में पारिवारिक जिम्मेदारियां से भागना शुरू कर देती है। जिससे धीरे–धीरे वह अपने परिवार से विलग हो जाती है। कुछ कामकाजी महिलाएं आकर्षक और सेक्स की भूख से गुमराह हो जाती है। भौतिक चक्र चांद में वह अपने भविष्य को नहीं देख पाती और चवुर पुरुष के द्वारा ब्लैकमेल की शिकार हो जाती है। अनच आईटी चाहते और कमजोरी का कुछ लोग पूरा पूरा लाभ उठाते हैं और वह अपने आप को रोक नहीं पाती यह स्थिति आंए ही नहीं चेतनाशील होना होगा भोग उपभोग की वस्तु बनने से इंकार की चेतन ही प्रस्तुत देह से ऊपर उठने की चेतना है। लेकिन स्त्री वहां क्या करें जब वह कुछ ना करें कुछ ना चाहे मर्द जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करें राजनीति में रहने वाली महिलाओं को भी इज्जत गवानी पड़ी है।

महिला सशक्ति करण :–

आज के इस दौर में महिला सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है खास तौर पिछड़े और प्रगतिशील देश में क्योंकि उन्हें इस बात का काफी बाद में पता चला कि बिना महिलाओं के तरक्की और सर्वशक्तिकरण के देश की तरक्की संभव नहीं है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं की उस क्षमता से है जिससे उनमें यह योग्यता आ जाती है ताकि वे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय ले सकती है। 8 मार्च के दिन पूरे विश्व अंतर्राष्ट्री में महिला दिवस मनाया जाता है। सही मायने में महिला दिवस मनाने का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब देश में महिलाओं की तरक्की और वह सशक्त बनेगी। यह वह तरीका है जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सके।

भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बहुत सारी बढ़ाएं आधे आ रही है यह निबंध प्रकार की है :–

रूढ़िवादी समाज :–

भारतीय समाज रूढ़िवादी समाज है वह आज भी लकीर का फकीर बनकर रहना चाहता है अर्थात लड़की पर्दे में और घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए बनी है। इस तरह की मिथ्या धारणाएं आज भी ग्रामीण परिवेश में कहीं ना कहीं विधमान है।

कार्य क्षेत्र में शारीरिक शोषण :–

कार्य क्षेत्र में होने वाला सॉल्यूशन भी महिला सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करता है। यह एक सच्ची बात है कि कार्य क्षेत्र पर महिलाओं का अवसरों द्वारा शोषण किया जाता है। इसी शोषण के डर से जागरूक और

जिम्मेदार लोग महिलाओं को कार्य करने की मनाही करते हैं। उन्हें डर रहता है कि उनकी बहू–बेटियों के साथ गलत ना हो इसलिए वह उन्हें घरों में रहने की ही सलाह देते हैं।

लैंगिक भेदभाव :–

आज भी परिवारों में लड़कियों के साथ लैंगिक भेदभाव किया जाता है क्योंकि उन्हें शुरू से ही पराया धन समझा जाता है पता है कि ज्यादा पढ़ा लिखा कर भी वह किसी और के आंगन का ही श्रृंगार बनेगी इसलिए लोग लड़कियों की बजाय लड़कों को ज्यादा महत्व देते हैं। लड़कों की पढ़ाई लिखाई के प्रति ज्यादा सजग रहते हैं। करने के उपरांत किस जाने वाले संस्कारों के लिए पुरुष को भी महत्व दिया जाता है क्योंकि ऐसा वे दो और शास्त्रों में वर्णित है समय के साथ लोग अब जागरूक होना शुरू हो गए हैं वह लड़कियों भी अब सभी संस्कार निभा रही है कुछ ऐसे मिथक हैं जो धीरे–धीरे खत्म हो रहे हैं।

कन्या भ्रुण हत्या :–

कन्या भ्रुण हत्या भी इसका एक मूल कारण है यदि किसी के घर में दो लड़कियां पैदा हो जाती है तो समाज जितना पढ़ा लिखा और जागरूक हो रहा है। उतना ही बेटी के जन्म के प्रति भ्रान्ति बड़ी है। पुरुष भी चाहता है कि बेटी पैदा ना हो परंतु स्त्री सामाजिक झूठी प्रतिष्ठा के लिए चाहती है कि बेटा ही पैदा होना चाहिए।

शिक्षा और जागरूकता की माध्यम से महिलाएं रूढ़िवादिता को चुनौती देने बाधाओं को कम करने और अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनती है। जब महिलाएं से सशक्त होती है तो वह परिवार कल्याण सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसे माहौल को बढ़ावा देना जारी रखना जरूरी है जहां महिलाएं आगे बढ़ाने और नेतृत्व करने के लिए सशक्त महसूस करें। महिला सशक्तिकरण में निर्देश करके समाज में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और सभी के लिए अधिक न्याय संगत और समावेशी दुनिया बना सकते हैं। किसी भी समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब उस समाज की महिलाओं को सशक्त किया जाए और उन्हें समान अधिकार मिले जब तक महिलाएं समाज में बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त करती तब तक वह समाज अपने पूर्ण रूप में विकसित नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति ने सदियों से नारी सशक्तिकरण के विषय से जागरूक रहीं है। महात्मा कबीर दास ने भी नारी की शक्ति को पहचान और कहा था :–

गाय रोये हंसी खेलिके, हरत सबौं के प्राण।
कहै कबीर या घात को समझे संत सुजान।।

जो दर्शाता है कि नारी के अस्तित्व में ऐसी शक्ति है जो समाज को हर रूप में प्रभावित करती है। महिला सशक्तिकरण पर विचारों के माध्यम से हम न केवल महिलाओं को जागरुक कर सकते हैं बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं।

इस संदर्भ में नारी पर लिखी 'रश्मि पटेल' की कविता की पंक्तियां याद आ रही है :–

अब हमें बढ़ना होगा
बहुत लोग हैं रोकने वाले
झांसी की रानी अब बनना होगा
महिलाओं को जग जाओ सशक्तिकरण अब हमें करना होगा।

इन पंक्तियों में एक नई कवित्री ने नारी को अपनी कलम से जगाने का प्रयास किया है।

नारी के प्रति कुछ और श्रेष्ठ पंक्तियां किसी कवि ने रची है जो समाज में नारी के महत्व को बताती है।

हे! नारी तुम रखती हो निज कितने ही रूप
सृष्टि में जो कुछ दिखता है सब है तेरा स्वरूप
तेरे बिना जग तिमिर युक्त है दिखे कहीं ना धूप
तेरे ममता मयी करो से निखराएं जग का रूप।

'ऊषा प्रियवंदा की स्त्रियां' प्रेम कुमार मणि जी के लेख 2021 में वर्णित कुछ तथ्य भी स्त्री सशक्तिकरण पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। कोई भी स्त्री पिता और पति का कुल नाम क्यों जोड़े? मां का नाम क्यों नहीं जोड़े? उषा ने जोड़ा दुनिया बदलने का अपना अपना तरीका होता है। एक तरीका यह भी है देखने में यह छोटी सी बात लगती है लेकिन नहीं इसके पीछे एक दृष्टिकोण है। यही दृष्टिकोण उषा के लेखक का वैचारिक आधार बनता है। सुभद्रा कुमारी चौधा द्वारा लिखी गई कविता 'झांसी की रानी' भी सांसद नारी जाति को प्रेरणा देती नजर आती है। कहीं न कहीं अंग्रेजी आदत वाले समय से ही नारी अपने अधिकारों के लिए जागरूक दिखने लगी थी। उसकी कविता की पंक्तियां निम्न है :–

दूर फिरंगी को करने की
सब्जी मन में ठानी है
खूब लड़ी मर्दानी की वह तो
झांसी वाली रानी है।

कविता इन पंक्तियों से औरत के हौसले और हिम्मत का ही पता नहीं चलता बल्कि यह भी पता चलता है कि चूल्हा चौका करने वाली स्त्री यदि तलवार हाथ में पकड़ ले तो किसी भी दुश्मन को पराप्त कर सकती है।

संदर्भ :–

1. शोध पत्र – कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम और निपटारा अधिनियम 2013 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
2. कवित्री अनामिका की कविता 'स्त्रियां'।
3. एक ऐसी भी निर्भया, उपन्यास, लेखिका मीना अरोड़ा, प्रकाशन वर्ष, सन 2018
4. कविता 'औरतें', लेखक रमाशंकर यादव विद्रोही।
5. नगाड़े की तरह बजते शब्द, पुस्तक, लेखक निर्मला पुतुल, प्रकाशन, वर्ष 2005
6. कवि ने कहा पुस्तक, लेखक, इब्बार रब्बी प्रकाशन, वर्ष 2012
7. लेख –आर्थिक दुर्व्यवहार, घरेलू दुर्व्यवहार का एक उपेक्षित पहलू, इंडियन एक्सप्रेस, 2023
8. सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी और माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्य का अध्ययन।
9. लेख – लेखक अजय जोशी, जनसत्ता अखबार, दिनांक 05–02–2025
10. शोध पत्र – नारी सशक्तिकरण एवं स्त्री मुक्ति का संघर्ष, लेखक, डॉ.प्रीति सिंह, प्रकाशन, वर्ष जुलाई 2016

11. कहीं कुछ और (1978), गोयल बुक डिपो, पालमपुर।
12. मिट्टी की गंध (1982), भावना प्रकाशन, पटपड़गंज, दिल्ली—91
13. नागफांस (1984), प्रवीन प्रकाशन, महरौली, नई दिल्ली—30
14. फूलों की छाया (1982), राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली।
15. हारे हुए लोग (1990), किताब घर प्रकाशन, अंसारी रोड, दिल्ली—6
16. खुलती हुई पाँख (1992), भावना प्रकाशन, दिल्ली—91
17. बंटवारा (2012), जनवाणी प्रकाशन, दिल्ली—32
18. उड़ान (2014) इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, दिल्ली—51
19. खिसकती हुई जमीन (2022), इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, कृष्णा नगर दिल्ली—51
20. हिमाचल के हिंदी उपन्यासों में नई परिवेश का विकास, निर्मल प्रकाशन दिल्ली—32, 2008

dr.ajaypal@deshbhagatuniversity.in
CONTACT : 9799188117

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 103–118

The Soundscape of Migration: Audio, Memory and Place-Making among New Urban Residents in Agra City

Dr. Arvind Kumar Gupta
Assistant Professor, Department of Sociology, Agra College, Agra.

Abstract :

This paper explores how sound—everyday urban noise, music, speech, and silence—shapes memory, identity, and place-making among recent migrants to Agra City. Drawing on qualitative fieldwork, soundwalks, and audio-elicitation interviews conducted with 40 new urban residents across three neighbourhoods, the study examines how migrants use sonic practices to negotiate belonging, recreate familiar auditory environments, and mark social boundaries. Findings reveal that (1) migrants actively reconstruct auditory memories through domestic and communal sound practices; (2) specific sonic markers (language, religious soundscapes, market rhythms) become anchors of identity; and (3) sound practices play a crucial role in informal place-making that complements material changes in the urban environment. The paper contributes to urban sociology and sensory studies by foregrounding sound as an active social medium in processes of migration and settlement (Feld, 1996; Schafer, 1994).

Keywords : migration, soundscape, place-making, memory, sensory sociology, urban studies.

1. Introduction :

Urban migration is not only a movement of bodies and resources but also a reconfiguration of sensory worlds. While visual and material aspects of migration—housing, employment, kin networks—have been widely studied, the sensory dimensions, especially sound, receive less attention (Pink, 2015). This paper focuses on the *soundscape* of migration: how sounds encountered, produced, and remembered by migrants shape their experiences of place and belonging in Agra City.

Agra offers a compelling setting : a historical city with layered soundscapes—from temple bells and mosque calls to tourist chatter and market rhythms—where new residents arrive seeking livelihoods and social footholds. Understanding how migrants navigate and (re)make sonic environments deepens our knowledge of urban integration and everyday cultural adaptation (Massey, 1994).

2. Literature Review

2.1 Sensory Sociology and Sound Studies :

The emergence of **sensory sociology** marks a significant paradigm shift in the social sciences, challenging the long-standing dominance of the visual in sociological inquiry (Howes, 2005; Vannini et al., 2010). For much of the twentieth century, sociology privileged vision as the principal mode of knowing, understanding, and representing the social world. This "ocularcentrism" (Jay, 1993) reinforced the idea that seeing is synonymous with understanding, leaving the other senses—particularly hearing—relatively underexplored. Sensory sociology, however, recognizes that human experience is inherently multisensory and that the social world is constructed through a continuous interplay of seeing, hearing, touching, tasting, and smelling. Within this growing field, **sound studies** has emerged as a distinct yet complementary approach that examines how auditory practices, environments, and technologies mediate social life (Bull & Back, 2016; Cox & Warner, 2004).

The Sensory Turn in Sociology :

The "sensory turn" (Howes, 2014) in sociology and anthropology has encouraged researchers to attend to the affective, embodied, and atmospheric dimensions of everyday life. Scholars such as Stoller (1989) and Pink (2015) have shown that social meaning cannot be fully understood without considering the sensory modalities through which individuals perceive and interpret their environments. The sensory approach thus moves beyond discourse and representation to encompass *lived experience*—the textures, rhythms, and sensations that constitute social reality. Within this framework, the auditory is not simply a backdrop but an active medium that structures social relations, temporal rhythms, and spatial practices.

Sound, unlike sight, operates in a relational and immersive way. It travels through, around, and between bodies, connecting people to each other and to their environments. It also penetrates walls, public and private spaces, and social boundaries, rendering the auditory inherently political (Kanngieser, 2012). Listening, therefore, becomes a social act—one that can include, exclude, dominate, or liberate. The sociology of sound invites scholars to investigate how listening and sounding practices are embedded within broader systems of power, culture, and identity (Back, 2007; Bull, 2000).

From Soundscape to Auditory Culture :

The foundational concept of the *soundscape* (Schafer, 1994) revolutionized the study of sound by conceptualizing it as the total sonic environment of a given space. Schafer argued that every place has its own acoustic character—its unique combination of natural, human, and mechanical sounds—that reflects and shapes social organization. For example, the bells, street cries, traffic noise, and market sounds that fill a city's air are not random—they are symbolic markers of social activity, cultural heritage, and economic vitality. In the case of Agra, the soundscape is shaped by overlapping rhythms of tourism, religious practice, and informal labor, forming a complex acoustic ecology that both migrants and long-term residents must navigate.

However, contemporary sound scholars have critiqued Schafer's deterministic tendencies and called for a more *cultural and relational* understanding of sound. Feld's (1996) notion of *acoustemology*—a blend of "acoustics" and "epistemology"—posits that sound is a way of knowing the world. Through listening, people not only gather information about their surroundings but also construct meaning and forge emotional attachments to place. Feld and Brenneis (2004) further emphasize that sound is both a sensory and social practice, produced and interpreted through culturally specific norms. Thus, sound is not merely a reflection of society—it is constitutive of it.

Sound, Identity, and the Social Body :

In urban contexts, sound is deeply tied to identity and belonging. The voices, accents, and musical preferences of individuals signal their social position, cultural background, and group affiliation (Pennycook & Otsuji, 2014). The auditory dimension becomes especially salient for migrants, who use familiar sounds—such as regional music, languages, and ritual chants—to sustain emotional continuity amid displacement (Eisenlohr, 2006). Listening thus becomes an act of memory and resistance, allowing individuals to reconstruct fragments of "home" within unfamiliar environments. The sensory sociology of migration underscores that hearing is not just physiological—it is *socially situated and historically conditioned.*

2.2 Migration, Memory and Place-Making :

Migration studies emphasize memory and translocal ties—how migrants retain attachments to origin places through practices, narratives, and material culture (Gupta & Ferguson, 1992). Place-making literature highlights informal practices by which residents produce meaningful spaces (Lefebvre, 1991). Few studies, however, combine these literatures to examine how sound and memory shape migrants' place-making.

2.3 Studies in Indian Urban Contexts :

Indian cities have complex acoustic ecologies : religious callings, street vendors, traffic, and festivity sounds (Manuel, 2015). For migrants—often from rural or smaller-town settings—these sonic ecologies are both unfamiliar and potentially familiar, depending on cultural matches. This paper builds on ethnographies of Indian urban life to examine how migrants reinterpret and reproduce soundscapes.

3. Theoretical Framework :

The theoretical foundation of this study rests on the intersection of **sound studies**, **migration theory**, and **urban sociology**, framed within the broader discipline of **sensory ethnography**. This framework enables an understanding of how migrants perceive, construct, and negotiate their sense of place through sound, and how auditory experiences shape processes of identity, belonging, and adaptation within Agra's urban landscape.

3.1 Sound and the Sociology of the Senses :

Sound has long been a neglected dimension in sociological inquiry, overshadowed by the visual bias that characterizes modern epistemologies (Howes, 2005). However, with the emergence of the *sociology of the senses* (Vannini et al., 2010), scholars have begun to appreciate the auditory dimension as central to understanding social life. Schafer's (1994) concept of the *soundscape* provides a foundational lens for this study—viewing sound as both a social construct and an environmental phenomenon that reflects the cultural, economic, and political conditions of everyday life.

In this framework, sound is not merely an acoustic event but a *social agent*—a medium through which social relations are performed and power is negotiated (Bull & Back, 2016). Feld's (1996) notion of *acoustemology*, or knowledge through sound, further deepens this understanding by suggesting that listening is an epistemological act that shapes how individuals inhabit and interpret space. In Agra's heterogeneous urban environment, migrants' auditory practices—listening to temple bells, market noises, traffic, and linguistic accents—constitute modes of knowing and feeling that are inseparable from their social experiences.

3.2 Migration, Memory, and Belonging :

Migration involves not only physical relocation but also the reconfiguration of *cultural memory* and *emotional geographies* (Appadurai, 1996; Basu & Coleman, 2008). The sounds migrants encounter in their new environments often trigger sensory memories of their places of origin, evoking feelings of nostalgia or dissonance. Such sonic recollections are instrumental in shaping *place attachment* and *identity continuity*.

Drawing on Lefebvre's (1991) *production of space* and Massey's (1994) *relational conception of place*, this study argues that migrants' auditory practices participate in the ongoing production of urban space. Places are not fixed or purely geographic; they are constantly being (re)made through human interactions, movements, and sensory engagements. Sound, therefore, becomes a critical dimension of this relational process—bridging personal histories and collective urban rhythms.

Moreover, the idea of *diasporic listening* (Eisenlohr, 2006) is relevant here: migrants use familiar music, linguistic sounds, and religious chants to re-create affective home spaces in alien surroundings. These auditory practices act as *portable homelands*, enabling individuals to sustain emotional and cultural continuity even amidst displacement.

3.3 Urban Soundscapes and Power Relations :

The urban soundscape of Agra is characterized by both *diversity and hierarchy*. Public spaces are layered with overlapping auditory territories—temple loudspeakers, traffic horns, street vendors, and multilingual conversations. These sounds symbolize not just diversity but also *acoustic power relations* (Simpson, 2017). Certain groups dominate public soundscapes, while others are marginalized, reflecting broader patterns of class, gender, and cultural inequality.

Following Lefebvre's (1991) spatial triad—*spatial practice, representations of space, and representational space*—the urban auditory environment can be analyzed as a field where social actors assert, negotiate, or resist sonic dominance. Women and lower-income migrants, for instance, may experience restricted auditory agency, being confined to quieter domestic or occupational spaces, while others occupy the louder, more public sonic arenas.

This dimension also intersects with Connell's (2009) *gender theory*, highlighting how soundscapes are gendered spaces where the politics of hearing and speaking are socially organized. Listening, in this sense, becomes an act of both participation and surveillance within unequal urban contexts.

3.4 Sensory Ethnography and Embodied Listening :

Methodologically, this framework aligns with Pink's (2015) *sensory ethnography*, which emphasizes the embodied, affective, and multisensory nature of human experience. Listening, as an ethnographic tool, offers a way to access migrants' tacit and emotional knowledge that conventional interviews might overlook. The act of "deep listening" (Back, 2007) allows the researcher to interpret how people make sense of their changing environments through affective resonance rather than verbal articulation alone.

By integrating Kanngieser's (2012) *sonic geography of voice* and Stoller's (1989) emphasis on sensory anthropology, this study situates sound as both method and subject. The researcher's own listening practices become part of the data, revealing how urban sonic environments mediate relationships between migrants, memory, and material space.

3.5 Integrative Conceptual Model :

Bringing together these strands, the theoretical framework posits that migrants' experiences of sound in Agra are simultaneously **epistemic, affective, and political**. Sound mediates three interrelated processes:

- **Memory and Continuity** – the evocation of familiar auditory cues linking migrants to their origins.
- **Place-Making** – the use of sound to construct, navigate, and inhabit urban spaces.
- **Power and Belonging** – the negotiation of sonic presence within hierarchically structured environments.

This tripartite model underscores that sound is not merely a reflection of migration but an active force shaping how migration is *felt*, *remembered*, and *performed*. Through this lens, the soundscape of Agra emerges as a living archive of mobility, social interaction, and identity transformation.

4. Research Questions :

- How do new urban residents in Agra recall and reconstruct auditory memories from their places of origin?
- What sonic practices do migrants employ to create familiarity and belonging in their new neighbourhoods?
- How do sonic markers contribute to social boundary-making and neighbourhood identity?

5. Methodology

5.1 Research Design :

This is a qualitative ethnographic study conducted over six months in 2024–2025 across three Agra neighbourhoods with substantial migrant populations: Sadar Bazaar-adjacent wards, Sikandra peri-urban localities, and a newly developed housing colony in Faizabad Road area (Creswell, 2013).

5.2 Sampling :

Purposive sampling identified 40 participants (22 men, 18 women) who had migrated to Agra within the last five years. Participants vary in origin (villages in Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan), occupation (construction, domestic work, petty trade, services), religion, and housing types (informal settlements, rented rooms, formal apartments).

5.3 Data Collection Methods :

- **In-depth interviews (n=40) :** Semi-structured interviews focused on migration histories, auditory memories, and everyday sound practices.
- **Soundwalks (n=12 group/individual):** Guided walks where participants led the researcher through neighbourhood soundscapes, pausing to discuss notable sounds (Blesser & Salter, 2007).
- **Audio-elicitation sessions (n=30):** Participants listened to short audio clips (e.g., village field sounds, market noise, local temple bells, popular music) and were asked to reflect on

feelings and memories evoked.

- **Participant observation:** Notes on domestic sound practices (music, radio, language use) and community events.
- **Audio recordings:** Field recordings of public and private soundscapes with informed consent.

5.4 Ethical Considerations :

Ethical clearance was obtained from the institutional review board. Participants gave informed consent for interviews and audio recording; pseudonyms are used. Sensitivities around religious sounds and privacy in private spaces were carefully navigated (American Sociological Association, 2018).

5.5 Data Analysis :

The analysis of data in this study followed a **qualitative interpretive approach** rooted in the principles of **sensory sociology** and **sound studies**, allowing for an in-depth exploration of how migrants in Agra construct meaning through sound. The data were analyzed in three overlapping phases: **thematic coding**, **interpretive synthesis**, and **contextual triangulation**. These stages facilitated both an empirical understanding of participants' lived sonic experiences and a theoretical interpretation of how sound mediates identity, belonging, and adaptation.

Phase 1 : Thematic Coding :

Data collected through ethnographic interviews, participant observation, and sound recordings were first organized into textual and audio datasets. The researcher transcribed the interviews verbatim and created field notes reflecting sensory impressions and environmental descriptions. Following Braun and Clarke's (2006) six-step method of *thematic analysis*, the data were coded inductively to identify patterns related to key themes such as **memory**, **mobility**, **adaptation**, **sound identity**, and **urban belonging**.

Initial codes such as "nostalgic sounds," "market rhythms," and "domestic soundscapes" were identified across narratives. These were later refined into broader thematic categories — namely :

- **Sonic Memory and Displacement** (evocations of homeland sounds),
- **Urban Noise and Adaptation** (responses to Agra's sound environment),
- **Auditory Belonging** (creation of familiarity through sound), and
- **Acoustic Power and Marginality** (differentiation across gender, class, and spatial access).

The process was iterative, with constant comparison between field data, theoretical constructs, and the researcher's sensory diary. This reflexive method ensured that analytical categories emerged organically from participants' lived experiences rather than being imposed externally.

Phase 2 : Interpretive Synthesis :

The second analytical phase involved interpreting the meaning of these themes through

acoustemological and **phenomenological** perspectives. Drawing on Feld's (1996) concept of *acoustemology* — knowledge through sound — the researcher examined how listening practices embodied migrants' ways of knowing and inhabiting Agra's urban environment. Participants often associated particular soundscapes with safety, nostalgia, or alienation. For example, the early morning *azaan* and temple bells were frequently described as grounding sounds that offered a sense of temporal continuity and emotional stability.

In contrast, the constant din of traffic and industrial noise represented the "unfamiliarity" of the city, often reinforcing feelings of exclusion and sensory fatigue. These contrasting auditory perceptions revealed how migrants negotiated dual sonic realities: one anchored in *memory* and another in *modern urban flux*. This duality resonated with Lefebvre's (1991) *production of space*, where sensory experience participates in the creation and contestation of social space.

Through interpretive analysis, it became evident that **sound functioned as a form of emotional cartography**—a way for migrants to map their identities within Agra's heterogeneous environment. Women participants, for instance, emphasized domestic sounds such as cooking utensils, children's chatter, and devotional songs, linking them to stability and care. Male participants, conversely, referred more often to occupational and public sounds such as factory machines, traffic horns, and vendor calls, illustrating gendered auditory domains consistent with Connell's (2009) analysis of gendered spatial practices.

Phase 3 : Contextual Triangulation :

To enhance analytical reliability, **triangulation** was applied across three dimensions — **methodological**, **temporal**, and **contextual**. Methodological triangulation involved comparing data from interviews, field recordings, and participant observations. This cross-verification highlighted how what participants said about sound often differed from how they actually interacted with it. For example, while several respondents complained about the "noise" of marketplaces, their daily routines revealed that such sounds provided structure, familiarity, and even reassurance — a paradox reflecting Bull's (2000) notion of *controlled noise* in urban life.

Temporal triangulation examined sound perceptions across time, comparing initial impressions of the city (first six months of settlement) with later reflections (after one year). This analysis indicated a gradual sensory adaptation process: sounds initially perceived as chaotic became normalized and even comforting, demonstrating a phenomenon of **sonic acclimatization** (Kanngieser, 2012). Migrants thus transitioned from sensory outsiders to participants in Agra's urban rhythms.

Contextual triangulation linked the sensory data with broader sociocultural and spatial contexts, drawing on Gupta and Ferguson's (1992) concept of *place-making through displacement*. Here, the soundscape was analyzed as a social field where community identity, religion, and occupational background intersected. Migrants from eastern Uttar Pradesh, for example, often recreated familiar sound environments in domestic spaces through regional music or dialects, thereby transforming auditory familiarity into a strategy of cultural resilience.

Analytical Interpretation and Theoretical Integration :

The final interpretive stage integrated empirical insights with theoretical constructs from **sound studies**, **urban sociology**, and **migration theory**. The data revealed that migrants' sonic experiences operated at three interrelated levels :

- **Cognitive Level :** Recognizing and interpreting familiar or unfamiliar sounds, reflecting conscious adaptation and memory processes (Schafer, 1994).
- **Affective Level :** Emotional responses to sound, such as nostalgia, comfort, or irritation, forming part of the emotional geography of migration (Appadurai, 1996).
- **Social Level :** Interaction and negotiation within shared auditory spaces, shaping identity and belonging in a plural urban context (Massey, 1994).

By situating individual narratives within these interconnected levels, the study elucidates how sound mediates both **continuity and change** in migrants' urban experiences. The findings demonstrate that auditory practices are not only personal but also socially structured — influenced by gender, class, religion, and spatial positioning. This aligns with Lefebvre's (1991) and Massey's (1994) arguments that urban spaces are dynamic products of social interaction and sensory production.

Conclusion of Analysis :

Overall, the data analysis reveals that migrants in Agra City transform the soundscape into an arena of **memory-making, adaptation, and identity negotiation**. The auditory dimension serves as a sensory bridge between the remembered past and the lived present. In doing so, migrants not only reinterpret their environment but also contribute to the ongoing sonic reconfiguration of Agra's urban fabric.

Sound, therefore, emerges as both a *method of survival* and a *medium of belonging* — shaping how new urban residents navigate displacement, social hierarchy, and cultural pluralism in the heart of India's historic city.

6. Findings

6.1 Reconstructing Auditory Memory :

Many participants described the *sound of home*—fields, village temple bells, livestock—evoked by certain audio cues. Migrants frequently used domestic practices (playing specific songs, keeping the same radio stations) to reproduce an auditory environment that felt like home (Feld, 1996). For instance, respondents from rural Uttar Pradesh described morning cowbells and folk songs as comfort sounds that reduced homesickness.

6.2 Sonic Practices of Belonging :

Sonic practices in domestic and community settings helped create familiarity :

- **Domestic playlists and radio :** Participants curated music from their home regions to sustain identity (Manuel, 2015).
- **Language use :** Speaking dialects in shared courtyards signalled belonging and created micro-communities within neighbourhoods.
- **Religious and ritual sounds :** Minor rituals, bhajans, or azaan timings served as rhythmic anchors that structured daily life and created shared temporalities (Eisenlohr, 2006).

6.3 Sound as Boundary-Making :

Sound also marked social differences. Neighbourhoods exhibited auditory stratification: colonial-era heritage zones had tourist noise, market areas had louder vendor calls, while certain residential pockets were quieter. Participants reported both positive and negative reactions to neighbours' sound practices—celebratory music could forge bonds during festivals but also become a site of friction regarding noise and timing (Thompson, 2002).

6.4 Migration, Gender and the Soundscape :

Women migrants often described using sound to manage domestic space—children's songs, radio channels targeting women, and calls to relatives—creating an audible domestic sphere that was distinct from public male-dominated soundscapes (Connell, 2009). Women reported more constraints on producing loud sounds but used quieter sonic practices (recitations, storytelling, phone calls) to sustain social ties.

6.5 Place-Making: Material and Sonic Interaction :

Participants described renovating living spaces and arranging furniture to emulate homes but placed equal importance on sonic rituals—morning tea music, evening prayers—that gave space its temporal and affective meaning. Sound practices often accompanied material changes, jointly contributing to place-making (Pink, 2015).

7. Discussion :

The findings show that sound is an active element in the migrant experience: it is not merely background noise but a medium through which migrants negotiate continuity and change (Schafer, 1994). Auditory memory operates as a technology of belonging: selective playback of songs, invocation of ritual sounds, and dialectal speech create networks of recognition (Feld, 1996). Sound also mediates conflict and conviviality—competing auditory expectations generate negotiations over acceptable noise and public time (Thompson, 2002).

Positioned in urban theory, these sonic practices demonstrate how migrants claim urban niches and resist erasure. The study underscores the need to integrate sensory dimensions into migration and urban policy: noise regulations, public event scheduling, and community planning often neglect acoustic justice and the culturally embedded meanings of sound (Howes, 2005; Eisenlohr, 2006).

8. Conclusion :

Sound matters. For new urban residents of Agra City, sonic engagements shape memory, identity, and place-making. Policy frameworks and urban design that ignore the cultural meanings of sound risk alienating migrant communities. Future research should map longitudinal changes in migrant soundscapes and explore how younger generations inherit and transform these practices (Creswell, 2013).

9. Policy Implications and Recommendations

9.1. Integrating Acoustic Awareness into Urban Planning :

Urban planning in Agra—and similar Indian cities—rarely accounts for the cultural and emotional dimensions of sound. Municipal corporations and development authorities should incorporate *acoustic mapping* into their master plans. By documenting and analyzing neighbourhood soundscapes (temple bells, street vendors, public transport), policymakers can design zoning that preserves meaningful community sounds while reducing harmful noise levels.

- **Action Point :** Introduce *Sound Impact Assessments* (similar to Environmental Impact Assessments) before major infrastructure or construction projects.
- **Expected Outcome :** Balanced coexistence of heritage, cultural, and residential sound environments.

9.2. Community Audio Spaces and Cultural Centers :

Migrants in Agra use sound—music, language, ritual—to sustain identity and belonging. Creating *community audio spaces* in local cultural centres can provide shared venues for musical exchange, storytelling, and ritual practices without conflict over noise.

- **Action Point :** Encourage NGOs and cultural departments to host *"sound heritage evenings"* where migrant communities share their traditional music and sonic memories.
- **Expected Outcome :** Strengthened intercultural understanding and community cohesion

through auditory exchange.

9.3. Promoting “Acoustic Justice” in Urban Governance :

Municipal policies often measure sound only in terms of decibels, ignoring cultural meanings. The concept of *acoustic justice* emphasizes fair access to sonic expression and the right to quiet or meaningful sound.

- **Action Point :** Create participatory *sound councils* under local ward committees to mediate disputes over festival noise, loudspeakers, or neighbourhood complaints.
- **Expected Outcome :** Inclusive decision-making that respects both cultural traditions and residents’ comfort.

9.4. Sound Heritage Preservation :

As Agra’s urban expansion continues, older soundscapes linked to local identity—handicraft markets, temple bells, and regional folk music—are being replaced by uniform traffic and commercial noise.

- **Action Point :** The Archaeological Survey of India (ASI) and Agra Development Authority should collaborate to document *“intangible sound heritage”* around historic sites such as Taj Ganj, Sadar Bazaar, and Kinari Bazaar.
- **Expected Outcome :** Recognition of sound as part of the city’s living heritage, complementing visual preservation efforts.

9.5. Incorporating Sensory Dimensions into Migration and Labor Policies :

Policies concerning migrant integration (housing, welfare, skill development) often focus on material aspects. Including sensory well-being—through culturally familiar soundscapes in public housing or workplace environments—can improve mental health and community belonging.

- **Action Point :** Integrate *sensory comfort* parameters into housing design guidelines for migrant settlements, supported by municipal architects and sociologists.
- **Expected Outcome :** Reduction in stress and alienation among new residents; enhanced urban livability.

9.6. Educational and Awareness Campaigns :

Public campaigns should raise awareness that not all sounds labeled as “noise” are nuisances—some are vital to cultural continuity.

- **Action Point :** Partner with local universities (e.g., Dr. B. R. Ambedkar University, Agra College) to conduct workshops on *sound literacy* and urban coexistence.

- **Expected Outcome :** Educated citizens who appreciate and negotiate sonic diversity in a plural city.

9.7. Policy Summary Table

Policy Area	**Action Strategy**	**Responsible Stakeholders**	**Anticipated Impact**
Urban Planning	Sound Impact Assessment	Agra Development Authority	Sustainable sound zoning
Cultural Integration	Community Audio Spaces	NGOs, Cultural Departments	Strengthened migrant identity
Governance	Sound Councils	Ward Committees, Nagar Nigam	Reduced noise conflicts
Heritage Preservation	Sound Documentation	ASI, Tourism Dept.	Safeguarded sonic heritage
Housing & Welfare	Sensory Design	Housing Boards, Sociologists	Better adaptation of migrants
Education	Sound Literacy Programs	Universities, Media	Inclusive civic culture

Conclusion :

Migration is not merely a spatial or economic transition—it is an experiential reorientation of the senses. This study of new urban residents in Agra City reveals that sound plays a fundamental role in shaping how migrants perceive, inhabit, and emotionally connect to their new environments. Far from being passive background noise, the urban soundscape becomes a dynamic medium through which memory, identity, and belonging are negotiated.

The findings show that migrants actively reconstruct their auditory worlds to maintain continuity with their places of origin. Familiar sounds—folk songs, temple bells, regional dialects, and daily rhythms—function as *mnemonic anchors* that bridge the gap between the remembered past and the urban present. Through domestic listening practices, ritual sounds, and everyday auditory routines, migrants cultivate comfort and a sense of control amid the flux of city life.

At the same time, the study highlights sound as a field of negotiation and power. Auditory boundaries—between communities, genders, and classes—are drawn and contested in the process of everyday cohabitation. Women, for instance, navigate auditory agency within domestic spaces, while men engage more directly with public soundscapes of labor and mobility. These differences underline how sonic practices intersect with social hierarchies and cultural norms in shaping urban experience.

Conceptually, this research expands the framework of urban and migration studies by integrating insights from sensory sociology and sound studies. It argues that understanding migration through sound deepens our grasp of *place-making* as both a sensory and social process. The soundscape emerges as a lived archive of adaptation—where personal memories, collective identities, and urban transformations converge.

Practically, the study calls for greater policy attention to *acoustic justice* and culturally sensitive urban design. Recognizing meaningful community sounds within planning and governance can foster more inclusive and empathetic urban environments. Cities like Agra, with their layered heritage and diverse migrant populations, stand to benefit from policies that balance cultural soundscapes with environmental health.

In conclusion, the soundscape of migration is both a metaphor and a material reality. It reflects how individuals and communities make sense of movement, difference, and belonging. By listening carefully—to both people and places—urban sociologists can better understand how the rhythms of migration compose the ever-changing symphony of the modern city.

References :

1. Adey, P. (2010). *Mobility.* Routledge.
   American Sociological Association. (2018). *Code of ethics.* American Sociological Association. https://www.asanet.org
2. Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization.* University of Minnesota Press.
3. Augoyard, J.-F., & Torgue, H. (2005). *Sonic experience: A guide to everyday sounds.* McGill-Queen's University Press.
4. Back, L. (2007). *The art of listening.* Berg.
5. Basu, P., & Coleman, S. (2008). Introduction: Migrant worlds, material cultures. *Mobilities, 3*(3), 313–330. https://doi.org/10.1080/17450100802376714
6. Blesser, B., & Salter, L. (2007). *Spaces speak, are you listening? Experiencing aural architecture.* MIT Press.
7. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
8. Bull, M. (2000). *Sounding out the city: Personal stereos and the management of everyday life.* Berg.
9. Bull, M., & Back, L. (Eds.). (2016). *The auditory culture reader* (2nd ed.). Bloomsbury

Academic.
10. Connell, R. (2009). *Gender in world perspective* (2nd ed.). Polity Press.
11. Cox, T., & Warner, D. (Eds.). (2004). *Audio culture: Readings in modern music.* Continuum.
12. Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage.
13. Eisenlohr, P. (2006). *Little India: Diaspora, time, and ethnolinguistic belonging in Hindu Mauritius.* University of California Press.
14. Feld, S. (1996). Waterfalls of song: An acoustemology of place resounding in Bosavi, Papua New Guinea. In S. Feld & K. Basso (Eds.), *Senses of place* (pp. 91–135). School of American Research Press.
15. Feld, S., & Brenneis, D. (2004). Doing anthropology in sound. *American Ethnologist, 31*(4), 461–474. https://doi.org/10.1525/ae.2004.31.4.461
16. Gupta, A., & Ferguson, J. (1992). Beyond "culture": Space, identity, and the politics of difference. *Cultural Anthropology, 7*(1), 6–23. https://doi.org/10.1525/can.1992.7.1.02a00020
17. Howes, D. (Ed.). (2005). *Empire of the senses: The sensual culture reader.* Berg Publishers.
18. Kanngieser, A. (2012). A sonic geography of voice: Towards an affective politics. *Progress in Human Geography, 36*(3), 336–353. https://doi.org/10.1177/0309132511423969
19. Kanngieser, A., & Behrendt, F. (2020). Listening as method. In S. Pink, V. Fors, & T. O'Dell (Eds.), *The Routledge handbook of sensory ethnography* (pp. 82–93). Routledge.
20. Lefebvre, H. (1991). *The production of space.* Blackwell.
21. Manuel, P. (2015). *Tales, tunes, and tassa drums: Retention and invention in Indo-Caribbean music.* University of Illinois Press.
22. Massey, D. (1994). *Space, place and gender.* University of Minnesota Press.
23. Pennycook, A., & Otsuji, E. (2014). Metrolingual multitasking and spatial repertoires: "Pizza mo two minutes coming." *Journal of Sociolinguistics, 18*(2), 161–184. https://doi.org/10.1111/josl.12079
24. Pink, S. (2015). *Doing sensory ethnography* (2nd ed.). Sage.
25. Schafer, R. M. (1994). *The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world.* Destiny Books.
26. Simpson, P. (2017). Sonic affect and urban space. *Cultural Geographies, 24*(1), 49–69. https://doi.org/10.1177/1474474016649400
27. Smith, S. J. (2000). Performing the (sound) world. *Environment and Planning D: Society and Space, 18*(5), 615–637. https://doi.org/10.1068/d246t
28. Stoller, P. (1989). *The taste of ethnographic things: The senses in anthropology.* University of Pennsylvania Press.
29. Thompson, E. (2002). *The soundscape of modernity: Architectural acoustics and the culture*

of listening in America, 1900–1933. MIT Press.

30. Thompson, E. (2017). *Beyond sound: The acoustic dimensions of sense, place, and power.* Routledge.
31. Tuhiwai Smith, L. (2012). *Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples* (2nd ed.). Zed Books.
32. Vannini, P., Waskul, D., Gottschalk, S., & Ellis-Newstead, T. (2010). The senses in self, society, and culture: A sociology of the senses. *Sociology Compass, 4*(1), 1–20. https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2009.00257.x

Email: arvindgupt1202@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 119-122
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

Green Schooling – A Healthy School Environment

Dr. Manoj Kumar Tyagi
(Director / Principal)
Noble Group of Institution, Meerut.

Introduction :

Green Schooling :

Green schooling is a concept which presents a paradigm that makes environmental education an integral part of student life. It helps in imbibing an environmental value structure that makes responsible and aware citizens out of young people. Green schooling is based on the premise of meaningful intervention on behalf of environmental awareness in schools at all levels. It is about forming and moulding attitudes that are environmentally responsible and encourage ethical consumption.

Green schooling is a way of making schools a hub of learning and practising skills like organic gardening, conservation of energy and water, rain water harvesting, waste recycling and other such environment-friendly activities. Students, by being at the centre of such change and activity, can develop their social and leadership qualities in the process. With gradual expansion of the purview of green schooling as time progresses, national as well as global issues can also be introduced to students and their roles developed. Green schooling should follow the principle of 'think global, act local'.

Green Schooling for :

Green schooling is meant to put students at the centre of all environmental activities and to bring their latent talents to fore-talents that often get overlooked in the academic structure of schools. Green Schooling is designed to develop schools into a learning space where 'values of life' are taught apart from pursuit of academic excellence.

- Green Schooling encourages all round, active participation from students without making any distinctions on basis of academic performances. It can grow into an avenue where every individual student can find his or her niche and discover his/her metier.
- Students who find it difficult to translate their learning experiences into academic excellence

in classrooms can learn and lead in Green Schooling activities and acquire confidence in their otherwise unnoticed abilities of creativity and parallel thinking.

- Green Schooling is an all-inclusive activity without the usual pressures of competitive rivalry. Its aim is to develop community activity among students with maximum participation and collective action.

Development of Green Schooling :

The first step to environment education is generating awareness. Students can be sensitised to a host of complex but basic issues surrounding them during the hours they spend in schools. They can be taught to identify problems and find solutions at individual and community levels. Every student in the school is part of a large community of students and teachers. This community is part of a still larger network of people and services outside the school. Thus as the spiral expands, the role of individuals must grow to synchronise with other stakeholders of this network and yet remain centred.

- Green Schooling provides the youth with life long self- empowerment and a thought process that explores the larger picture of environmental conservation and its relevance to every facet of life on earth, be it the economy, the market scenario, societal changes or technological advances.
- Learning about the environment and understanding its significance for improving the quality of life is an important exercise/aptitude that every student must learn.
- Many Educational Institutes aim at pursuing excellence in human development. This can be further enhanced through the introduction of Green Schooling at all levels. A beginning has already been made by the initiation of environmental and consumer education activities in schools. This consciousness can be further cemented and given a definite vision if the concept of Green Schooling is introduced in conjunction with the existing initiatives and also as an independent, extra-curricular and practical activity. Every aspect of school life can be used as an arena for promotion of Green Schooling.

School Green Component :

1) Water conservation :

Installing water-efficient fixtures, promoting refillable water bottles, and implementing rainwater harvesting reduce water usage.

2) Garden :

- The Garden can be used to introduce approaches to conservation of Biodiversity.
- Activities like vermiculture, composting and use of organic manure can be practised.
- This can also help in reduction of kitchen waste as garbage is converted into into manure.

3) Library :

- The Garden and Office can be used for introduction of paper recycling. Waste paper collected in offices can be either recycled or re-used. Paper making can be taught to student as an activity.

4) Canteen :

- Th canteen and water supply points can be important examples of water conservation. Principles of food hygiene, nutrition and packaging-free food can also be introduced.

5) Waste reduction :

Programs for recycling, composting cafeteria scraps, and minimizing printed materials help divert waste from landfills. The stationery and uniform shops can be used as exposure points for students to marketing practices. They can learn about fair price, quality and value for money.

Activities for Primary to Secondary Level Students :

- Students can be shown practical experiments of how paper can be made and recycled. The connection between paper and trees should be explained to them. Student(s) conserving paper can be awarded for their responsible behaviour.
- The importance of nutritious and healthy food can be explained to them. Similarly, the junk value of fast food can also be explained.
- Children can be taken to field trips or a 'nature walk' around their school campus to be shown the wildlife on the campus or threes in bloom.
- Primary school students should be encouraged to conserve electricity and water by turning off taps and lights when they are not in use.

Activities for Higher Class Students :

- Students living in hostels can adopt a sustainable pattern of life by initiating activities like 'organic farming' or 'kitchen gardening' within hostel premises. The canteen or mess can support this activity.
- Solar energy can be harnessed to operate solar devices. Night lighting and heating can be done by solar energy. Even water pumps can be operated with his technology. This can be an important lesson for students in energy conservation and in the use of alternative, non-polluting energy. Residential schools, especially, can initiate an all-round sustainable way of life among students.
- The concept of relating responsibility to action should be introduced. Examples of how agrarian poisoning by pesticides affects end users like students, the introduction of Genetically Modified food in the country and the impact of consumer choices on immediate and distant environment should be explained to students.
- Students can be taken on field trips, like a ride to a river or water harvesting site. This will

strengthen their theoretical knowledge base and help in comprehension of environmental issues.

- Students can initiate waste paper collection in office, library and other components of the school structure. Paper recycling activities and vermiculture can be carried out within the school campus.

Community engagement :

- **School and community collaboration :** Partnering with local organizations, government agencies, and businesses for expertise and resources strengthens the school's green initiatives.
- **Public communication:** Sharing the school's progress with the wider community through newsletters and assemblies can inspire broader behavioral change.
- **Community roles:** Schools can serve their communities by acting as recycling centers or drop-off points for local initiatives.

Curriculum and education :

- **Environmental audits :** Students conduct surveys to assess the school's environmental performance, such as energy use, waste production, and water consumption, which helps them understand where improvements can be made.
- **Hands-on learning:** School gardens provide a practical way to teach students about biology, food systems, and responsibility.
- **Teacher training:** Workshops for teachers equip them with the skills to integrate green topics and sustainability concepts into their lessons.
- **Curriculum integration:** Sustainability is embedded in the curriculum, teaching students about climate action and equipping them to be climate-ready citizens.

Conclusion :

The ultimate aim of Green Schooling is to initiate a process that will make students environmentally responsible and improve their quality of lives as adults. It can also present parallel avenues of development for students who are not at the forefront of the academic scene in school. The endeavour is to instil confidence in students and nurture their over all talent and ability.

References :

1. "The Concept of Green Schooling." Pg.25 by Dr. Roopa Vajpayee.
2. Green School Program, Centre for science and environment.
3. Environmental Education, S. S. Sirohi ,Tandon Publications, Ludhiana.
4. www.sciencedirect.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 123–127

Sustainable Learning : Navigating the Tensions of Digital Ecology in Future-Ready Classrooms

Dr. Anuradha Aggarwal
Head of the Education Department, SD PG College, Ghaziabad.

Abstract :

This article explores the concept of **sustainable learning** within the context of **future-ready classrooms**. argues that the uncritical adoption of digital technologies creates a complex "digital ecology" fraught with tensions that can undermine long-term educational goals. These tensions are examined across four key domains: the **cognitive tension** between deep and shallow learning; the **social and emotional tension** between connection and isolation, the **ethical tension** between datafication and privacy; and the **ecological tension** between innovation and e-waste. By analyzing these challenges, the article proposes that a sustainable approach to educational technology is not about maximizing tool usage, but about cultivating a balanced, healthy, and equitable learning environment. It calls for a shift in the educator's role from a mere "tech integrator" to a thoughtful "digital ecologist" who curates technology with pedagogical intentionality. Ultimately, sustainable learning prioritizes human-centered development, equipping students with the critical awareness and resilience needed to thrive in an increasingly complex digital world.

Sustainable Learning : Navigating the Tensions of Digital Ecology in Future-Ready Classrooms :

The vision of the "future-ready classroom" is captivating. It conjures images of students with personalized learning pathways, collaborating with peers across the globe, and accessing a universe of information with a single click. Technology, in this vision, is the great enabler, the engine of equity, and the architect of 21st-century skills. Yet, as schools accelerate their digital transformation, a critical question emerges: Is this new learning environment **sustainable**?

Sustainability in this context transcends the purely environmental. It refers to an educational approach that is enduring, equitable, and healthy for both students and educators. A sustainable learning environment nurtures deep thinking over shallow processing, fosters genuine community over fractured online interactions, protects student agency over commercial data interests, and considers its physical footprint. As we integrate evermore sophisticated tools, we simultaneously create a complex **digital ecology**—an interdependent system of hardware, software, platforms, data streams, and human behaviors. Navigating the inherent tensions within this ecology is the central challenge for creating classrooms that are not just technologically advanced but truly future-ready.

The Tensions of the Digital Ecology :

The promise of educational technology is undeniable, but its uncritical implementation creates significant friction. To build sustainable learning environments, we must first identify and consciously navigate these core tensions.

1. The Cognitive Tension: Deep vs. Shallow Learning :

The modern digital experience is engineered for distraction. The constant barrage of notifications, the allure of multitasking, and the hyperlink-driven nature of online content create a cognitive environment that favors shallow, rapid-fire information processing over the sustained focus required for deep learning. This "attention economy" has infiltrated the classroom, pulling students away from complex problem-solving and critical analysis.

- **The Challenge :** When a student is writing an essay in a cloud-based word processor, they are simultaneously a few clicks away from social media, streaming videos, and a dozen other open tabs. This constant context-switching increases **cognitive load**, making it harder to retain information and form complex neural connections. The very tools designed to enhance learning can become its greatest impediment.
- **A Sustainable Approach :** Sustainability here means reclaiming focus. This involves a pedagogy of **digital minimalism**, where educators intentionally select a few high-impact tools rather than adopting every new trend. It requires explicitly teaching students metacognitive skills for managing attention, the benefits of single-tasking, and the importance of "deep work." Crucially, it involves balancing screen time with analog activities—discussions, hands-on projects, and quiet reflection—that allow the brain to consolidate learning without digital interruption.

2. The Social & Emotional Tension: Connection vs. Isolation :

Digital platforms promise a world of connection, enabling collaboration beyond the classroom walls. While these tools can facilitate group projects and communication, an over-reliance on screen-mediated interaction can erode the development of essential social and emotional skills. Empathy, non-verbal cue reading, and the art of civil discourse are honed through face-to-face interaction.

- **The Challenge :** A classroom where students primarily interact through discussion boards and collaborative documents may be efficient, but it can also foster a sense of isolation. The disinhibition of online communication can also create fertile ground for cyberbullying and misunderstanding, issues that are more complex to resolve when not grounded in established, real-world relationships.

- **A Sustainable Approach :** A sustainable social ecology uses technology to **augment, not replace**, genuine human connection. Tools should be chosen to facilitate real-world collaboration—for instance, using a platform to plan a community garden or to share data from a local environmental project. The curriculum must include robust **digital citizenship** education that goes beyond online safety to teach empathy, perspective-taking, and ethical online behavior actively. Prioritizing presence and creating space for unstructured, face-to-face conversation is essential for building a resilient classroom community.

3. The Ethical Tension: Datafication vs. Privacy :

Perhaps the most insidious tension is the trade-off between the personalization promised by EdTech and the data privacy of students. Modern learning platforms are powerful data-harvesting tools. Every click, every answer, every pause is logged, analyzed, and used to build a detailed profile of the learner. This process of **datafication** raises profound ethical questions.

- **The Challenge :** Who owns a student's learning data? How is it being used? Is it being sold to third parties or used to train algorithms that may entrench existing biases? The lack of transparency in many EdTech products creates a surveillance-based model of education where students may be penalized by biased algorithms or have their data used for commercial purposes without their consent.
- **A Sustainable Approach :** Ethical sustainability requires a proactive stance on data privacy. Schools and districts must implement stringent **ethical procurement policies**, thoroughly vetting software for its data security and privacy standards. Both educators and students need to be taught **data literacy**—understanding what data is being collected and how it is being used. A truly sustainable model would champion student agency, giving learners ownership and control over their own data, using it as a tool for self-reflection rather than external judgment.

4. The Ecological Tension: Innovation vs. E-Waste :

The push for future-ready classrooms has fueled a relentless upgrade cycle. Devices are often seen as disposable, with schools pressured to purchase the "latest and greatest" to stay current. This has a tangible environmental cost, contributing to the growing global crisis of electronic waste (e-waste) and consuming significant energy resources.

- **The Challenge :** Many educational devices are not designed for longevity. They are difficult and expensive to repair, and proprietary software can render older hardware obsolete. This planned obsolescence is antithetical to the principle of sustainability.

- **A Sustainable Approach :** Environmental sustainability in EdTech involves shifting from a consumer mindset to one of stewardship. This means advocating for and purchasing technology that is durable, modular, and **repairable**. Schools can extend device lifecycles through refurbishment programs and partner with certified recyclers for responsible end-of-life disposal. Most importantly, it requires a pedagogical shift: focusing on the instructional value of a tool rather than its novelty, and asking whether a new device is truly necessary or if existing resources can be used more creatively.

The Educator as a Digital Ecologist :

Navigating these tensions requires a fundamental rethinking of the educator's role. The term "tech integrator" is no longer sufficient. It implies a primary function of simply plugging tools into the existing curriculum. The future-ready educator must instead become a **digital ecologist**—a thoughtful curator of the classroom's learning environment.

A digital ecologist does not ask, "What is the latest tool I can use?" but rather, "What is the effect of this tool on my students' cognition, their relationships, and their well-being?" They understand that every piece of technology introduced affects the balance of the entire system. They model responsible digital habits, foster open dialogue about the challenges of the digital world, and empower students to become critical, conscious users of technology, not just passive consumers.

In conclusion, a truly future-ready classroom is not defined by the quantity of its devices, but by the quality of the learning and interaction it supports. It is a space of intentionality, where technology serves a clear pedagogical purpose and is balanced with other modes of learning. By confronting the tensions of the digital ecology head-on, we can move beyond the brittle hype of technological solutionism and build a more sustainable, human-centered foundation for education—one that prepares students not just for a future of work, but for a future of well-being, connection, and lifelong learning.

Bibliography :

1. Carr, N. (2011). *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. W. W. Norton & Company.
2. Ito, M., et al. (2013). *Connected Learning: An Agenda for Research and Design*. Digital Media and Learning Research Hub.
3. Selwyn, N. (2016). *Is Technology Good for Education?* Polity Press.
4. Turkle, S. (2017). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.
5. Turow, J. (2017). *The Aisles Have Eyes: How Retailers Track Your Shopping, Strip Your Privacy, and Define Your Power*. Yale University Press.

6. Watters, A. (2019). *The 100 Worst Ed-Tech Debacles of the Decade*. Hack Education. Retrieved from http://hackeducation.com/2019/12/31/top-ed-tech-deacles-decade
7. Williamson, B. (2017). *Big Data in Education: The Digital Future of Learning, Policy and Practice*. SAGE Publications.
8. Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

aanuradhawork@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 128–133

संस्कृत साहित्य में काव्य के प्रयोजन

Kalpanabahen Sangada
Phd Scolar
Agrwaldal Mill Talav Faliya Chhapri, Dahod, Pin-389151, Gujarat.

कवि के प्रयोजन तथा उसकी शिक्षा :

भारतीय कवियों तथा अलंकार–शास्त्र–सम्बन्धी ग्रन्थों के लेखकों के विचारों में कवि के प्रयोजन के सम्बन्ध में तात्त्विक ऐकमत्य है। उनको रुचिकर लगने वाले दो महान् लक्ष्य है. यशःप्राप्ति और आनन्द–प्रदान। भामह का कथन है कि कवि के स्वर्गवासी हो जाने के अनन्तर भी उसका काव्यमय शरीर पवित्र तथा कान्तियुक्तरूप में पृथ्वी पर स्थित रहता है। इसमें सन्देह नहीं कि कविता के अन्य प्रयोजनों को भी साथ में जोड़ा जा सकता है। स्वयं भामह ने काव्य से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कलाओं के सम्बन्ध में नैपुण्य की प्राप्ति का उल्लेख किया है, परन्तु ये केवल गौण बातें हैं जिनकी प्राप्ति अन्य साधनों हसे भी की जा सकती है। अतः ये उल्लेख के योग्य नहीं हैं। उपदेश देना श्री कवि के प्रयोजन का आवश्यक भाग नहीं है, पर यदि वह चाहे तो अपनी कृति में किसी प्रकार के उपदेश का समावेश कर सकता है। यदि उसका यह उद्देश्य हो तो, धार्मिक गुरुओं के प्रभुसम्मित तथा शास्त्रकारों के सुहृत्सम्मित उपदेशों के विपरीत, कवि का उपदेश कान्तासम्मित होता है। काव्य का बानन्द पाठक या श्रोता को ही प्राप्त होता है। साग्रह प्रश्न किये जाने पर भारतीय रससिद्धान्त काव्यसर्जन में आनन्दप्राप्ति को स्वीकार नहीं करता। कवि अपनी कविता का आनन्द तभी ले सकता है जब अपनी रचना की समाप्ति पर वह सहृदय वन जाता है, और अपने इस रूप में वह उस रस का आस्वाद लेता है जो आस्वाद की अवस्था में आनन्द का शुद्धतम रूप है। सिद्धान्त का सादृश्य उपलब्ध होता है कि नाट्य के रस का नहीं, अपितु प्रेक्षक को होता है। यहां हमें इस आस्वाद नट को परन्तु यदि कवि अपनी कीति के लिए इच्छुक होते थे तो उन्हें इस बात का ज्ञान था कि बिना किसी आश्रय के वे इसे नहीं प्राप्त कर सकते, और स्वभावतः यह आश्रय उन्हें मुख्यतः राजा से और यदि उससे नहीं तो किसी समृद्ध आश्रय–दाता से ही मिल सकता था। राजाओं को प्रभावित कर सकने वाले अभीष्ट अर्थ बारम्बार तथा अत्यधिक प्रभावपूर्ण रीति से व्यक्त किए गए हैं।

दण्डी के अनुसार वाणी में प्रतिबिम्बित प्राचीन राजाओं की कीति उनकी मृत्यु के अनन्तर भी स्थित रहती है। रुद्रट कहते हैं कि मनुष्य के कर्मों का स्वर्गादि फल भले ही नष्ट हो जाय, किन्तु उनके नामों को कवि सदा के लिए सुरक्षित बना सकता है, और जैसा कि हम देख चुके हैं, इस विषय में कल्हण तो सबसे अधिक जोर देते हैं।

राजशेखर ने काव्य तथा अन्य विद्याओं के प्रति राजा के कर्त्तव्य पर बहुत अधिक बल दिया है राजा को

नियमतः एक दरबार करना चाहिए जिसमें बहुत अधिक संख्या में कवि तथा अन्य जन उपस्थित हों और विचार के लिए प्रस्तुत किये गये ग्रन्थ के गुण–दोष की परीक्षा करें, साथ ही उसे वासुदेव, सातवाहन, शूद्रक और साहसांक के उदाहरण का अनुकरण करते हुए कवियों को उनके गुणों के अनुसार पुरस्कृत करना चाहिए। उसे राज्य के बड़े नगरों में ब्रह्मसभाएँ भी स्थापित करनी चाहिएँ, जिससे वहां राजकीय समर्थन के लिए उपस्थापित ग्रन्थों की परीक्षा की जा सके। कालिदास, मेण्ठ अमर रूप, सूर, २ भारवि, हरिचन्द्र और चन्द्रगुप्त इन महान् कवियों की सूची हमें प्राप्त है, जो उज्जैन में प्रशंसित हुए थे। इसी प्रकार शास्त्रों के रचयिता उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वररुचि तथा पतञ्जलि को पाटलिपुत्र में राजकीय सम–धंन प्राप्त हुआ था। भोजप्रबन्ध में, यद्यपि वह परवर्ती और अनैतिहासिक है राजसभा में ऐसी प्रतियोगिताओं के मनोरञ्जक चित्र उपलब्ध होते हैं, और प्रबन्धचिन्तामणि में भी ऐसे ही चित्र खीचे गये हैं, जो यह प्रकट करते हैं कि राजशेखर का आदर्श प्रायः चरितार्थ होता था, जबकि राजसभा का एक अधिक औपचारिक चित्र मंख से प्रस्तुत किया है। इसमें भी हमें सन्देह नहीं करना चाहिए कि कवि तथो राजा का पारस्परिक सम्बन्ध दोनों के लिए सुखकर होता था। यदि हर्ष की उदारता से प्राप्त बाण का सम्पत्तिलाभ प्रख्यात था, तो उस अज्ञातनामा कवि की उक्ति में भी पर्याप्त सत्य विद्यमान है जो पूछता है कि धन की वे राशियां और मदस्रावी हाथी कहां गये जो वाण के गुणों के कारण महान् सम्राट हर्ष ने बाण को दिये थे, जबकि उस कवि के प्रवाहपूर्ण पचों में चित्रित हर्ष की कीति कल्प की समाप्ति हो जाने पर भी नष्ट न होगी।

कविजन निश्चय ही आशा करते थे कि राजा लोग परिष्कृत रुचि के व्यक्ति होंगे, परन्तु वे यह भी स्मरण रखते थे कि उन्हें राजाओं की अपेक्षा अधिक बडे श्रोतुसमुदाय की आवश्यकता है और शाश्वत ख्याति प्राप्त करने के लिए उन्हे इसिकों के चित्त को आकृष्ट करना चाहिए, जो अपनी कुणाल निर्णायक–शक्ति से उनके ग्रन्थों की परीक्षा करेंगे। रसिक उसे कहते है जिसने काव्य का गम्भीर अध्ययन किया हो जिससे उसके मतिदर्पण में कोई दोष न रह जाये, और जो अपनी सहृदयता के कारण लेखक के लक्ष्य से अपना तादात्म्य स्थापित कर सके।

ऐसा मनुष्य वास्तविक कविता के सुनने पर अनुभव करेगा कि जिस प्रकार अधिक सुरापान से हृदय उत्तेजित हो जाता है वैसा ही उसका हो गया है, और जब वह कवि के शब्दों को दुहराने का प्रयत्न करेगा तब उसको रोमाञ्च हो आयेगा, उसका मस्तक काँपने लगेगा, उसके कपोल रक्तिम–युक्त हो जायेगे, उसकी आँखें अश्रुपूर्ण हो जायेंगी, और उसकी वाणी हकलाने लगेगी। और जैसा कि हम देख चुके हैं, अपने को एक पाठक की स्थिति में रखने पर एक सच्चा कवि भी इन्हीं बातों का अपने में अनुभव करेगा, और इस प्रकार वह स्वयं अपनी रचनाओं का विषयगत दृष्टि से, निष्पक्ष होकर, रसास्वादन करता है।

परन्तु इस प्रकार की उत्कृष्ट कविता की रचना कर सकना अनेक कारणों पर निर्भर है। इसके लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति, और अभ्यास का होना आवश्यक है। भामह इत्यादि अन्य विद्वानों से मतभेद रखते हुए दण्डी इस बात पर बल देते हैं कि प्रतिभा के अभाव में भी उपर्युक्त अन्य दो कारणों से पर्याप्त सफलता मिल सकती है। तो भी उत्कृष्टतम कविता के लिए उक्त तीनों का संयोग सभी को मान्य है। यह विचार, कि एक सीधे–सादे असंस्कृत हृदय से भी कविता की स्वच्छ तथा सरल घारा फूट सकती है, निश्चय ही संस्कृत कवियों को रुचिकर नहीं लग सकता था। अलङ्कारशास्त्र के लेखक कवियों में उपयोगी ज्ञान का भण्डार चाहते हैं, और कवि भी अपनी रचनाओं में प्रयत्नपूर्वक इसके दिखाने का प्रयास करते हैं। कवि के लिए किन–किन बातों का ज्ञान

आवश्यक है, इसकी वामन द्वारा हमें एक बहुत कुछ स्पष्ट सूची प्राप्त होती है।

कवि को सांसारिक बातों का ज्ञान होना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि क्या सम्भव है और क्या असम्भवः उसे व्याकरण में निष्णात होना चाहिए, शब्दकोषों में बतलाये गये शब्दार्थों से परिचित होना चाहिए। छन्दःशास्त्र का अध्ययन करना बाहिएरू गान, नृत्य तथा चित्रकला इत्यादि कलाओं में दक्ष होना चाहिए। और प्रेम के व्यवहारों की जानकारी के लिए कामशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही, नीति और अनीति के ज्ञान के लिए और घटनाओं का औचित्य समझने के लिए उसे राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। परन्तु कवि के सारे कर्तव्य ये ही नहीं हैं। उसे कुछ अन्य छिटपुट बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसे अपने को वर्तमान कविता से परिचित बनाना चाहिए, कविताओं के अथवा कम से कम उनके अंशों के लेखन का अभ्यास करना चाहिए काव्यकला की शिक्षा देने वाले आचार्यों के प्रति आदरयुक्त आज्ञाकारिता प्रदर्शित करनी चाहिए, ऐसे उपयुक्त शब्द के चयन का अभ्यास करना चाहिए जिसके उपलब्ध होने पर उसे बदलने से कविता की हानि होती हो। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए उसे अपनी प्रतिभा को समाहित करना चाहिए। इस बात के लिए ब्राह्म मुहूर्त सर्वोत्तम है। इस बात का समर्थन कालिदास तथा माध के साक्ष्य से किया जा सकता है।

कविता के स्रोतों के सिद्धान्त में परिष्कारों से कोई विशेष मूल्यवान् बात नहीं निकलती। 'राजशेखर' ने कारयित्री अथवा भावयित्री के भेद से प्रतिभा के कार्य का विवेचन किया है। यह अन्तर वस्तुतः सर्जन–शक्ति और आलोचना–शक्ति के भेद से सम्बद्ध है। इन दोनों शक्तियों में भेद करते हुए कालिदास को उद्धृत किया गया है। राजशेखर ने कवि का रोचक चित्र भी खींचा है। उसे आवश्यक रूप से पेशल रुचि का तथा धनी होना चाहिए। उसका भवन सुसंमृष्ट होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक ऋतु के अनुकूल कमरे हों और एक छायायुक्त उद्यान हो जिसमें दीधिका हो, पुष्करिणी, मण्डप, स्नानगृह, पालकी हंस तथा चकोर पक्षी भी हों। कबि को वाणी, बुद्धि तथा शरीर से शुचि होना चाहिए। उसके नख कटे हुए हों और शरीर पर अंगराग का लेप किया हुआ हो। उसे ऐसे बहुमूल्य वस्त्र धारण करने चाहिए जो भड़कीले न हों, और भोजन के अनन्तर पान खाना चाहिए। उसके परिजनों को उसकी शान शौकत के अनुकूल होना चाहिए। परिचारकों को अपभ्रंश, परिचारिकाओं को मागधी, अन्तः पुरिकाओं को संस्कृत तथा प्राकृत और मित्रों को सब भाषाएँ बोलनी बाहिये। उसके लेखक को उसके समान ही योग्य तथा स्वयं कवि होना बाहिए। अपने घर में भाषा–विषयक विशेष नियमों पर बल देने की सीमा तक भी कुछ लोग जा सकते हैं, जैसे मगध का शिशुनाग, जिसने ण के अतिरिक्त अब मूर्धन्यों, ऊष्मवों तथा क्ष का प्रयोग अपने सम्मुख निषिद्ध कर दिया था। सूरसेन देश के कुचिम्द ने परुव संयोगाक्षरों का प्रयोग बन्द कर दिया था। कुन्तल देश का सातवाहन प्राकृत के प्रयोग पर ही बल देता था, और उज्जैन का साह–साङ्क अपने दरवार में संस्कृत के ही प्रयोग किए जाने की इच्छा करता था। कवि की दिनचर्या भली–भाँति विभक्त है। उसे प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, विद्या की देवी सरस्वती को श्रद्धाञ्जलि अर्पित करके शास्त्रों का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन करना चाहिए, तदनन्तर कुछ समय काव्य रचना में लगाना चाहिए, फिर मध्याह्न का भोजन करना चाहिए और उसके पश्चात् अपनी कविता की मीमांसा में लगना चाहिए या काव्यगोष्ठी का आनन्द लेना चाहिए, फिर अपने कुछ मेधावी मित्रों के साथ बैठ कर उसे अपनी कविता को परीक्षा करनी चाहिए। सायंकाल उसे फिर सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए और रात्रि के प्रथम पहर में अपनी कविता का अन्तिम रूप लिख लेना चाहिए। इन सब जातों में वस्तुतः कुछ–न–कुछ कृत्रिमता का पुट है, किन्तु, ग्रन्थों में शास्त्र द्वारा लिये गये भाग के अनुसार

शास्त्रकवियों के भेदों की भाँति राजशेखर के ग्रन्थ में सर्वत्र ही यह देखने में आता है कि कविता मूलतः विद्वानों की वस्तु थी और वह अत्यधिक अनुशीलन का फल थी।

राजशेखर ने एक विषय पर बहुत अधिक ध्यान दिया है, जिस पर उनके पूर्वजों ने उतनी पूर्णता के साथ विवेचन नहीं किया, और वह है एक कवि द्वारा अन्य कवि की शब्दावली और विचारों के आदान का विषय। आनन्द–वर्धन अन्य कवियों से अत्यधिक आदान के पक्ष में नहीं हैं। यद्यपि शताब्दियों से सैंकड़ों कवि रचना करते चले आ रहे है, तो भी काव्य का क्षेत्र असीमित है। दो प्रतिभाशाली कवियों की कृतियों में समानताएँ हो सकती हैं। इन समानताओं में, प्रतिबिम्ब–कल्प समानता या वह समानता जो किसी वस्तु और उसके चित्र में उल्लसित होती है त्याज्य है, किन्तु वैसी समानता, जैसी दो मनुष्यों के बीच दिखलाई पड़ती है (तुल्यबेहिसुल्य समानता) गर्हणीय नहीं है। राजशेखर ने शब्दावली, पद्य के एक भाग या सम्पूर्ण पद्य के आदान के विषय में भिन्न–भिन्न मत प्रस्तुत किये है, और यद्यपि उन्होंने विश्व चोरी और स्वायत्तीकरण में भेद किया है तो भी इस विषय में उनके मत शिथिल ही है। उन्होंने वस्तुतः इस उत्तम नीतिवचन को उद्धृत किया है,

पुंसः कालातिपातेन चौर्यमन्य द्विशीर्यति।
अपि पुत्रेषु पौत्रेषु वाक्चौर्य च न शीर्यति।।

'पुरुष की अन्य चोरी तो समय के बीतने पर विशीर्ण हो जाती है, पर वाणी की चोरी पुत्रों और पौत्रों तक भी शीर्ण नहीं होती।' पर इसके साथ ही उन्होंने शब्दहरण अथवा अर्थहरण के पक्ष में अपनी पत्नी अवन्तिसुन्दरी का बचन उद्धृत किया है। इस प्रकार वह कह सकता है, वह अप्रसिद्ध है, मैं प्रसिद्धिमान् हैं। उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मैं प्रतिष्ठावान् हूँ। उसका यह संविधानक अप्रक्रान्त है और मेरा प्रक्रान्त है, उसके बचन गुडूची जैसे हैं और मेरे मृढीका जैसे, अर्थात् हमारी शैलियों में भेद है। वह भाषा की विशेषताओं का अनादर करता है और मैं उनका आदर करता हूँ; उसे लेखक के रूप में कोई नहीं जानता; लेखक दूर देशान्तर में रहता है; उसकी लिखी हुई पुस्तक गतकालिक है; यह तो केवल एक म्लेच्छ की कृति है।' संस्कृत के परवर्ती कवियों ने इन बहानों का स्पष्टतः ही पूरा लाभ उठाया है, और आधुनिक व्यवहार में भी ये इतने अधिक प्रसिद्ध हैं कि गम्भीरतापूर्वक इनकी निन्दा नहीं की जा सकती। राजशेखर का अपना मत इस सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि 'ऐसा कोई कवि नहीं है जो चोर न हो, और ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जो ठग न हो, किन्तु वह व्यक्ति निन्दा से रहित होकर मौज करता है, जो अपनी चोरी को छिपाने की कला जानता है। कोई कवि उत्पादक होता है और कोई परिवर्तक कोई आच्छादक होता है और कोई संवर्गक। जो शब्द, अर्थ और उक्तियों में यहाँ कुछ नूतन देखता है और कुछ प्राचीन बातों को लिखता है, उसे महाकवि माना जा सकता है।'

अर्थहण के सम्बन्ध में राजशेखर ने एक सिद्धान्त निरूपित किया है, जिसको मान्यता मिली है और जिसका हेमबन्द्र ने संक्षेप किया है। प्रतिबिम्बकल्पता की निन्दा की गई है। उसकी परिभाषा है कि 'जहाँ अर्थ तो सारा का सारा बही हो, किन्तु उसकी रचना दूसरे वाक्यों में की गई हो।' आलेल्यप्रत्यता में कुछ संस्कारकर्म के वस्तु मित्रवत् दिख–लाई जाती है और यह प्रतिबिम्बकल्पता से श्रेष्ठतर है। तुल्यदेहितुल्य समानता वहाँ होती है जहाँ वस्तु के भिन्न होने पर भी अत्यधिक साम्य के कारण तादात्य का आभास होता है; निपुण कविजनों की कृतियाँ भी इस प्रकार की होती है। पर–पुर–प्रवेश समानता में प्रतिपाद्य विषय की एकरूपता रहती है, किन्तु शब्द संस्कार अत्यधिक भिन्न रहता है, और अत्युत्तम कविजन भी इस पद्धति को अपनाते है। इस प्रवृति का दूसरा

पक्ष भी वर्तमान है; हर्षचरित की अवत–रणिका में बाण ने निन्दनीय चोर की भांति उस कवि की स्पष्टतया भर्त्सना की है जो शब्दावली को परिवर्तित करके अन्य लेखक के कर्तृत्व के चिह्नों को छिपाता है।

अनुकरण की प्रवृत्ति का, अर्थ की विशेष चिन्ता छोड़ कर अभ्यासार्थ पद्य–रचना करने की प्रवृत्ति का तथा सुप्रसिद्ध विषयों पर विस्तृत रचनाओं की प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि समयों की स्थापना हो गई जिनको काव्यों में लगभग यान्त्रिक ढंग से दुहराया गया है। चक्रवाक पक्षी रात्रि में अपनी प्रियतमा से वियुक्त हो जाता है और मानवीय दुःख का निरन्तर स्मरण दिलाता है। चकोर को चन्द्रमा की किरणें पीकर जीवित रहने वाला बताया जाता है, और विषमय भोजन को देखते ही उसकी आँखे लाल हो जाती हैं। चातक केवल मेघों का ही जल पीता है; हंस पानी से दूष को अलग कर देता है; कीत्ति और हास समान रूप से श्वेत हैं; अनुराग को लाल माना गया है। अन्धकार मुष्टिग्राह्य है; ईर्ष्या का मुख दो जिह्वाओं वाला और विष से पूर्ण है; राजा के चरणनख उसके चरणों पर दण्डवत् पड़े हुए सामन्तों की चूड़ा–मणियों से प्रदीप्त रहते हैं। दिन में खिलने वाले कमल सन्ध्या समय अपने बाह्य–दल–रूपी नेत्रों को बन्द कर लेते हैं। अशोक वृक्ष प्रियतमा के पाद प्रहार से खिल उठता है, और बहुत बड़ी संख्या में समान 'अभिप्राय कवि परम्परा द्वारा बराबर वणित किये गये हैं। राजशेखर ने इन कविसमयों का पूर्णता के साथ वर्णन किया है, और इनकी साधारण रूप में ही यह कहकर व्याख्या कर दी है। ये कविसमय हम लोगों से विप्रकृष्ट भिन्न–भिन्न देशों और कालों में किये गये वास्तविक निरीक्षणों पर आधारित हैं। इस प्रकार हमें यह नियम मिलता है कि नदियों में सदा ही कमल पाये जाते हैं, हंस सब जला–दायों में होते हैं. प्रत्येक पर्वत पर स्वर्ण और रत्न होते हैंय या, फिर, सत्य की जोर से आँख मूंद ली जाती है. उदाहरणार्थ जब कि मालती को वसन्त में खिलने का अधिकार नहीं दिया जाता, चन्दनवृक्षों को फलपुष्प से रहित कहा जाता है, और अशोकों में फल न होने का वर्णन किया जाता है। या, फिर, वस्तुओं के अस्तित्व पर कृत्रिम बन्धन लगाये जाते हैं; मकर समुद्रों में ही पाये जाते हैं और मोती ताम्रपर्णी नदी में ही। राजशेखर ने इसी प्रकार की रूढ़ियाँ द्रव्य, गुण और क्रिया के सम्बन्ध में उदाहृत की है, और कवियों द्वारा मानी गई ऋतुओं की विशेषतायें भी दी हैं। अधिक विस्तृत क्षेत्र में भी विचारों की पुनरावृत्ति उपलब्ध होती है, और हिन्दू कथा–साहित्य में विचारों के प्रतिपादन के विविध प्रकारों के रोचक संकलन भी किये जा चुके हैं : इस प्रकार के 'अभिप्राय' हैं– दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की कला हँसने और रोने का 'अभिप्राय' वात करने वाले पक्षी, सत्य का प्रभाव, गर्भवती स्त्रियों की इच्छा या दोहद, कपटी संन्यासी और बनी हुई भिक्षुणियाँ जैसा 'अभिप्राय' अर्थात् कामातुर पर असफल स्त्री द्वारा परपुरुष को बदनाम करने का 'अभिप्रायं', अरिष्ट का प्रतीकार, काकतालीय कथा, लिङ्ग का परिवर्तन, और अन्य बहुत से महत्त्वपूर्ण या छोटे–मोटे :अभिप्राय'।'

संस्कृत साहित्यिक रुचि के विकास में दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य आशु–कविता की रचना अथवा दिये गये विषय पर यथासम्भव शीघ्रता से पद्यरचना करने के प्रति अनुराग था। यह कौशल, अत्यधिक शीघ्रता के साथ कवि को पद्यरचना में समर्थ बनाने के लिए, काव्यगत रूढ़ियों पर पूर्ण और सिद्ध अधिकार के प्रति सीमा से अधिक समादर प्रदर्शित करने का कारण हो सकता था। शीघ्रकवि की जो प्रशंसा की गई है, वह हमें अतिरञ्जित प्रतीत हो सकती है, किन्तु इस प्रकार के भाव का अस्तित्व स्पष्टतः प्रमाणित है। समस्यापूरण' का अभ्यास काव्यगत नैपुण्य के प्रयोग के रूप में उतना निन्दनीय नहीं था। इसमें कवि प्रायः किसी दी हुई पंक्ति पर पद्यरचना करता था। प्राचीन परम्परा कालिदास तक को इस मनोरञ्जन में प्रवीण बतलाती है।

संदर्भ सूची :

१. गीत गोविंदम भारतीय काव्यशास्त्र, डॉ. रामानंद शर्मा।

२. काव्यशास्त्र, श्रवण कुमार गुप्ता।

३. भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत, जितेंद्र नाथ मिश्रा।

४. काव्यशास्त्र एवं साहित्य समालोचना, रविंद्र के दास।

५. संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पी. वी. काने।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 134–141

To Study the Impact of Gamification on Student's Memory and Cognitive Development in Jind District Public School

Anu Rani, Ph.D. Scholar
Dr. Rajpal Singh Yadav, Research Supervisor
Education Department, Singhania University. Rajasthan, india.

Summary :

This study set out to explore the impact of gamification on diverse aspects of student learning, ranging from motivation and attentiveness to problem-solving, confidence and teamwork. The evidence obtained through statistical analysis and classroom observations consistently pointed to one central finding: gamification has the power to transform the learning experience from passive reception into active participation. Students exposed to gamified platforms displayed stronger willingness to engage, greater persistence in completing tasks and higher levels of accuracy and retention compared to their peers in traditional settings. Beyond academic outcomes, they also exhibited growth in confidence, readiness to collaborate and willingness to take leadership roles-qualities that prepare them not only for examinations but also for the demands of real life. The findings affirm that when thoughtfully designed, gamification serves as more than just entertainment; it becomes a structured pedagogical tool that enhances both cognitive and socio-emotional learning. At the same time, the study acknowledges the limitations of short-term exposure, context-specific conditions and reliance on extrinsic rewards, emphasizing that gamification must be implemented with balance and foresight.

Key Words : Gamification, Memory and Cognitive Development

Introduction :

Games are played everywhere. For the sole goal of recreation, they freely include people of different ages, races, backgrounds and historical eras. Playing games encourages players to take initiative, persevere, set and meet more difficult goals and commit time and energy to learning new abilities and information. These elements are crucial to everyone's developmental process and games are undoubtedly one of the primary means by which kids can acquire and refine lifelong abilities that they will need in the future (Lillemyr et al., 2011). In addition, playing video games is believed to provide a positive mental experience, making it a possible welfare indication. Playing games can also have long-term mental advantages in the form of developed skills like logical and critical thinking, as well as socio-communicative and relational skills for handling group conflicts. Research has also demonstrated that games are useful instruments for increasing student participation and activity levels in formal teaching-learning processes (Nell et al., 2013). Games can help students become more focused, imaginative, driven and social. Additionally, games provide a secure setting where students can use their own abilities and make mistakes without worrying about consequences or frustrations. This allows students to use the successful trial-and-error learning methodology (Holland and Skinner, 1961), which can be especially helpful when faced with challenges. Less notably, games play a significant role in students' everyday after-school activities. For this reason, they are an excellent means of communicating the implicit acquisition of various abilities.

Several concepts have evolved in the study of game use for education since the 1980s, including gamification, games-based learning, edutainment, serious games and entertainment education. Since these ideas are based on "activities with the structure, spirit and rules of a game to make learning fun and motivating," they all share the intrinsic goal of using games for purposes that go beyond pure entertainment and to support learning in a playful way (see Table 1 for some examples of how these ideas differ from one another). The current study examines the effectiveness of gamification, which has been receiving increased attention in the sectors of education and rehabilitation since 2010.

The value of games in learning lies in their ability to engage learners, promote active participation, provide immediate feedback, foster motivation, develop skills, facilitate experimentation, offer personalization and encourage social interaction. By harnessing the power of games, educators can create dynamic and immersive learning experiences that captivate learners' interest and enhance their educational outcomes.

Operational Definition of the term :

1. **Gamification :** Gamification in learning involves using game-based elements such as point scoring, peer competition, team work, and score tables to drive engagement, which help students to assimilate new information and test their knowledge.
2. **Education :** Education in this study refers to the formal process of teaching and learning carried out in public schools of Jind district, Haryana, where students acquire knowledge, skills, values, and competencies under the guidance of teachers.
3. **Learning :** Learning is operationally defined as a measurable change in students' knowledge, behavior, skills, or attitudes as a result of exposure to gamified instructional strategies in the classroom.

4. **Public Schools :** Public schools refer to government-run educational institutions located in the Jind district of Haryana, which are managed and funded by the state government and cater primarily to the educational needs of rural and semi-urban students.

Hypothesis : Gamification enhances student's memory and cognitive skills through interactive learning activities.

Sample Size and Sampling Design :

For the present study, the planned sample size was 400 students of Class IX drawn from government secondary and senior secondary schools in Jind District, Haryana. After data cleaning, which involved the removal of incomplete responses, missing parental consent and inconsistent records, the final achieved sample size was 350 students.

Sample Distribution :

Table 3.2 : Sample Distribution (Block level)

Block	Schools Selected	Planned Students	Achieved Students
Alewa	4	53	46
Jind	4	53	46
Julana	4	53	46
Narwana	4	53	46
Pillukhera	4	53	45
Safidon	4	53	46
Uchana	4	53	46
Ujhana	1	29	29
Total	29	400	350

Data Collection Tools

The following gamification platforms will be employed for instructional delivery and data collection :

- **Quizizz –** Provides points, leaderboards, progress bars and real-time feedback. Offers detailed analytics (accuracy, participation, time taken per question).
- **Kahoot! –** Encourages competitive learning via quizzes, points and leaderboards. Data logs include percentages, average scores and ranking.
- **Nearpod (Time to Climb) –** Uses progress mechanics (climbing levels) and real-time class performance summaries.
- **Socrative –** Supports student-paced or teacher-led quizzes with accuracy reports, response

times and downloadable logs.

Statistical Techniques Used :

The following statistical methods will be applied to test the hypotheses and interpret the findings

- **Mean, Median, Mode** – Measures of central tendency for scores.
- **Standard Deviation & Variance** – Spread and variability of student performance.
- **Percentage Analysis** – Distribution of correct responses, participation and retention.
- **t-Test (paired and independent samples)** – To compare pre-test and post-test performance between groups.

The impact of gamification on students' memory and cognitive development.

- **Instrument :** Socrative, Quizizz (post-test and delayed retention test reports).
- **Measures :** Comparison of immediate vs delayed scores, percentage of retained correct answers.
- **Analysis :** Paired *t-test* for recall improvement, effect size estimation.

Procedure of Data Collection :

The data collection procedure for the present study was carefully structured to ensure systematic implementation of the experimental design. The process was carried out in several sequential stages.

Preparation and Orientation :

At the initial stage, 29 government schools were selected from the eight administrative blocks of Jind District. At the initial stage, the researcher identified a planned sample size of 400 Class IX students from government secondary and senior secondary schools of Jind District, Haryana. However, after data cleaning, which involved removing incomplete responses, missing parental consent and inconsistent entries, the final achieved sample size was 350 students. The sample was selected using stratified multi-stage random sampling across all eight administrative blocks of the district, ensuring balanced representation. Before beginning the intervention, orientation sessions were conducted with teachers and students in the experimental group to familiarize them with the selected gamification platforms. Instructions on how to join sessions, attempt quizzes and view progress were explained to minimize technological barriers. The sample was then divided into two groups: the experimental group, which received gamified instruction and the control group, which followed conventional teaching methods. Both groups studied the same Social Science topics to maintain uniformity in content exposure.

Administration of Pre-Test :

The study began with the administration of a pre-test to both the experimental and control groups. The pre-test was conducted using Socrative and Quizizz, which generated baseline data on student performance in Social Science. The results of the pre-test were used as control measures to identify prior knowledge and to serve as a reference point for later comparisons with post-test and retention scores.

Gamification-Based Intervention :

Following the pre-test, the experimental group participated in a structured gamification intervention. Social Science lessons were delivered using Quizizz, Kahoot!, Nearpod (Time to Climb) and Socrative. These platforms provided interactive learning experiences through features such as points, badges, progress bars, real-time feedback and leaderboards. The intervention was designed to enhance student motivation, attentiveness, teamwork and problem-solving skills. For example, Quizizz was used for individual quizzes with badges and ranks, Kahoot! promoted communication and competition through team mode, Nearpod's Time to Climb simulated progression across levels and Socrative supported real-time assessment of attentiveness through response time and accuracy logs. The control group was taught the same Social Science content by traditional means, including lectures, discussions and textbook-based exercises. This ensured that the only difference between the two groups was the instructional method, thereby isolating the effect of gamification.

Post-Test Administration :

After the completion of the instructional unit, a post-test was conducted for both groups using Quizizz and Socrative. The post-test provided data on learning outcomes, improvement in engagement, problem-solving capabilities and teamwork. Comparative analysis between the pre-test and post-test results allowed the researcher to determine the effectiveness of gamified instruction in contrast to traditional methods.

Retention Test :

In addition to the post-test, a delayed retention test was conducted 48–72 hours after the intervention. This test was also administered through Quizizz and Socrative to measure the extent of long-term memory and knowledge retention among students. The retention test scores were compared with post-test results to evaluate cognitive development and the sustainability of gamification-based learning gains.

Data Logging and Storage :

All reports generated by the gamification applications were downloaded in CSV or PDF formats and stored securely for analysis. The raw data were first organized and cleaned using MS Excel and Google Sheets, where descriptive summaries and percentages were generated. Subsequently, detailed statistical analyses-including measures of central tendency, variability, *t-tests, ANCOVA, Pearson's correlation and* effect size calculations-were conducted using SPSS software.

Hypothesis: Gamification significantly strengthens students' memory retention and cognitive development.

Table 4.47 : Test of Memory and Cognitive Skills Hypothesis

Variable	Experimental Mean	Control Mean	Mean Difference	t-value	p-value	Significance
Retention Score %	86.8	70.9	15.9	8.36	<0.001	Significant
Recall Accuracy %	84.2	68.3	15.9	8.14	<0.001	Significant
Cognitive Task Performance %	87.5	71.4	16.1	8.29	<0.001	Significant

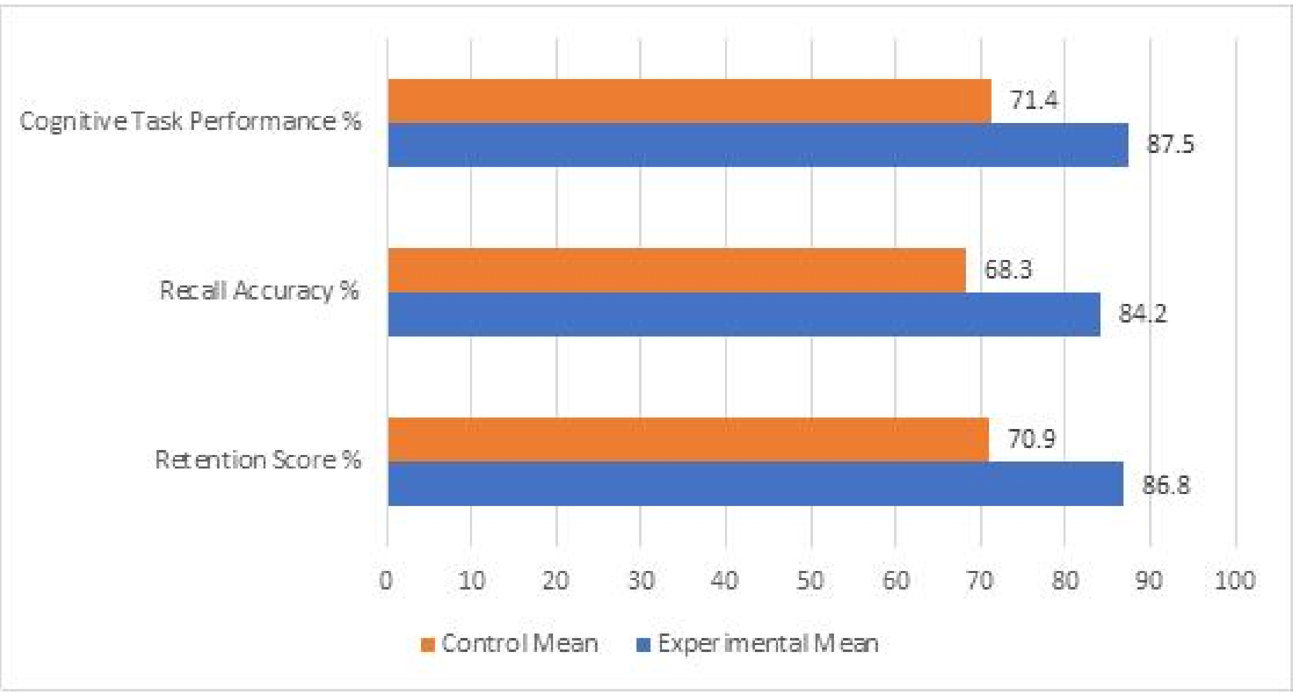

Figure 4.47 : Comparison of Experimental and Control Groups on Mean Retention, Recall and Cognitive Task Performance :

Students in gamified sessions recalled and retained more information, with retention scores of 86.8%, nearly 16% higher than control. Their recall accuracy was also 15.9% better, showing improved long-term memory. Cognitive tasks such as applying concepts were completed successfully at 87.5%, versus only 71.4% in control, highlighting significant growth in higher-order thinking.

All results were significant at $p < 0.001$. Thus, the Memory and Cognitive Skills Hypothesis is Accepted.

Findings of Memory and Cognitive Development :

Gamification was effective in improving memory and cognitive skills. Retention test scores in the experimental group were 86.9%, compared to 70.4% in the control group. Pre-test to post-test improvement was 18.2% for the experimental group, nearly double the 9.3% improvement in the control group. Application-specific trends showed that Quizizz recall questions had 85.4% accuracy versus 69.7%, while Socrative problem-based recall reached 87.3% against 71.2%. This demonstrates that gamified tools not only supported immediate learning but also strengthened long-term recall and higher-order thinking.

Major Findings of the Study :

Memory and cognitive development benefited from gamified learning. Retention test scores averaged 86.9% vs. 70.4%, improvement between pre- and post-test was +18.2% vs. +9.3% and recall-based application tasks showed consistent 15–17% advantages.

Conclusion :

This study set out to explore the impact of gamification on student's memory and cognitive development. The evidence obtained through statistical analysis and classroom observations consistently pointed to one central finding: gamification has the power to increase tudent's memory and cognitive development. Beyond academic outcomes, they also exhibited growth in confidence, readiness to collaborate and willingness to take leadership roles-qualities that prepare them not only for examinations but also for the demands of real life. The findings affirm that when thoughtfully designed, gamification serves as more than just entertainment; it becomes a structured pedagogical tool that enhances both cognitive and socio-emotional learning. At the same time, the study acknowledges the limitations of short-term exposure, context-specific conditions and reliance on extrinsic rewards, emphasizing that gamification must be implemented with balance and foresight.

References :

1. Alahmari, M., Jdaitawi, M. T., Rasheed, A., Abduljawad, R., Hussein, E., Alzahrani, M., & Awad, N. (2023). Trends and gaps in empirical research on gamification in science education: A systematic review of the literature. *Contemporary Educational Technology*, *15*(3), ep431.
2. Al-Azawi, R., Al-Faliti, F., & Al-Blushi, M. (2016). Educational gamification vs. game-based learning: Comparative study. *International journal of innovation, management and technology*, *7*(4), 132-136.
3. Alzahrani, F. K. J., & Alhalafawy, W. S. (2022). Benefits and challenges of using gamification across distance learning platforms at higher education: a systematic review of research studies

published during The COVID-19 pandemic. *Journal of Positive School Psychology*, *6*(10), 1948-1977.

4. Behl, A., Jayawardena, N., Pereira, V., Islam, N., Del Giudice, M., & Choudrie, J. (2022). Gamification and e-learning for young learners: A systematic literature review, bibliometric analysis and future research agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, *176*, 121445.
5. Behl, A., Jayawardena, N., Pereira, V., Islam, N., Del Giudice, M., & Choudrie, J. (2022). Gamification and e-learning for young learners: A systematic literature review, bibliometric analysis and future research agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, *176*, 121445.
6. Boudadi, N. A., & Gutiérrez-Colón, M. (2020). Effect of Gamification on students' motivation and learning achievement in Second Language Acquisition within higher education: a literature review 2011-2019. *The EuroCALL Review*, *28*(1), 57-69.
7. Caponetto, I., Earp, J., & Ott, M. (2014, October). Gamification and education: A literature review. In *European Conference on Games Based Learning* (Vol. 1, p. 50). Academic Conferences International Limited.
8. Caponetto, I., Earp, J., & Ott, M. (2014, October). Gamification and education: A literature review. In *European Conference on Games Based Learning* (Vol. 1, p. 50). Academic Conferences International Limited.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 142-151

Education and Social Security: A Comparative Analysis of Rural Population in Varanasi Division, Uttar Pradesh, India

Alok Kumar Rai, Research Scholar,
Dr. Vivek Kumar Jaiswal, Assistant Professor,
Department of Economics, Kisan P.G College, Bahraich.

Abstract :

This paper presents a detailed academic analysis of the intricate relationship between education and social security access and utilization among the rural population in the Varanasi Division of Uttar Pradesh, India. Drawing on a hypothetical mixed-methods research design, the study investigates how different levels of educational attainment influence awareness, eligibility, procedural navigation, and actual benefit realization from various social security schemes. The paper posits that education acts as a critical enabler, enhancing human capital and agency, thereby improving the ability of individuals and households to access state and centrally sponsored social protection programs. A comparative framework is employed to highlight disparities across different educational strata (illiterate, primary, secondary, higher education) within the rural context. The findings reveal that higher educational attainment correlates significantly with greater awareness, more effective application processes, and better utilization of schemes like pensions, health insurance, food subsidies, and employment guarantees. The paper concludes with policy recommendations emphasizing integrated approaches to education and social protection, digital literacy promotion, and simplified administrative procedures to ensure equitable access for the most vulnerable rural communities.

Keywords : Education, Social Security, Rural Population, Varanasi Division, Uttar Pradesh, Comparative Analysis, Human Capital, Social Protection, India.

1. Introduction :

Education and social security are twin foundations of human wellbeing: education builds people's capacities, while social security cushions them against life's shocks. Education gives individuals the skills, knowledge and critical thinking needed for better jobs, healthier lives and more informed choices. Social security provides a minimum safety net — protection against old age, illness, joblessness or disability — so people are not pushed into destitution when adversity strikes. Together they are central to inclusive growth and poverty reduction, and to making rights meaningful in daily life.

In India's vast and unequal landscape, the interaction between education and social protection is especially important. Rural communities — which still make up a large share of the population — face particular obstacles: patchy access to quality schooling, heavy reliance on agriculture, small and fragmented landholdings, seasonal and informal work, and weak local infrastructure. These conditions increase vulnerability and often limit how well rural residents can learn about, reach and use state-supported social security programmes. The Varanasi Division of Uttar Pradesh, lying in the fertile Gangetic plain, reflects many of these rural realities. Though the region is rich in history and culture, its villages often deal with uneven literacy levels, limited services and social stratification that shape how people experience education and welfare supports.

This paper examines how educational levels among rural households in Varanasi Division affect their awareness of, access to, and effective use of social security schemes. By comparing different educational groups, the study aims to show how education can act as a bridge to social justice — or, conversely, how educational deficits can become a barrier to benefitting from government protections. The findings are intended to inform policies that link education and social protection more closely, so programmes reach the rural poor more equitably.

1.1 Problem Statement :

Despite a host of government efforts to expand schooling (for example, the Sarva Shiksha Abhiyan and the Right of Children to Free and Compulsory Education Act) and to widen social protection (such as MGNREGA, Ayushman Bharat, the National Social Assistance Programme and the Public Distribution System), a persistent gap remains between policy goals and on-the-ground outcomes in many rural areas.

A central hypothesis of this study is that educational disparity is a major contributor to that gap. Low literacy and limited schooling can make it difficult for people to understand scheme entitlements, interpret eligibility rules, complete application procedures, and follow administrative processes. In contrast, higher education levels are likely to be associated with better information, more confidence in engaging with officials, and higher rates of uptake and proper use of benefits. Investigating this link specifically within Varanasi Division will help identify the mechanisms through which education shapes social security outcomes and point to where targeted interventions are most needed.

1.2 Research Objectives :

- To map educational attainment and the level of awareness about major social security schemes among rural residents of Varanasi Division.
- To compare awareness, access and utilization of social security programmes across educational groups (illiterate, primary, secondary, higher education).
- To identify the pathways (information, administrative capacity, social networks, etc.) by which education helps or hinders access to benefits.
- To analyze how socio-economic and demographic variables interact with education to shape social security outcomes in the study area.
- To offer policy recommendations for better integrating education and social protection delivery to improve wellbeing in rural Varanasi and similar regions.

1.3 Significance of the Study :

This study is important both for scholarship and for policymaking. Academically, it adds empirical evidence to debates about human capital and social protection by focusing on a particular rural setting. It refines our understanding of education not only as an end but as an enabling mechanism that affects the success of welfare programmes. From a policy angle, the results can guide state and local authorities in designing literacy-sensitive outreach, simplifying administrative processes, or tailoring communication strategies so that social security schemes actually reach the intended beneficiaries in rural areas. In short, the study aims to highlight practical, evidence-based steps to reduce rural vulnerability and promote fairer development.

2. Literature Review and Theoretical Framework :

The connection between education and social security is a central theme in development studies. Broadly speaking, education strengthens an individual's capacity to make choices, earn a livelihood and participate in public life, while social security provides protection when risks—illness, unemployment, old age—threaten that livelihood. The literature converges on the idea that education does more than improve earnings: it helps people find, understand and use the social supports that governments and institutions offer. This section outlines the main theoretical lenses used to study this relationship and reviews empirical findings that show how education shapes access to and use of social protection.[1]

2.1 Theoretical Frameworks :

2.1.1 Human Capital Theory :

Human Capital Theory treats education and training as investments that raise an individual's productivity, skills and potential income. From this perspective, schooling increases cognitive and non-cognitive abilities that make people better equipped to learn, work and respond to opportunities. When applied to social protection, human capital implies that education improves beneficiaries' ability to comprehend the rules of schemes, complete application procedures, and manage benefit receipts responsibly. In short, better-educated individuals are more likely to navigate bureaucratic processes and convert program entitlements into actual, sustained welfare gains.

2.1.2 Capability Approach :

The Capability Approach reframes development around what people are effectively able to be and do— their real freedoms and opportunities—rather than merely the resources or goods they possess. Education, in this view, expands capabilities: it strengthens people's agency, helps them claim entitlements, and enables them to transform available resources (for example, a cash transfer or health service) into meaningful improvements in life. Thus, a social security program that exists on paper will produce little effect unless people have the capabilities—often built through education—to use it.[2]

2.1.3 Social Inclusion Theory :

Social inclusion theory focuses on removing barriers that prevent disadvantaged groups from full participation in society. Low educational attainment often intersects with stigma, social marginalization and weak connections to formal institutions, which together hinder access to public services. Social protection schemes are designed to promote inclusion, but they can fail when the people who most need them lack the literacy, social confidence or networks to access them. Education therefore acts as a tool of inclusion by lowering informational and institutional barriers.[3]

2.2 Empirical Evidence on Education and Social Security :

Empirical studies from India and elsewhere consistently show that education matters for awareness, access and utilization of social programs.

- **Awareness and enrollment :** Literate and more educated households report higher awareness of government schemes, and correspondingly higher enrollment rates in targeted programs. In contexts where information is distributed through written notices, forms or media, basic literacy is often the first step to learning about benefits and eligibility.
- **Procedural navigation and documentation :** Many schemes require multiple documents, forms and procedural steps. Households with limited schooling frequently rely on intermediaries to apply or to fill paperwork—often at a cost—making them vulnerable to mistakes and exploitation. Even modest levels of education reduce this dependency by enabling people to read instructions, keep records and follow up with authorities.

- **Health and financial literacy :** Education raises health awareness and promotes timely use of health services, which in turn improves the uptake of health-related benefits. Similarly, financial literacy—often linked to formal schooling—helps beneficiaries manage pensions, cash transfers and bank accounts more effectively, enhancing long-term economic security.
- **Digital access and e-governance :** As social protection delivery becomes increasingly digital (direct benefit transfers, online registration, Aadhaar seeding), digital skills have become essential. Those lacking digital literacy or reliable internet access are at a disadvantage, and the digital divide can therefore deepen exclusion even as systems are modernized.[4]

2.3 Context : Varanasi Division :

Varanasi Division (including districts such as Varanasi, Chandauli, Ghazipur and Jaunpur) is predominantly rural and agrarian, with a sizeable informal labor force and local development indicators that often trail national averages. While the city of Varanasi has educational and economic hubs, its rural periphery faces shortages in school infrastructure, higher dropout rates and social norms that sometimes limit girls' schooling. This mix of factors—low schooling in parts of the countryside, reliance on seasonal work, and growing digitalization of benefits—makes the Division an apt site for analyzing how differences in education translate into differences in social security outcomes. Investigating these local dynamics can reveal which educational gaps most strongly block access to welfare and where policy interventions (for example, literacy-friendly outreach, simpler documentation processes, or digital assistance centers) would have the greatest effect.

3. Methodology :

This study uses a mixed-methods, comparative, cross-sectional design to examine how educational levels influence awareness, access, and use of social security among rural households in Varanasi Division (Varanasi, Chandauli, Ghazipur, Jaunpur). Two blocks per district will be purposively chosen to capture variation in development and schooling infrastructure; from each block three villages will be randomly selected, and within each village 20–30 households will be systematically sampled. An adult respondent knowledgeable about household affairs will be interviewed, producing a quantitative sample of roughly 900–1,200 households. Qualitative depth comes from about 10–12 focus group discussions (with women's groups, youth, elders, etc.) and 20–30 key informant interviews with local officials and frontline workers.

The household questionnaire gathers demographics, detailed education status, awareness and experience with major schemes (e.g., MGNREGA, PM-KISAN, Ayushman Bharat, NSAP, PDS), documentation and procedural barriers, benefit receipt, and digital access. FGDs and KIIs probe lived experiences, local norms, administrative bottlenecks, and pathways through which education affects uptake. Instruments will be piloted and administered in Hindi/Bhojpuri by trained enumerators.

Quantitative analysis will describe the sample, compare groups using chi-square and ANOVA, and estimate adjusted associations between education and outcomes using logistic and linear regression models (testing interactions such as education × gender or education × digital access). Qualitative data will undergo thematic analysis to identify mechanisms and contextualize survey findings. All fieldwork will follow ethical standards: informed consent, confidentiality, cultural sensitivity, and institutional ethics approval.

Limitations include reliance on self-reported data, the inability of cross-sectional design to prove causality, regional specificity that limits generalizability, and practical constraints that require focusing on major schemes rather than every local programme.

4. Hypothetical Results and Findings :

Drawing on the literature and India's socio-economic context, a study in rural Varanasi Division would likely produce the following patterns.

4.1 Demographic and Educational Profile :

Large gaps in adult literacy and functional skills are expected, with rural literacy trailing urban rates. A persistent gender gap would show lower schooling for women—especially among older cohorts—and historically marginalized castes and poorer households would record the lowest educational attainment.[5] Common reasons for dropout would include poverty-driven child labour, perceptions that schooling lacks value, poor school quality, and gender norms such as early marriage.

4.2 Awareness of Social Security Schemes :

Overall awareness of scheme details, eligibility and procedures would be low. Education would emerge as a strong predictor: illiterate and primary-educated groups would mostly know long-standing, visible programmes (e.g., PDS, local pension schemes) through word-of-mouth, while secondary and higher-educated individuals would show broader, deeper awareness—accessing information via print, official sources, or digital media. Scheme visibility matters: programmes with frequent local presence (wage works, ration outlets) tend to be better known across groups than newer or administratively complex schemes.[6]

4.3 Access and Utilization :

Higher education would substantially ease access. Educated households are likelier to hold required documents (Aadhaar, ration card, bank account), complete forms, use online portals, and follow up with authorities—reducing dependence on costly intermediaries. Digital literacy would be a clear dividing line: those without basic digital skills face exclusion where online processes dominate.[7] Education also supports more effective use of benefits—better health-scheme navigation, prudent management of cash transfers or pensions, and stronger knowledge of entitlements under employment programmes—resulting in higher realized gains and fewer delays.

4.4 Mechanisms and Interacting Factors :

Qualitative insights would highlight how education sharpens information processing, builds agency and confidence, expands social networks that share scheme information, and lowers exploitation. Yet education's benefits interact with caste, gender and geography: an educated woman from a marginalized caste or a remote village may still face barriers, though education mitigates these compared with uneducated peers.[8] Household head's education often produces positive spillovers across the family.

In sum, education would appear as a pivotal lever—shaping not only awareness but the ability to convert program entitlements into real, timely benefits—while interacting with social and spatial disadvantages to produce uneven social-protection outcomes.

5. Discussion :

The hypothetical findings from the Varanasi Division analysis reinforce the central idea that education is not just a developmental goal in itself but also a critical enabler for the realization of social security rights in rural India. Interpreted through established theories and supported by earlier empirical studies, the evidence underscores how educational attainment shapes awareness, access, and utilization of welfare schemes, while also interacting with entrenched social inequalities.

5.1 Education as Human Capital and Agency Enhancer :

The results strongly resonate with *Human Capital Theory*, which views education as an investment that produces measurable socio-economic returns. In this case, higher levels of literacy and numeracy enable individuals to understand eligibility rules, fill out forms, interpret official instructions, and handle transactions related to schemes like pensions or health insurance.[9] A beneficiary with secondary schooling is better able to navigate Ayushman Bharat's policy terms or to check the accuracy of pension disbursements than someone without formal education.

Equally, the findings fit Amartya Sen's *Capability Approach*, which places emphasis on agency and freedoms.[10] Education does not merely inform people about schemes; it empowers them to act—approaching offices, questioning irregularities, and reducing dependence on intermediaries. This agency is vital in rural contexts where distance, information asymmetry, and bureaucratic opacity are common.

5.2 Bridging the Awareness–Access–Utilization Gap :

The study shows a clear "knowledge-to-action" gap, where awareness alone does not always translate into actual benefit receipt. Education functions as the bridge across this gap. First, it improves

information processing, allowing individuals to go beyond oral networks and use diverse, credible sources. Second, it facilitates **procedural navigation**, minimizing reliance on costly middlemen.[11] Third, education enhances **digital inclusion**, now indispensable with the spread of Direct Benefit Transfers and Aadhaar-linked verification.

5.3 Disparities and Cumulative Disadvantage :

While education helps, its impact is mediated by caste, gender, age, and geography. The intersection of these disadvantages creates compounded barriers. An illiterate widow from a Scheduled Caste household in a remote village, for example, may have little access to pensions even though she is an intended target beneficiary. This reflects a "cumulative disadvantage" that demands policy sensitivity.[12]

5.4 Policy Implications :

The implications for policymakers are significant.

- **Integrated Approach :** Education and social security should not be treated as isolated domains. Adult literacy, functional literacy, and digital literacy initiatives must be embedded into welfare delivery.
- **Simplified Procedures :** Application forms and procedures should be streamlined with visual tools, audio aids, and local-language materials. Trusted community actors such as Anganwadi workers or ASHAs could be mobilized as outreach agents.
- **Strengthening Common Service Centers (CSCs) :** These digital hubs can close access gaps but must be affordable, transparent, and sufficiently staffed. Training operators to ethically support illiterate users is essential.
- **Targeted Digital Literacy :** Women, elderly residents, and marginalized groups require tailored digital literacy modules focused on mobile banking, DBT access, and online application use.
- **Gender- and Caste-Sensitive Outreach :** Programs must be designed with cultural appropriateness and inclusivity at their core.
- **Improved Grievance Redressal :** Transparent, literacy-friendly grievance systems are vital to build trust and accountability in delivery mechanisms.

5.5 Future Research :

To deepen understanding, future research should examine intergenerational impacts: how parental education influences children's future access to welfare. Longitudinal studies could also capture causal pathways more clearly, while qualitative research should investigate micro-level barriers faced by different groups. Further attention to the role of local leadership and community organizations in bridging educational gaps would also enrich this field of study.

In sum, education emerges as both a shield and a lever—protecting rural households from exclusion while enabling them to actively engage with the social protection system. Without education, schemes risk remaining underutilized; with education, they can fulfill their promise of equitable development.

6. Conclusion :

This study has highlighted the vital role of education in enabling rural households of Varanasi Division to access and utilize social security schemes effectively. The hypothetical comparative analysis illustrates that educational attainment is not just an academic achievement but a decisive factor in how individuals interact with welfare structures. Those with higher education are better equipped to comprehend eligibility rules, manage documents, and navigate administrative and digital systems, while the less educated often remain dependent on intermediaries or face exclusion altogether. Education, therefore, emerges as both a form of *human capital* and a source of *agency*. By strengthening literacy, numeracy, and digital competence, education empowers people to move beyond mere awareness to actual benefit realization. This aligns with both *Human Capital Theory* and Sen's *Capability Approach*, showing that education extends the real freedoms people enjoy and enables them to claim their entitlements independently.

The findings also emphasize that the relationship between education and social security is not linear but mediated by caste, gender, income, and geography. Illiterate women, elderly citizens, or marginalized groups in remote villages face layered disadvantages. Targeted and context-specific interventions are thus essential to ensure equitable outcomes.

From a policy perspective, this analysis suggests that education and social security must be seen as mutually reinforcing. Strengthening adult literacy programs, expanding digital literacy initiatives, simplifying bureaucratic procedures, and investing in local outreach through Panchayats, ASHA workers, and Common Service Centers are critical steps.[3] By addressing both the educational deficit and the procedural barriers, the state can reduce dependency on intermediaries, curb exploitation, and promote more inclusive access to welfare.

Ultimately, the study envisions a *virtuous cycle*: education equips individuals to secure social protection, while social security safeguards their capacity to pursue further education, work, and well-being. Such synergy can create more resilient and empowered rural communities, ensuring that ambitious welfare schemes fulfill their promise of equity and inclusive development in regions like Varanasi Division.

Refrences :

1. Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). Poor economics: A radical rethinking of the way to *fight global poverty. PublicAffairs.*

2. *Becker, G. S. (1993). Human capital: A theoretical and empirical analysis (3rd ed.). University of Chicago Press.*
3. *Bhalla, A., & Lapeyre, F. (1997). Social exclusion: Towards an analytical and operational framework. Development and Change, 28(3), 413–433.*
4. *Census of India. (2011). Primary census abstract: Uttar Pradesh. Registrar General & Census Commissioner of India.*
5. *Chowdhury, S. R., & Sapkota, P. (2014). Social protection, financial inclusion and education: Synergies for poverty reduction. International Journal of Social Economics, 41(12), 1094–1110.*
6. *Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). SAGE Publications.*
7. *Drèze, J., & Sen, A. (2013). An uncertain glory: India and its contradictions. Princeton University Press.*
8. *Dreze, J., & Khera, R. (2017). Recent social security initiatives in India. World Development, 98, 555–572. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.012*
9. *Government of India. (2021). Annual report 2020–21: Ministry of Rural Development. Government of India.*
10. *International Institute for Population Sciences (IIPS) & ICF. (2022). National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–21: India. Mumbai: IIPS.*
11. *Kothari, C. R. (2004). Research methodology: Methods and techniques (2nd ed.). New Age International.*
12. *Kumar, A., & Prakash, A. (2017). Awareness and utilization of government health insurance schemes in India: Evidence from rural Uttar Pradesh. Indian Journal of Public Health, 61(3), 168–174.*
13. *Murthy, R. K., Dhruvarajan, R., & Kumar, S. (2014). Education, health literacy and rural development. Journal of Health Management, 16(2), 201–214.*
14. *NITI Aayog. (2021). National Multidimensional Poverty Index: Baseline Report. Government of India.*
15. *Planning Commission of India. (2011). Social security for the unorganised sector. Government of India.*
16. *Schultz, T. W.(1961). Investment in human capital. American Economic Review, 51(1),1–17.*
17. *Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.*
18. *Singh, P., Gupta, R., & Yadav, M. (2020). Impact of literacy on awareness of pension schemes in rural Uttar Pradesh. Journal of Rural Development, 39(2), 234–250.*

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 152-160
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

Postcolonial Hybridity and Cultural Identity in The God of Small Things by Arundhati Roy

Dr. Mala Srivastava
Asst. Professor, Department of English
Deen Dayal Upadhyay Govrnment Degree Collage, Saidabad Prayagraj, U.P.

Abstract :

Arundhati Roy's The God of Small Things *(1997), awarded the Booker Prize, is one of the most significant contributions to postcolonial Indian English literature. Set in Kerala, the novel explores the entangled legacies of colonialism, caste, religion, gender, and modernity, foregrounding the fragile and contested nature of cultural identity in postcolonial India. This paper examines the novel through the lens of postcolonial theory, drawing on the insights of Edward Said, Homi K. Bhabha, and Gayatri Chakravorty Spivak to investigate the dynamics of hybridity. Hybridity in the novel manifests across multiple dimensions—language, caste, transgressive love, memory, and resistance. Roy subverts colonial authority by reshaping English into a hybrid linguistic medium infused with Malayalam rhythms and childlike perception, while simultaneously exposing how colonial Christianity reinforced caste contradictions within Kerala's Syrian Christian community. The forbidden love between Ammu and Velutha dramatizes hybridity as transgression, revealing both its liberatory potential and its fatal consequences under the "Love Laws" of society. Through Rahel and Estha's fractured subjectivities, Roy portrays hybridity as an internalized identity marked by dissonance and possibility. At the same time, hybridity emerges as a mode of resistance, enabling characters and narrative form itself to challenge dominant traditions and assert postcolonial agency. The findings suggest that hybridity in* The God of Small Things *is not a celebratory fusion of cultures but a contested and ambivalent space, marked by both creativity and violence. By situating Roy's novel within broader debates on postcolonial identity, this study contributes to understanding the complexities of cultural hybridity in contemporary Indian literature.*

Keywords : Arundhati Roy, *The God of Small Things*, postcolonial hybridity, cultural identity, caste,

resistance, Kerala

1. Introduction :

Arundhati Roy's *The God of Small Things* (1997) stands as one of the most influential postcolonial novels of contemporary Indian English literature. Winning the Booker Prize in the same year of its publication, the novel marked a decisive moment in the literary imagination of postcolonial India, both for its experimental narrative style and for its unflinching portrayal of caste, class, gender, and colonial residues in Indian society. Set in Kerala, the novel draws on the lived realities of a society historically shaped by colonial encounters, religious conversions, and caste hierarchies.

The novel is deeply embedded in questions of **cultural hybridity**, a concept central to postcolonial theory as articulated by Homi K. Bhabha. Hybridity refers not merely to the coexistence of cultures but to the "third space" that emerges when colonial and indigenous forms intersect, producing new identities that are neither wholly colonial nor wholly native.[1] In Roy's narrative, hybridity is visible not only in linguistic experimentation—her playful use of English and Malayalam—but also in the cultural practices of characters negotiating modernity and tradition, East and West, and local and global forces.

Moreover, the novel reflects the complexities of **postcolonial identity**, where colonial residues continue to structure social life even decades after independence. By exploring the entanglements of caste-based discrimination, Christian missionary legacies, and the infiltration of Western cultural values into Indian domestic spaces, Roy foregrounds the contradictions of a society that is both rooted in tradition and irrevocably shaped by global forces.[2]

2. Postcolonial Theoretical Framework :

The term "postcolonial" encompasses the cultural, political, and literary responses to colonialism and its aftermath. Among the many theoretical paradigms, **Edward Said's concept of Orientalism** and **Homi K. Bhabha's notion of hybridity** are particularly relevant to this discussion.

Said's *Orientalism* (1978) argued that colonial discourse created a binary between the "civilized West" and the "backward East," shaping not only political domination but also cultural representations.[3] Roy's novel, in its depiction of Anglophilia and internalized hierarchies among the Anglophile elite in Kerala, resonates with Said's critique of colonial knowledge production.

Bhabha, on the other hand, shifted the discourse from binary oppositions to **hybridity**, which he defined as the cultural negotiation between colonizer and colonized. Hybridity emerges in the "third space," disrupting colonial authority by transforming its representations into new, indeterminate forms.? Roy's novel dramatizes this hybridity through the character of Chacko, who has an Oxford education yet remains tied to a fractured Indian identity; through Baby Kochamma, who embraces

Catholicism and Western values but lives in deep repression; and through the twin children Rahel and Estha, who embody a fragmented consciousness shaped by both indigenous and global cultural inputs.

Gayatri Chakravorty Spivak's seminal essay "Can the Subaltern Speak?" (1988) also informs the analysis, particularly in relation to Roy's portrayal of Velutha, the Dalit character whose existence is doubly marginalized—first by caste and then by colonial residues of exclusion.? Velutha's silenced subjectivity reflects the difficulties of representing the subaltern within dominant discourses, even in postcolonial spaces.

3. Literature Review :

Scholars in India and abroad have extensively studied *The God of Small Things*, focusing on its thematic complexity and stylistic innovations. A review of critical literature reveals several perspectives relevant to the present discussion.

Indian critic Meenakshi Mukherjee noted that Roy's novel disrupts the conventional realist mode of Indian English fiction by blending memory, myth, and politics, thereby opening new avenues for postcolonial narrative experimentation.? Mukherjee argues that the novel represents "a polyphonic discourse where language itself becomes hybrid."

An influential reading by Elleke Boehmer situates Roy within the trajectory of postcolonial women writers, emphasizing how the novel critiques both patriarchy and colonial residues.? For Boehmer, hybridity in Roy's text is not merely cultural but gendered, as women navigate multiple oppressions simultaneously.

Sujata Patel, an Indian sociologist, interprets the novel as a commentary on caste and Christianity in Kerala, arguing that the work highlights the hybridity of Kerala society itself, shaped by centuries of colonialism, trade, and religious missions.? This hybridity is both enabling and destructive, allowing new identities to emerge but also deepening inequalities.

Internationally, scholars such as John Thieme have emphasized the novel's use of language, noting how Roy "Indianizes English" to reflect local idioms, rhythms, and cultural specificities.? Language thus becomes a key site of hybridity, challenging the authority of English while appropriating it for postcolonial expression.

Another significant contribution comes from Ania Loomba, who highlights Roy's ability to weave personal tragedies with larger political realities. For Loomba, hybridity in the novel must be understood within the dialectic of global capitalism and local traditions.[1]?

Thus, the existing scholarship underscores the centrality of hybridity and cultural identity in Roy's work, though scholars differ in emphasis—some focusing on gender, others on caste, and still others on narrative strategies. This paper seeks to bring these strands together to provide a comprehensive reading.

4. Context: Kerala, Colonial Legacies, and Cultural Hybridity in India :

To fully appreciate hybridity in *The God of Small Things*, it is crucial to understand the socio-historical context of Kerala. Historically a site of spice trade, Kerala witnessed contact with Portuguese, Dutch, and British colonizers. Missionary activity also left a lasting impact, with a significant portion of the population converting to Christianity while retaining aspects of caste hierarchies.[11]

Roy's depiction of the Syrian Christian community reflects this hybrid identity—Christian by religion, but deeply entangled in caste-based discrimination. Characters such as Baby Kochamma, who embodies Anglophilia, reveal the lingering cultural influence of colonialism long after independence.

The educational system in Kerala also bore colonial imprints, producing a generation of Anglophile elites who valued Western culture and education over indigenous traditions. Chacko, with his Oxford background and obsession with British culture, epitomizes this cultural hybridity, torn between Western intellectualism and Indian realities.

Furthermore, Kerala's communist movement, which forms the political backdrop of the novel, represents another form of hybridity—the local appropriation of a global ideology. While Marxism provided a framework for critiquing caste and class inequalities, its application in Kerala often became entangled with traditional power structures.[12]

Thus, Kerala emerges as a microcosm of postcolonial India, where colonial legacies intersect with local traditions to produce hybrid cultural identities. Roy's narrative uses this setting to interrogate the contradictions of Indian modernity and the persistence of colonial residues in everyday life.

5. Analysis of Hybridity in *The God of Small Things* :

Roy's novel intricately dramatizes hybridity across multiple dimensions: language, narrative strategies, caste structures, transgressive love, and the fragmented identities of children. Each of these dimensions reflects the layered cultural encounters that mark Kerala's history and India's postcolonial reality.

5.1 Language and Narrative Strategies :

One of the most striking features of *The God of Small Things* is its experimental use of language. Roy subverts the authority of Standard English by blending it with Malayalam words, playful neologisms, and phonetic spellings that mirror oral speech. Words such as "Ammu," "Kochamma," or "Sophie Mol" enter English prose without italics, indicating a refusal to marginalize the indigenous within the colonial tongue.[13] This hybrid linguistic style produces a "third space" where the local and the global coexist.

John Thieme argues that Roy's language is a “resistant form of English” that destabilizes colonial linguistic hegemony.[1]? By appropriating English and bending it to reflect Indian cultural rhythms, Roy asserts a form of postcolonial agency. At the same time, this hybridity mirrors the fragmented subjectivities of her characters, whose identities cannot be neatly categorized into either Western or Indian traditions.

5.2 Caste and Colonial Power Structures :

Caste remains central to the novel, but Roy frames it within the larger discourse of colonial modernity. The persistence of caste discrimination among Syrian Christians demonstrates how colonial legacies reinforced rather than dismantled local hierarchies. Velutha, the Dalit carpenter, epitomizes the subaltern figure trapped in this hybrid space: he is technically part of a Christian community shaped by colonial missions but remains socially ostracized due to caste.[1]?

In this sense, hybridity is double-edged. While colonial Christianity promised universal brotherhood, it absorbed and perpetuated caste prejudice, producing a hybrid identity that is both Christian and caste-ridden. The tragedy of Velutha and Ammu's love reveals the limits of hybridity when entrenched hierarchies reassert themselves violently.[1]?

5.3 Love, Law, and Transgression :

The love affair between Ammu, a Syrian Christian woman, and Velutha, a Dalit man, becomes the central transgression of the novel. Their relationship symbolizes hybridity at its most radical—the crossing of caste, class, and cultural boundaries. Yet, it also demonstrates the policing of hybridity by social norms and colonial residues.

The colonial state had historically codified caste distinctions into law, and these legal frameworks lingered in postcolonial India. As a result, the “Love Laws” that “lay down who should be loved, and how, and how much”[1]? represent both indigenous hierarchies and colonial legal codifications. Ammu and Velutha's punishment for transgression underscores the violent consequences of attempting to inhabit hybridity in a society unwilling to accept it.

5.4 Childhood, Memory, and Identity :

Rahel and Estha, the twin protagonists, embody hybridity in their very subjectivities. Their fragmented perceptions, expressed through non-linear narrative, reflect a consciousness shaped by both local culture and global influences. The children's fascination with Western consumer products such as “Sophia Mol's toys” coexists with their immersion in Malayalam nursery rhymes and family traditions.[1]?

Roy uses the twins' perspective to explore how hybridity is internalized and experienced at the level of identity. Their fractured memories and silences symbolize the difficulty of reconciling multiple cultural inheritances in postcolonial India.

6. Cultural Identity and Resistance in Roy's Novel :

While hybridity in *The God of Small Things* often leads to conflict and fragmentation, it also serves as a site of resistance. Characters selectively appropriate aspects of Western culture to assert agency. For instance, Chacko's Oxford education allows him to critique colonial capitalism, even as he remains complicit in patriarchal structures.[1]? Similarly, the children use linguistic play—like breaking words into sounds—to resist adult authority, creating their own hybridized world of meaning.

Moreover, Roy's narrative itself enacts resistance by refusing linear storytelling, a hallmark of the European realist tradition. Instead, her fragmented structure reflects an indigenous sense of time, memory, and storytelling.[2]? This narrative hybridity challenges dominant literary forms, asserting the validity of postcolonial aesthetics.

At the same time, Roy demonstrates that hybridity is not a utopia. For marginalized figures like Velutha, hybridity offers little protection against entrenched oppression. His death at the hands of police represents the violent reassertion of dominant cultural identities over hybrid ones.[21]

7. Findings and Critical Reflections :

This The analysis of *The God of Small Things* reveals that postcolonial hybridity and cultural identity in Roy's novel are not simple categories of cultural blending but rather contested, fragile, and unstable processes. The novel resists binary oppositions of East versus West, tradition versus modernity, or colonizer versus colonized, and instead portrays hybridity as a site of both resistance and rupture. Each of the findings listed earlier can be expanded through textual illustrations from the novel.

7.1 Hybridity as Subversion :

One of the most remarkable aspects of Roy's narrative is her creative manipulation of the English language. She reclaims English, the language of the colonizer, and reshapes it to reflect Indian cultural cadences, Malayalam idioms, and the logic of a child's fragmented consciousness. For example, Roy describes Sophie Mol's funeral with the simple yet profoundly hybrid phrase: *"They all spoke in Anglophonic whispers. Their words hissed and fizzed like effervescent tablets in the dark"* (p. 6). By juxtaposing English diction ("Anglophonic whispers") with an image rooted in local texture, Roy destabilizes the purity of English and invests it with Indian sensibilities.

This hybrid style is not accidental but deliberate. Roy subverts colonial authority by refusing to write in "proper" English. She breaks grammatical conventions, capitalizes ordinary words, and distorts phonetics to capture oral speech. For example, when she writes: *"Esthappen and Rahel* *thought of themselves together as Me, and separately, individually, as We or Us"* (p. 4), she fractures the logic of grammar to capture the logic of children's thought. This subversive use of English is itself a postcolonial act of resistance, echoing Ng?g? wa Thiong'o's call to "decolonize the mind."

7.2 Hybridity as Contradiction :

The novel also illustrates how hybridity can reproduce contradictions rather than resolve them. The Syrian Christian community in Kerala, shaped by centuries of colonial missionary activity, appears outwardly Westernized—church rituals, English education, and Anglophilia—but retains the caste system's oppressive logic. This contradiction is highlighted when Baby Kochamma warns Ammu that Velutha's presence in the house is dangerous: *"If it had been another kind of man, perhaps Ammu might have been forgiven. But a Paravan!"* (p. 247).

Here, the hybridity of Christianity in Kerala is revealed as incomplete and compromised. The Christian community, introduced by colonial missions, should in principle reject caste. Yet, in practice, it reproduces caste prejudice with renewed force. As Roy shows, colonial hybridity has not erased caste but reconfigured it in a Christian form, deepening rather than dismantling hierarchies. This contradiction reflects what Homi Bhabha terms the "ambivalence" of hybridity, where colonial influence both empowers and oppresses.

7.3 Hybridity as Transgression :

The forbidden love between Ammu and Velutha epitomizes hybridity as transgression. Their relationship cuts across caste, class, and religious boundaries, embodying the dangerous potential of cultural mixing. Roy frames this moment of transgression with startling beauty: *"They stood there. Skin to skin. As though they were joined—one organism. His hand on her bare shoulder, her hand in his hair"* (p. 316).

Yet, this hybridity is not tolerated by society. The "Love Laws," Roy tells us, "lay down who should be loved, and how. And how much" (p. 33). Ammu and Velutha's love violates these laws, provoking violent retribution. Velutha's brutal death in police custody illustrates how hybrid identities that transgress entrenched boundaries are punished with extreme violence. Hybridity here is both liberatory (a radical crossing of lines) and perilous (a fatal challenge to social order).

7.4 Hybridity and Identity Formation :

The twin children, Rahel and Estha, embody hybridity at the level of subjectivity. Their fragmented perceptions and disjointed memories are narrated in a hybrid style that collapses time and space. Consider the passage: *"Things can change in a day. One day can contain a thousand years. Or just one second"* (p. 32). This collapsing of temporal categories reflects a consciousness that cannot be neatly aligned with either Western linear temporality or Indian cyclical temporality.

Rahel and Estha's obsession with Western toys, Hollywood films, and Coca-Cola coexists with their immersion in local traditions and Malayalam culture. For instance, they chant: *"Plymouth. La-dy. Like a musical. La-dy. Like a Plymouth car"* (p. 139). Their play with words illustrates the internalization of global consumer culture within a local linguistic world. This hybridity shapes their fractured identities: they are neither fully Westernized nor fully traditional, but suspended in-between.

7.5 Hybridity as Resistance :

Finally, hybridity in Roy's novel is a mode of resistance. By appropriating English and bending it to her narrative needs, Roy destabilizes colonial literary traditions. The fragmented structure of the novel—its non-linear temporality, shifting perspectives, and repetition of key motifs—refuses the conventions of Western realist fiction.

For example, when describing Ammu's inner world, Roy writes: *"She was a woman trapped by history, caught between the love she longed for and the laws that prohibited it"* (p. 223). This collapsing of personal tragedy into historical structures exemplifies how Roy fuses private and political narratives, creating a hybrid form that challenges dominant storytelling modes.

Moreover, hybridity is enacted through cultural appropriation as a strategy of survival. Rahel and Estha's linguistic games, Ammu's defiance of patriarchal rules, and even Chacko's Oxford-inflected critiques of capitalism all represent ways in which characters resist dominant power structures by inhabiting hybrid spaces.

8. Conclusion :

The God of Small Things offers a profound meditation on postcolonial hybridity and cultural identity in India. Through its characters, narrative strategies, and linguistic experimentation, the novel reveals how colonial residues persist in shaping social life even as new hybrid identities emerge. Roy demonstrates that hybridity is not merely a cultural synthesis but a deeply political process, fraught with conflict, resistance, and violence.

By situating the novel within postcolonial theory—drawing on Said's Orientalism, Bhabha's hybridity, and Spivak's subalternity—we see how Roy's narrative negotiates the complexities of identity in postcolonial India. The novel ultimately suggests that hybridity, while a site of creativity and resistance, cannot be divorced from the historical realities of caste, class, and colonialism.

In this way, *The God of Small Things* continues to resonate as a text that both reflects and critiques the cultural hybridity of contemporary India, offering insights not only into literature but also into the broader dynamics of postcolonial identity formation.

Refrences :

1. *Bhabha, Homi K. The Location of Culture. London: Routledge, 1994, p. 37.*

2. *Nayar, Pramod K. Postcolonial Literature: An Introduction. Delhi: Pearson, 2008, pp. 65–68.*
3. *Said, Edward. Orientalism. New York: Vintage Books, 1978, p. 12.*
4. *Bhabha, Homi K. Nation and Narration. London: Routledge, 1990, pp. 210–215.*
5. *Spivak, Gayatri Chakravorty. “Can the Subaltern Speak?” in Marxism and the Interpretation of Culture, edited by Cary Nelson and Lawrence Grossberg. Urbana: University of Illinois Press, 1988, pp. 271–313.*
6. *Mukherjee, Meenakshi. The Perishable Empire: Essays on Indian Writing in English. Delhi: Oxford University Press, 2000, p. 183.*
7. *Boehmer, Elleke. Colonial and Postcolonial Literature. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 243.*
8. *Patel, Sujata. “Caste, Christianity, and Social Change in Kerala.” Economic and Political Weekly 35, no. 34 (2000): 2975–2981.*
9. *Thieme, John. Postcolonial Con-Texts: Writing Back to the Canon. London: Continuum, 2001, pp. 119–124.*
10. *Loomba, Ania. Colonialism/Postcolonialism. London: Routledge, 1998, pp. 203–206.*
11. *Bayly, Susan. Saints, Goddesses and Kings: Muslims and Christians in South Indian Society, 1700–1900. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, pp. 90–96.*
12. *Jeffrey, Robin. Politics, Women and Well-Being: How Kerala Became ‘a Model’. Delhi: Oxford University Press, 1992, pp. 212–218.*
13. *Roy, Arundhati. The God of Small Things. London: Flamingo, 1997, p. 36.*
14. *Thieme, John. The Arnold Anthology of Postcolonial Literatures in English. London: Arnold, 1996, p. 414.*
15. *Chacko, Priya. “The Globalised World of The God of Small Things.” Journal of Commonwealth Literature 38, no. 1 (2003): 33–45.*
16. *Devika, J. “Caste and the Politics of Love in Kerala: Reading Arundhati Roy.” Indian Journal of Gender Studies 9, no. 2 (2002): 223–239.*
17. *Roy, Arundhati. The God of Small Things. London: Flamingo, 1997, p. 31.*
18. *Ghosh, Bishnupriya. “Arundhati Roy’s Postcolonial Cosmopolitanism.” Public Culture 14, no. 1 (2002): 147–171.*
19. *Paranjape, Makarand. “The God of Small Things and the Crisis of the Postcolonial.” World Literature Today 74, no. 1 (2000): 34–39.*
20. *Krishnaswamy, Revathi. “Myth, Memory, History: The Politics of Postcolonial Identity in The God of Small Things.” Modern Fiction Studies 45, no. 1 (1999): 235–263.*
21. *Satchidanandan, K. “Caste and Literature in Kerala.” Indian Literature 45, no. 3 (2001): 123–135.*

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 161-168
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

US Tariff Policies and Their Global Repercussion : A study of Trade Diversion and Realignment in Asia and Europe

Pro. Dr. Neetu Singh
Professor, Economics,
Navyug Kanya Mahavidyalay, Rajendra Nagar, Lucknow.

Abstract :

Over the past decade, tariffs have become a core piece of the United States' playbook for industrial security and supply-chain resilience rather than one-off trade skirmishes. The combination of Section 301 actions on China, Section 232 duties on steel and aluminum, and 2024 clean-tech hikes has nudged sourcing away from China toward Mexico and parts of ASEAN, while prompting Europe to respond with its own tools—including the Carbon Border Adjustment Mechanism and new trade-defense measures on electric vehicles. In practice, supply routes that once ran directly through China now detour through North America and Southeast Asia, and European carbon rules increasingly shape the delivered cost of energy-intensive goods.

This study distills what government reports and prior academic studies reveal about how these policies work on the ground: the mechanics of rules of origin, the role of forced-labor enforcement, and the ways firms redesign products or reorganize assembly to qualify for relief. We summarize where price pass-through shows up, how investment and contracting shift, and why headline trade tallies can be misleading when Chinese value added is embedded in third-country exports.

Keywords : U.S. tariffs, clean-tech tariffs, de-risking, trade diversion, supply-chain realignment, rules of origin, value-added trade (TiVA)

1. Introduction :

The contemporary U.S. tariff turn began in 2018 with Section 301 tariffs on Chinese goods and Section 232 actions on steel and aluminum, and it has persisted across administrations as part of a long-run "tariff-plus" regime that pairs border measures with export controls and domestic industrial incentives.[1]

In May 2024, the United States announced a steep escalation targeting clean-tech supply chains—EVs, batteries, battery parts, and selected critical minerals—and the U.S. Trade Representative (USTR) finalized these changes in September 2024 after the statutory four-year study, signaling durable policy rather than a temporary bargaining spasm.[2] This study synthesizes **secondary** evidence—official U.S. and EU documents, multilateral analyses, and peer-studyed/working papers—rather than producing new econometric estimates, with attention to measurement issues in global value chains.[3]

2. Method and Sources :

This study prioritize government publications (USTR, USITC, Commerce/CBP, DHS, Census, European Commission, WTO) for institutional facts and timelines, and peer-studyed or widely cited papers for price pass-through, welfare, and diversion, where bilateral data may mislead, I reference OECD–WTO TiVA documentation on value-added accounting.? Findings are reported narratively with selective quantification drawn from these sources and grouped citations to keep the total number of footnotes within the cap.?

3. Institutional Architecture and Timeline

3.1 Section 301 (2018–2024) :

Following a 2017 investigation into Chinese practices concerning technology transfer and IP, the United States imposed multi-wave Section 301 tariffs at headline rates of roughly 10–25 percent with an evolving exclusion process.?

USTR's September 13, 2024 determination maintained broad coverage and raised rates in clean-tech lines (EVs, EV batteries and parts, selected critical minerals), integrating 301 with industrial-security goals.?

3.2 Section 232 Metals (2018) :

On June 1, 2018, the United States imposed a 25 percent tariff on steel and a 10 percent tariff on aluminum on national-security grounds, subsequently managing allied relationships through a 2021 U.S.–EU tariff-rate-quota (TRQ) arrangement.?

WTO panels circulated reports in December 2022 finding elements of the U.S. measures inconsistent with certain obligations, while the U.S. invoked GATT Article XXI and the broader Appellate Body crisis limited final adjudication, encouraging interim diplomacy.?

3.3 2024 Clean-Tech Escalation :

In May 2024 the Administration set a 100 percent tariff on Chinese EVs and 25 percent on many EV batteries, battery parts, and specified critical-minerals lines, with staging to 2026 for natural graphite and permanent magnets, and USTR finalized the package after public comment.[1]?

4. Concepts: Diversion, De-Risking, and Value-Added Dependence :

"Trade diversion" refers to sourcing shifts from a targeted partner toward third countries in response to relative-price changes, while "de-risking" emphasizes deliberate rebalancing away from concentrated suppliers in strategically sensitive inputs.[11] Because global value chains embed foreign value in third-country exports, **gross** bilateral statistics can overstate reductions in true dependence when targeted content is re-routed, thus, **value-added** and **mirror-trade** perspectives are needed to assess policy success.[12]

5. Empirical Signatures of Diversion and Realignment

5.1 Partner Turnover :

By 2023, **Mexico** overtook **China** as the leading source of U.S. goods imports, consolidating that position into early 2024 and reflecting the combined influence of tariffs, USMCA rules, and near-shoring logistics advantages.[13]

Official tables and bank research report share gains for **Vietnam** and selected ASEAN economies in tariff-sensitive consumer goods and electronics assemblies, consistent with firm-level "China-plus-one" strategies.[1]?

UNCTAD's early work on the 2018–2019 period already documented diversion from China toward third countries in electronics-related categories, a pattern that subsequent updates suggest persisted in selected product lines.[1]?

5.2 Incidence: Prices, Imports, and Output :

The U.S. International Trade Commission (USITC) reports that, on average, import prices rose roughly one-for-one with tariff rates in affected sectors, that imports from China declined where measures applied, and that U.S. production increased modestly, with substantial heterogeneity across sectors and products.[1]? Prominent academic papers estimate significant pass-through to U.S. importers and consumers and quantify short-run welfare losses, while noting distributional differences across regions and industries.[1]?

USITC sector chapters and communications highlight pronounced aluminum effects under Section 232 and more muted consumer-price impact where third-country substitution was readily available.[1]?

5.3 Measuring "True" Diversification :

A 2025 New York Fed analysis argues that U.S. imports from China have fallen by **less** than U.S. data indicate once re-routing through third countries is considered, implying that part of the observed partner turnover masks continuing Chinese value added.[1]? This supports complementing gross trade statistics with **TiVA-style** indicators and customs-enforcement outcomes when evaluating de-risking.[2]?

6. Enforcement, Evasion, and Compliance :

6.1 Rules-of-Origin Risk and EAPA :

Higher tariffs raise incentives for **transshipment** and minor processing to alter origin, and U.S. Customs and Border Protection's **Enforce and Protect Act (EAPA)** provides an on-the-record administrative process to investigate and remedy AD/CVD duty evasion.[21] CBP's public program materials—overviews, statistics, and allegation checklists—document the scale and mechanics of origin risk across sectors and lanes and illustrate how enforcement complements tariffs by limiting leakage.[22]

6.2 Forced-Labor Compliance (UFLPA) :

The **Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA)** imposes a rebuttable presumption of inadmissibility on goods mined, produced, or manufactured in whole or in part in Xinjiang, and DHS updates identify high-priority sectors (including solar-grade polysilicon and aluminum) while expanding the Entity List and specifying traceability expectations.[23]

7. Europe's Response and Cross-Atlantic Interactions

7.1 CBAM's Transitional Phase and 2026 Regime :

The EU **CBAM** entered a **transitional phase** on October 1, 2023, with quarterly reporting through December 2025 and **certificate purchases** beginning in 2026 for iron/steel, aluminum, cement, fertilizers, electricity, and hydrogen, aligning border pricing with the phase-out of EU ETS free allowances.[2]?

7.2 Trade-Defense in BEVs :

In late 2024, the European Commission adopted **definitive countervailing duties** on Chinese BEVs after an anti-subsidy investigation, and China requested WTO consultations, indicating a multi-forum contest over evidence and methodology.[2]?

7.3 Allied Metals Management :

The 2021 **U.S.–EU TRQ** on steel and aluminum replaced 232 duties on EU exports with quota-based access and initiated discussions on a **carbon-based sectoral arrangement**, providing a template for allied calibration that tempers fragmentation risks while preserving bargaining leverage.[2]?

8. Welfare, Prices, and Investment

8.1 Pass-Through and Output :

USITC's quantitative findings align with partial-equilibrium intuition: where substitutes and third-country supply exist, consumer-price effects can be tempered even as bilateral imports from the targeted source fall, whereas in capacity-tight inputs or under stringent rules of origin, pass-through to domestic prices rises. Academic work estimates near-term welfare costs that vary with identification strategy and coverage, emphasizing that incidence and efficiency depend on substitution elasticities and market structure.

8.2 Location Decisions and FDI :

Tariffs and export controls have operated alongside **IRA** and **CHIPS** incentives to steer **FDI** and contract manufacturing toward **Mexico** and **Asia ex-China** in electronics, automotive components, and selected clean-tech inputs, expanding diversified assembly footprints more than wholesale reshoring to the United States. Partner-table data and bank research document Mexico's consolidated top-supplier status, though value-added analysis cautions that some flows still embed Chinese inputs.

8.3 System-Level Risks from Fragmentation :

IMF analyses warn that persistent **geoeconomic fragmentation** can reduce global welfare by eroding scale economies, impeding diffusion, and amplifying volatility in concentrated upstream inputs, which suggests benefits from allied coordination and interoperable rules.

9. Synthesis :

Evidence supports **durable reorientation** of U.S. sourcing away from China toward North America and parts of ASEAN in tariff-exposed categories, but **value-added** perspectives indicate that underlying dependence on Chinese inputs has likely fallen by **less** than gross flows suggest. Europe's CBAM and BEV trade-defense actions, alongside allied metals management, show how transatlantic policy can either **discipline** the welfare costs of fragmentation through coordination or **compound** them through overlapping requirements.

10. Policy Recommendations :

(A) Tighten rules of origin with targeted facilitation.

Expand **EAPA** capacity, integrate mirror-trade anomaly detection, and deepen information-sharing with allied customs, while offering trusted-trader lanes for firms with robust traceability to keep enforcement precise and compliance costs proportionate.

(B) Align tariffs with climate-trade instruments.

Where concerns are subsidized overcapacity or carbon intensity, calibrate tariffs with **CBAM-consistent** metrics or negotiated sectoral arrangements, using TRQs and time-bound studys to avoid stacking protections that increase deadweight loss without improving resilience.

(C) Invest in value-added statistics and content-origin dashboards.

Mainstream **TiVA-style** measures and experimental content-origin estimates in official releases for strategic sectors so that policymakers and firms can distinguish genuine diversification from re-routing and design supply chains that meet origin and carbon standards efficiently.

(D) Coordinate transatlantic responses to clean-tech surges.

Adopt interoperable evidence thresholds for subsidy findings, shared circumvention guidance, and off-ramps when verified content-origin and carbon-intensity benchmarks are met, thereby reducing uncertainty while preserving incentives to diversify.

(E) Support dispute-settlement repair and interim fixes.

Because appellate paralysis invites **appeal-into-the-void**, pragmatic steps toward credible second-tier study—alongside plurilateral interim arrangements—are essential to reduce uncertainty around security-framed measures and high-stakes trade-defense cases.

Conclusion :

U.S. tariff policy has undeniably **reallocated** trade geography, reducing direct exposure to China in targeted categories while deepening links to Mexico and parts of ASEAN. Yet the **value-added** and **enforcement** perspectives show that part of the "diversification" reflects **re-routing**, not full disentanglement. As Europe rolls out CBAM and deploys trade-defense in green sectors, the shape of transatlantic coordination will determine whether the system converges toward **efficient de-risking** or fragments into overlapping, costly regimes. The most credible path forward pairs **origin integrity** with **climate-consistent border design** and **transparent value-added statistics**, so strategic aims—resilience, fair competition, and rapid clean-tech deployment—are achieved with the least collateral welfare loss.

References :

1. *Office of the United States Trade Representative. (2018–2024). Section 301 investigation of China's acts, policies, and practices related to technology transfer, intellectual property, and innovation (lists, exclusions, dockets). Washington, DC.*
2. *The White House. (2024, May 14). Fact sheet: President Biden takes action to protect American workers and businesses from China's unfair trade practices. Washington, DC, Office of the United States Trade Representative. (2024, Sept. 13). USTR finalizes action on China tariffs following statutory four-year study. Washington, DC.*
3. *U.S. International Trade Commission. (2023, March 15). The economic impact of Section 232 and 301 tariffs on U.S. industries (Pub. 5405). Washington, DC, OECD & WTO. (2023–2024). Trade in Value-Added (TiVA): Guides and explanatory notes. Paris/Geneva.*
4. *OECD & WTO. (2023–2024). TiVA documentation (measurement framework). Paris/Geneva.*
5. *Methodological triangulation rationale drawing on government, multilateral, and academic*

sources, see notes 3–4 for frameworks.

6. *Office of the United States Trade Representative. (2018–2024). China Section 301 tariff actions & exclusion process. Washington, DC.*
7. *Office of the United States Trade Representative. (2024, Sept. 13). Final action on China tariffs (EVs, EV batteries/parts, critical minerals). Washington, DC.*
8. *U.S. Department of Commerce. (2018). Section 232 steel and aluminum actions (25% steel, 10% aluminum), Office of the United States Trade Representative. (2021, Oct. 31). Fact sheet: U.S.–EU arrangements on global steel and aluminum excess capacity and carbon intensity (TRQ). Washington, DC.*
9. *World Trade Organization. (2022, Dec. 9). Panel reports on U.S. steel and aluminum measures (DS544 et al.), WTO resources on Appellate Body paralysis (2019–2024). Geneva.*
10. *The White House. (2024, May 14). Clean-tech tariff changes (EVs at 100%, EV batteries/ parts and selected critical minerals at 25% with staging to 2026), Office of the United States Trade Representative. (2024, Sept. 13). Final action (post-comment finalization).*
11. *UNCTAD. (2019). Trade and trade diversion effects of United States tariffs on China (Research Paper No. 37). Geneva.*
12. *OECD & WTO. (2023–2024). TiVA: Guide and explanatory notes (value-added vs. gross flows). Paris/Geneva.*
13. *U.S. Census Bureau. (2023–2024). U.S. trade in goods—country tables (partner turnover). Washington, DC, Associated Press. (2024, Feb. 7). Mexico overtakes China as top exporter to U.S.*
14. *BBVA Research. (2024, Mar.–Apr.). Mexico is now the largest exporter to the U.S., Near-shoring and export diversification in Mexico. Mexico City/Madrid.*
15. *UNCTAD. (2019). Trade diversion effects..., updates in UNCTAD (2024). Import diversification and trade diversion (Working Paper). Geneva.*
16. *U.S. International Trade Commission. (2023). Economic impact... (price pass-through, import declines, modest output). Washington, DC.*
17. *Fajgelbaum, P. D., Goldberg, P. K., Kennedy, P. J., & Khandelwal, A. K. (2020). The Return to Protectionism. Quarterly Journal of Economics, Amiti, M., Redding, S. J., & Weinstein, D. E. (2019). The Impact of the 2018 Tariffs on Prices and Welfare. Journal of Economic Perspectives.*
18. *U.S. International Trade Commission. (2023, Mar. 15). News release: Certain effects of Section 232 and 301 tariffs... (aluminum example). Washington, DC.*

19. *Federal Reserve Bank of New York (Liberty Street Economics). (2025, Feb. 26). Clark, H. L., et al., U.S. imports from China have fallen by less than U.S. data indicate, SSRN working-paper version. New York, NY.*

20. *OECD & WTO. (2023–2024). TiVA documentation (policy use of value-added indicators). Paris/Geneva.*

21. *U.S. Customs and Border Protection. (n.d.). Enforce and Protect Act (EAPA) overview. Washington, DC.*

22. *U.S. Customs and Border Protection. (2023–2025). EAPA statistics and allegation checklists (program scale and mechanics). Washington, DC.*

23. *U.S. Department of Homeland Security. (2024, July 9). 2024 Updates to the Strategy to Prevent the Importation of Goods Mined, Produced, or Manufactured with Forced Labor in the PRC (UFLPA), U.S. Government interagency updates on Entity List and enforcement expectations. Washington, DC.*

24. *European Commission (DG TAXUD). (2023–2025). CBAM portal and guidance (transitional reporting 2023–2025, certificates from 2026). Brussels.*

25. *European Commission / EUR-Lex. (2024, Oct.–Dec.). Implementing Regulation (EU) 2024/2754 (definitive BEV duties) and accompanying DG TRADE communication, WTO. (2024, Nov.). Request for consultations on EU BEV duties. Geneva.*

26. *Office of the United States Trade Representative. (2021, Oct. 31). U.S.–EU metals TRQ fact sheet (sectoral arrangement discussions). Washington, DC.*

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 169-174

Exploring the role and Impact of Artificial Intelligence on the Retail Industry

Hema Verma
Guest Assistant Professor, Commerce
Naveen Government College Komakhan, Dist – Mahasamund – 493449, Chhattishgarh, India

Abstract :

The paper examines the growing role of Artificial Intelligence (AI) in retailing with an emphasis on enhancing customer experience, operational optimization, and business efficiency. This research investigates AI technologies used in retail, namely customer service chatbots, personalized marketing, demand forecasting, and supply chain management. A literature review and discussion of case studies underscore the transformative nature of AI on the retailing industry. The paper concludes with future perspectives on the role of AI in retailing and the challenges posed in that implementation.

Keywords : Artificial Intelligence, Retailing, customer, Supply chain, Inventory management.

1. Introduction :

Artificial intelligence (AI) is significantly influencing the shape of modern retail by maximizing efficiency, personalization, and decision-making. AI's importance to today's retailing lies in the analyzing of complex sets of data through which retailers offer experience customization and inventory optimization. The technology used has, over the years, transformed the retail sector from the use of ordinary cash registers and manual inventory systems to advanced integrated ecommerce platforms and omnichannel strategies. AI has many aspects as it encompasses machine learning predicting consumer trends and natural language processing for seamless customer interactions. Thus, in its new form, artificial intelligence is going toward intelligent automated systems that not only predict what customers want but also streamline supply chains, therefore revolutionizing the way retailers do business and interact with shoppers.

2. Literature Review :

The literature on AI in retailing covers various topics, from enhancing customer experience to improving supply chain management. Researchers have pointed out that AI enables retailers to offer a more personalized shopping experience, streamline operations, and make decisions based on data. Below is a summary of key findings from previous studies.

2.1 Historical Context and Evolution of AI in Retail :

The introduction of AI in retail probably dates back to the early 2000s when automation in retail system models first found its way. However, the past decade saw the onset of exploiting retail by AI in the full extent allowed by technological advancements. Kumar et al. (2018) reported that predictive analytics and autonomous delivery systems are among AI applications in retail. In parallel, an accelerating sophistication of AI technologies increased their capability of influencing consumer expectations and business models.

2.2 AI in Enhancing Customer Experience :

AI is widely perceived as a tool for enhancing customer experience, particularly in applications focusing on personalized services and customer support. Natural language processing-powered chatbots are extensively deployed to manage customer inquiries and deliver real-time support, offering a seamless customer service experience. According to Smith and West (2019), AI recommendation engines (like those of Amazon) allow retailers to deliver extremely personalized product recommendations that enhance conversion rates and customer satisfaction further.

2.3 AI in Retail Operations :

AI also has an important place in operational efficiency. AI systems predict demand and regulate stock levels to avoid overstocking and stockouts with operational-costs improvement and customer satisfaction enhancement. Zhang et al. (2020) have demonstrated that AI demand forecasting eliminates the incompetence in inventory management usually found using manual processes.

2.4 AI Marketing and Personalized Advertising :

AI allows retailers to analyze consumer behavior in real time, creating highly targeted advertising campaigns. Machine-learning algorithms work with vast data from social media, purchasing history, and browsing behavior to serve more relevant and timely promotions. Mikalef et al. (2021) say that AI tools can predict consumer preferences with great accuracy, thus allowing retailers to tailor their marketing strategies.

2.5 Challenges and Barriers of AI Adoption in Retail Sector :

The obstacles to AI implementation in retail are multiple, although its promise seems almost limitless. The price of implementing AI solutions is one significant hurdle. Data privacy is an issue, for AI requires access to very large datasets that may include sensitive customer information. In this regard, Turner and Davis (2020) discuss the ethical dimensions of AI in retail, stressing maintaining consumer trust and ensuring full compliance with data protection laws.

3. Methodology :

This specific research design uses qualitative methods for exploring the effects of Artificial Intelligence (AI) in relation to the retail industry. This study gathered data using a combination of case studies, expert interviews, and a literature survey. The true cases show example applications of AI in retail; they provide a basis for the analysis of the outcomes, successes, and failures.

Interviews with experts provide their interpretation of the practical implications of the adoption of AI through careful and detailed perspectives from industry professionals. An umbrella literature survey puts all this research into context, comparing it to what other academic and industry researchers have found, and pointing to some key themes and gaps. The analysis categorizes different applications of AI and assesses their contributions to operational efficacy, customer experience, and challenges such as technical obstructions and ethical dilemmas. This mixed method approach provides the best possible grasp by both academia and industry practice concerning contemporary and future impacts of AI in retail.

4. AI in Retailing :

a. AI in Enhancing Customer Experience :

AI technologies such as chatbots, virtual assistants, and personalized recommendations are changing the nature of retailers' engagement with customers. Chatbots, for example, work instantly by answering queries, being available 24-7, and creating an experience that is more accessible and thus efficient. Among other retailers, H&M and Sephora use AI virtual assistants to lead consumers through the choices of their products, thus improving sales and consumer satisfaction.

b. AI in Inventory Management :

AI systems help retailers predict the demand for items with much greater accuracy, hence avoiding unnecessary costs associated with overstocking or stockouts. RFID (Radio Frequency Identification) and smart-shelf technologies keep real-time track of inventory, ensuring stock levels are in agreement with consumer demand. Retail giants like Walmart use AI-enabled supply chains for efficient inventory flow management.

c. Market and Personalization :

Artificial intelligence provides retailers with solutions to design marketing campaigns. These mature campaigns seem to be driven by consumers' behavior. Based on past purchases, previous browsing activity, or social media engagement, AI predicts certain products likely entering a customer's shopping cart. For instance, content recommendations are suggested by AI algorithms to Netflix on the basis of users' viewing history. Amazon, likewise, recommends products to customers on the basis of their browsing behaviors, algorithmically guessing what they might buy next.

d. **AI for Supply Chain Optimization :**

Artificial intelligence has also provided the much-awaited boost to supply chain management in retail. With predictive analytics or autonomous delivery vehicles at work, AI complements every aspect of a supply chain. Amazon's use of AI-enabled warehouse robots to move products across warehouse setups is perhaps one of the biggest examples of supply chain optimization through AI.

5. **Effects of AI on Retail Operations :**

AI is all set to reap many benefits for retail operations such as increased operational efficiency and cost savings along with increased customer satisfaction. AI systems will enable streamlined process execution between inventory tracking, order processing, and demand forecasting. Retailing operational cost while improving the accuracy and speed of service delivery dramatically freed employees for more value-added tasks.

For instance, with AI-enabled predictive analytics, retailers can predict trend development and act in advance on product offerings and stock levels. The same AI- powered logistics touching the consumers use features that allow retailers to minimize waste by optimizing delivery routes and reducing energy consumption within warehouses.

6. **Challenges of AI Adoption in Retail :**

Though promising, there are quite a number of challenges that AI poses to retail.

1. **Huge costs of implementation :** Small and medium-sized retailers suffer from the problem of higher initial costs when it comes to AI implementation.
2. **Consumer Information Privacy :** AI systems are known for consuming huge amounts of customer information, which creates privacy issues. Retailers would likely be keen on ensuring compliance with data protection regulations, such as the GDPR.
3. **Technology Constraints :** Not all retail firms have the appropriate infrastructure or a team of professionals to use AI successfully.
4. **Change Resistance :** Employees and managers may have an element of resistance to the implementation of AI technologies due to reasons that stem from negative implications such as fear about job loss or misunderstanding of the usefulness of that technology in the retailer's future.

7. **Future Trends of AI in Retailing :**

The future of AI in retail is proliferating as machine learning, robotics, and augmented reality (AR) continue to advance. One of the most interesting areas that retailers try to figure out is how AI can improve omnichannel retailing, integrating better yet both online and offline shopping into one experience.

AI is poised to play a significant role in promoting sustainability in retail by allowing for the optimization of resource usage and waste reduction. 8. Conclusion AI can enhance the transformation of retail with considerable advantages in customer experience, operational efficiency, and profitability for the retailer. Nevertheless, impediments exist such as implementation cost, data privacy, and technology-related impediments. In spite of these challenges, the future of AI in retail looks promising as the ongoing developments will bring larger changes to the retail landscape.

Conclusion :

It is obvious that AI is significantly transforming the future of the retail industry with the innovative technologies and customer experiences that it brings. Predictive analytics, personalized recommendations, and the efficient management of smart inventories that define AI technologies increasingly feature in the retail field. More and more, retailers are learning how they can operate efficiently, owing to the astonishing developments of AI innovative approaches, and customized solutions for consumers. Automating tasks with AI opens up a lot for businesses in terms of better pricing strategies and targeted marketing that lead to customer loyalty but it also faces a number of challenges like privacy and data security, job loss, and the introduction of new technologies.

Nevertheless, despite these impediments to AI systems, their growing importance always piles more expectations on the part of retailers to capitalize on the current consumer trends while it exposes yet more opportunities for seamless integration of shopping experiences and significantly long-term sustained competitive growth.

References :

1. Kumar, S., Raj, S., & Sharma, M. (2018). Artificial Intelligence in Retail: Applications and Challenges. Journal of Retailing and Consumer Services, 45(4), 156-167.
2. Smith, L., & West, M. (2019). Enhancing Customer Experience Through AI: A Study of Chatbots in Retail. International Journal of Retail and Distribution Management, 47(3), 233-248.
3. Zhang, X., Li, Q., & Wang, Z. (2020). AI in Retail Inventory Management: A Case Study. International Journal of Production Economics, 224, 107-118.
4. Mikalef, P., Krogstie, J., & Pappas, I. O. (2021). AI and Machine Learning in Retail Marketing: Opportunities and Challenges. Journal of Business Research, 128, 334-342.
5. Turner, M., & Davis, R. (2020). Ethical Considerations of AI in Retail: Privacy and Data Protection. Journal of Business Ethics, 169(2), 455-471.
6. Weber, F. D., & Schütte, R. (2019). State-of-the-art and adoption of artificial intelligence in retailing. Digital Policy, Regulation and Governance, 21(3), 264-279.

7. Moore, S., Bulmer, S., & Elms, J. (2022). The social significance of AI in retail on customer experience and shopping practices. Journal of Retailing and Consumer Services, 64, 102755.
8. Heins, C. (2023). Artificial intelligence in retail–a systematic literature review. foresight, 25(2), 264-286.
9. Haenlein, M., & Kaplan, A. (2019). A brief history of artificial intelligence: On the past, present, and future of artificial intelligence. California management review, 61(4), 5-14.
10. Lu, Y. (2019). Artificial intelligence: a survey on evolution, models, applications and future trends. Journal of Management Analytics, 6(1), 1-29.

Presenting Author, email: hemav8509gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 175–180

नरेन्द्र कोहली के दीक्षा उपन्यास के परिपेक्ष्य में सांस्कृतिक अध्ययन

जोगिन्द्र कुमार
शोधार्थी, हिन्दी विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखंड)–249404

शोध सारांश :–

नरेन्द्र कोहली हिन्दी साहित्य के एक सशक्त साहित्यकार हैं। इन्होंने महाभारत और रामकथा को अपने उपन्यासों का आधार बनाकर, इन उपन्यासों के पौराणिक कथानक को आधुनिकता से जोड़कर प्रस्तुत किया हैं। इनका 'दीक्षा' उपन्यास रामकथा पर आधारित, रामकथाश्रित उपन्यास श्रृंखला का ही एक भाग है। इसमें रामायण की कथा का आधुनिक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों का इस प्रकार चित्रण किया है कि यह एक धार्मिक आख्यान न होकर भारतीय समाज में फैली जटिलताओं एवं सामाजिक अन्यायों जैसे शिक्षा, जातिगत भेदभाव, नारी की स्थिति, नैतिक मूल्य आदि का गहराई से विश्लेषण करता है। इस उपन्यास में 'दीक्षा' शब्द का अर्थ केवल शस्त्र और शास्त्र की दीक्षा से नहीं अपितु उससे भी बढ़कर जीवन मूल्यों, अनुशासन, कर्तव्यों एवं लोक कल्याण के आदर्शों को आत्मसात करने की प्रक्रिया से है। जिससे एक साधारण राजकुमार आदर्श, धर्म और त्याग की शिक्षा प्राप्त कर लोकनायक तथा 'मर्यादा पुरुषोत्तम' बनने की दिशा में अग्रसर होता है। कोहली ने विश्वामित्र को पौराणिक संदर्भों से निकालकर, आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से ही नहीं जोड़ा अपितु भारतीय संस्कृति के ज्ञान, सामाजिक सुधार, तपस्या और नैतिक जागरण के प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत किया है। जिससे वह पारंपरिक ऋषि से आगे बढ़कर एक दूरदर्शी और क्रांतिकारी व्यक्तित्व धारण कर राम और लक्ष्मण को सामाजिक अन्याय के विरुद्ध खड़ा करते हैं। कोहली ने उपन्यास में कौशल्या, सुमित्रा, सीता, अहिल्या, सदानिरा, वनजा एवं निषाद स्त्रियों के माध्यम से त्याग, समर्पण, मातृत्व, प्रेम और शोषण आदि अनेक रूप प्रस्तुत किए हैं। राक्षस अत्याचार, अन्याय, दुराचार, पाप, दुष्कर्म आदि बुराइयों के प्रतीक हैं, जिन पर विजय, धर्म की अधर्म पर विजय का परिचायक है।

बीज शब्द – पुनरुत्थान, आध्यात्मिकता, आधुनिकता, संस्कृति, श्रृंखला, अनुशासन, आत्मसात, अनासक्त, संरक्षण, भ्रष्टाचार, निष्पक्ष, उच्छृंखल, पुनरावृति, सर्वोत्कृष्ट आदि।

मुख्य आलेख :–

भारतीय पौराणिक कथाएं, भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं, जो समाज के मार्गदर्शन का कार्य करती

है। रामकथा और महाभारत भी ऐसी ही महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं हैं, जो भारतीय संस्कृति में केवल धार्मिक आख्यान न होकर जीवन मूल्यों, मर्यादाओं एवं आदर्शों की अनुपम गाथा है। कोहली इन कथाओं को आधुनिकता के साथ जोड़कर भारतीय संस्कृति के अनेक रूपों को प्रस्तुत करते हैं। भारतीय समाज में फैले विभिन्न धर्मो के रीति–रिवाज, आचार–विचार, खान–पान, परंपराएं और विश्वास आदि में संस्कृति के अनेक स्वरूप विद्यमान हैं। जो समाज को प्रभावित कर, उसे सभ्य बनाने की दिशा प्रदान करती है। संस्कृति मनुष्य की आत्मा और विचारों को परिष्कृत कर, उसके सर्वगुणों को सर्वोत्कृष्ट करने की प्रक्रिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार– ”मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है।.... नाना प्रकार की धार्मिक साधनाओं, कलात्मक प्रयत्नों और सेवा, भक्ति तथा योगमूलक अनुभूतियों के भीतर से मनुष्य उस महान सत्य के व्यापक और परिपूर्ण रूप को क्रमशः प्राप्त करता जा रहा है, जिसे हम 'संस्कृति' शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं।”[1] डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के शब्दों में– ”संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है, हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। संस्कृति हवा में नहीं रहती, उसका मूर्तिमान रूप होता है। जीवन की नानाविद रूपों का समुदाय ही संस्कृति है।”[2] एडबर्ड टाइलर के अनुसार– ”संस्कृति अपने मानव शास्त्रीय अर्थ में उस सन्निकट परिकल्पना को कहते हैं, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि–विधान, रीति–रिवाज, और अन्य व्यवहार और सामर्थ्य सम्मिलित हैं, जिन्हें मनुष्य अपने समाज से ग्रहण करता है।“[3] कोहली ने दीक्षा उपन्यास में संस्कृति के विभिन्न तत्व धर्म, आध्यात्मिकता, वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कार, कर्म, आस्था, वैदिक ज्ञान, रहन–सहन, रीति–रिवाज, वेशभूषा एवं आचार–विचार का आधुनिक ढंग से सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, कुरीतियों, रूढ़िवादी परंपराओं, राजनीतिक मुद्दों, अन्याय और स्त्री विषयों को पौराणिक संदर्भ के साथ जोड़कर प्रस्तुत कर, उनका निराकरण करने का भी प्रयास किया है।

पौराणिक लोककथा और सांस्कृतिक पुनरूत्थान :–

नरेन्द्र कोहली ने 'रामायण' को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत कर, भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता एवं निरंतरता को दिखाने का कार्य किया है। दीक्षा उपन्यास भारतीय संस्कृति की गुरु–शिष्य परंपरा तथा पौराणिक कथाओं के महत्व को रेखांकित करता है। भारतीय संस्कृति में राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र द्वारा दीक्षा देना, शिक्षा एवं आध्यात्मिकता के महत्व का प्रतीक है। विश्वामित्र, चली आ रही पौराणिक कथाओं के विश्वामित्र से हटकर, एक ऐसे निर्भीक बुद्धिजीवी के रूप में हैं, जिनके लिए सामाजिक कल्याण ही सर्वोपरि है। वे आर्य संस्कृति को बचाने और राक्षसी संस्कृति के विस्तार को रोकने के लिए, राम को अयोध्या से लेने के लिए जाते हैं। दशरथ के द्वारा राम को उनके साथ न भेजने पर, वे सम्राट दशरथ को भी चेतावनी देते हुए कहते हैं– 'हम बुद्धिजीवियों ने अनासक्त होकर तुम्हें शासन सौंप दिया, तो तुम सत्ताधारी यह समझते हो कि सामान्य प्रजा तुम्हारे भोग के साधन जुटाने का माध्यम मात्र है। तुम समझते हो प्रजा मात्र कीट–पतंग है। पर दशरथ! आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि हमारी रक्षा कर, तुम हम पर कोई कृपा नहीं करते। वह तुम्हारा कर्तव्य है।'[4] वे राम और लक्ष्मण को गुरु के रूप में युद्धकला, धर्म, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की शिक्षा के साथ–साथ सांस्कृतिक ज्ञान के संरक्षण एवं प्रसार के मार्ग पर भी अग्रसर करते हैं। पौराणिक कथाओं में इंद्र द्वारा अहिल्या के साथ छल से संबंध बनाए जाने पर ऋषि गौतम अहिल्या को शीला बनने का श्राप देते हैं। श्रीराम बाद में अहिल्या को पैरों से छूकर, श्राप मुक्त करते हैं। वहीं कोहली इसे आधुनिकता से जोड़ते हैं, जिसमें गौतम अहिल्या को श्राप न देकर

उसका साथ देते हैं। वे अहिल्या को सांत्वना देते हुए कहते हैं– 'तुम मेरी धर्मपत्नी और पूर्णतः मेरे योग्य पत्नी हो। तुम पतित नहीं हो, तुम्हें पतित कहने का साहस कोई नहीं कर सकता। तुम पूर्णतः शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र हो।'[5] अहिल्या ही सामाजिक कारणों से और इंद्र से प्रतिशोध लेने के लिए उन्हें स्वयं को त्यागने के लिए प्रेरित करती है। अहिल्या उन्हे कहती है कि– "आर्यपुत्र ! यदि आप लोग मेरे मोह में यही पड़े रहे", अहिल्या का स्वर किसी अन्य लोक से आता हुआ प्रतीत हो रहा था, "तो इंद्र बेदाग बच जाएगा। पाप करके भी वह सम्मानित और पूज्य रहेगा। हम पीड़ित और अपमानित। उस दुष्ट को दंडित करने के लिए मुझे कितनी ही असह्य यातना झेलनी पड़े, मैं सहर्ष झेलूँगी।"[6] अहिल्या आश्रम में एकांकी रहकर, समाज द्वारा अपनाए जाने की प्रतीक्षा करती है। पच्चीस वर्ष बाद राम उन्हें समाज में सम्मान दिलाते हैं। कोहली ने राम को भगवान की जगह, मानवीय चरित्र राम का एक आदर्श रूप दिखाकर, भारतीय संस्कृति के आदर्श एवं यथार्थ मेल को दिखाया है।

सामाजिक विषमताओं का सांस्कृतिक निरूपण :–

भारतीय समाज शुरू से ही वर्ण व्यवस्था पर आधारित रहा है, जिसकी चार श्रेणियां मानी जाती हैं– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह श्रेणियाँ समाज के विभाजन का कार्य करती थी। ब्राह्मणों का धार्मिक और बौद्धिकता, क्षत्रियों का सत्ता, वैश्यों का व्यापार एवं अर्थव्यवस्था पर अधिकार था, जबकि शूद्रों को निम्न कोटि का समझा जाता था। दीक्षा उपन्यास में इन वर्णों के बीच सामाजिक दूरी तथा असमानता को भी दिखाया है। कोहली ने उपन्यास में स्पष्ट किया है कि यह वर्ण व्यवस्था धर्म, कर्म एवं संस्कृति के आधार पर स्थापित थी, परंतु इसमें फिर भी मानवीय विषमता विद्यमान थी। यह सामाजिक दूरी, असमानता ऋषियों में भी व्याप्त थी। विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ के बारे में कहते हैं– "आर्य सम्राट के गुरु के पद पर वशिष्ट बैठा है, जो मानव–मात्र को समान नहीं मानता। वह अन्य जातियों से आर्यों को श्रेष्ठ मानता है, आर्यों से ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मानता है और पुरुषों को नारियों से श्रेष्ठ मानता है। वह शबरों, किरातों, निषादों, वानरों, ऋक्षों, कोल–भीलों जैसी अनेक आर्येतर जातियों तथा दूर–दूर तक फैले हुए वशिष्ठ–दर्शन को न मानने वाले आर्य ऋषि–मुनियों पर होने वाले अत्याचारों से पीड़ित नहीं होता।"[7] यह सामाजिक विषमताओं के प्रति मानसिकता बुद्धिजीवियों में ही नहीं, सत्ताधारियों में भी थी। सेनापति बहुलाश्व और उसका पुत्र देवप्रिय अपनी सत्ता और शक्ति का समाज में दुरुपयोग करते हैं। वे राक्षसों से बहुमूल्य उपहार ग्रहण करते हैं, जिससे राक्षस प्रजा पर अपनी मनमानी करते हैं। कोहली ने सेनापति बहुलाश्व और उनके पुत्र देवप्रिय को आधुनिक समाज के भ्रष्टाचार के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है। देवप्रिय निषाद जाति के परिवार पर अत्याचार करता है। वह अपने साथियों के साथ उनके घर जाकर, उनकी स्त्रियों को अपनी सेवा के लिए मांगता है। उनके स्त्रियों को न भेजने पर कहता है– "नीच जाति की स्त्रियों की भी कोई मर्यादा होती है क्या? वह होती ही किस लिए हैं? सवर्ण आर्यों के भोग के लिए ही तो!"[8] राम भारतीय न्याय व्यवस्था का अनुसरण करते हुए आर्य सेनानायक बहुलाश्व और उसके पुत्र को दंडित करते हुए समाज के सम्मुख वर्ण भेद रहित निष्पक्ष न्याय करते हैं। राम सबको संदेश देते हुए कहते हैं कि– "अपने राजसी अधिकारों का प्रयोग करने वाले, निरीह प्रजा को पीड़ित करने वाले, यह लोग आर्य नहीं है– चाहे यह लोग आर्य सेनानायक के पुत्र क्यों ना हो। 'आर्य' किसी जाति, वर्ण, आकार अथवा पक्ष का नाम नहीं है, वह मानवीय सिद्धांत, आदर्श और महान चरित्र का नाम है।"[9] राक्षसी संस्कृति को समाप्त करने और अन्याय के विरोध के लिए, राम आश्रमवासियों, ग्रामीणों तथा निषादों में साहस एवं आत्मविश्वास पैदा करते हैं।

ज्ञान एवं सांस्कृतिक मूल्य :-

इस उपन्यास में दीक्षा (शिक्षा) को रूढ़िवादी परंपराओं, कुरीतियों और अन्याय व्यवस्था में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, एक आवश्यक एवं शक्तिशाली साधन के रूप में प्रस्तुत करना ही कोहली का मुख्य उद्देश्य रहा है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा पद्धति मात्र ज्ञान प्राप्ति न होकर नैतिक विकास एवं चरित्र निर्माण का भी कार्य करती है। उपन्यास में शिक्षा के माध्यम से राम का चरित्र निर्माण, केवल व्यक्तिगत विकास ही नहीं सामाजिक सुधार भी है। जो सामाजिक प्रगति के लिए भारतीय संस्कृति को एक साधन के रूप में देखने की परंपरा को मजबूत करता है। विश्वामित्र द्वारा दी गई दीक्षा, ज्ञान, कौशल तथा नैतिकता के समन्वय के साथ–साथ भारतीय संस्कृति की समग्र शिक्षा को दिखाती है। जिसमें युद्धकला, धर्म, नीति एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भी शामिल है।

विश्वामित्र कर्तव्यपरायणता के लिए राम को समझाते हैं कि– "वत्स ! ऋषि का चोला ओढ़कर ही कोई ऋषि नहीं हो जाता, जैसे केवल लेखनी चलाकर कोई कवि नहीं हो जाता या शिष्यों को लिखा–पढ़ाकर कोई गुरु नहीं हो जाता। केवल बाह्यचार ही पर्याप्त नहीं। कर्म, दायित्व, सत्यनिष्ठा और दृढ़ चरित्र की भी आवश्यकता होती है।"[10] विश्वामित्र राम को मानवता की रक्षा के लिए, राक्षसों को समाप्त करने का भी ज्ञान देते हैं। उस समय समाज की स्थिति अच्छी नहीं थी, राक्षस हिंसक पशुओं के सामान स्वच्छंद घूमते थे। अपने सामने आने वाले ऋषि–मुनियों, दुर्बल जनसाधारण की हड्डियां को चबाना ही उनका कार्य हो गया था। वे नहीं चाहते थे कि ऋषि–मुनियों का अर्धविकसित जातियों को नेतृत्व मिले, इसलिए वे ऋषि–मुनियों को खाने के लिए तत्पर रहते थे। विश्वामित्र राम को कहते हैं कि– "यदि उच्छृंखल राक्षस अपनी इस क्रिया की इसी प्रकार पुनरावृत्ति करते रहे तो क्रमशः ये ऋषि समाप्त हो जाएंगे, इस देश में स्वतंत्र, मौलिक चिंतन समाप्त हो जाएगा, न्याय का विचार समाप्त हो जाएगा। सदाचरण और संस्कृति समाप्त हो जाएगी।"[11] रामकथा को वर्तमान समय के साथ जोड़ते हुए कोहली सत्ताधारियों की दशा का वर्णन करते हैं, जिनका केवल स्वयं का स्वार्थ ही सर्वोपरि था। समाज में हो रही घटनाओं एवं जनता के हित में उनकी कोई रुचि नहीं थी। प्रजा के न्याय–अन्याय की ओर भी सम्राट या उनके सेनानायकों का कोई ध्यान नहीं था। समाज की दशा को सुधारने के लिए विश्वामित्र, राम को एक अच्छे शासन की शिक्षा देते हैं। वे राम को आदर्श व्यवस्था के ज्ञान से परिचित करते हुए कहते हैं कि– 'ये समस्त ऋषि अपनी तथा अपने पक्ष की सुरक्षा के लिए याचना करने तुम तक नहीं आएंगे। तुम्हे अपना शोध कर उन तक पहुंचना होगा। आदर्श–व्यवस्था स्वयं नागरिक तक पहुंचकर उसका कष्ट पूछती है। नागरिक को परिवाद लेकर स्वयं शासन तक पहुंचना पड़े तो वह आदर्श व्यवस्था नहीं है।"[12] नरेन्द्र कोहली ने इस उपन्यास में शिक्षा के उस महत्व को रेखांकित किया है, जो केवल औपचारिक ज्ञान न होकर बल्कि नैतिक जागरण, जीवन के मार्गदर्शन एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। वह केवल किताबी ज्ञान नहीं है अपितु तर्क, विवेक तथा आसावादी मूल्य का समन्वय भी है, जो मनुष्य को शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा होने का ज्ञान देती है।

स्त्री परिवेश और सामाजिक बोध :-

कोहली ने उपन्यास में स्त्री के लगभग सभी सामाजिक रूपों का उद्घाटन किया है। उन्होंने कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सीता, अहिल्या, सदानिरा, वनजा, निषाद की पत्नी, पुत्री और पुत्र वधू आदि के माध्यम से स्त्री के अनेक रूप प्रस्तुत किए हैं। जिनमें स्त्री त्याग, समर्पण, मातृत्व एवं प्रेम आदि के साथ–साथ शोषण की शिकार भी है। वह धर्म, मर्यादा के साथ सामाजिक संबंधों का अनुसरण कर, सामाजिक चेतना की आधारशिला बनती

है। प्राचीन काल से नारी को केवल एक गृहणी के रूप में ही देखा जाता था, जिसका का कार्य और अधिकार केवल गृहकार्य तक ही सीमित था। सामाजिक अत्याचार को नारी प्रारंभ ही से भोगती आई है। उपन्यास में अहिल्या, वनजा, निषाद की पत्नी, पुत्रवधू तथा अन्य महिलाओं के साथ अनेक अत्याचारों का चित्रण हुआ है। अहिल्या स्वयं के साथ हुए अन्याय को सहते हुए अपने पति और पुत्र के लिए स्वयं का बलिदान देती है। वह ऋषि गौतम से कहती है कि– "मुझे अपनी बलि देनी होगी। आपके और शत के बिना रहना मेरे लिए कितना कठिन होगा। शारीरिक असुरक्षा या असुविधा, मानसिक यातना, भावनात्मक क्लेश– और जाने क्या–क्या सहना पड़े। किंतु मैं अपने पति और पुत्र का भविष्य तो नष्ट नहीं कर सकती।"[13] वनजा को राक्षसों, अहिल्या को इंद्र, निषाद गहन की पत्नी, पुत्री और पुत्र वधू को सेनानायक के पुत्र देवप्रिय तथा उनके साथियों द्वारा पीड़ित किया जाता है। जनक आर्यों, असुर और नाग राजाओं से रक्षा के लिए सीता को वीर्य शुक्ला घोषित करते हैं। कौशल्या भारतीय संस्कृति की आदर्श नारी के रूप में है, जो अपने पति, पुत्र, परिवार और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने कुल की मर्यादाओं से भी बंदी है। सुमित्रा एक साहसी एवं निर्भीक स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। कैकेयी अपने चरित्र में आधुनिक समाज के नारी के गुणों को लिए हुए हैं। वह हठीली, उग्र, महत्वाकांक्षिणी के साथ सुंदर नारी भी है, जिसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना भली भांति आता है। सीता एक ऐसी कन्या है, जिसे समाज की रूढ़ियों, परंपराओं एवं अपने पिता की विवशता का ज्ञान है। वह अपने पिता की इच्छा के अनुरूप ही सहयोग करने वाली कन्या है।

प्रतीकात्मकता और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि :–

रामकथा को आधार बनाकर कोहली ने प्रतिकों और रूपकों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की गहराई को उजागर करने का कार्य किया है। इस उपन्यास में नारी की स्थिति, शिक्षा के महत्व, गुरु–शिष्य परंपरा और सामाजिक सुधार को आधुनिकता से जोड़ते हुए प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्कृति में राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं परंतु कोहली ने उन्हें एक साधारण मानवीय रूप में प्रस्तुत किया है। जो मानवीय कमजोरियों एवं सांस्कृतिक आदर्शों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। कोहली राम के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं– "उन्होंने विलास में नहीं, परिश्रम और शस्त्राभ्यास में आकार ग्रहण किया था। राम का वर्ण सांवला था, बड़ी–बड़ी स्वच्छ, ईमानदार, निर्भीक, आंखें, चौड़ा माथा, तीखी नाक, मोहक हंसी से आवेष्टित होंठ, दृढ़ संकल्प वाली ठुड्डी।"[14] राक्षस समाज में व्याप्त अत्याचार, अन्याय, दुराचार, दुरूशासन, पाप, अहिंसा, दुष्कर्म आदि नैतिक बुराइयों के प्रतीक है। इन्हें मारना भारतीय संस्कृति की स्थापना और धर्म की अधर्म पर विजय की प्रतीकात्मकता को दर्शाता है। वर्तमान में शिक्षा के नाम पर फैले भ्रष्टाचार, गुरु–शिष्य के मध्य स्वार्थ, लोभ, शोषण आदि के सम्मुख कोहली विश्वामित्र के माध्यम से ज्ञान, तप, न्याय, और समाज कल्याण का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जिसका उद्देश्य केवल स्वयं का स्वार्थ न होकर समाज कल्याण है। जिससे वे समाज को रूढ़िवादी परंपराओं, कुरितियों एवं भेदभावपूर्ण व्यवस्था से बाहर निकालते हैं। अहिल्या एक ऐसी स्त्री के रूप में है, जो इंद्र द्वारा पीड़ित एवं समाज द्वारा बहिष्कृत होने पर भी आत्महत्या नहीं करती बल्कि परिस्थितियों का दृढ़ता के साथ सामना करती है। सीता, कौशल्या, सुमित्रा और अहिल्या यह प्रमाणित करते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी केवल ग्रहस्त जीवन की सहचरी न होकर आदर्श, सहनशीलता एवं त्याग का प्रतिरूप भी है।

निष्कर्ष :-

नरेन्द्र कोहली ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अवयवों गुरु–शिष्य परंपरा, शिक्षा के महत्व, सामाजिक सुधार और नारी की स्थिति का गहराई से चित्रण किया है। इन्होंने रामकथा को आधुनिक संदर्भ में ढालकर संस्कृति की प्रासंगिकता एवं चुनौतियां को उद्घाटित किया है। पौराणिकता और समकालीनता का सामंजस्य, प्रतीकात्मकता तथा सामाजिक चिंतन इस उपन्यास को हिंदी साहित्य में एक विशेष सांस्कृतिक दस्तावेज बनाते हैं। यह उपन्यास भारतीय समाज की सांस्कृतिक जटिलताओं को उजागर कर, सामाजिक परिवर्तन एवं नैतिक पुनरुत्थान के महत्व पर बल देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ० बाबूराम (2002), हिन्दी निबंध साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन, प्रथम संस्करण, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 94
2. अग्रवाल, वासुदेवशरण (1960), कल्पवृक्ष, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, पृ. 26
3. डॉ० बाबूराम (2002), हिन्दी निबंध साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन, प्रथम संस्करण, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 93
4. कोहली, नरेन्द्र, (2005), दीक्षा, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 27
5. कोहली, नरेन्द्र, (2005), दीक्षा, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 126
6. कोहली, नरेन्द्र, (2005), दीक्षा, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 140
7. कोहली, नरेन्द्र, (2005), दीक्षा, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 43
8. कोहली, नरेन्द्र, (2005), दीक्षा, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 15
9. कोहली, नरेन्द्र, (2005), दीक्षा, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 73
10. कोहली, नरेन्द्र, (2005), दीक्षा, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 119
11. कोहली, नरेन्द्र, (2005), दीक्षा, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 49
12. कोहली, नरेन्द्र, (2005), दीक्षा, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 50
13. कोहली, नरेन्द्र, (2005), दीक्षा, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 140
14. कोहली, नरेन्द्र, (2005), दीक्षा, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 168

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 181-186

क्षेत्रीय एकता को सुदृढ़ करने में सांस्कृतिक कूटनीति की भूमिका : सार्क के परिप्रेक्ष्य में

धर्मेन्द्र कुमार
SRF, राजनीति विज्ञान विभाग,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखण्ड।

शोध सारांश :-

दक्षिण एशिया दुनिया का एक समृद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र है जहाँ धर्म, भाषा, जीवन शैली एवं कलाएँ में विविधता के साथ गहरे साझा ऐतिहासिक संबंध मौजूद हैं। यहाँ पर परम्परागत कुटनीति ने इन क्षेत्रों पर कई बार अस्थायी समझौते किए, परन्तु स्थायित्व और विश्वसनीयता नहीं बनी रहीं। सांस्कृतिक क्षेत्र पर काम करने के लिए सार्क द्वारा कई बार सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संस्थागत पहल की गई परन्तु राजनीतिक गतिरोधों के कारण नियमित रूप से कार्य कार्य संभव ना हो सका। सार्क ने लोक कला एवं विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कई पहले की है। इस पहलू मे मुख्य केन्द्र सार्क सांस्कृतिक केन्द्र (SCC) है। इसका प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना एवं दक्षिण एशिया के लोगों को करीब लाना है। सदस्य देशों में अत्याधिक भाषाई और सांस्कृतिक विविधता है। इन देशों में सैकड़ों भाषाएँ एवं हजारों बोलियाँ बोली जाती हैं। यह भाषाई विविध चुनौती और सहयोग का अवसर प्रदान करती है। इन क्षेत्र में विभिन्न धर्म, परंपराओं, कला, खान–पान और जीवन–शैली पाई जाती है। इस क्षेत्र में हिंदू, इस्लाम, बौद्ध सिख, जैन आदि कई धर्मो का जन्मस्थान और प्रमुख केन्द्र रहा है। विविधता एक ताकत होती है परन्तु समान संदेश एवं सामग्री सभी तक पहुचाने में जटिलता भी होती है।

मुख्य शब्द – सार्वभौमिक, दृष्टिकोण, आकर्षण, आत्मनिर्भरता, परियोजनाओं, जागरूकता।

प्रस्तावना –

क्षेत्रीय संगठन केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता तक सीमित नहीं रहते है – वे इतिहास एवं संस्कृति तथा साझा पहचान के आधार पर दीर्घकालिक स्थिरता एवं सहयोग का विकसित करते है। दक्षिण एशिया दुनिया का एक समृद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र है जहाँ धर्म, भाषा, जीवन शैली एवं कलाएँ में विविधता के साथ गहरे साझा ऐतिहासिक संबंध मौजूद हैं। यहाँ पर परम्परागत कुटनीति ने इन क्षेत्रों पर कई बार अस्थायी समझौते किए, परन्तु स्थायित्व और विश्वसनीयता नहीं बनी रहीं। वास्तविक स्थायित्व और विश्वसनीयता तभी बनती है जब लोगों से लोगों (People to people) के रिश्ते सांस्कृतिक स्मृतियाँ और साझा जड़ों पर काम होता है। इस दृष्टिकोण से

सांस्कृतिक कूटनीति क्षेत्रीय एकता के निर्माण में प्रमुख साधन बन सकता है–खासकर सार्क जैसे संगठन में। राजनीतिक जटिलताएँ एवं विश्वास की भारी कमी अक्सर सार्क को सार्वभौमिक नीतिगत पहल को बाधित करता है।

सांस्कृतिक कूटनीति –

सांस्कृतिक कूटनीति का तात्पर्य यह है कि एक राज्य द्वारा अपनी संस्कृति के आदान–प्रदान के माध्यम से दूसरे राज्य के साथ संबंध विकसित करना, समझ को बढ़ावा देना एवं अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। यह किसी राज्य की ''सॉफ्ट पावर'' का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो, रख सख्त शक्ति (Hard Power) के बजाय आकर्षण के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते है।

सांस्कृतिक कूटनीति के प्रमुख पहलू –

- समझ और सहयोग को बढ़ावा देना।
- सकारात्मक छवि का निर्माण।
- कूटनीतिक लक्ष्यों को पूरा करना।
- लोगों के बीच संबंध स्थापित करना।

सार्क – दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक भू–राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन जिसे सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) कहा जाता है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई जिसमें प्रारम्भ में 7 देश भारत बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका था। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान 8वाँ सदस्य के रूप में शामिल हुआ। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सामूहिक आत्मनिर्भरता तथा स्थिरता को बढ़ावा देना हैं।

सार्क के सांस्कृतिक कूटनीति के प्रमुख माध्यम –

सांस्कृतिक क्षेत्र पर काम करने के लिए सार्क द्वारा कई बार सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संस्थागत पहल की गई परन्तु राजनीतिक गतिरोधों के कारण नियमित रूप से कार्य कार्य संभव ना हो सका। सांस्कृतिक कूटनीति एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ राजनीति की सीमाओं के पार लोगों के बीच संपर्क स्थापित किया जा सकता है जिससे संबंध प्रगाढ़ होगें। सार्क के सांस्कृतिक कूटनीतिक प्रमुख माध्यम निम्नलिखित है :–

1. **सार्क सांस्कृतिक केन्द्र (SCC) और संस्थागत नेटवर्क** – सार्क सांस्कृतिक केन्द्र श्रीलंका के कोलंबो में 2009 में स्थापित किया गया था, प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा सार्क सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय एकता को मजबूत करना था। यह केन्द्र कला के रूपों नृत्य, संगीत, नाटक, मूर्तिकला, चित्रकला एवं साहित्य को बढ़ावा देता है। यह प्रतियोगिताएँ, सांस्कृतिक उत्सव, वार्षिक कार्यक्रम एवं प्रकाशनों (समचार पत्रिका एवं सांस्कृतिक पत्रिका) का आयोजन करता है। यह केन्द्र विभिन्न सांस्कृतिक एवं कलात्मक संस्थाओं के द्वारा एक विस्तृत नेटवर्क बनाता है।

2. **सांस्कृतिक और फिल्म महोत्सव** – श्रीलंका के कोलंबो में 1999 से सार्क सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा सार्क फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। यह सार्क देशों के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देता है। यह इस क्षेत्र के फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने और सदस्यों के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान को मजबूत करने में मदद करता है। सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्क देशों के

बीच अलग–अलग शहरों में एक वर्ष तक भोजन, साहित्य, नृत्यों और फिल्मों संबंधित आयोजन किए जाते है।

3. शिक्षा एवं छात्र आदान–प्रदान – सार्क देश शिक्षा को मानव विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए एक मौलिक अधिकार मानते है। सार्क देशों ने साक्षरता को बढ़ावा देने एवं सभी स्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सहयोग पर बल दिया है। सदस्य देशों के द्वारा 1996 को ''साक्षरता के सार्क वर्ष'' के रूप में मनाया गया। सदस्य देशों के द्वारा एक पहल करते हुए नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU) की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय द्वारा सदस्य देशों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करती है तथा इसकी डिग्री सभी सदस्य देशों में मान्य होती है। सार्क सचिवालय काठमांडू में सार्क ईटर्नशिप कार्यक्रम (SIP) चलाया जाता है जिसमें जागरूकता और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सार्क देशों के बीच फेलोशिप, छात्रवृत्तियाँ एवं सार्क चेयर स्थापित करने पर सहमति बनी है।

4. लोक कला एवं विरासत परियोजनाएँ – सार्क ने लोक कला एवं विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कई पहले की है। इस पहलू मे मुख्य केन्द्र सार्क सांस्कृतिक केन्द्र (SCC) है। इसका प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना एवं दक्षिण एशिया के लोगों को करीब लाना है। सार्क द्धारा सार्क विरासत मंच (SAARC Heritage Feum) फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटस एंड लिटरेचर (FOSWAL), कला और संस्कृति कार्यक्रम, सार्क कल्चर जर्नल एवं सार्क आर्ट मैगजीन तथा संगोष्ठी जैस विभिन्न गतिविधियों और परियोजनाओं का आयोजन कर रहा है। ये सभी पहल एवं परियोजनाएँ सदस्य देशों के बीच अंतर–सांस्कृतिक सेवा को बढ़ावा देने एवं सांस्कृतिक एकीकरण तथा क्षेत्र की समृद्ध एवं विविध मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रचार एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

5. खेल और युवा-संबंधी कार्यक्रम :–

सार्क के एजेंडे मे, जिसे सार्क ''एकीकृत कार्यक्रम कार्रवाई'' या ''कार्य के क्षेत्रीय कार्यक्रम'' में खेल एवं कला शामिल है। सदस्य देशों के बीच दक्षिण एशियाई खेल (South Asian Games) में एथलीटों के बीच होने वाला एक बहु–खेल आयोजन है। यह प्रत्येक चार साल में आयोजित किया जाता है। सार्क द्वारा प्रत्येक वर्ष 20–35 वर्ष की आयु के युवाओं को विभिन्न होतों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ''सार्क युवा'' पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें प्रशस्ति पत्र, स्वर्ण पदक एवं 3000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाता है।

सांस्कृतिक कूटनीति के फायदे –

नियमित सांस्कृतिक आदान–प्रदान से पारस्पारिक विश्वास बढ़ता है, जिससे राजनीतिक तनाव कम करने में सहायक हो सकता है। भाषा, संगीत एवं साझा सांस्कृतिक विरासत सदस्य देशों के लोगों को जोड़ती है। जब राजनीतिक गतिरोध होता है उस समय संस्कृति माध्यम के रूप में बातचीत जारी रख सकती है। पर्यटन, धार्मिक यात्राएँ तथा सांस्कृतिक उत्पादों के बाजार बनाने से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ प्राप्त होता है। युवा, कला और नवाचार के द्वारा से क्षेत्रीय ज्ञान नेटवर्क बनाएँ जा सकते है।

चुनौतियाँ एवं बाधाएँ –

सार्क सदस्य देशों में सांस्कृतिक कुटनीति लाभों के बावजूद कई चुनौतियाँ और बाधाएँ है, जो निम्न है–

(1) राजनीतिक अस्थिरता और द्विपक्षीय तनाव :– सदस्य देशों, खासकर छोटे देशों में, नेतृत्व और सरकार में बार–बार परिवर्तन होने से (श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल) होने से क्षेत्रीय पहलों और समझौते के प्रति

प्रतिबद्धता में निरंतरता का कभी रहता है। आंतरिक राजनीतिक संकट, नागरिक संघर्ष एवं राजनीतिक गतिरोध के कारण क्षेत्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका केन्द्रित नहीं कर पाते है। सार्क की संरचना का यह सिद्धांत है कि द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दो पर चर्चा नहीं की जाएगी, परन्तु सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय तनाव ने अप्रत्यक्ष रूप से सार्क की प्रणाली को प्रभावित करता है। द्विपक्षीय मुद्दो कारण कई सार्क शिखर सम्मेलन को रद्द करना पड़ा है।

2) वित्तीय एवं संसाधन सीमाएँ :-

सार्क के पास परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी संसाधनों की भारी कमी है। सार्क विकास कोष (SDF) के पास अपर्याप्त धन और प्रभावशाली परियोजनाओं के कमी के कारण पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। साफ्टा (SAFTA) का क्रियान्वयन असंतोषजनक रहा है। इन देशों के बीच में टेरिफ और गैर–टैरिफ बाधाएँ बहुत ही ज्यादा है। जिससे अंतर–क्षेत्रीय व्यापार में बाधा उत्पन होती है। सदस्य देशों में अंतर–क्षेत्रीय निवेश का स्तर काफी कम है, जिससे आर्थिक–निर्भरता कमजोर होती है।

3) भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता :-

सदस्य देशों में अत्याधिक भाषाई और सांस्कृतिक विविधता है। इन देशों में सैकड़ों भाषाएँ एवं हजारों बोलियाँ बोली जाती हैं। यह भाषाई विविध चुनौती और सहयोग का अवसर प्रदान करती है। इन क्षेत्र में विभिन्न धर्म, परंपराओं, कला, खान–पान और जीवन–शैली पाई जाती है। इस क्षेत्र में हिंदू, इस्लाम, बौद्ध सिख, जैन आदि कई धर्मो का जन्मस्थान और प्रमुख केन्द्र रहा है। विविधता एक ताकत होती है परन्तु समान संदेश एवं सामग्री सभी तक पहुचाने में जटिलता भी होती है।

4) असमान शक्ति संतुलन :-

असमान शक्ति संतुलन मुख्य रूप से भारत की अन्य सदस्य देशों की तुलना में हैं। यह असंतुलन भारत की बड़ी भौगोलिक, आर्थिक एवं सैन्य शक्ति के कारण अक्सर भारत के छोटे पड़ोसी देश भारत की ''बड़े भाई'' वाले रवैये को लेकर सशंकित रहते है एवं उन्हें लगता है कि भारत क्षेत्रीय सहयोग के बजाय द्विपक्षीय संबंधों पर अधिक महत्व देता है। असमान शक्ति संतुलन सार्क के भीतर ऐसी वास्तविकता है जिससे क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करने एवं संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाएँ उत्पन्न होती है।

5) नागरिक स्तर पर अविश्वास एवं सुरक्षा चिंताएँ :-

नागरिक स्तर पर अविश्वास एवं सुरक्षा चिंताएँ मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गहरे राजनीतिक मतभेद और ऐतिहासिक शत्रुता से उत्पन्न होती है। यह अविश्वास क्षेत्रीय सहयोग में खलल डालती है और लोगों के बीच में भी प्रभाव डालती है। ये अविश्वास और चिंताए अंतर–सरकारी अविश्वास एवं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, सुरक्षा संबंधी मुद्दे (सीमा–पार आतंकवाद), बड़े एवं छोटे देशों की बीच अविश्वास तथा क्षेत्रीय विवादों को विभिन्न मंचों पर उठाने के कारण बनी है। ये सभी कारण एक ऐसा माहौल बनाती है जिससे नागरिको के बीच आपसी संदेह तथा शत्रुता बनी रहती है।

6) संस्थागत कमजोरी :-

सार्क में कोई भी निर्णय सभी सदस्य देश सर्वसम्मति से करते हैं। अर्थात किसी बड़े फैसले या पहल के लिए सभी सदस्यों का सहमति आवश्यक होता है। इस कारण कई महत्वपूर्ण फैसले या पहल नहीं हो पाते

है, सार्क के द्वारा यदि कोई समझौते या निर्णय लिया जाता है तो उसे कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र की कमी है। सार्क के संस्थागत ढाँचे को धीमा, अप्रभावी एवं नौकरशाही वाला बताया गया है जिसे अपने एजेंडे को प्रभावी ढंग से बढ़ाने में असमर्थ है। ये संस्थागत कमजोरी सार्क की प्रभावशीलता को कम कर देती है।

नीति सुझाव :–

सार्क में सांस्कृतिक कूटनीति को प्रभावी बनाने के लिए सार्क कुछ ठोस नीतिगत कार्य करने होगें –

- सार्क स्तर पर सांस्कृतिक कोष एवं एक स्वतंत्र मिशन जो परियोजना के लिए दीर्घकालिक बजट सुनिश्चित कर सके।
- सदस्य देशों के शोधकर्ताओं व छात्रों लिए छात्रवृत्ति/फेलोशिप की व्यवस्था हो ताकि मानव नेटवर्क का विकास हो सके।
- भाषा रूपांतरण के साथ एक साझा डिजिटल आर्काइव जिसमें नृत्य, लोकगीत, फिल्में, ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध हो।
- कलाकार – विनिमय प्रोग्राम तथा नगर–स्तरीय (City to City) ''सांस्कृतिक और प्रदेश स्तर पर सांस्कृतिक पहल'' हो।
- संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प एवं स्थानीय कला बाजार के लिए साझा प्रशिक्षण प्रोग्राम व बाजारों में पहुँच हो।
- क्षेत्रीय युवा शिखर सम्मेलन, खेल टूर्नामेंट एवं संयुक्त कैंप का आयोजन हो।
- NGOs, सांस्कृतिक संस्थान और निजी प्रायोजन को प्रोत्साहित करके परियोजनाओं की वित्तीय स्थिरता मजबूत करना।
- राजनैतिक तनाव के समय भी सांस्कृतिक संवाद को जारी रखना ताकि तनाव को कम किया जा सके।

निष्कर्ष :–

सार्क जैसे बहु–आयामी और विविध क्षेत्र में राजनीतिक जटिलताओं के बावजूद सांस्कृतिक कूटनीति एक व्यवहार्य एवं आवश्यक मार्ग है। सांस्कृतिक कूटनीति केवल ''सही– भावना'' या ''सौंदर्यात्मक'' की बात नहीं हैं बल्कि यह सांस्कृतिक कूटनीति व्यावहारिक तौर पर विश्वास निर्माण, पहचान संवर्धन और आर्थिक सहयोग की नींव रखती है। परन्तु इसके लिए नियमित रूप से वित्तपोषण, संस्थागत प्रतिबद्धता, भाषा–समर्थन एवं नागरिक स्तर पर भागीदारी अनिवार्य है। सार्क की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब सांस्कृतिक पहले राजनीतिक संस्कारों से आंशिक रूप से स्वतंत्र होकर लोगों की प्रतिदिन जीवन का हिस्सा बनें। ऐसे समय में जब भू–राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता बढ़ रही सांस्कृतिक कूटनीति सार्क को पुनः सक्रिय करने एवं क्षेत्रीय एकता को मजबूत करने का सबसे उत्तम रास्ता प्रदान कर सकती है।

सन्दर्भ सूची :–

1. सिंह, स्वरन. (2011). दक्षिण एशिया : सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग. नई दिल्ली : पेंटागन प्रेस।
2. सार्क सचिवालय. (2020). सार्क सांस्कृतिक केंद्र वार्षिक रिपोर्ट 2020. कोलंबो : सार्क सांस्कृतिक केंद्र।

3. थरूर, शशि. (2012). पैक्स इंडियाः इक्कीसवीं सदी में भारत और विश्व. नई दिल्लीः पेंगुइन बुक्स।
4. राणा, के. एस. (2013). इक्कीसवीं सदी की कूटनीति : एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका. नई दिल्ली : कंटीन्युअम।
5. आचार्य, अमितव. (2011). दक्षिण पूर्व एशिया में सुरक्षा समुदाय का निर्माण : आसियान और क्षेत्रीय व्यवस्था की समस्या. लंदन : रूटलेज।
6. शशि, एन. (2018). सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावरः वैश्विक दक्षिण का दृष्टिकोण. अंतरराष्ट्रीय संबंध अध्ययन पत्रिका, 14(2), 45–63।
7. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, (2019). दक्षिण एशिया में भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति. नई दिल्लीः नीति पत्र श्रृंखला।
8. सार्क सचिवालय. (2018). दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का चार्टर. काठमांडूः सार्क सचिवालय।
9. भट्टाचार्य, सौम्या. (2019). भारत की विदेश नीति में सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति. भारतीय राजनीतिक विज्ञान पत्रिका, 80(4), 675–692।
10. सार्क सचिवालय. (2021). दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक एकीकरण की दिशा मेंः नीति पत्र. काठमांडूः सार्क सचिवालय।
11. यूनेस्को. (2017). दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय सहयोग. पेरिसः यूनेस्को प्रकाशन।

मो०– 9708641843
Email- dharmendracri@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 187–192

कुमारसम्भव में प्रकृति चित्रण

हिमांशु कुमार
SRF, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखण्ड।

शोध सारांश :–

महाकवि कालिदास प्रणीत सात काव्यों की प्राप्ति होती है, जिसमें से दो महाकाव्य (रघुवंशम् एवं कुमारसम्भवम्), दो खण्डकाव्य (ऋतुसंहार एवं मेघदूत), तीन रूपक (अभिज्ञानशाकुन्तलम्, विक्रमोर्वशीयम् एवं मालविकाग्निमित्रम्) शामिल है। इन काव्यों में प्रकृति के विविध रूपों की प्राप्ति होती है, जो कालिदास के प्रकृति प्रेम को दर्शाती है। इस महाकाव्य में कवि कहता है कि ''भारतवर्ष के उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा वाला पर्वतों का राजा हिमालय अवस्थित है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों का अवगाहन करके पृथ्वी के मापने के दण्ड के समान स्थित है।'' तपोवन में आकर ब्रह्मचारी द्वारा पार्वती से यह पूछने पर कि तपोवन की लताओं एवं वृक्षों में कोपल फूटना उचित प्रकार से तो हो रहा है ना ! किसी प्रकार का अवरोध तो नहीं है? वन का जल तुम्हारे स्नान करने योग्य तो है? दूषित तो नहीं हैं? इत्यादि। इसके बाद सूर्य के किरणों का जाल समेट लिए जाने का वर्णन है जिसके कारण हिमालय के निर्झरो पर अंकित इन्द्रधनुष धीरे–धीरे मिटते जा रहे हैं। कमल का कोश बन्द हो रहा है, पर भीतर प्रवेश करते भ्रमर को स्थान देने के लिए कमल अपने पत्तों को ढँकते हुए ठहर गया है।

मुख्य शब्द – इन्द्रधनुष, अवगाहन, प्रगल्भ, साङ्गोपाङ्ग, सकारात्मक, सेतुबन्ध आदि।

प्रस्तावना –

महाकवि कालिदास ने कुमारसम्भव की रचना 17 सर्गों में की है। कुमार कार्तिकेय के जन्म को आधार बनाकर प्रस्तुत महाकाव्य का निर्माण किया गया है। विद्वानों द्वारा प्रस्तुत महाकाव्य के प्रथम आठ सर्ग ही कालिदास प्रणीत स्वीकार किये जाते हैं क्योंकि मल्लिनाथ आदि टीकाकारों ने इस महाकाव्य के प्रथम आठ सर्गों तक ही टीका लिखा है। इस महाकाव्य में कुमार के जन्म के अतिरिक्त हिमालय का वर्णन किया गया है। इसमें कवि पार्वती के विविध रूपों का वर्णन करता है। जैसे– बाला पार्वती, तपस्वी पार्वती, विनयवती पार्वती और प्रगल्भ पार्वती आदि के रूप में उनका वर्णन किया गया है। इसी महाकाव्य में शिव की प्राप्ति हेतु पार्वती की तपस्या का वर्णन किया गया है तथा पार्वती को तपस्या से दूर करने हेतु ब्रह्मचारी के द्वारा शिव की निन्दा किए जाने का उल्लेख है। इसमें वसन्त ऋतु के आगमन का वर्णन किया गया है साथ में शिव और पार्वती के विवाह का भी वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में उक्त विषयों का विशेष वर्णन प्राप्त होता है साथ ही प्रकृति का मानवीय

एवं जीवन्त चित्रण महाकवि कालिदास के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। साहित्यदर्पण में महाकाव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि इसमें सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न, शिकार, पर्वत, ऋतु, वन एवं समुद्र जैसे उपादानों का साङ्गोपाङ्ग वर्णन होना चाहिए—

सन्ध्यासूर्येन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः।
प्रातर्मध्याह्नमृगयाशैलर्तुवनसागराः।।[1]

कालिदास और उनका प्रकृति प्रेम –

महाकवि कालिदास प्रणीत सात काव्यों की प्राप्ति होती है, जिसमें से दो महाकाव्य (रघुवंशम् एवं कुमारसम्भवम्), दो खण्डकाव्य (ऋतुसंहार एवं मेघदूत), तीन रूपक (अभिज्ञानशाकुन्तलम्, विक्रमोर्वशीयम् एवं मालविकाग्निमित्रम्) शामिल है। इन काव्यों में प्रकृति के विविध रूपों की प्राप्ति होती है, जो कालिदास के प्रकृति प्रेम को दर्शाती है। रघुवंशम् में राजा दिलीप के द्वारा किए जा रहे गोसेवा का उल्लेख, पर्वतीय झरनों का उल्लेख, सन्ध्याकालीन सूर्य एवं उनके तेज का उल्लेख, प्रातःकालीन वायु से वृक्षों से गिरने वाले पुष्पों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत महाकाव्य के पञ्चम सर्ग में ओंस की बूँदों का, इन्दुमती के स्वयंवर के समय वर्षा ऋतु का एवं गोवर्धन पर्वत पर मयुर के नृत्य का मनोहर चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार से महाकवि कालिदास प्रस्तुत महाकाव्य में प्राकृतिक सौन्दर्य का बडा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

कालिदास प्रणीत दो खण्डकाव्यों ऋतुसंहार एवं मेघदूत में प्रकृति का विशद वर्णन प्राप्त होता है। ऋतुसंहार में छह ऋतुओं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर का वर्णन किया गया है। इसमें प्रत्येक ऋतुओं की विशिष्टता, वनस्पति, जीवों आदि का विशेष वर्णन किया गया है, जो मानवीय चेतना पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसी प्रकार मेघदूत में भी प्रकृति के सौन्दर्य का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। इसमें मेघ का, वनों का, नदियों का विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें अलकापुरी के भवनों की तुलना मेघ से की गई है एवं वहाँ की स्त्रियों एवं प्रकृति का वर्णन किया गया है।

अभिज्ञानशाकुन्तल में प्रकृति का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रकृति को मानवीय रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा वृक्षों से शकुन्तला के वियोग को बहुत ही गम्भीरता से कालिदास ने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार प्रकृति के अन्य रूप विक्रमोर्वशीयम् एवं मालविकाग्निमित्रम् में प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास प्रकृति प्रेमी थे क्योंकि इन्होंने प्रकृति का अत्यन्त सूक्ष्म वर्णन किया तथा उसे मानव रूप में प्रस्तुत किया।

कुमारसम्भव में प्रकृति के विविध रूप –

इस महाकाव्य में कवि प्रकृति के अनेकों रूपों को प्रस्तुत करता है। वह सर्वप्रथम हिमालय का वर्णन करते हुए कहता है –

अस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्यां इव मानदण्डः।।[2]

यहाँ कवि कहता है कि ''भारतवर्ष के उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा वाला पर्वतों का राजा हिमालय अवस्थित है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों का अवगाहन करके पृथ्वी के मापने के दण्ड के समान स्थित है।''

यश्चाप्सरोविभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति।बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्।।[3]

इसी महाकाव्य में हिमालय के ऊँचे शिखरों एवं वहाँ तपस्या करने वाले सिद्ध महात्माओं का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसी महाकाव्य में प्रकृति के सहज सौन्दर्य, मानवीय राग, कोमल भावनाओं तथा कल्पना के नवनवोन्मेष के अनेकों रूप दृश्यमान होते हैं, उसे भारतीय साहित्य का शिखर कहा जा सकता है। कवि ने सन्ध्या का वर्णन और रात्रि का चित्रण किया है तथा हिमालय के पावन प्रदेश में शिखर के गरिमामय वचनों के द्वारा पार्वती को सम्बोधित कराया है। इसके पश्चात कवि पश्चिम में डूबते हुए सूर्य की रश्मियों का सरोवर के जल में लम्बी–लम्बी होकर प्रतिबिम्बित होने का वर्णन करता है, तो ज्ञात होता है कि अपनी सुदीर्घ परछाइयों के द्वारा भगवान सूर्य ने जल में सोने के सेतुबन्ध रव डाले हों। इसके बाद वृक्ष के शिखर पर बैठा मयूर ढलते सूर्य के घटते चले जाते सोने के जैसे गौरमण्डलयुक्त आतप को बैठा पी रहा हो।[4] पूर्व में अंधेरो बढ़ रहा है, आकाश के सरोवर से सूर्य ने जैसे आतप रूपी जल को सोख लिया, तो इस सरोवर के एक कोने में जैसे कीचड़ ऊपर आ गया हो –

न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुञ्जरविन्दुशोणाः।
व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणामनङ्गलेख क्रिययोपयोगम्।।[5]

इसके बाद सूर्य के किरणों का जाल समेट लिए जाने का वर्णन है जिसके कारण हिमालय के निर्झरो पर अंकित इन्द्रधनुष धीरे–धीरे मिटते जा रहे हैं। कमल का कोश बन्द हो रहा है, पर भीतर प्रवेश करते भ्रमर को स्थान देने के लिए कमल अपने पत्तों को ढँकते हुए ठहर गया है। अस्त होते हुए सूर्य की किरणें बादलों पर पड़ रही है जिससे उनकी नोंके रक्त, पीत और कपिश हो गयी है, जैसे सन्ध्या ने पार्वती को दिखाने के लिये तूलिका उठा कर उन पर रंग–बिरंगी छवियों उकेर दी हों। इसी महाकाव्य में चन्द्रमा की किरणों के लिये जौ के ताजा अंकुर का उपमान देकर उन्होंने मानो स्वर्ग को धरती से मिला दिया है।

इसके उपरान्त धूम का वर्णन किया गया है तथा पार्वती के लिए माला गूँथे जाने का वर्णन करते हुए कहा गया है–

धूपोष्मणा त्याजितमार्द्रभावं केशान्तमन्तः कुसुमं तदीयम्।
पर्याक्षिपत्काचिदुदारबन्धं दूर्वावता पाण्डुमधूकदाम्ना।।[6]

इसके बाद चारों दिशाओं को भुद्ध करने के लिए हवन, यज्ञ एवं चन्दन के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है।

सा लाजधूमाञ्जलिमिष्टगन्धं गुरूपदेशाद्वदनं निनाय।
कपोलसंसर्पिशिखः स तस्या मुहूर्तकर्णोत्पलतां प्रपेदे।।[7]

पुष्पों के लताओं का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं –

पर्याप्तपुष्पस्तवकस्तनाभ्यः स्फुरत्प्रवालौष्ठमनोहराभ्यः।
लतावधूभ्यस्तरवोऽप्यवापुर्विनम्रशाखाभुजवन्धनानि।।[8]

इंद्र ने कामदेव को अपना कार्य बताते हुए कहा कि "शिव के मन में पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न करो।" कामदेव उद्यत होकर अपने सहचर वसंत और पत्नी रति के साथ शिव के समाधि स्थल पर जा पहुँचते हैं। वसंत ने सारे वातावरण को सकाम कर दिया–

मधु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमानः।

श्रृंगेण च स्पर्शनिमीलिताक्षी मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः।।[9]

भ्रमर और भ्रमरी एक ही पुष्प में मधुपान करने लगे। ये तो जीवधारी ही हैं। जड़ वृक्षों की कामुकता देखते ही बनती थी। उन्होंने भी अपनी शाखारुपी भुजाओं को फैलाकर लताओं का आलिंगन किया। ऐसे वातावरण में योगी शिव के समीप कामदेव पहुँचता है। उन्हें देखकर ''काम के धनुर्बाण अनजाने ही हाथ से गिर जाते हैं।'' वह डरा, परन्तु तभी सुंदरी पार्वती के रुप में उसे सहारा दिखाई दिया। वह शंकर की सेवा करने आ पहुँची थी। यही अवसर था कि काम अपना काम बनाता। कवि के अनुसार प्रकृति में जो सौन्दर्य व्याप्त है। मानव का सौन्दर्य उसी का अंग है, इसीलिए प्रकृति से आदर्श स्थितियों का चयन करके कवि ने उसको अपनी सौन्दर्यानुभूति की व्यंजना का साधन बनाया है। मानवीय सौन्दर्य एवं प्राकृतिक सौन्दर्य में से अपेक्षाकृत कौन सा अधिक सुन्दर है, इसका निर्णय कर पाना कठिन कार्य है। पार्वती की रूपशोभा का चित्रण इसका प्रमाण है, जहाँ स्तनों के भार से कुछ झुकी हुई और बालसूर्य के सदृश अरुणवस्त्र धारण किए, पर्याप्त फूलों के गुच्छों से झुकी हुई चलती फिरती लता के समान प्रतीत हो रहीं हैं –

आवर्जिता किं चिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरूणार्करागम्।
पर्याप्तपुष्पस्तवकावनम्रा सञ्चारिणी पल्लविनी लतेव।।[10]

तपोवन में आकर ब्रह्मचारी द्वारा पार्वती से यह पूछने पर कि तपोवन की लताओं एवं वृक्षों में कोपल फूटना उचित प्रकार से तो हो रहा है ना! किसी प्रकार का अवरोध तो नहीं है? वन का जल तुम्हारे स्नान करने योग्य तो है? दूषित तो नहीं हैं? इत्यादि प्रश्न प्रकृति के मूलभूत (जल, वृक्ष, वनस्पति आदि) तत्वों की शुद्धता एवं संवर्द्धन के प्रति मानव को जागरूक रहने का संदेश देते हैं–

विरोधिसत्त्वोज्झितपूर्वमत्सरं द्रुमैरभीष्टप्रसवार्चितातिथि।
नवोटजाभ्यन्तरसम्भृतानलं तपोवनं तच्च बभूव पावनम्।।[11]

वास्तव में देखा जाये तो प्राचीन ग्रन्थों में जल को दूषित करना महापाप माना गया है। यथा– रामायण में महर्षि वाल्मीकि भरत के मुख से इस प्रसंग को प्रकट कराते हुए कहते हैं कि ''जिस की अनुमति से मेरे भ्राता राम वन गये हैं, उसे उसी प्रकार का भयंकर पाप लगना चाहिए जो जल को दूषित करने या किसी को विष देने पर लगता है–

पानीयदूषके पापं तथैव विषदायके।
यत्तदेकः स लभतां यस्योर्यानुमते गतः।।[12]

अर्थात् पानी को दूषित करना किसी को विष देकर जीवन समाप्त करने के समतुल्य स्वीकार किया गया है। प्राणियों के जीवन में जल की अपरिहार्य आवश्यकता एवं उसके अभाव में प्राणियों के जीवन संबंधित दुःख को दर्शाया गया है।

इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग में पार्वती को पुष्पों से भी सुन्दर चित्रित करते हुए कवि कहते हैं –

शिरीषपुष्पाधिकसौकुमार्यौ बाहू तदीयाविति मे वितर्कः।
पराजितेनापि कृतौ हरस्य यौ कण्ठपाशौ मकरध्वजे।।[13]

साथ ही कवि कहता है –

पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थम्।

ततो नुकुर्याद्विशदस्य तस्यास्ताम्रौष्ठपर्यस्तरुचः स्मितस्य।।[14]

इसके बाद कवि ने उमा (पार्वती) के सौन्दर्य का वर्णन प्रकृति से जोड़कर करते हुए कहा है :–

चन्द्रपाजनितप्रवृत्तिभिश्चन्द्रकानतजलबिन्दुभिर्गिरिः।
मेखलातरुषु निद्रितानमून्बोधयत्यसमये शिखण्डिनः।।[15]

तथा

कल्पवृक्षशिखरेषु सम्प्रति प्रस्फुरदिभरिव पश्य सुन्दरि।
हारयष्टिरचनामिवांशुभिः कर्तुमद्यतकुतूहलः शशी।।[16]

इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत महाकाव्य में प्रकृति के विविध रूपों को प्रस्तुत किया है एवं साथ में अनेक प्राकृतिक उपमाओं के द्वारा दृश्यों को मनोहर रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है।

निष्कर्ष –

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि जो प्रतिभा के धना कवि हैं उन्होंने अपने अन्य काव्यों की भाँति इस काव्य में भी प्रकृति को बड़े ही मनोरम रूप में प्रस्तुत किया है। जहाँ वह प्रथम सर्ग में मुख्य रूप से हिमालय एवं उसके आस–पास के सौन्दर्य आदि का वर्णन किया है, ठीक उसी प्रकार का वर्णन कवि ने पार्वती का वर्णन करते हुए एवं तपोभूमि का वर्णन करते हुए किया है। जो कि कवि का प्रकृति प्रेम के साथ उसका दृश्टिकोण भी प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत महाकाव्य में प्रकृति के अनेकों रूप दृश्टिगत होते हैं जिन सभी को यहाँ प्रस्तुत कर पाया सम्भव नहीं है। अतः यह अवश्य कहा जा सकता है कि कालिदास ने अपनी प्रत्येक रचनाओं में प्रकृति को विशेष स्थान दिया है, जिसकी झलक हमें ''कुमारसम्भवम्'' में भी देखने को मिलती है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए विश के वृक्ष को इस प्रकार चित्रित करते हैं–

इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीर्नेत एवार्हति क्षयम्।
विषवृक्षोऽपि संवर्धय स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्।।[17]

सन्दर्भ सूची –

1. साहित्यदर्पण, षष्ठ परिच्छेद, 322
2. पाण्डेय, परमेश्वरदीन, कुमारसम्भवम्, वाराणसी, चौखम्भा कृष्णदास अकादमी, 2013, प्रथम सर्ग, श्लोक संख्या–01
3. वही, प्रथम सर्ग, श्लोक–04
4. सिंह नीतू, कुमारसम्भवम् महाकाव्य में पर्यावरण : एक विमर्श, Gyanshauryam International Scientific Refereed Research Journal (GISRRJ), March- April 2019, Vol. 02, Page no- 15-19, ISSN: 2582-0095
5. पाण्डेय, परमेश्वरदीन, कुमारसम्भवम्, वाराणसी, चौखम्भा कृशणदास अकादमी, 2013, प्रथम सर्ग, श्लोक संख्या–07
6. वही, सप्तम सर्ग, श्लोक–14
7. वही, सप्तम सर्ग, श्लोक–81

8. वही, तृतीय सर्ग, श्लोक–39
9. वही, तृतीय सर्ग, श्लोक–36
10. वही, तृतीय सर्ग, श्लोक–54
11. वही, पञ्चम सर्ग, श्लोक–17
12. वाल्मीकीय रामायण, अयोध्याकाण्ड, सर्ग–75, श्लोक–53
13. वही, प्रथम सर्ग, श्लोक–41
14. वही, प्रथम सर्ग, श्लोक–44
15. वही, अष्टम सर्ग, श्लोक–67
16. वही, अष्टम सर्ग, श्लोक–68
17. वही, द्वितीय सर्ग, श्लोक–55

मो०– 6203018775
Email- himansukumarhns@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 193–199

कबीर के साहित्य में सामाजिक चेतना

डॉ. बाल किशोर राम भगत
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी
एम. टी. शासकीय कन्या महाविद्यालय, रायगढ़ छ.ग.–496001

सारांश :

कबीर भारतीय संत परंपरा के ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में समाज की विसंगतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों के प्रति गहरी सामाजिक चेतना झलकती है। उन्होंने जाति–पांति, उंच–नीच, पाखण्ड और धार्मिक कट्टरता के विरूद्ध आवाज उठाई। कबीर का साहित्य केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार का माध्यम भी है। उनकी वाणी मानवतावाद, समानता और प्रेम की शिक्षा देती है। यह शोध पत्र कबीर के साहित्य में निहित सामाजिक चेतना, उनके समाज सुधारक दृष्टिकोण तथा आधुनिक संदर्भो में उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है।

बीज शब्द – कबीर, समाज, सामाजिक चेतना, समानता भक्ति आंदोलन, मानवतावाद, सुधार, प्रेम, जातिवाद, पाखंड।

प्रस्तावना :–

भारतीय साहित्य में संत काव्य परंपरा का एक प्रमुख स्थान है और इस परंपरा के सबसे प्रखर कवि हैं–संत कबीर। 15वीं शताब्दी में जन्मे कबीर का जीवन समाज के गहरे विरोधाभासों के बीच बीता। उस समय भारीतय समाज जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर और पाखंड से ग्रस्त था। कबीर ने इन विकृतियों के विरूद्ध अपनी निर्भक आवाज उठाई। उनका साहित्य केवल ईश्वर भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का उद्घोष है। उन्होंने 'मानव' को ही ईश्वर का प्रतीक मानकर, धर्म के नाम पर किये जा रहे भेदभावों को चुनौती दी।

कबीर कहते हैं –

> **'जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान,**
> **मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।'**

यह दोहा कबीर की सामाजिक चेतना का परिचायक है।

कबीर का युगीन परिप्रेक्ष्य :

कबीर का समय भारतीय समाज के लिए संक्रमणकाल था। एक ओर भक्ति आंदोलन का उदय हो रहा था, तो दूसरी ओर समाज में छुआछूत, उँच–नीच और धर्मांधता का बोलबाला था। हिन्दू–मुस्लिम दोनों ही समाजों

में धार्मिक पाखंड और कर्मकांड का वर्चस्व था।

कबीर ने इसी परिवेश में जन्म लेकर सत्य, प्रेम और मानवता के संदेश से समाज को झकझोरा। उन्होंने कहा–

'पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।'

यह दोहा धार्मिक ज्ञान के नाम पर फैले अज्ञान और पाखंड पर करारा प्रहार है।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

कबीर का जीवनकाल लगभग 15वीं शताब्दी का माना जाता है। एक ऐसा समय जब भारत राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से गहन परिवर्तन से गुजर रहा था। दिल्ली सल्तनत का पतन और मुगल सामाज्य के उदय का काल था। विदेशी आक्रमणों, आर्थिक असमानता और धर्मान्धता के कारण समाज अस्थिर था।

2. धार्मिक स्थिति :

धर्म के नाम पर समाज दो भागों में बँट चुका था– हिन्दू और मुस्लिम में। हिन्दू समाज कर्मकांड, मूर्तिपूजा, जातिवाद और ब्राहमणवादी रूढ़ियों में जकड़ा था। मुस्लिम समाज में भी बाहय आडंबर, कट्टरता और सूफी विचारधारा के बीच संघर्ष था। इस धार्मिक अंधकार में कबीर ने सच्चे आध्यात्मिक अनुभव और मानवता के धर्म की बात की। ''माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर।'' यह पंक्ति उनके युग में धर्म के बाहय रूप की आलोचना करती है।

3. सामाजिक स्थिति :

कबीर का समय सामाजिक दृष्टि से अत्यंत जटिल था। जाति प्रथा ने मनुष्यता को बॉट रखा था। अस्पृश्यता और उँच–नीच की भावना चरम पर थी। स्त्रियों की स्थिति भी दोयम दर्जे की थी। कबीर ने इन बुराइयों के विरूद्ध अपनी वाणी से क्रांति की। ''जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।'' उनकी दृष्टि में मनुष्य का मूल्य कर्म और ज्ञान से है, न कि जाति से।

4. आर्थिक स्थिति :

कबीर स्वयं बुनकर थे। श्रमिक वर्ग से जुड़े हुए थे। उनके समय में शिल्पकार वर्ग आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे, परन्तु उनके श्रम पर ही समाज टिका था। कबीर ने श्रम की प्रतिष्ठा की बात की ओर कहा कि सच्चा धर्म कर्मयोग है।

5. सांस्कृतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि :

15वीं शताब्दी भक्ति आंदोलन का उत्कर्ष काल था। तुलसी, सूर, मीरा जैसे संत कवि इसी धारा से जुड़े। कबीर इस आंदोलन के निर्गुण भक्ति पक्ष के प्रवर्तक थे। उनकी भाषा सधुक्कड़ी थी। लोकजीवन से जुड़ी, सरल और व्यंग्यपूर्ण थी।

6. दार्शनिक दृष्टि :

कबीर ने ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापक और मानवीय अनुभूति का केन्द्र माना। उन्होंने ज्ञान, प्रेम और अनुभव को मुक्ति का मार्ग बताया। उनकी वाणी उस युग की आध्यात्मिक खोज का सार है– जहॉ ईश्वर और मनुष्य के बीच कोई मध्यस्थ नहीं।

7. युगीन प्रभाव और परिवर्तन :

कबीर ने अपने समय की सामाजिक चेतना को झकझोरा। उनकी वाणी ने भक्ति आंदोलन को लोकधारा से जोड़ा। उन्होंने वर्ग, जाति और धर्म से उपर उठकर मानव धर्म की स्थापना की। उन्होंने धार्मिक एकता को बल दिया। समानता और श्रम की गरिमा को प्रतिष्ठित किया और समाज में आत्मा की स्वतंत्रता का संदेश फैलाया।

कबीर की सामाजिक चेतना :

कबीर की सामाजिक चेतना कई स्तरों पर व्यक्त होती है।

1. जाति-पांति और ऊँच-नीच के विरोध में चेतना :

कबीर ने जातिवाद को समाज की सबसे बड़ी बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मूल्य उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और व्यवहर से आंका जाना चाहिए।

'एक बूंद, एक मलमूत्र, एक चाम, एक गूदा,
कह कबीर ते नर काहे भये, जाति-पांति का झूला।'

उनका यह दृष्टिकोण मानव समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है।

2. धार्मिक कट्टरता और पाखंड के विरोध में चेतना :

कबीर ने हिन्दू–मुस्लिम दोनों समाजों की कुरीतियों पर खुलकर प्रहार किया। उन्होंने मन्दिर–मस्जिद दोनों को असत्य आचरण के प्रतीक बताया और कहा कि सच्चा ईश्वर मनुष्य के हृदय में है, न कि बाहरी कर्मकाण्डों में।

'माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर,
कर का मनका डार दे, मन का मनका फेर।'

यह दोहा धार्मिक कर्मकाण्ड की निष्प्रभाविता को उजागर करता है।

3. मानवतावाद और प्रेम की चेतना :

कबीर की वाणी का सबसे बड़ा संदेश है मानवता और प्रेम। उन्होंने कहा कि सभी धर्मो का मूल सार प्रेम है, और यही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है।

'प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट विकाय,
राजा परजा जेही रूचै, शीश दे ले जाय।'

कबीर का यह भाव सम्पूर्ण मानव जाति को जोड़ने वाला है। वे न हिन्दू हैं, न मुसलमान—वे केवल इंसान है।

4. श्रम और स्वावलंबन की चेतना :

कबीर स्वयं जुलाहा थे और उन्होंने श्रम को ईश्वर की पूजा कहा। उनके अनुसार मेहनत करने वाला व्यक्ति समाज का आधार है।

'कबिरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ,
जे घर फूंके आपना, चल हमारे साथ।'

यह प्रतीकात्मक दोहा उस व्यक्ति की चेतना का प्रतिनिधित्व करना है जो अपने भीतर की बुराईयों को

जलाकर समाज में प्रकाश फैलाना चाहता है।

5. नारी के प्रति दृष्टिकोण :

कबीर का नारी संबंधी दृष्टिकोण कुछ दोहों में आलोचनात्मक प्रतीत होता है, किन्तु वास्तविक रूप में उन्होंने नारी को सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग माना। उन्होंने नारी को साधना की सहयोगी और सृजन की जननी कहा।

> **'नारी नर का रूप है, नर नारी का मान,**
> **दोनों मिल जग उपजै, ताते करै बखान।'**

यह दृष्टिकोण समाज में लैंगिक समानता की भावना जगाता है।

6. सामाजिक समानता और भाईचारा :

कबीर की सामाजिक चेतना का मूल आधार भाईचारा और एकता है। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति, भाषा, वर्ण–सभी भेद कृत्रिम है, मनुष्य का असली धर्म है 'मानवता'।

> **'हिन्दू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना,**
> **आपस में दोउ लरि मरिहैं, मरम न कोउ जाना।।'**

इस दोहे में कबीर धार्मिक संघर्षो पर गहरी चोट करते है और मानवता को सर्वोच्च धर्म बताते हैं।

7. अंधविश्वास और कर्मकांड पर प्रहार :

कबीर ने समाज में फैले अंधविश्वासों को मूर्खता बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे मन और आचरण की जरूरत है।

> **'कंकर पाथर जोड़ि के, मस्जिद लई चुनाय,**
> **ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाय?'**

यह दोहा धार्मिक आडंबर के खिलाफ सीधा सवाल उठाता है।

8. आर्थिक और श्रमिक वर्ग के प्रति सहानुभूति :

कबीर समाज के गरीब और श्रमिक वर्ग के पक्षधर थे। वे स्वयं उस वर्ग से आते थे और उनकी कविताओं में उस वर्ग की पीड़ा, संघर्ष और आत्मसम्मान झलकता है। उनकी वाणी में 'श्रम की गरिमा' और 'मानव परिश्रम का आदर 'स्पष्ट दिखता है।

कबीर की भाषा और शैली में सामाजिकता :

कबीर ने साधारण जन की भाषा–साधु हिन्दी या सधुक्कड़ी में अपनी बातें कही। उनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा गया जिसमें अवधी, भोजपुरी, ब्रज खड़ी बोली और पंजाबी के शब्दों का समावेश मिलता है। इससे उनकी वाणी सीधे जनता के हृदय में उतर गई। उनकी भाषा में देशज शब्द, लोकोक्तियाँ, व्यंग्य और प्रतीक का प्रयोग समाज की वास्तविकता को उजागर करता है। उदाहरण के लिए–

> **'माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय,**
> **एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोय।।'**

यह दोहा सामाजिक और दार्शनिक दोनों दृष्टियों से गहराई लिए हुए हैं।

1. **भाषा में सामाजिक चेतना :**

कबीर की भाषा में सामाजिक अन्याय और विसंगतियों के विरूद्ध तीखा व्यंग्य है। उन्होंने पंड़ित, मुल्ला, राजा, साधु सभी को समान रूप से प्रश्नों के घेरे में रखा।

'पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंड़ित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंड़ित होय।।'

यहाँ भाषा सीधे समाज के हृदय पर चोट करती है किसी दार्शनिक या शास्त्रीय ढंग से नहीं, बल्कि जनभाषा में।

2. **कबीर की शैली में सामाजिकता :**

कबीर की शैली अनेक रूपों में प्रकट होती है, व्यंग्य, संवाद, प्रतीकात्मक, रहस्यवादी और लोक धर्मी। इन सभी में समाज के प्रति उनकी गहरी दृष्टि विद्यमान है।

1. **व्यंग्यात्मक शैली** – कबीर दास समाज के दोषों पर व्यंग्य करते हैं, पर उनका उद्देश्य निंदा नहीं बल्कि सुधार है।

"माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर,
कर का मनका डार दे, मन का मनका फेर।।"

यह व्यंग्य समाज के पाखंड़ी धामिक आचरण पर प्रहार है।

2. **प्रतीकात्मक शैली** – कबीर ने समाज की सच्चाइयों को प्रतीकों में व्यक्त किया, घट–शरीर, जल–आत्मा, जाल–माया, आदि। ये प्रतीक जनजीवन से लिए गये हैं, जिससे उनके विचार जनसुलभ बन गए।

"घट-घट में पहुँचे साहिब, घट ही के भीतर देख।"

3. **संवादात्मक शैली** – कबीर की वाणी में प्रश्नोत्तर का रू॰ मिलता है जो विचार–विमर्श को जन्म देता है। यह शैली समाज में तकशीलता और आत्मचिन्तन को प्रेरित करती है।

4. **लोकधर्मी शैली** – उनकी शैली में लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें और लोकलय का सहज प्रयोग हुआ है। यही उनकी वाणी को सामाजिक आधार देता है।

"कबीरा खड़ा बजार में, सबकी मांगे खैर।"

यह वाक्य लोकवृति और सामाजिक करूणा का उत्कृष्ट उदाहरण है।

कबीर की सामाजिक चेतना की आधुनिक प्रासंगिकता :

कबीर की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 15वीं शताब्दी में थी। आज भी समाज में जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, और असमानता विद्यमान है। कबीर का संदेश हमें मानवता, समानता और सहिष्णुता की राह दिखाता है। उनकी वाणी हमें सिखाती है कि–

"सच्चा धर्म मंदिरों में नहीं,
बल्कि मनुष्य के आचरण में है।"

आज जब समाज वर्ग, जाति और धर्म के नाम पर बंटा हुआ है, कबीर की सामाजिक चेतना समरसता और एकता का आधार प्रदान करती है।

1. **जातिवाद के संदर्भ में** – आज भी भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव मौजूद है। शिक्षा, रोजगार और

सामाजिक जीवन में ऊंच–नीच की भावना बरकरार है। कबीर दास जी कहते हैं–'' सब मनुष्य एक देह का, सबका एक रक्त।'' हमें समानता और सामाजिक समरसता की दिशा में आगे बढ़ने को प्रेरित करता है।

2. **धार्मिक असहिष्णुता के संदर्भ में** – कबीर ने हिन्दू और मुस्लिम दोनों समाजों में व्याप्त कट्टरता पर प्रहार किया।आज के समय में जब धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, तब कबीर की यह वाणी विशेष रूप से उपयोगी है–

''हिन्दू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना,
आपस में दोउ लरि मरिहैं, मरम न कोउ जाना।।''

यह दोहा हमें धर्म से उपर उठकर मानवता के धर्म को स्वीकारने का आवहान करता है।

3. **स्त्री की स्थिति के संदर्भ में** – कबीर ने नारी को जीवन का सहचर और सृजन का मूल माना। उन्होंने कहा–

''नारी नर का रूप है, नर नारी का मान,
दोनों मिल जग उपजै, ताते करै बखान।।''

आज जब लैंगिक समानता का प्रश्न समाज में उठ रहा है, कबीर की दृष्टि हमें संतुलन और सम्मान की शिक्षा देती है।

4. **पर्यावरण और प्रकृति के प्रति दृष्टि** – कबीर की वाणी में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है, वे जल, मिट्टी, वायु जैसे तत्वों को जीवन का आधार मानते हैं।

''जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी।''

आज जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, कबीर का यह भाव प्रकृति और जीवन की एकता का बोध कराता है।

5. **उपभोक्तावाद और नैतिक पतन के संदर्भ में** – आज का समाज भौतिक सुख–सुविधाओं के पीछे भाग रहा है और नैतिकता पीछे छूटती जा रही है। कबीर की सादगी, संतोष और आत्मनिष्ठा का आदर्श इस स्थिति में अत्यंत प्रेरणादायक है।

कबीर के विचार और आधुनिक मानवाधिकार :

कबीर ने बिना किसी औपचारिक संविधान या आंदोलन के मानवाधिकारों की नींव रखी थी –

1. **जीवन का अधिकार** – हर मनुष्य को जीने का समान अधिकार है।
2. **विचार की स्वतंत्रता** – उन्होंने तर्क, आत्मज्ञान और स्वतंत्र चिंतन को महत्व दिया।
3. **धर्म की स्वतंत्रता** – उन्होंने किसी एक धर्म की श्रेष्ठता नहीं मानी।

आधुनिक भारत के संदर्भ में :

आज भारत जिस दौर से गुजर रहा है, जहॉ धर्म और राजनीति का संबंध जटिल होता जा रहा है, सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं, और नैतिक मूल्य घट रहे हैं–ऐसे में कबीर की वाणी फिर से ''मार्गदर्शक दीप'' बन जाती है। उनकी चेतना ''समानता, सत्य और प्रेम'' पर आधारित एक मानवीय समाज के निर्माण की प्रेरणा देती है।

निष्कर्ष :

कबीर भारतीय समाज के ऐसे युगद्रष्टा कवि थे। जिन्होंने अपने समय की सामाजिक बुराईयों को पहचाना

और उनसे संघर्ष किया। उनकी वाणी में धार्मिक, नैतिक और सामाजिक चेतना का अद्भूत संगम है। कबीर का साहित्य केवल भक्ति नहीं, बल्कि मानवता का घोषणा पत्र है। उन्होंने समाज में जब समाज फिर से विभाजन और असहिष्णुता की ओर बढ़ रहा है, कबीर की सामाजिक चेतना हमें पुनः सत्य, प्रेम और करूणा की ओर लौटने की प्रेरणा देती है।

कबीर का संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म मंदिरों–मस्जिदों में नहीं, बल्कि मनुष्य के व्यवहार और प्रेम में है। कबीर का संदेश है ''सबका मालिक एक'', प्रेम ही सच्चा धर्म'', ''मानवता सर्वोपरि''। कबीर अपने युग के अंधकार में मानवता का दीपक जलाया, जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है।

संदर्भ सूची :

1. द्विवेदी, हजारी प्रसाद–कबीर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 1943
2. शुक्ल, आ. रामचन्द्र –हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, वर्ष 1929
3. सिंह, नामवर – कविता के नए प्रतिमान, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 1957
4. भारती, डॉ. धर्मवीर – संत साहित्य और समाज, राजकमल, नई दिल्ली, वर्ष 1952
5. विश्वनाथ त्रिपाठी – लोक और साहित्य।
6. कबीर ग्रंथावली – सम्पादक, आचार्य परमहंस यादव।
7. डॉ. रामविलास शर्मा– भक्ति आंदोलन और समाज परिवर्तन।
8. कबीर–बीजक, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, वर्ष 1872
9. अज्ञेय – भक्ति आंदोलन और संत साहित्य।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 200–206

उषा प्रियंवदा के कथा साहित्य में नारी के प्रति दृष्टिकोण

भारती अग्रवाल, शोधार्थी,
डॉ. हुसैनी बोहरा, शोध–निर्देशक, सहायक आचार्य,
हिन्दी विभाग, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर।

हिन्दी साहित्य का इतिहास इस तथ्य का प्रमाण है कि समय–समय पर स्त्री जीवन और उनकी समस्याएं कथा साहित्य के केन्द्र में रही है। उषा प्रियंवदा ने स्त्री और समकालीन समाज की सच्चाई को अपने साहित्य द्वारा दर्शाया है। उषा जी का साहित्य नारी के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को उजागर करता है व समाज में स्त्री को उसकी जगह दिलाता है। उनके लेखन का समय भारतीय समाज में तेज बदलाव का दौर रहा है। स्त्रियां शिक्षा और नौकरी में आगे बढ रही थी परंतु मानसिक व सामाजिक बंधन अब भी बने हुए थें। उषा प्रियंवदा ने समाज में स्त्री की स्थिति दोहरी जिंदगी जीती नारियों की समस्या, आधुनिक नारी की बदलती हुई तस्वीर दांपत्य जीवन का कटु सत्य वर्तमान समय में बनते–बिगड़ते रिश्तों में नारी की भूमिका, नारी शिक्षा, नारी के संघर्षों आदी पर गहन और अत्यंत तल्खी के साथ रचनाएं प्रस्तुत की हैं। स्त्री दृष्टिकोण उषा जी के साहित्य में इसलिए भी उभरा है कि आधी दुनिया में प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत अनुभव समाज में बांटना शुरू कर दिया।

समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर का हक मिला है, परंतु पुरुषवादी सोच ने स्त्री को हमेशा से दोयम दर्जा दे रखा है। इसी दोयम दर्जे की सोच ने उषा जी को विवश करते हुए कलम उठाने को प्रेरित किया व उन्होने स्त्री मानसिकता, भावनाएं, आदि पर कथा साहित्य लिख डाला। 21वीं सदी के आने पर भी स्त्री की दशा कुछ खास सुधरी नहीं है, जितनी कि होनी चाहिए। स्त्रियों को आज भी न तो अधिकार प्राप्त है ना ही समाज और घर में सम्मान। इसी के साथ नारी आज भी शिक्षा व स्वतंत्रता से वंचित है। आज भी स्त्री को सामाजिक मर्यादा का पाठ पढ़ाकर चुप रहने पर विवश किया जाता है। उषा जी के साथ–साथ कई लेखकों द्वारा स्त्री शिक्षा व सम्मान पर लिखने व तमाम प्रयासों के बाद भी समाज के कुछ हिस्सों में ही नारी के जीवन में बदलाव व चेतना का प्रकाश नजर आता है। अभी भी समाज में बहुत सुधार की आवश्यकता है। स्त्री को बड़े केनवास पर देखा जाए तो यह मुद्दा मात्र नारी और नारीत्व के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, वरन् राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए भी आवश्यक है। उषा जी ने अपने देखे और भोगे यथार्थ को स्त्री सम्मान के माध्यम से अभिव्यक्त करना प्रारंभ किया। कई महिला कथाकारों ने अपने लेखन व साहित्य में स्त्री दृष्टिकोण को दर्शाया है। जैसे की शिवानी, मन्नू भंडारी, मृणाल पांडे, कृष्णा सोबती व मृदुला गर्ग। इनके अतिरिक्त पुरुष कथाकारों ने भी स्त्री संवेदना पर प्रभावी लेखन किया है। जैसे की मोहन राकेश, भीष्म साहनी लक्ष्मीकांत, नरेन्द्र मोहन, पुष्पपाल, सिंह

आदि ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्री की स्थिति पर लेखन किया। उषा जी ने नारी–चेतना की अभिव्यक्ति भी की है अपने लेखन में साथ ही उनका मानना है कि स्त्री केवल घर–परिवार तक सीमित नहीं है, उसके भी अपने सपने, इच्छाएं और स्वतंत्र व्यक्तित्व है। उनका साहित्य नारी की स्वायत्ता और आत्मसम्मान की तलाश का दर्पण है। जिन्होने अपने साहित्य में विशेष रूप से नारी के जीवन, उसकी मन स्थितियों संघर्षों और बदलती भूमिकाओं को प्रमुखता दी है। वे स्वयं एक शिक्षित, आत्मनिर्भर व संवेदनशील महिला है। उन्होनें देखा कि समाज मे स्त्री को परिवार पंरपरा और समाज की जकड़ में किस प्रकार अपनी इच्छाएं सपने और अस्तित्व को कुर्बान करने पड़ते हैं। यही अनुभव उन्हें स्त्री के भीतर की पीड़ा और शक्ति लिखने के लिए प्रेरित करते है।

उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से बताया है कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का दर्पण है और सुधार का माध्यम भी है। इसलिए या इसी कारण उषा जी ने अपने साहित्य को स्त्री दर्पण और आत्मसम्मान की लेखनी बनाई। ताकि स्त्री की स्थिति पर चर्चा हो और समाज जागरूक बने। लेकिन हमारे समाज में लंबे समय से स्त्री को या तो देवी या त्याग की मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है या फिर उन्हें पुरुष जीवन का सहायक बनाकर समाज में प्रस्तुत किया गया। उषा जी के साहित्यों में स्वतंत्र नारी चेतना उसके अधिकार उसकी इच्छाएं और उनकी संवेदनाएं बहुत देर बाद साहित्य में अपनी जगह बना पाईं। इसी परिप्रेक्ष्य में उषा जी का कथा–साहित्य उल्लेखनीय है। उन्होंने स्त्री को न केवल जीवन का यथार्थ रूप प्रदान किया बल्कि उनकी मनोवैज्ञानिक गइराई, सामाजिक संघर्ष और आत्म–सम्मान की खोज को भी केन्द्र में रखा।

उनके साहित्य में स्त्री केवल पांरपरिक गृहिणी या पुरुष–आश्रित नहीं है बल्कि वह स्वयं में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। उषा प्रियंवदा ने आधुनिक मध्यवर्गीय स्त्री की समस्याओं का अपनी कहानियों और उपन्यासों में ऐसा यथार्थ चित्रण किया है, जो एक और उसकी पीडा और संघर्ष को उजागर करता है, वहीं दूसरी और उसकी स्वतंत्रता और आत्म–सम्मान की आकांक्षा को भी स्वर देता है। उषा जी ने स्त्री को मानव के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। अपने लेखन के द्वारा पारंपरिक साहित्य में स्त्री को केवल या अकसर त्याग की मूर्ति या, देवी प्रलोभन मानकर दिखाया गया है। लेकिन इन सब से अलग उषा जी ने स्त्री को पहली बार एक साधारण इंसान की तरह प्रस्तुत किया। जिसकी अपनी कमजोरियां, अपनी इच्छाएं और अपना संघर्ष है। यही उषा प्रियंवदा के लखेन की सबसे बडी विशेषता है। उषा जी ने अपनी नायिकाओं को पाठकों से जुड़ाव के लिए उनको आम जीवन की स्त्रियों के रूप में प्रस्तुत किया है, जिन्हें पाठक अपने आस–पास पहचान सकते है। यही कारण है उनका साहित्य लोकप्रिय बना और स्त्री–दशा का सशक्त माध्यम रहा। उषा जी ने दोहरी जिम्मेदारियों के बीच पीसती नारी का भी यर्थाथ चित्रण किया है। नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते–निभाते स्त्री अपनी स्वयं की खुशी पसंद–नापसंद चाहतों, आदि को तिलांजली दे देती है। उषा जी ने साहित्य में महिलाओं पर इसलिए लिखा क्योंकि वे स्वयं महिला होने के नाते उनकी पीडा और संघर्ष को गहराई से समझती है।

समाज का बदलता रूप उन्हें बार–बार स्त्री के अस्तित्व की ओर खीचता है। उषा प्रियंवदा ने स्त्री को सिर्फ 'भूमिका' नहीं बल्कि स्वत्रंत व्यक्तिगत के रूप में प्रस्तुत करना चाहा और ऐसा उन्होंने अपनी लेखनी में किया भी है। उषा जी की लेखनी व साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि उन्होंने नारी मन की गहराईयों को बड़ी बारीकी से उद्धघाटित किया है। उनकी नायिकाएं बाहर से भले ही साधारण दिखे, लेकिन भीतर से वह गहरी भावनाओं आशंकाओं और आकांक्षाओं से भरी होती है। वे प्रेम करती है बिखरती है फिर भी

उठ खड़ी होती है। वे चाहती है उनका अस्तित्व केवल किसी के 'संबंध' से परिभाषित न हो। उषा जी का साहित्य पाठकों को यह बताता है कि यह समाज स्त्री को हमेशा सीमाओं में बांधने की कोशिश करता है। कभी उस पर अच्छी गृहिणी बनने का दबाव, कभी उसे त्यागमयी मां, की छवी तो कभी 'शालीन स्त्री' की मर्यादाओं में रहने को सिखाता है। लेकिन साथ ही साथ उषा जी की नायिकाएं इन सब को चुनौती देती है। वे घर से बाहर निकलकर काम करती है, स्वतंत्र निर्णय लेती है और अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानती हैं। उषा जी का कथा–साहित्य नारी–जीवन का यथार्थ दस्तावेज है। पाठक यह अच्छी तरह देख सकते हैं कि कैसे उनकी नायिकाएं संघर्ष करती हैं।

लेकिन आत्म–सम्मान की खोज नहीं छोड़ती है। उन्होंने समाज को यह बताया कि नारी भी सोच सकती है, समझ सकती है। इससे यह पता चलता है कि समाज में एक नारी न तो पुरुष पर ना ही परिवार पर आश्रित है वो स्वयं पूर्ण है और स्वतंत्र नारी है। उषा जी का साहित्य नारी चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति है और हिन्दी कथा–साहित्य की अमूल्य धरोहर है। उषा प्रियंवदा ने अपने कथा–साहित्य में स्त्री के अधिकारों एवं मानसिक उत्पीडन तथा चुनौतियों को विषयवस्तु बनाया है। आज भी इतना विकास होने पर भी स्त्री का अस्तित्व परंपरा के भंवर के फंसा हुआ है। इसी के साथ उषा जी की कहानियों व उपन्यासों के कथानक में गहरी संवेदनशीलता है जो पाठकों को उपन्यास के पात्रों के साथ जोडने में मदद करती है।

उषा प्रियंवदा की कहानियों में स्त्री के मन की भावनात्मक जटिलताएं और उसके अनुभवों को संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया गया है। उषा प्रियंवदा की कहानी मान और हठ में नायिका अमृता और मुकल के बीच के जटिल रिश्ते को दर्शाया है। यहां पर भावनात्मक आदान–प्रदान को दर्शाया है। किस तरह अमृता की इच्छाओं को मारकर एक कुरूप धनवान व्यक्ति से उसकी शादी कर दी जाती है। जिसको अपने पैसों का घमंड होता है। ''मुकूल को उन्हीं सब बातों की साध थी, जो हर एक युवक को होती है। और शायद भाग्य से उसे ऐसी पत्नी भी मिल गई थी। जो देखने में अनन्य सुन्दरी थी। पर मुकुल ने एक बार भी यह सोचने की कोशिश नहीं कि उस उर्वशी जैसी अमृता के भी न जाने क्या–क्या अरमान होंगे। उसकी समझ में स्त्रियों को केवल यही चीजे चाहिए–रुपया और मोटर और वह यह सब चीजें अमृता को दे सकता है।''[1] इस संवाद से पुरुष मानसिकता को बोध होता है कि वे सिर्फ स्त्री को एक वस्तु समझते है उनके लिए स्त्री की भावनाएं, आत्मसम्मान, आदि कुछ मोल नहीं रखते है। अमृता नायिका का संवाद मैं क्यों जाऊं बात शुरू तो उन्होंने ही की है। यह तो नहीं की अपने आचरण से अपनी कुरूपता को ढांकने का प्रयास करे ऊपर से धौंस जमाते है।''[2] यह वाक्य स्पष्ट करता है कि नारी केवल भोजन पकाने बच्चों को पालने वाली मशीन नहीं है। उसे भी प्रेम सम्मान और भावनात्मक सहारे की आवश्यकता होती है। अपने पति की उपेक्षा और संवेदनहीनता नायिका को भीतर तक तोड़ देती है। देश में स्त्री होना ही दश है। जन्म लेते ही अवहेलना की शिकार होती नारी अपमानजनक जीवन जीते–जीते बड़ी हो जाती है। बहुत बार तो लिंग परीक्षण द्वारा गर्भ में ही मार दी जाती है। एक नारी अपने–आप को खोजने में आत्मसम्मान आदि के लिए समझौता नहीं करती है। जैसे अमृता अपने सपनों से समझौता नहीं करती। उसका वाक्य ''बस, मुझे ही दोष दो। यह तो नहीं कि मुझसे जरा–सी सहानभूति दिखाओं। क्या मेरे अरमान मेरी चाहें कुछ भी नहीं? औरत की चाहे अरमान कुछ महत्व नहीं रखते। यह दुनिया पुरुषों की है। फिर आखिर रूप–रंग में रखा ही क्या है।''[3] यह मार्मिक संवाद स्पष्ट करता है कि स्त्री की भी इच्छाएं है, उसके भी

अपने अरमान है जिसको दबा दिया जाता है, पुरुषवादी सोच के नीचे। हर बार स्त्री को ही मौन का पाठ पढाकर चुप करवाने की कोशिश की जाती है।

स्त्री भी मान–सम्मान व मर्यादा के पीछे उनकी हाँ में हां कर देती है। यह मान और हठ की नायिका अमृता के अनुसार गलती उसकी अवश्य थी कि उसने शादी से पहले मुकूल को नहीं देखा मगर वह कहती भी कैसे कि वह उसे देखना चाहती है। भाई ने पहले ही कह दिया था कि देखने में मुकुल साधारण है और फिर भी मुकुल का यह गर्व यह मान एक पत्र भी नहीं डाला, पूरे दो साल हो गए। अगर मुकूल झुकता तो वह उसे स्वीकार कर लेती। पर स्वंय झुकना उसे सह्म नहीं था।''[4] यह वाक्य बताता है कि उषा जी कि नायिकाएं झुकना नहीं जानती। वह गिरती है और फिर उठ खडी होती है। वह अपने मान–सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती है। रूकोगी नहीं राधिका में स्वयं राधिका कहती है ''मै अपनी राह पर चलना चाहती हूं, किसी के लिए रूकना मेरे स्वभाव में नहीं है।''[5] राधिका स्वतंत्र स्त्री का चित्र प्रस्तुत करती है। यहां राधिका सारे ही बंधनो को तोडते हुए नौकरी, आत्मनिर्भर व आत्मसम्मान पाना चाह रही है।

राधिका स्वयं परंपरागत मर्यादाओं से मुक्त हो उसकी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा करती है। स्त्री का सर्वाधिक शोषण परिवार की मान प्रतिष्ठा की आड में किया जाता है। एक स्त्री कैसे अकेलेपन और आत्मबोध की गहन अभिव्यक्ति से खुद को भूल जाती है। ''शेष यात्रा'' कहानी में नारी स्वयं की खोज करते हुए मिलती है।'' अनु का यह वाक्य इस बात की पुष्टि करता है अनु को लगता है कि कही कुछ अलक्ष्य घटा है। जिंदगी की जो गाडी आराम से पटरी पर चली जा रही थी, जैसे लडखड़ाने लगी है।''[6] कारण या प्रणवाद उसकी लम्बी–लम्बी चुप्पियों उसका अनमनापन उसका बात बात पर गरम हो जाना अनु को झिडक देना यह जानकारी देता है या स्त्री जीवन के उस संघर्ष को उजागर करता है जिसमें वह अपने अस्तित्व की सार्थकता स्वयं खोजती है। यह स्त्री जीवन और उसके संघर्षो को दर्शाता है।

इससे पता चलता है कि स्त्री की स्वतंत्रता और आत्म खोज की यात्रा कैसे पूर्ण होती है। यहां नायिका अकेलापन, ऊब, घुटन और अजनबीपन जैसे पहलुओं में बंधी हुई है। नारी–जीवन की वेदना, प्रेम की अधूरी प्यास और सामाजिक बंधनों की कठोरता दिखाई देती है। स्त्री केवल मां, पत्नी या बहन नहीं है बल्कि उसकी भी एक अलग पहचान है। उसे भी प्रेम और आकर्षण की आवश्यकता होती है। स्त्री को भी उसके हक का सम्मान मिलना चाहिए। स्वत्रंयतयोत्तर भारतीय समाज की त्रासदी दो स्तरों पर उजागर होती है– पूंजीवादी शोषण और मध्यवर्गीय भटकाव। नारी को भी प्रेम करने का पूरा हक है पर पारिवारिक दबाव के कारण वह अपना प्रेम त्याग देती है। स्त्री को समाज, कभी परिवार तो कभी खुद के लोग मानव मानने की जगह केवल खिलौना समझते है। पंचपन खंभे लाल दीवारें उपन्यास का यह वाक्य ''अम्मा ने बडे मजे से उत्तर दिया तुम जानो कृष्णा सुषमा को शादी तो अब हमारे बस की बात रही नहीं।''[7]

उपन्यास में सुषमा की अम्मा अपने स्वार्थ के लिए सुषमा की शादी नहीं करवाती और अम्मा की बहन कृष्णा जब उनसे सुषमा की शादी के बारे में पूछती है तो अम्मा कहती है सुषमा जाने और उसका काम। अम्मा जवाब में बड़े मजे से उत्तर देते हुए कहती है। सुषमा जाने उसका काम। यहां अम्मा जैसा सोचती है वास्तव में सुषमा वैसा ही व्यवहार करके अपने प्रेम का परिवार के लिए त्याग कर देती है पचपन खंभे लाल दिवारें उपन्यास में प्रवासी जीवन जी रही स्त्री का भी चित्रण हुआ है। नई जगह, नई सस्कृति और अकेलापन सुषमा

के लिए चुनौती बन जाता है। इस उपन्यास में नायिका के मन की गहराइयों को बडी संवेदनशीलता से दर्शाया गया है। सुषमा नील से प्रेम करती है लेकिन पारिवारिक दबावों के चलते अपने प्रेम को दबा देती है। त्याग कर देती है।

एक नारी पारिवारिक दबाव में समाज की सोच आदी से पीडित होकर अपने आत्म–सम्मान आत्मविश्वास आदि को कही खो देती है। वह समाज के बंधनों से बंध जाती है और आत्म–खोज को कही ताक पर रख देती है। उपन्यासों व साहित्य में स्त्री दृष्टिकोण की आवश्यकता के संदर्भ में ममता कालिया का कहना है कि ''मैं नहीं मानती की स्त्री में विविध आयाम है। यह विषय नहीं है यह तो हर जगह है वहां जहां दोहरे मानदंड है। स्त्री को स्वंत्रत रूप से समानता की दृष्टि से देखना चाहिए।'' स्त्री को भी बराबरी मिले वो भी सम्मान के साथ हर स्त्री को अपने सपनों को जीने का अधिकार मिले। उषा प्रियवंदा की कहानियों व उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक यथार्थ और पात्रों के अंतर्द्वद को बारीकी से दर्शाया गया है।

शरीर की पूर्णता अपूर्णता का प्रश्न किसी न किसी स्तर पर मन और जीवन की पूर्णता के प्रश्न से भी जुड जाता है। यही सवाल है कि क्या सौन्दर्य के प्रचलित मापदंडों और समाज की रूद दृष्टि के अनुसार एक अधूरे शरीर को उन सब इच्छाओं को पालने का अधिकार है जो स्वस्थ और सम्पूर्ण देहवाले व्यक्तियों के लिए स्वाभाविक होती है।'' उपन्यास की नायिका लीली स्वयं को कैंसर की बीमारी होने पर कहती है। ''मुझे ही क्यों? कैसे। खानदान में नानी मौसी, मां किसी को नहीं। वह अपने आप से बाते करती है। प्रश्न करती है। ''इस शरीर को कितने यत्न से सजाया संवारा फिर भी यह शरीर धोखा दे गया ये कैंसर कही भी सकता है। ग्रंथियों में फेंफडे में, कलेजे में, दिमाग में, हड्डियों में, विचारों पर कोई रोक नहीं है। कहां–कहां के भय किन–किन अंधेरे कोनो में मन भटक जाता है। मन बहुत आक्रोशित भी हैं।''[8]

अपने शरीर से सभी को प्रेम होता है। लीली कहती है मुझे कैंसर हो गया है? मैं अपने आपसे पूछती हूं। हां मुझे कैसर हो गया है बमिया में बैठे–बैठे अपने आप दोहराती हूं फिर अविश्वास क्यों? कैसे? मुझे कैसे हो सकता है? नहीं अवश्य पैथोलॉजी लैब में किसी से गलती हो गई है किसी और का होगा। अर्थात् नायिका को सौदर्य, शोभा क्रांति और दिप्ती से युक्त होना ही चाहिए। ऐसा समाज का मानना है। साहित्य उस अथाह सागर के समान है जिसकी सीमा और गहराई का निर्धारण करना कोई मामूली काम नहीं है। इसी प्रकार हिन्दी साहित्य भी उस अथाह सागर के समान है जिसकी विशालता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक क्षण सागर रूपी इस साहित्य की विशालता बदलती ही जा रही है। नारी तू नारायणी जहां हमारे शास्त्रों में नारी को देवी का रूप मान कर उसे पूजने येाग्य माना गया हैं वहीं आज नारी की यह स्थिति है कि कुछ लोग उसे देवी मानना तो दूर एक स्त्री होने का सम्मान भी नहीं देना चाहते। आदि–अनादि काल से ही नारी का शोषण होता चला आ रहा है। साथ ही नारी का स्वयं पर हो रहे शोषण के खिलाफ संघर्ष भी निरंतर चलता रहता है। स्वयं के खिलाफ संघर्ष करना किसी भी नारी की सबसे बडी जीत है। क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक स्त्री के प्रति देखने का नजरिया नहीं बदला जा सकेगा और ना ही स्त्री पर हो रहे अन्याय को ही खत्म किया जा सकता है। स्त्री जीवन के यथार्थ और संघर्षो को गहराई से चित्रित करती है ''नदी''। उपन्यास की नायिका आकाश गंगा (गंगा) के जीवन के माध्यम से स्त्री के संघर्ष, पीडा और आत्म–खोज की यात्रा को इंगित किया गया है। गंगा का जीवन विभिन्न परिस्थितियों में विस्थापित होता है, जिसमें वह अपने अस्तित्व और स्वाभिमान

के लिए संघर्ष करती दिखाई देती है। साथ ही भारतीय पारिवारिक संरचना और विदेशी परिवेश के विरोधाभास को भी उजागर किया है।'' बस बहने दो जीवन सरिता को कही न कही जल्दी या देर से कोई न कोई तो हल निकलेगा।''[9]

यह वाक्य गंगा के जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को प्रकट करता है, जो जीवन को एक प्रवाह के रूप में देखती है। ''गंगा का यह वाक्य मैं उदास हो गयी थी, तुम भी उदास हो गये थे। तुम्हें उदास करना मैं नहीं चाहती थी।''[10] यहां पर गंगा की संवेदनशीलता और उसके रिश्तों के प्रति उसकी गहराई का पता चलता है। ''मैं टूट गयी हूं, भुवन मेरे जीवन में मैं एसी पहले कभी नहीं टूटी थी।''[11] यहां गंगा के भावनात्मक दर्द और उसके जीवन के उतार–चढाव का पता चल रहा है। गंगा का जीवन विभिन्न परिस्थितियों में विस्थापित होता है और उससे संघर्ष चलता रहता है। गंगा अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करती है और अपने लिए एक नई राह तलाशती है। गंगा का पति उसे विदेश में अकेला छोड देता है और उसके पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से अकेली हो जाती है। और अपने जीवन के उतार –चढाव और उसके आत्म संघर्षो के लिए लड़ते हुए अपना जीवन व्यतीत करती है। नियति, अबूझ जीवन या प्रारब्ध–नाम दे उस घटनाक्रम को जो नदी की नायिका आकाशगंगा को न जाने किस किस रूप में कहां–कहां से विस्थापित करता है। विदेश में निवास करती आकाश गंगा पुत्र भविष्य की मृत्यु के लिए इस सीमा तक अपने पति द्वारा उत्तरदायी मानी जाती है कि वह परिवार से अलग कर दी जाती है।

यही से एकांकी छूट गई आकाश गंगा का संघर्ष प्रारम्भ होता है। आकाशगंगा अपने जीवन–प्रवाह में जिन ऊँचाइयों, गहराइयों, मैदानों, घाटियों, संकीर्ण प्रशस्त पांटो से गुजरती है, उन्हें यहां जीवन्त कर दिया है। यहां पर आकाशगंगा के बहाने स्त्री–जीवन के कटु–कठोर यथार्थ का मार्मिक चित्रण किया है। उषा प्रियंवदा स्त्री की विवशता को उजागर करते हुए बताती है उसे वो केवल रिश्तों में बांधकर रखने वाली वस्तु नहीं समझा जा सकता। वह आत्मसम्मान और स्वतंत्र अस्तित्व की अधिकारी है। उसके भीतर विद्रोह करने और अपने निर्णय स्वयं लेने की शक्ति है। उषा जी ने अपनी कहानी 'मछली' में नारी के आत्म सम्मान और स्वाभिमान को प्रेम से ऊपर रखा है, मछली की नायिका मुकी नटराजन के छलावें को ठुकराकर अपने आत्मसम्मान को चुनती है। मछली कहानी की नायिका कहती है– ''मुकी ने सिर उठाकर उसे देखा फिर तेजी से बांयी उंगली से अंगुठी निकालकर उसकी ओर फेंकती हुई बोली– यह लो अपनी अंगुठी और चले आओ यहां से मैं तुमसे बोलना तक नहीं चाहती।''[12]

इस अप्रत्याशित घटना से नटराजन क्षण–भर खडा रहा फिर उसने मुकी को उतर नहीं दिया। उसके शरीर से तडपती मछली की तरह एक लहर दौड गई। यहां पर स्त्री दृष्टिकोण को समझा जा सकता है। अंगूठी फेंक देना एक विद्रोही कदम है। यह स्त्री का आत्म–सम्मान प्रकट करता है। वह समझौता या चुप्पी नहीं चुनती, बल्कि अपने असंतोष और पीडा को स्पष्ट रूप से सामने रखती है। पुरुष नियंत्रण के विरूद्ध प्रतिकार अंगूठी यहां केवल संबंध का प्रतीक नहीं है। बल्कि उस बंधन का भी प्रतीक है, जिसमें स्त्री को बांधकर रखा जाता है। यहां स्त्री उस बंधन और पुरुष–प्रधान सता को ठुकराती है। यहां पर बताया गया है कि नारी अब केवल अत्याचारों को सहन करने वाली नहीं है। वह अपने अधिकार, सम्मान और आत्म–निर्णय के लिए खडी हो सकती है।

समाज और संबंधों में नारी को बराबरी का स्थान नहीं मिलता। समाज पुरुष को केन्द्र मानता है और स्त्री को दूसरे दर्जे पर रखता है। अर्थात् यहां उषा जी का स्त्री के प्रति नजरियां संवेदनशील, यथार्थवादी और प्रगतिशील है। उषा जी स्त्री की उस गहरी पीड़ा को आवाज देती नजर आती है, जो उसे उपेक्षा, असमानता और आत्मसम्मान के हनन से मिलता है। यहां स्त्री केवल घर की मछली नहीं है अपितु जिसे कैद किया जाए बल्कि वह स्वतंत्र नारी और पुरुषों के समान अधिकारी भी है। उनके स्त्री पात्र अपनी क्षमता से संघर्ष करते है और अंततः अपने लक्ष्य को पाने में सफल होते है। उषा जी ने अपने उपन्यासों में प्रवासी भारतीयों के जीवन के अनुभवों को भी दर्शाया है। विदेश में बेहतर जीवन की तलाश में गई नारी मोहभंग का शिकार होती है और उसे नए जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होने नारी की मानसिक जटिलताओं, अपेक्षाओं और स्वत्रंतता की लालसा को मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। अंततः स्त्री सामाजिक बंधनों और पुरुषवादी सोच के खिलाफ संघर्ष करती है और अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए आगे बढती है। उनके पात्र आधुनिक मूल्यों और पांरपरिक संस्कारों के बीच भंवर में फंसे हुए समाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते है। उषाजी ने अपनी रचनाओं में नारी की बदलती हुई मानसिक तस्वीर को उभारा है।

संदर्भ सूची :

1. उषा प्रियंवदा : मान और हठ (प्रतिनिधि कहानियां) राजकमल, प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 14
2. उषा प्रियंवदा : मान और हठ (प्रतिनिधि कहानियां) राजकमल, प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 15
3. वहीं पृ. 15
4. उषा प्रियंवदा : मान और हठ (प्रतिनिधि कहानियां) राजकमल, प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 18
5. उषा प्रियंवदा : रूकोगी नहीं राधिका,
6. उषा प्रियंवदा : शेष यात्रा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 46
7. उषा प्रियंवदा : पचपन खंभे लाल दीवारें, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 13
8. उषा प्रियंवदा : भया कबीर उदास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 30
9. उषा प्रियंवदा : नदी, http//www.wikipedia
10. उषा प्रियंवदा : नदी, http//www.wikipedia
11. उषा प्रियंवदा : नदी, http//www.wikipedia
12. उषा प्रियंवदा : मछलियां (प्रतिनिधि कहानियां) राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 101

Bharti Agrwal
Research Scholar, Hindi Department
Bhupal Nobles' university Udaipur
Dr.Hussaini Bohra, Supervisor
Email.bhartiagrawal180@gmail.com
Mob. No. 9414255060

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 207–214

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मूल्यों का अध्ययन

डॉ. दया कुमारी
असिस्टेंट प्रोफेसर – शिक्षाशास्त्र
महिला महाविद्यालय, बहराइच।

सारांश :

यह शोध पत्र बरेली जनपद के विकास खण्ड मीरगंज में कार्यरत परिषदीय सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मूल्यों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन की आवश्यकता हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षकों के मूल्यों पर बहुत कम शोध उपलब्ध हैं, जबकि वे बालकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इन दोनों प्रकार के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मूल्यों का अध्ययन करना था। अध्ययन के लिए वर्णनात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया। सोद्देश्य विधि द्वारा 35 परिषदीय विद्यालयों से 50 शिक्षक और 44 निजी विद्यालयों से 217 शिक्षकों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया। आँकड़े एकत्र करने के लिए डॉ. एच. एल. सिंह एवं डॉ. एस. पी. अहलूवालिया द्वारा निर्मित 'मूल्य मापनी' का उपयोग किया गया। यह मापनी छह प्रमुख मूल्यों का आकलन करती हैः सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक। आँकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष रूप में दोनों ही समूहों (परिषदीय एवं निजी) के शिक्षकों में सामाजिक मूल्य उच्च स्तर पर पाया गया। तथा परिषदीय शिक्षकों में केवल सौंदर्यात्मक मूल्य निम्न स्तर पर पाया गया, जबकि उनके सैद्धांतिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक मूल्य औसत स्तर पर थे। निजी विद्यालयों के शिक्षकों में सौंदर्यात्मक एवं राजनैतिक मूल्य, दोनों ही निम्न स्तर पर पाए गए, और उनके सैद्धांतिक, आर्थिक व धार्मिक मूल्य औसत स्तर पर थे। अतः, यह शोध स्पष्ट करता है कि जहाँ दोनों प्रकार के शिक्षक सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं, वहीं परिषदीय शिक्षक राजनैतिक मूल्यों में औसत और निजी शिक्षक इन्हीं मूल्यों में निम्न स्तर दर्शाते हैं।

मुख्य शब्द – प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक, मूल्य, परिषदीय विद्यालय।

प्रस्तावना –

प्रारंभिक युग में मानव, पशुओं की भांति आचरण करता था एवं उसका जीवन नैतिक सिद्धांतों से रहित था। उसका पूरा ध्यान केवल अपने अस्तित्व को बचाने पर केंद्रित था। उस काल में, शारीरिक शक्ति ही सर्वोच्च थी; बलवान व्यक्ति को ही सर्वाधिक महत्व मिलता था और अन्य लोग उसके अधीन रहते थे। कालांतर में, इस

दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। मनुष्यों ने एक–दूसरे की आवश्यकता और महत्व को पहचाना। वे परस्पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगे और संगठित होकर समूहों में रहने लगे। 'समाज–रहित मनुष्य' केवल एक कोरी कल्पना है। कोई भी मनुष्य दूसरों के सहयोग के बिना सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। इसके परिणामस्वरूप, अब केवल शारीरिक बल को ही प्रधानता नहीं दी जाती। प्रत्येक समाज कुछ आदर्शों, परंपराओं और रीति–रिवाजों का निर्माण करता है और अपने सदस्यों से उनके पालन की अपेक्षा रखता है। जो सदस्य समाज द्वारा निर्धारित इन मूल्यों और परंपराओं का निर्वाह नहीं करता, वह सामाजिकता के ताने–बाने से वंचित कर दिया जाता है।

विभिन्न समाजों में परंपराएँ भिन्न अथवा समान हो सकती हैं, और ये आदर्श परंपराएँ व रीति–रिवाज ही वहाँ के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। समाज, व्यक्तियों के भीतर इन मूल्यों के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। व्यक्ति स्वयं को समाज की स्थापित धारणाओं और मान्यताओं के अनुसार ढालने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, उसके भीतर उन्हीं मूल्यों का विकास होता है जो समाज में निहित हैं। अतः यह स्पष्ट है कि मूल्य समाज से ही प्राप्त होते हैं। जैसे–जैसे समाज बदलता है, उसके मूल्य भी परिवर्तित होते है। समय और अनुभवों के साथ ये मूल्य और अधिक परिपक्व होते जाते हैं।

मनुष्य सृष्टि में इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह विवेकशील है, जो उसे अन्य प्राणियों से अलग करता है। जानवरों का जीवन आत्मरक्षा और स्वयं तक सीमित होता है, जबकि मनुष्य का जीवन आदर्शों, संस्कृति और मूल्यों से संचालित होता है। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जीता है। जानवरों का जीवन इन्द्रियों तक सीमित है और वही उनकी चेतना का अंत है, जबकि इंसानों के लिए यह चेतना का सबसे निचला स्तर है। मानव जीवन की सार्थकता मूल्यों से है। ये मूल्य इंसानियत के लिए आभूषणों के समान हैं; जैसे आभूषण से स्त्री की शोभा बढ़ती है, वैसे ही मूल्यों को धारण कर मनुष्य समाज में सर्वोत्तम बनता है। हर व्यक्ति में मूल्य होते हैं, पर वे अलग–अलग हो सकते हैं और कभी–कभी उनमें विरोधाभास भी पाया जाता है। जीवन में मूल्यों का स्थान सर्वोच्च है, किंतु आज के दौर में, भौतिक सुखों के मृग मरीचिका में पड़कर, लोग सही–गलत की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, जिससे ये मूल्य ह्रासित होते जा रहे हैं। मूल्यों को मनुष्य की इच्छाओं का मार्गदर्शक, शाश्वत सत्य और अच्छे कर्मों का मापदंड माना गया है। पारंपरिक दर्शन में, मूल्यों की अवधारणा सच्चाई, सुंदरता और अच्छाई पर टिकी है, जिसे हमारे मनीषियों ने 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम' के सिद्धांत के रूप में बताया है।

सिंह (1991), राठौर (1992), सक्सैना (1995), प्रतिभा (1996), के0के0 चौधरी (1997), केसरवानी (1999–2000), सौम्या (2003). दीपक कुमार गुप्ता (2005), संजीव कुमार भारद्वाज (2007), आर. कुमार (2018), वी. राणा एवं जे. मेहरा (2021). एस रेड्डी एवं के. नायर (2021), ए शर्मा एवं वी. यादव (2021), पी. वर्मा एवं वी. राव (2021) उक्त अध्ययनों में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के सन्दर्भ में शोध कार्यों की संख्या बहुत अल्प है। अतः बालकों के विकास में प्राथमिक शिक्षकों के महत्तव को समझते हुए शोध का विषय 'बरेली जनपद के विकास खण्ड मीरगंज के परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन' रखा है जिस पर अभी तक एक भी शोध कार्य नहीं हुआ है। अतः इस विषय पर अध्ययन करना महत्वपूर्ण है।

अध्ययन के उद्देश्य –

परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मूल्यों का अध्ययन करना।

अध्ययन विधि :

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मूल्यों का अध्ययन करना है। इस अध्ययन हेतु शोध की वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श :

प्रस्तुत अध्ययन में बरेली जनपद के विकास खण्ड मीरगंज के परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को जनसंख्या के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में सौद्देश्य न्यादर्श विधि का चयन किया गया है। चयनित न्यादर्श का विवरण इस प्रकार से हैः– बरेली जनपद के विकास खण्ड मीरगंज के 35 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से 50 शिक्षकों को चयनित किया गया है तथा 44 मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों से 50 शिक्षकों को चयनित किया गया है।

उपकरण :

अध्ययन के उद्देश्य एवं मापनियों की विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन हेतु उपकरण के रूप में डॉ० एच० एल० सिंह तथा डॉ० एस० पी० अहलूवालिया द्वारा निर्मित मूल्य मापनी का चयन किया गया है। इसमें कुल 25 प्रश्न हैं जो कि छः मूल्यों का मापन करते हैं। इस परीक्षण का प्रशासन शिक्षकों के विभिन्न मूल्यों के मापन के संदर्भ में किया गया है। इस परीक्षण में निम्न मूल्य सम्मिलित हैं :

1. सैद्धान्तिक मूल्य।
2. आर्थिक मूल्य।
3. सौन्दर्यात्मक मूल्य।
4. सामाजिक मूल्य।
5. राजनैतिक मूल्य।
6. धार्मिक मूल्य।

आँकड़ों का संकलन –

आंकड़ो के संकलन हेतु अनुसंधानकर्त्री ने विभाग से प्रदत्त संकलन हेतु से अनुमति प्राप्त करके, अध्यापकों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके परिसूची भरने का अनुरोध किया। शिक्षकों द्वारा भरी गई परिसूची का निरीक्षण करके यह निश्चित कर लिया गया कि कोई प्रश्न अनुत्तरित तो नहीं रह गयाा। प्रदत्तों के संकलन के पश्चात प्रत्येक शिक्षक द्वारा व्यक्त किये गये उत्तरों पर मैनुअल द्वारा निर्देशित अंक दिए गए। अंकन कुंजी की सहायता से प्रदत्तों का फलांकन किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या –

फलांकन के पश्चात प्रदत्तों को पृथक–पृथक वर्गों में वर्गीकृत किया गया। यही वर्गीकरण सारणीयन कहलाता है। शिक्षकों के समूह को परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालय में वर्गीकृत कर लिया गया। जिनका विवरण निम्नलिखित है–

तालिका सं0 1

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मूल्यों का अध्ययन

मूल्य	शिक्षकों की संख्या (N) 100	
	मध्यमान	मानक विचलन
1. सैद्धान्तिक मूल्य	93.75	11.96
2. आर्थिक मूल्य	84.05	11.13
3. सौन्दर्यात्मक मूल्य	76.1	13.65
4. सामाजिक मूल्य	104.75	14.12
5. राजनैतिक मूल्य	76.35	12.57
6. धार्मिक मूल्य	91.3	15.38

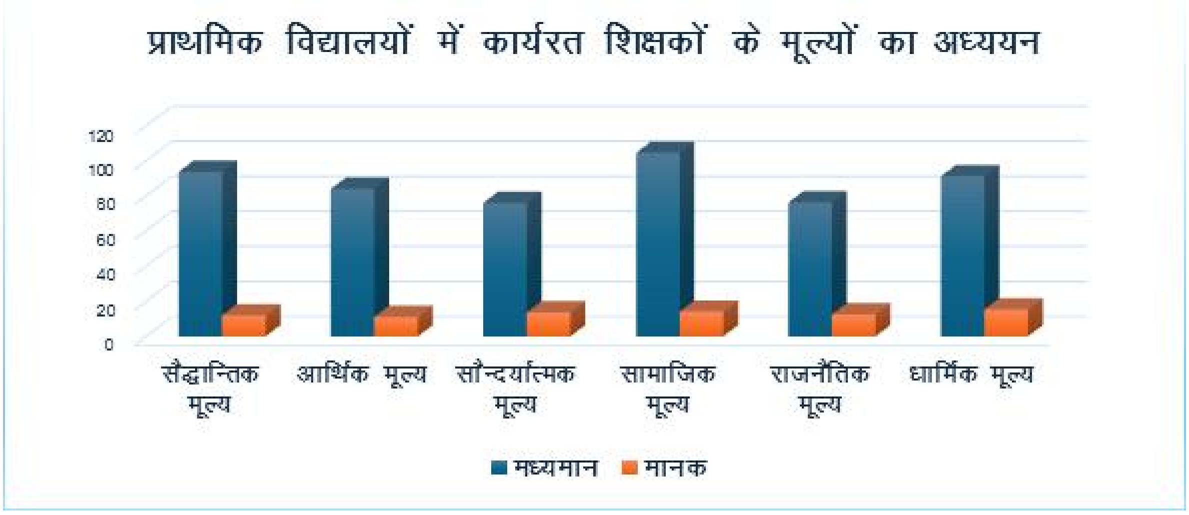

तालिका एवं दंड आरेख – 1 से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में सैद्धान्तिक, मूल्य, आर्थिक मूल्य, सौन्दर्यात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य तथा धार्मिक मूल्य का मध्यमान क्रमशः 93.75, 84.05, 76.1, 104.75, 76.35 तथा 91.3 पाया गया।

ये सभी मध्यमान औसत मूल्य स्तर के द्योतक हैं। इन्हीं शिक्षकों के सौन्दर्यात्मक मूल्य तथा राजनैतिक मूल्य का मध्यमान क्रमशः 76.1 तथा 76.35 पाया गया, यह मध्यमान निम्न मूल्य स्तर को प्रदर्शित करता है। सामाजिक मूल्य का मध्यमान 104.75 पाया गया, यह मध्यमान उच्च मूल्य स्तर का द्योतक है।

शिक्षकों के विभिन्न मूल्यों के मानक विचलनों को देखने से ज्ञात होता है कि सामाजिक मूल्य तथा धार्मिक मूल्यों का मानक विचलन सर्वाधिक 14.1222 तथा 15.387 पाया गया। इससे विदित होता है कि सामाजिक मूल्य तथा धार्मिक मूल्य के सम्बन्ध में शिक्षकों की राय में अन्य मूल्यों की अपेक्षा अधिक असमानता थी। सबसे कम

मानक विचलन सैद्धान्तिक तथा आर्थिक मूल्यों का क्रमशः 11.956 तथा 11.126 पाया गया। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अन्य मूल्यों की अपेक्षा इन मूल्यों के सम्बन्ध में शिक्षकों में कम विविधता थी।

तालिका सं0 2

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मूल्यों का अध्ययन

मूल्य	परिशदीय विद्यालय		मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय	
	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन
1. सैद्धान्तिक मूल्य	94.6	11.27	91.7	11.23
2. आर्थिक मूल्य	84.3	12.20	84.6	11.09
3. सौन्दर्यात्मक मूल्य	65.8	14.12	78.4	12.95
4. सामाजिक मूल्य	107.0	14.24	102.71	13.44
5. राजनैतिक मूल्य	75.0	12.56	78.0	12.67
6. धार्मिक मूल्य	90.4	16.56	92.5	13.49

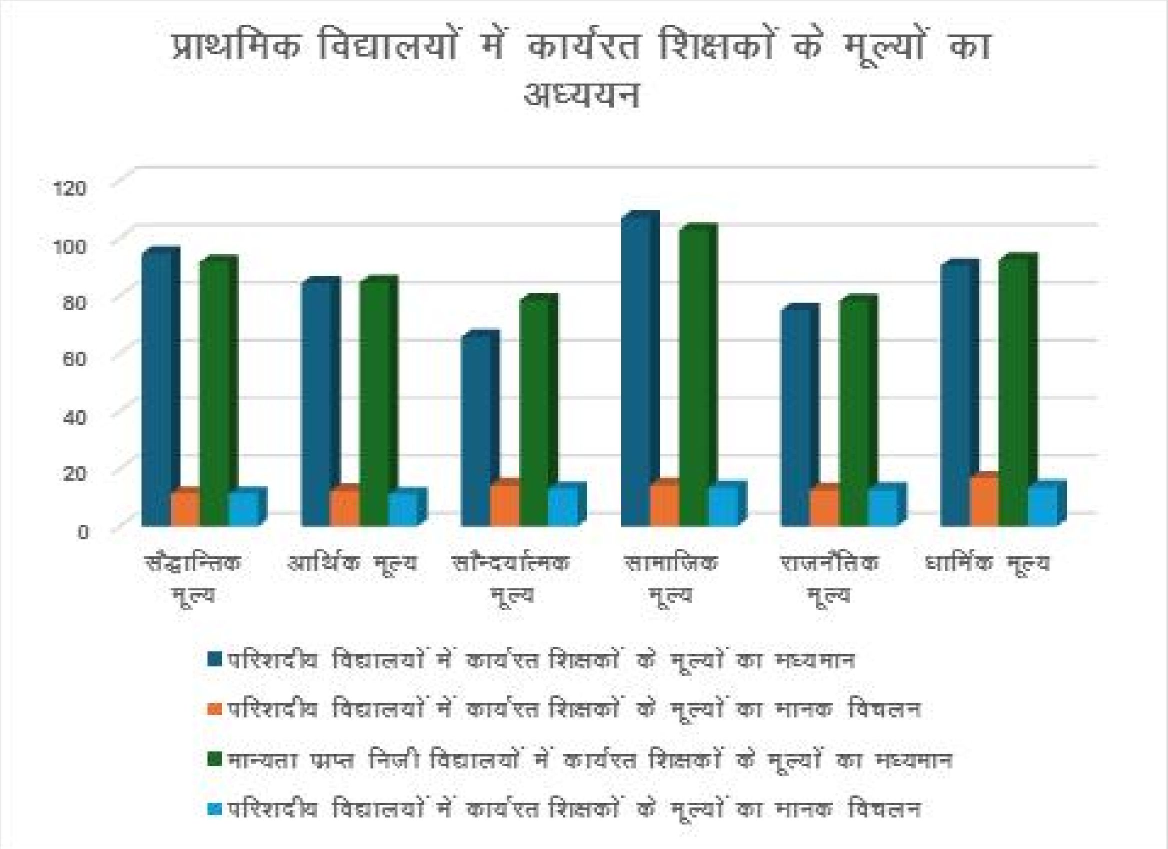

तालिका एवं दंड आरेख – 2 से स्पष्ट होता है कि परिशदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में सैद्धान्तिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सौन्दर्यात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य तथा धार्मिक मूल्य का मध्यमान क्रमशः 94.6, 84.3, 65.8, 107.0, 75.0 तथा 90.4 पाया गया। ये सभी मध्यमान औसत मूल्य स्तर के द्योतक हैं। सौन्दर्यात्मक मूल्य का मध्यमान 65.8 निम्न मूल्य स्तर तथा सामाजिक मूल्य का मध्यमान 107.0 उच्च मूल्य स्तर को प्रकट करते हैं।

मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में सैद्धान्तिक, मूल्य, आर्थिक मूल्य, सौन्दर्यात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य तथा धार्मिक मूल्य का मध्यमान क्रमशः 91.7, 84.6, 78.4, 102.71, 78.0 तथा 92.5 पाया गया। ये सभी मध्यमान औसत मूल्य स्तर के द्योतक हैं। सौन्दर्यात्मक मूल्य तथा राजनैतिक मूल्य का मध्यमान क्रमशः 78.4 तथा 78.0 पाया गया। यह मध्यमान निम्न मूल्य स्तर को प्रकट करते हैं। सामाजिक मूल्य का मध्यमान 102.71 पाया गया, यह मध्यमान उच्च मूल्य स्तर का द्योतक है।

अतः परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में मात्र सामाजिक मूल्य उच्च स्तर पर पाया गया, सौन्दर्यात्मक मूल्य एवं राजनैतिक मूल्य निम्न स्तर पर पाये गये तथा सैद्धान्तिक मूल्य, आर्थिक मूल्य एवं धार्मिक मूल्य औसत स्तर पर पाये गये।

शिक्षकों के विभिन्न मूल्यों के मानक विचलनों को देखने से ज्ञात होता है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के धार्मिक मूल्य का मानक विचलन सबसे अधिक 16.56 पाया गया, जबकि मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में धार्मिक मूल्य तथा सामाजिक मूल्य का मानक विचलन सर्वाधिक क्रमशः 13.49 तथा 13.44 पाया गया। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में सैद्धान्तिक मूल्य का मानक विचलन सबसे कम 11.27 पाया गया, जबकि मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में सबसे कम मानक विचलन सैद्धान्तिक मूल्य तथा आर्थिक मूल्य का क्रमशः 11.23 तथा 11.09 पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के धार्मिक मूल्य में सबसे अधिक विविधता विद्यमान थी, जबकि मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में सबसे अधिक विषमता धार्मिक मूल्य तथा सामाजिक मूल्य में पायी गयी।

निष्कर्ष एवं चर्चा :

प्रस्तुत शोध पत्र में सांख्यिकीय विवेचन एवं प्रदत्तों के विश्लेषण एवं व्याख्या से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए:

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में सैद्धान्तिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य तथा धार्मिक मूल्य औसत स्तर पर विद्यमान थे। सौन्दर्यात्मक मूल्य निम्न स्तर के पाये गये तथा सामाजिक मूल्य उच्च स्तर पर पाये गये। शर्मा एवं यादव, 2021; कुमार, 2018 ने भारतीय शिक्षकों में सामाजिक और धार्मिक/आध्यात्मिक मूल्यों की प्रबलता की पुष्टि की है। यह उच्च सामाजिक मूल्य 'गुरु–शिष्य परंपरा' को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ शिक्षा को मात्र एक पेशा नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति एक कर्तव्य माना जाता है। कोठारी शिक्षा आयोग (1964–1966) ने स्पष्ट रूप से सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया था ताकि शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ा जा सके। इसी प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी अपने मूलभूत सिद्धांतों में मानवीय और संवैधानिक मूल्यों जैसे कि सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, और सामाजिक उत्तरदायित्व (NEP 2020, पैरा 4.3) पर जोर देती है।

मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में समााजिक मूल्य उच्च स्तर के पाए गए, तथा सैद्धान्तिक, आर्थिक एवं धार्मिक मूल्य औसत स्तर पर पाए गए जबकि सौन्दर्यात्मक एवं राजनैतिक मूल्य निम्न स्तर के पाए गए। सैद्धांतिक मूल्य शिक्षकों के लिए स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनका 'औसत' होना दर्शाता है कि ज्ञान–प्राप्ति की रुचि अक्सर उनके शिक्षण कार्य और अन्य मूल्यों, जैसे सामाजिक सेवा या आर्थिक आवश्यकता, से संतुलित रहती है। आर्थिक मूल्यभी औसत हैं, जो यह बताता है कि प्राथमिक शिक्षक अपने वेतन को महत्व देते हैं, राधाकृष्णन आयोग (1948–49) ने शिक्षकों के बेहतर वेतन और सेवा शर्तों की आवश्यकता पर बल दिया था, लेकिन शिक्षण कार्य मुख्यता आर्थिक लाभ से प्रेरित नहीं है, यह सामाजिक और नैतिक प्रेरणाओं से जुड़कर संतुलन बनाता है। धार्मिक मूल्य का औसत स्तर भारत की विविध सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है, जहाँ शिक्षक अपने व्यक्तिगत विश्वासों को बनाए रखते हैं, लेकिन शैक्षिक वातावरण में उन्हें धर्मनिरपेक्षता और समावेशिता के साथ संतुलन बनाना होता हैं।

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में सौन्दर्यात्मक मूल्य निम्न स्तर पर पाए गए। जबकि मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों में राजनैतिक मूल्य, निम्न स्तर के पाए गए। दोनों ही (परिषदीय विद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक) विद्यालय के शिक्षकों में सामाजिक मूल्य उच्च स्तर पर पाये गये। सौन्दर्यात्मक मूल्य कला, प्रकृति, सुंदरता, और रचनात्मक अभिव्यक्ति में रुचि से संबंधित होते हैं। इन मूल्यों का निम्न स्तर अक्सर संसाधन की कमी, बुनियादी सुविधाओं के अभाव (रेड्डी एवं नायर, 2021), और सरकार द्वारा संचालित स्कूलों पर केवल पाठ्यचर्या (Curriculum) को पूरा करने के व्यावहारिक दबाव को इंगित करता है। परिषदीय विद्यालय अक्सर बड़े छात्र–शिक्षक अनुपात और सीमित कलात्मक संसाधनों के कारण सौन्दर्यात्मक शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दे पाते। यदि शिक्षक स्वयं इन मूल्यों को कम महत्व देते हैं, तो वे छात्रों के सर्वांगीण विकास (Holistic Development) के लिए आवश्यक कला, शिल्प, और रचनात्मक गतिविधियों (NEP 2020, पैरा 4.6) को कक्षाओं में प्रभावी ढंग से एकीकृत नहीं कर पाएँगे। यह निष्कर्ष NEP 2020 के कला–एकीकृत शिक्षा (Art & Integrated Education) के लक्ष्य को लागू करने में एक संभावित बाधा को दर्शाता है।

राजनैतिक मूल्य शक्ति, प्रभाव, नेतृत्व, और संगठनात्मक व्यवस्था में रुचि से जुड़े होते हैं। निजी क्षेत्र के शिक्षकों में इसका निम्न स्तर उनके संस्थागत प्रकृति से संबंधित हो सकता है। निजी विद्यालयों में शिक्षक अपनी ऊर्जा को मुख्य रूप से संस्थागत लक्ष्यों, व्यावसायिकता, और आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित करते हैं (वर्मा एवं राव, 2021)। परिषदीय शिक्षकों में औसत राजनैतिक मूल्य उनकी सरकारी सेवा प्रकृति के कारण हो सकता है, जिसमें उन्हें नीतियों के क्रियान्वयन और संगठनात्मक विषयों में अधिक संलग्न होना पड़ता है।

उपरोक्त निष्कर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समग्र और बहु–विषयक शिक्षा के दृष्टिकोण को लागू करने में दो प्रमुख चुनौतियों को भी उजागर करते हैं : 1. कक्षाओं में सौन्दर्यात्मक मूल्य का अभावः NEP 2020 के तहत कला–एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए परिषदीय शिक्षकों के सौन्दर्यात्मक मूल्यों को बढ़ाने हेतु तत्काल और लक्षित सेवाकालीन प्रशिक्षण (In-service Training) कार्यक्रमों की आवश्यकता है। 2. शिक्षकों की राजनीतिक (नीतिगत) भागीदारी : NEP 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों को केवल नीति का प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि सक्रिय हितधारक होना चाहिए (राणा एवं मेहरा, 2021)। निजी विद्यालय के शिक्षकों में निम्न राजनैतिक

मूल्य नीति निर्माण और क्रियान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी को सीमित कर सकता है।

सन्दर्भ :

1. कपिल, एच०के० : अनुसंधान विधियाँ आगरा हरप्रसाद भार्गव पुस्तक प्रकाशन, 1995.
2. कटियार, पी०सी० : वैल्यू एण्ड वोकेशनल प्रीफ्रेंस, आगराः एच०पी० भार्गव बुक हाउस, 1987.
3. कुमार, आर. (2018). शहरी और ग्रामीण परिवेश के प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के मूल्यों का एक तुलनात्मक अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, 12(1), 101–115.
4. सिंह : आधुनिकता का प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के मूल्यों पर प्रभावक्ता पर अध्ययन, एम०एड० लघु शोध प्रबन्ध एम०जे० पी० रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, 1991.
5. भारद्वाज, संजीव कुमार : माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की अभिवृत्ति, मूल्य एवं शिक्षण दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन, पी–एच० डी० डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, 2007.
6. भार्गव, महेश : आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन, आगराः एच०पी० भार्गव बुक हाउस, 2001.
7. पाण्डेय, आर०एस० : शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, आगराः विनोद पुस्तक मन्दिर, 1998
8. पाण्डेय, आर०एस० एवं के० एस० मिश्र : मूल्य शिक्षण, आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर, 1997–98.
9. राणा, वी., और मेहरा, जे. (2021). एनईपी 2020 में नीति कार्यान्वयन और संकाय का प्रतिरोध. जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन पॉलिसी, 32(3), 123–137.
10. राय, पी० एन० : अनुसंधान परिचय, आगराः लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, 2002.
11. रेड्डी, एस., और नायर, के. (2021). ग्रामीण विश्वविद्यालयों में एनईपी के कार्यान्वयन की बाधाएँ. रूरल एजुकेशन जर्नल, 8(1), 34–48.
12. शर्मा, ए., और यादव, वी. (2021). एनईपी 2020 को लागू करने में शिक्षक मूल्यों की भूमिका : एच.एल. सिंह और अहलूवालिया के मूल्य स्केल का उपयोग करते हुए एक अध्ययन. जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 25(3), 45–60.
13. वर्मा, पी., और राव, वी. (2021). भारतीय विश्वविद्यालयों में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में वित्तीय बाधाएँ. इंडियन जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन फाइनेंस, 29(3), 76–90.
14. चौधरी, के०के० : इक्कीसवीं शताब्दी में मूल्य शिक्षा, भारतीय आधुनिक शिक्षा, नई दिल्ली एन० सी० ई० आर० टी० 2000.
15. चौधरी, के०के० : माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की पुनर्सरचनाः मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में, जौनपुर पूर्वाचल जनरल ऑफ एजूकेशन स्टडीज, 1997.
16. गुप्ता, दीपक कुमार : प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत तथा पूर्व सेवारत शिक्षक प्रशिक्षुओं के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन, एम० एड० लघु शोध प्रबन्ध एम०जे०पी० रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली 2005.

Websites :

- https://www.education.gov.in/
- https://ncert.nic.in/
- https://www.niepa.ac.in/
- http://upbasiceducation.gov.in/

dayakumari12@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 215–227
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ‘संस्कृति के चार अध्याय’ के ऐतिहासिक रूप के तात्विक विवेचना

डॉ. सीमा कुमारी
सहायक अध्यापक, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सेक्टर–14, पंचकूला।

सारांश

रामधारी सिंह दिनकर की कृति *संस्कृति के चार अध्याय* भारतीय संस्कृति के विकासक्रम का एक गहन ऐतिहासिक और तात्त्विक विवेचन प्रस्तुत करती है। दिनकर ने इसमें संस्कृति को स्थिर सत्ता नहीं, बल्कि निरंतर गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा है, जो विभिन्न कालखंडों की चार प्रमुख क्रांतियों से निर्मित हुई—आर्य और आर्येत्तर जातियों का मेल, बौद्ध-जैन विद्रोह और आध्यात्मिक चेतना, इस्लाम के आगमन से गंगा-जमुनी तहज़ीब, तथा यूरोपीय संपर्क से उत्पन्न नवजागरण और आधुनिकता। उनका मत है कि भारतीय संस्कृति की आत्मा सहिष्णुता, समन्वय और विविधता में एकता है, जिसने उसे हर चुनौती में और अधिक समृद्ध बनाया। इस ग्रंथ में दिनकर ने जनता को संस्कृति का असली शिल्पकार मानते हुए ऐतिहासिक घटनाओं को सामाजिक-दार्शनिक दृष्टि से व्याख्यायित किया। इस प्रकार यह कृति केवल इतिहास का पुनर्पाठ नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना का घोषणापत्र है, जिसने आधुनिक भारत को अपनी जड़ों और भविष्य की राह पहचानने की दृष्टि दी।

रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1956 ई. में रचित *संस्कृति के चार अध्याय* भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक यात्रा और उसके तात्त्विक स्वरूप का अद्वितीय विवेचन प्रस्तुत करता है। स्वतंत्र भारत के आरंभिक काल में लिखी गई यह कृति केवल अतीत का विवरण नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए सांस्कृतिक चेतना का मार्गदर्शन है। दिनकर ने भारतीय संस्कृति को चार बड़ी ऐतिहासिक क्रांतियों के संदर्भ में देखा—प्रथम, आर्यों और आर्येत्तर जातियों के मेल-मिलाप से उत्पन्न सांस्कृतिक संलयन; द्वितीय, बौद्ध और जैन धर्मों के विद्रोही-सुधारवादी आंदोलनों द्वारा प्रदत्त नई आध्यात्मिकता और नैतिकता; तृतीय, इस्लाम के भारत आगमन से उत्पन्न गंगा-जमुनी तहज़ीब तथा हिंदू-मुस्लिम सांस्कृतिक संवाद; और चतुर्थ, यूरोप से संपर्क के परिणामस्वरूप शिक्षा, समाज, धर्म और राजनीति में आए नवोत्थान और आधुनिकता के प्रभाव। दिनकर का मानना था कि संस्कृति एक स्थिर या जड़ित सत्ता नहीं, बल्कि सतत गतिशील प्रक्रिया है जो आंतरिक संघर्षों, बाहरी संपर्कों और वैचारिक आंदोलनों से आकार लेती है। उन्होंने इस ग्रंथ में यह प्रतिपादित किया कि भारतीय संस्कृति की आत्मा

विविधता में एकता, सहिष्णुता और समावेशिता है, जिसने उसे हर संकट के बाद और अधिक परिपक्व बनाया। इतिहास की घटनाओं को उन्होंने केवल कालक्रम में नहीं, बल्कि उनके अंतर्निहित तात्त्विक आशयों के साथ व्याख्यायित किया, जैसे सामाजिक न्याय, समन्वय, समावेशन और राष्ट्रीय चेतना। इस दृष्टि से यह कृति महज ऐतिहासिक विवरण न होकर सांस्कृतिक-दार्शनिक ग्रंथ है, जो भारत की राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को समझने का आधार देता है। प्रस्तावना स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह ग्रंथ समकालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्श का भी हिस्सा था। दिनकर ने 'जनता' को संस्कृति की असली निर्माता माना और उसके जीवन-संघर्षों को भारतीय इतिहास की धारा में केंद्रीय स्थान दिया। इस प्रकार *संस्कृति के चार अध्याय* भारतीय इतिहास की व्याख्या को केवल शासकों और राजवंशों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि समाज, धर्म, दर्शन और जनमानस की रचनात्मकता को केंद्र में लाकर प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ न केवल इतिहास का पुनर्पाठ है, बल्कि सांस्कृतिक चेतना का तात्त्विक घोषणापत्र भी है, जिसने भारतीय साहित्य और चिंतन दोनों को नई दृष्टि प्रदान की।

अध्ययन का उद्देश्य-रामधारी सिंह दिनकर की कृति *संस्कृति के चार अध्याय* पर आधारित इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक स्वरूप और उसके तात्त्विक आयामों का गहन विश्लेषण करना है। यह अध्ययन यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि भारतीय संस्कृति किस प्रकार विभिन्न कालखंडों में आक्रमणों, संघर्षों, धार्मिक आंदोलनों और बाहरी प्रभावों के बावजूद अपनी आत्मा को अक्षुण्ण रखते हुए निरंतर विकसित होती रही है। अनुसंधान का लक्ष्य संस्कृति की उस निरंतरता को पहचानना है, जो भारतीय समाज को "एकता में विविधता" के सूत्र में बाँधती है और राष्ट्रीय अस्मिता को सशक्त बनाती है। इसके माध्यम से यह भी समझा जाएगा कि दिनकर का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, सहिष्णुता और समावेशिता की अवधारणा आज के समय में भी क्यों प्रासंगिक है। इस अनुसंधान से न केवल भारतीय संस्कृति की जड़ों की पहचान होगी, बल्कि यह भी उद्घाटित होगा कि संस्कृति किसी राष्ट्र के भविष्य-निर्माण में किस प्रकार मार्गदर्शक शक्ति बन सकती है।

अध्ययन का महत्त्व-रामधारी सिंह दिनकर की *संस्कृति के चार अध्याय* पर किया गया अनुसंधान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक यात्रा और उसके मूल तत्वों को नये दृष्टिकोण से समझने का अवसर प्रदान करता है। इस शोध का महत्त्व सबसे पहले इसलिए है कि यह भारतीय संस्कृति की निरंतरता, सहिष्णुता और समावेशिता को उजागर करता है, जिसने सदियों तक आक्रमणों, संघर्षों और परिवर्तनशील परिस्थितियों में भी अपनी आत्मा को सुरक्षित रखा। दूसरा, यह अनुसंधान हमें यह बोध कराता है कि भारतीय संस्कृति केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक शक्ति है, जो राष्ट्र की एकता, पहचान और प्रगति की आधारशिला बनती है। तीसरा, दिनकर की राष्ट्रवादी दृष्टि और "एकता में विविधता" की अवधारणा आज के वैश्वीकरण और सांस्कृतिक विखंडन के दौर में और भी प्रासंगिक हो उठती है। इस प्रकार, यह अनुसंधान भारतीय समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने, राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करने और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता की राह दिखाने में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है।

संस्कृति की संकल्पना-संस्कृति का अर्थ केवल परंपराओं, आचार-विचार या कला-साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव-जीवन के समग्र मूल्यों की वह निरंतर धारा है जो समाज के नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास को दिशा देती है। रामधारी सिंह दिनकर ने *संस्कृति के चार अध्याय* में इसे 'जीवन-मूल्यों की निरंतर धारा' कहा है, अर्थात् संस्कृति वह सतत प्रवाह है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुभव, आदर्श, नैतिकता और जीवन-दृष्टि का हस्तांतरण होता रहता है। संस्कृति केवल बाह्य उपलब्धियों का संग्रह नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना और जीवन को सुगठित करने वाली शक्ति है। सभ्यता और संस्कृति में भी मौलिक भेद है—सभ्यता का संबंध बाहरी जीवन-व्यवस्था, साधनों, भौतिक प्रगति और तकनीकी कौशल से है, जबकि संस्कृति मानव की अंतःप्रवृत्तियों, मूल्यबोध, नैतिकता और आध्यात्मिक संवेदनाओं से जुड़ी होती है। सभ्यता का स्वरूप यांत्रिक और दृश्य होता है, परंतु संस्कृति अदृश्य, गूढ़ और आत्मा को पोषित करने वाली शक्ति है। सभ्यता के विनाश पर भी संस्कृति जीवित रह सकती है, क्योंकि उसका आधार भौतिक उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों पर टिका होता है। भारतीय संस्कृति की विशिष्टता इसी बात में है कि उसने युगों-युगों से बाहरी आक्रमणों, संघर्षों और परिवर्तनों के बावजूद अपनी मूल आत्मा को सुरक्षित रखा। इसमें समन्वय, सहिष्णुता और विविधता में एकता के आदर्श सर्वोपरि रहे हैं। वैदिक काल से लेकर उपनिषदों की दार्शनिक चेतना, बौद्ध और जैन धर्मों की अहिंसा और करुणा, भक्ति आंदोलन की समरसता, इस्लामी प्रभाव से उत्पन्न गंगा-जमुनी तहज़ीब और आधुनिक काल में यूरोपीय विचारधाराओं से हुए नवजागरण—ये सभी प्रवृत्तियाँ भारतीय संस्कृति के विस्तार और समृद्धि की द्योतक हैं। भारतीय संस्कृति का दूसरा विशेष लक्षण इसकी समावेशिता है; इसने विदेशी प्रभावों को अस्वीकार करने के बजाय आत्मसात् किया और उन्हें अपने अनुरूप ढालकर एक नवीन रूप दिया। तीसरा लक्षण है इसका अध्यात्मप्रधान स्वरूप—भारतीय संस्कृति भौतिक उपलब्धियों से अधिक आत्मिक शांति, धर्म, नैतिकता और मोक्ष की ओर उन्मुख रही है। चौथा लक्षण इसका लोकमंगल दृष्टिकोण है, जहाँ संस्कृति केवल उच्चवर्ग या अभिजात्य तक सीमित न रहकर सामान्य जनता की आस्था, कर्म, उत्सव और जीवनशैली में भी गहराई से रची-बसी है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने समय-समय पर सामाजिक अन्याय और विघटन को चुनौती दी और नए मूल्यों का सृजन किया। दिनकर के शब्दों में, यह संस्कृति जीवन का 'रससिद्ध रूप' है, जो मनुष्य को केवल जीना नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण और मूल्यपूर्ण जीवन जीना सिखाती है। इस प्रकार संस्कृति की संकल्पना हमें यह बोध कराती है कि वह इतिहास की गति, सभ्यता की उपलब्धियों और मानव-चेतना के गहन मूल्यों का संश्लेषण है, जो भारत की आत्मा को युगों-युगों तक जीवित और प्रगतिशील बनाए हुए है।

ग्रंथ की रचना का काल और ऐतिहासिक संदर्भ-रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित *संस्कृति के चार अध्याय* का प्रकाशन सन् 1956 ईस्वी में हुआ, जब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के एक दशक के भीतर था और राष्ट्रीय जीवन में आत्मचेतना, नवसंस्कार तथा सांस्कृतिक आत्मनिर्माण की तीव्र आवश्यकता महसूस की जा रही थी। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बाद भारतीय समाज केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं होना चाहता था, बल्कि उसे अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक सांस्कृतिक सेतु की खोज थी। इस समय भारत विभाजन के घावों से भी जूझ रहा था, धार्मिक विद्वेष, भाषायी अस्मिताओं और क्षेत्रीय असंतुलनों के बीच एक अखिल भारतीय पहचान गढ़ना एक चुनौती थी। ऐसे दौर में दिनकर जैसे चिंतनशील कवि और विचारक ने इतिहास के आलोक में भारतीय संस्कृति की यात्रा का विवेचन किया, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि भारत की आत्मा केवल बाहरी सत्ता परिवर्तन से नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति की निरंतरता और सहिष्णुता से जीवित है। इस ऐतिहासिक संदर्भ में *संस्कृति के चार अध्याय* की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह कृति न केवल अतीत की घटनाओं का मूल्यांकन करती है, बल्कि भविष्य की राह दिखाने वाली सांस्कृतिक घोषणापत्र के रूप में भी सामने आती है। इस कालखंड में शीतयुद्ध का वातावरण था, पश्चिमी पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच वैचारिक संघर्ष चल रहा था, और भारत पंचशील के सिद्धांतों तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से अपनी स्वतंत्र वैचारिक स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे समय में दिनकर ने संस्कृति की व्याख्या को केवल धर्म या परंपरा तक सीमित न रखकर उसे मानव मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के आधार के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति चार बड़ी ऐतिहासिक क्रांतियों से बनी है—आर्यों और आर्येत्तर जातियों का मेल, बौद्ध-जैन विद्रोह, इस्लाम का आगमन तथा यूरोप से संपर्क—और यही विविध प्रभाव भारतीयता की आधारशिला हैं। 1950 के दशक का भारत आधुनिक विज्ञान, तकनीक और लोकतंत्र की ओर अग्रसर था, किंतु साथ ही अपनी जड़ों से जुड़ाव की चिंता भी थी। इसीलिए दिनकर ने इस ग्रंथ में यह दिखाने का प्रयास किया कि भारतीय संस्कृति समय-समय पर बाहरी आघातों और अंतर्विरोधों से गुज़रकर भी अपने मूल स्वभाव को बनाए रखने में सक्षम रही है। इस रचना का ऐतिहासिक संदर्भ यह स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रनिर्माण के लिए सांस्कृतिक आधार को समझना क्यों आवश्यक था। इसी कारण *संस्कृति के चार अध्याय* केवल साहित्यिक ग्रंथ न रहकर स्वतंत्र भारत की सांस्कृतिक पुनर्समीक्षा और ऐतिहासिक चेतना का दस्तावेज़ बन गया, जिसने न केवल दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया बल्कि उन्हें 'राष्ट्रीय कवि' की उपाधि भी स्थायी रूप से स्थापित कर दी।

स्वतंत्रता-उत्तर भारत की सांस्कृतिक खोज-स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने केवल राजनीतिक पुनर्निर्माण का कार्य नहीं था, बल्कि उससे भी बड़ी चुनौती थी – अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए युग की परिस्थितियों में पुनः परिभाषित करना। दो शताब्दियों की औपनिवेशिक दासता ने भारतीय समाज को मानसिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर गहरी चोट पहुँचाई थी। अंग्रेज़ी शासन ने आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का परिचय कराया, किंतु साथ ही भारतीय परंपराओं, भाषाओं और जीवन-मूल्यों को हीन समझने की प्रवृत्ति भी फैलाई। स्वतंत्रता के बाद यह प्रश्न उभर कर सामने आया कि क्या भारत पश्चिमी सभ्यता के मार्ग पर अंधानुकरण करेगा या अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर आधुनिकता को आत्मसात करेगा। इस दौर में सांस्कृतिक खोज का पहला आयाम था – **राष्ट्रीय एकता की तलाश**। विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक हिंसा के बीच यह आवश्यक हो गया कि संस्कृति को वह सूत्र बनाया जाए, जो विविधता को जोड़ सके। दूसरा आयाम था – **अतीत के गौरव का पुनर्मूल्यांकन**। प्राचीन वैदिक परंपरा से लेकर बौद्ध, जैन, भक्ति और सूफी आंदोलनों तक, इतिहास की हर धारा को नए सिरे से देखा जाने लगा, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, समन्वय और समावेशिता की परंपरा सदैव जीवित रही है। तीसरा आयाम था – **आधुनिकता और परंपरा का संतुलन**। औद्योगिकीकरण, लोकतंत्र और वैज्ञानिक चेतना को अपनाते हुए भी भारतीय समाज अपने आध्यात्मिक मूल्यों, नैतिकता और मानवीय दृष्टिकोण को अक्षुण्ण रखना चाहता था। स्वतंत्रता-उत्तर भारत की सांस्कृतिक खोज का चौथा पहलू था – **जनता की भूमिका का स्वीकार**। संस्कृति अब केवल शासक वर्ग या अभिजात्य का विषय न रहकर लोकजीवन, लोककला, लोकभाषाओं और ग्रामीण परंपराओं तक विस्तृत हो गई। इस सन्दर्भ में रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकारों ने संस्कृति को जनता की रचना बताया और इतिहास को शासकों की गाथा के बजाय जनजीवन के संघर्ष और सृजन के रूप में परिभाषित किया। इस खोज का अंतिम और महत्वपूर्ण पहलू था – **राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक व्याख्या**, जिसमें भारत को केवल भौगोलिक इकाई न मानकर एक सांस्कृतिक धारा के रूप में देखा गया। यही कारण है कि *संस्कृति के चार अध्याय* जैसी कृतियाँ स्वतंत्रता-उत्तर भारत की सांस्कृतिक खोज का दार्शनिक और ऐतिहासिक आधार बन गईं। इस खोज ने भारतीय समाज को यह समझने में मदद की कि आधुनिक भारत की शक्ति केवल राजनीतिक स्वतंत्रता में नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति की निरंतरता, समन्वय और जीवन-मूल्यों की धारा को जीवित रखने में निहित है।

भारतीय संस्कृति के मूल तत्व-भारतीय संस्कृति की विशिष्टता उसकी गहराई, विविधता और समन्वयशीलता में निहित है, जिसने सहस्राब्दियों तक विभिन्न परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच स्वयं को संरक्षित और विकसित किया। यह संस्कृति केवल धार्मिक आस्था या सामाजिक संरचना भर नहीं, बल्कि जीवन के सभी आयामों—धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, राजनीति और लोकजीवन—को अपने भीतर समाहित करने वाली सतत प्रवाहमान धारा है। इसके मूल तत्वों को समझने के लिए हमें चार प्रमुख आधारों पर दृष्टिपात करना होगा, जो समय-समय पर भारतीय समाज की दिशा और धारा को निर्धारित करते रहे हैं।

1. वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना-भारतीय संस्कृति का सर्वप्रथम आधार वैदिक परंपरा है, जिसने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का सूत्रपात किया, बल्कि समाज की संरचना और जीवन-मूल्यों की बुनियाद रखी। वेदों में वर्णित ऋचाएँ प्रकृति-पूजा से आरंभ होकर धीरे-धीरे एकेश्वरवाद और सार्वभौमिक सत्य की खोज की ओर अग्रसर होती हैं। यज्ञ, मंत्र और ऋचाओं के माध्यम से मनुष्य ने ईश्वर, प्रकृति और अपने बीच एक संवाद स्थापित किया। वैदिक संस्कृति ने धर्म को केवल अनुष्ठान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जीवन की नैतिकता, कर्तव्य और ऋत (सत्य और नियम) के पालन पर बल दिया। आध्यात्मिक चेतना की जड़ें भी इसी वैदिक काल में पड़ीं, जिसने यह प्रतिपादित किया कि संसार केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और ब्रह्म से संचालित है।

2. उपनिषद, गीता और दार्शनिक परंपराएँ-वेदांत की गहनता उपनिषदों में प्रकट हुई, जहाँ 'अहं ब्रह्मास्मि', दौर में सांस्कृतिक खोज का पहला आयाम था – **राष्ट्रीय एकता की तलाश**। विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक हिंसा के बीच यह आवश्यक हो गया कि संस्कृति को वह सूत्र बनाया जाए, जो विविधता को जोड़ सके। दूसरा आयाम था – **अतीत के गौरव का पुनर्मूल्यांकन**। प्राचीन वैदिक परंपरा से लेकर बौद्ध, जैन, भक्ति और सूफी आंदोलनों तक, इतिहास की हर धारा को नए सिरे से देखा जाने लगा, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, समन्वय और समावेशिता की परंपरा सदैव जीवित रही है। तीसरा आयाम था – **आधुनिकता और परंपरा का संतुलन**। औद्योगिकीकरण, लोकतंत्र और वैज्ञानिक चेतना को अपनाते हुए भी भारतीय समाज अपने आध्यात्मिक मूल्यों, नैतिकता और मानवीय दृष्टिकोण को अक्षुण्ण रखना चाहता था। स्वतंत्रता-उत्तर भारत की सांस्कृतिक खोज का चौथा पहलू था – **जनता की भूमिका का स्वीकार**। संस्कृति अब केवल शासक वर्ग या अभिजात्य का विषय न रहकर लोकजीवन, लोककला, लोकभाषाओं और ग्रामीण परंपराओं तक विस्तृत हो गई। इस सन्दर्भ में रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकारों ने संस्कृति को जनता की रचना बताया और इतिहास को शासकों की गाथा के बजाय जनजीवन के संघर्ष और सृजन के रूप में परिभाषित किया। इस खोज का अंतिम और महत्वपूर्ण पहलू था – **राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक व्याख्या**, जिसमें भारत को केवल भौगोलिक इकाई न मानकर एक सांस्कृतिक धारा के रूप में देखा गया। यही कारण है कि *संस्कृति के चार अध्याय* जैसी कृतियाँ स्वतंत्रता-उत्तर भारत की सांस्कृतिक खोज का दार्शनिक और ऐतिहासिक आधार बन गईं। इस खोज ने भारतीय समाज को यह समझने में मदद की कि आधुनिक भारत की शक्ति केवल राजनीतिक स्वतंत्रता में नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति की निरंतरता, समन्वय और जीवन-मूल्यों की धारा को जीवित रखने में निहित है।

भारतीय संस्कृति के मूल तत्व-भारतीय संस्कृति की विशिष्टता उसकी गहराई, विविधता और समन्वयशीलता में निहित है, जिसने सहस्राब्दियों तक विभिन्न परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच स्वयं को संरक्षित और विकसित किया। यह संस्कृति केवल धार्मिक आस्था या सामाजिक संरचना भर नहीं, बल्कि जीवन के सभी आयामों—धर्म,

दर्शन, कला, साहित्य, राजनीति और लोकजीवन—को अपने भीतर समाहित करने वाली सतत प्रवाहमान धारा है। इसके मूल तत्वों को समझने के लिए हमें चार प्रमुख आधारों पर दृष्टिपात करना होगा, जो समय-समय पर भारतीय समाज की दिशा और धारा को निर्धारित करते रहे हैं।

1. वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना-भारतीय संस्कृति का सर्वप्रथम आधार वैदिक परंपरा है, जिसने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का सूत्रपात किया, बल्कि समाज की संरचना और जीवन-मूल्यों की बुनियाद रखी। वेदों में वर्णित ऋचाएँ प्रकृति-पूजा से आरंभ होकर धीरे-धीरे एकेश्वरवाद और सार्वभौमिक सत्य की खोज की ओर अग्रसर होती हैं। यज्ञ, मंत्र और ऋचाओं के माध्यम से मनुष्य ने ईश्वर, प्रकृति और अपने बीच एक संवाद स्थापित किया। वैदिक संस्कृति ने धर्म को केवल अनुष्ठान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जीवन की नैतिकता, कर्तव्य और ऋत (सत्य और नियम) के पालन पर बल दिया। आध्यात्मिक चेतना की जड़ें भी इसी वैदिक काल में पड़ीं, जिसने यह प्रतिपादित किया कि संसार केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और ब्रह्म से संचालित है।

2. उपनिषद, गीता और दार्शनिक परंपराएँ-वेदांत की गहनता उपनिषदों में प्रकट हुई, जहाँ 'अहं ब्रह्मास्मि', 'तत्त्वमसि', और 'नेति-नेति' जैसे सूत्रों ने मनुष्य और ब्रह्मांड के अद्वैत संबंध को स्पष्ट किया। उपनिषदों की दार्शनिकता ने आत्मा, ब्रह्म और जगत के बीच के रहस्य को उद्घाटित कर भारतीय चिंतन को सार्वभौमिक आयाम प्रदान किया। इसके साथ ही *भगवद्गीता* भारतीय संस्कृति का एक केंद्रीय ग्रंथ बनी, जिसने कर्म, ज्ञान और भक्ति को एक साथ जोड़कर जीवन का समन्वित दर्शन प्रस्तुत किया। गीता ने न केवल व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग दिखाया, बल्कि लोकमंगल और कर्तव्यपालन को भी धर्म का अंग माना। दार्शनिक परंपराओं में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत जैसी छह दर्शनों ने भिन्न-भिन्न दृष्टियों से सत्य और मोक्ष की खोज की, जिनसे भारतीय संस्कृति में वैचारिक बहुलता और गहनता आई।

3. बौद्ध, जैन और भक्ति-आंदोलन का योगदान-भारतीय संस्कृति के विकास में बौद्ध और जैन धर्मों का विशेष स्थान है। महावीर और बुद्ध ने वैदिक परंपरा के जटिल कर्मकांडों का विरोध कर साधारण जन के लिए धर्म को सहज और व्यावहारिक बनाया। अहिंसा, करुणा, संयम और समानता जैसे सिद्धांतों ने सामाजिक अन्याय और असमानता को चुनौती दी तथा मानवता के सार्वभौमिक मूल्यों को सुदृढ़ किया। बौद्ध धर्म के संघ, त्रिरत्न और मध्यम मार्ग तथा जैन धर्म के अनुव्रत और अपरिग्रह के सिद्धांत भारतीय संस्कृति की मानवीय संवेदना और नैतिकता को गहराई तक प्रभावित करते हैं। बाद के समय में भक्ति आंदोलन ने इन परंपराओं को और अधिक जनमानस से जोड़ दिया। कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, नानक आदि संतों ने भक्ति को जाति-धर्म की सीमाओं से परे सार्वभौमिक प्रेम और समर्पण का स्वरूप दिया। भक्ति आंदोलन ने समाज में समानता, भाईचारा और मानवीय मूल्य स्थापित किए तथा हिंदू-मुस्लिम सांस्कृतिक संवाद को नया आधार दिया।

4. मुस्लिम काल और गंगा-जमुनी संस्कृति-भारतीय संस्कृति का एक और प्रमुख तत्व मुस्लिम काल के दौरान विकसित गंगा-जमुनी तहज़ीब है। इस्लाम के आगमन ने भारतीय समाज को नए धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान किए। कला, स्थापत्य, साहित्य और संगीत में इस्लामी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दिल्ली, आगरा और लखनऊ जैसे नगरों में विकसित स्थापत्य—जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल और जामा मस्जिद—भारतीय और इस्लामी शैलियों के अनूठे संगम के उदाहरण हैं। सूफी संतों और भक्ति कवियों ने मिलकर धार्मिक सहिष्णुता और मानव प्रेम का संदेश दिया, जिससे एक समन्वित सांस्कृतिक परंपरा का निर्माण हुआ। गंगा-जमुनी संस्कृति केवल धार्मिक संवाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि भाषा, संगीत और खानपान में भी इसका गहरा असर देखा गया। हिंदुस्तानी संगीत का विकास, उर्दू भाषा का उत्कर्ष और साझा लोकपरंपराएँ इसी काल की उपज हैं।

इस प्रकार भारतीय संस्कृति के मूल तत्व वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक निरंतर विकसित होते रहे, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा एक ही रही—समन्वय, सहिष्णुता और आध्यात्मिक गहराई। वैदिक ऋचाओं की प्रकृति-पूजा से लेकर उपनिषदों के अद्वैत दर्शन, बुद्ध और महावीर की करुणा व अहिंसा, संत कवियों की भक्ति-भावना और मुस्लिम काल की गंगा-जमुनी तहज़ीब—ये सभी धाराएँ मिलकर उस विराट सांस्कृतिक धारा का निर्माण करती हैं, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाता है। यही संस्कृति भारत की पहचान है और यही उसे विश्व की अन्य संस्कृतियों से अलग विशिष्ट स्थान प्रदान करती है।

संस्कृति का गतिशील स्वरूप-भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका गतिशील स्वरूप है, जिसने उसे समय-समय पर आने वाले आक्रमणों, संघर्षों और नई चुनौतियों के बीच भी न केवल जीवित रखा, बल्कि और अधिक समृद्ध और प्रगतिशील बनाया। यह संस्कृति स्थिर या जड़ित सत्ता नहीं, बल्कि सतत प्रवाहित धारा है, जिसमें परिवर्तन और विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह विद्यमान रहे हैं। इसके गतिशील स्वरूप को तीन प्रमुख पहलुओं में समझा जा सकता है।

1. आक्रमणों, संघर्षों और समन्वय की प्रक्रिया-भारत का इतिहास बाहरी आक्रमणों, संघर्षों और उनसे उपजे सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों से भरा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्यों का आगमन और आर्य-आर्येत्तर संस्कृतियों का मेल ही पहला उदाहरण है कि कैसे संघर्ष के बावजूद समन्वय की प्रक्रिया ने भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी। इसके बाद बौद्ध और जैन धर्मों का उदय भी पारंपरिक वैदिक कर्मकांडों के विरुद्ध एक सांस्कृतिक विद्रोह था, जिसने नए जीवन-मूल्यों और नैतिकताओं को जन्म दिया। मध्यकालीन काल में इस्लाम का आगमन और मुस्लिम शासन के साथ हुए संपर्क ने भी अनेक संघर्ष उत्पन्न किए, परंतु यही संघर्ष अंततः गंगा-जमुनी तहज़ीब के रूप में सांस्कृतिक समन्वय का आधार बने। हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का मेल स्थापत्य, भाषा, संगीत और साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार अंग्रेज़ों का शासन और यूरोपीय विचारधाराओं का प्रवेश प्रारंभ में सांस्कृतिक टकराव का कारण बना, लेकिन धीरे-धीरे इसने शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और लोकतांत्रिक मूल्यों को भारतीय समाज में स्थापित कर दिया। यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति संघर्षों से टूटती नहीं, बल्कि नए तत्वों को आत्मसात कर और अधिक परिपक्व बनती है।

2. भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता और समावेशिता-भारतीय संस्कृति की आत्मा सहिष्णुता और समावेशिता में निहित है। इसने हमेशा विभिन्न धर्मों, भाषाओं और परंपराओं को स्थान दिया और उन्हें आत्मसात करके अपनी शक्ति बढ़ाई। वैदिक युग से ही भारतीय विचार में यह धारणा रही कि सत्य एक है, परंतु उसे जानने के मार्ग अनेक हो सकते हैं—"एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति।" यही दृष्टिकोण आगे उपनिषदों, गीता और दार्शनिक परंपराओं में भी दिखाई देता है। बौद्ध और जैन धर्मों ने भी भारतीय संस्कृति के भीतर स्थान पाया और अहिंसा, करुणा तथा अपरिग्रह जैसे मूल्य इसके मूल तत्व बन गए। मध्यकाल में सूफी संतों और भक्ति कवियों ने हिंदू-मुस्लिम संबंधों को मानवीय प्रेम और भक्ति के आधार पर जोड़ा। यही नहीं, आधुनिक काल में जब पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा का प्रवेश हुआ, तो भारतीय संस्कृति ने उसमें से लोकतंत्र, मानवाधिकार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ग्रहण किया, परंतु अपनी आध्यात्मिकता और नैतिकता को भी बनाए रखा। सहिष्णुता और समावेशिता का यही गुण भारतीय संस्कृति को अद्वितीय बनाता है और यही इसकी जीवंतता और स्थायित्व का कारण है।

3. संस्कृति का निरंतर विकास और परिवर्तनशीलता-भारतीय संस्कृति का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू इसकी निरंतर विकासशीलता और परिवर्तनशीलता है। यह संस्कृति समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने रूप-स्वरूप में बदलाव करती रही है, परंतु उसकी मूल आत्मा अपरिवर्तित रही है। उदाहरण के लिए, वैदिक युग की कर्मप्रधानता को उपनिषदों ने ज्ञान और ध्यान की ओर मोड़ा, गीता ने इसे कर्म, भक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी संगम में बदल दिया, बौद्ध और जैन धर्मों ने इसे नैतिकता और करुणा से समृद्ध किया, और भक्ति आंदोलन ने इसे जनसाधारण की आस्था और प्रेम से जोड़ दिया। इसी तरह मुस्लिम काल में भारतीय संस्कृति ने स्थापत्य, संगीत और भाषा में नए रूप ग्रहण किए, और आधुनिक काल में उसने लोकतंत्र, विज्ञान और शिक्षा के आदर्शों को अपनाया। संस्कृति का यही निरंतर विकास और परिवर्तनशीलता उसे जड़ता से बचाकर उसे जीवन्त और प्रासंगिक बनाए रखती है। दिनकर का कहना था कि संस्कृति वह जीवनधारा है, जो हर कालखंड में नई परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करके और अधिक परिपुष्ट होती है। यही कारण है कि भारत में आज भी धर्म, भाषा, कला, साहित्य और परंपराओं की अपार विविधता के बावजूद एकता और साझा सांस्कृतिक चेतना विद्यमान है। भारतीय संस्कृति का गतिशील स्वरूप ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। आक्रमणों और संघर्षों के बीच उसने समन्वय किया, सहिष्णुता और समावेशिता के कारण सबको स्थान दिया, और निरंतर विकास व परिवर्तनशीलता के कारण हर युग में अपने को नया रूप प्रदान किया। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों से विश्व की सबसे प्राचीन और जीवंत संस्कृतियों में गिनी जाती है, जो आज भी मानवता को मार्गदर्शन प्रदान कर रही है।

दिनकर की दृष्टि-रामधारी सिंह दिनकर की कृति *संस्कृति के चार अध्याय* भारतीय इतिहास और संस्कृति का केवल वर्णन मात्र नहीं है, बल्कि यह उनके राष्ट्रवादी चिंतन और सांस्कृतिक दृष्टि का सार है। दिनकर ने संस्कृति को केवल अतीत की स्मृति या धार्मिक परंपरा के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे राष्ट्रनिर्माण की आत्मा और जनता के जीवन-मूल्यों का प्रवाह माना। उनके विचार तीन मुख्य आयामों में स्पष्ट होते हैं।

1. राष्ट्रवादी दृष्टिकोण-दिनकर का दृष्टिकोण मूलतः राष्ट्रवादी था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने केवल राजनीतिक एकता की चुनौती नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक एकता का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण था। दिनकर मानते थे कि राष्ट्र का निर्माण केवल संविधान और कानूनों से नहीं होता, बल्कि उसकी असली नींव संस्कृति होती है, जो लोगों के जीवन, मूल्य और दृष्टिकोण को जोड़ती है। उन्होंने इतिहास को इस दृष्टि से देखा कि वह जनता की सांस्कृतिक यात्रा का दर्पण है, जहाँ हर संघर्ष और आक्रमण ने भारतीय आत्मा को और अधिक दृढ़ बनाया। दिनकर राष्ट्रवाद को संकीर्ण न मानकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें धर्म, जाति और भाषा से परे एक साझा भारतीय अस्मिता की कल्पना की जाती है। उनके लिए भारतीय संस्कृति स्वतंत्रता का प्रेरक स्रोत भी थी और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र की स्थिरता और विकास का आधार भी।

2. भारतीय संस्कृति की 'एकता में विविधता' की अवधारणा-दिनकर की दृष्टि का दूसरा प्रमुख पहलू है भारतीय संस्कृति की "एकता में विविधता" की अवधारणा। भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों और परंपराओं का देश है, लेकिन इन विविधताओं के बावजूद यह एक सांस्कृतिक धारा में बंधा हुआ है। दिनकर ने स्पष्ट किया कि भारतीय संस्कृति का असली सार उसकी समावेशिता में है—आर्यों और द्रविड़ों का मेल, बौद्ध और जैन परंपराओं का योगदान, इस्लाम के प्रभाव से गंगा-जमुनी तहज़ीब का निर्माण, और यूरोप के संपर्क से आधुनिक चेतना का उदय—ये सभी धाराएँ अलग-अलग होकर भी एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का हिस्सा हैं। उन्होंने दिखाया कि भारत की एकता किसी एक धर्म या जाति पर आधारित नहीं है, बल्कि उन साझा मूल्यों पर आधारित है जो मानवता, सहिष्णुता, करुणा और लोकमंगल को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि विविधताओं के बावजूद भारतीय संस्कृति का आधारभूत ढाँचा कभी टूटा नहीं, बल्कि और अधिक समृद्ध हुआ। दिनकर की यह अवधारणा स्वतंत्रता-उत्तर भारत की सबसे बड़ी चुनौती—राष्ट्रीय एकता—के समाधान के रूप में भी महत्वपूर्ण थी।

3. संस्कृति को जोड़ने वाला सूत्र-दिनकर की दृष्टि में संस्कृति केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला सूत्र है। उन्होंने माना कि संस्कृति वह शक्ति है, जो जनता को आंतरिक रूप से एक करती है और उसे बाहरी चुनौतियों के सामने स्थिर खड़ा करती है। उनके लिए संस्कृति का सूत्र सहिष्णुता, समन्वय और निरंतर विकास है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास केवल राजवंशों का इतिहास नहीं, बल्कि जनता की संस्कृति का इतिहास है, जिसमें हर युग ने नए मूल्यों को जन्म दिया और पुरानों को परिष्कृत किया। संस्कृति ने भारत को यह शक्ति दी कि वह हर आक्रमण और संघर्ष से नए रूप में उभर सके और आधुनिक काल में लोकतंत्र, विज्ञान और शिक्षा को आत्मसात करते हुए भी अपनी आत्मा को सुरक्षित रख सके। दिनकर का यह दृष्टिकोण बताता है कि संस्कृति केवल स्मृति का संग्रह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और प्रगति का जीवंत सूत्र है, जो विविधताओं को एक डोर में पिरोकर भारत को विश्व में विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। अतः स्पष्ट है कि दिनकर की दृष्टि में *संस्कृति के चार अध्याय* भारतीय संस्कृति की राष्ट्रवादी व्याख्या है, जिसमें "एकता में विविधता" को उसका केंद्रीय आधार माना गया और संस्कृति को जोड़ने वाले सूत्र के रूप में सहिष्णुता और समन्वय को प्रतिष्ठित किया गया। यह दृष्टि न केवल स्वतंत्रता-उत्तर भारत के सांस्कृतिक संकट का उत्तर थी, बल्कि आज भी राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता का मार्गदर्शन करती है।

साहित्य की समीक्षा-कुमार (2020) ने हैबरलिन दर्पण से भारत को देखने का प्रयास करते हुए संवैधानिक सिद्धांत और भारतीय लोकतंत्र के बीच संबंधों को स्पष्ट किया है। यह लेख बताता है कि भारतीय संविधान केवल विधिक ढांचा नहीं है, बल्कि समाज के सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर, सिंह (2008) ने भारत में बहुसांस्कृतिक पहचान और लोकतंत्र पर चर्चा करते हुए यह दिखाया है कि विविधताओं से भरे इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब वह बहुलता और समावेशिता को मान्यता दे। इन दोनों लेखों का सम्मिलित अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत का संवैधानिक ढांचा और बहुसांस्कृतिक समाज परस्पर जुड़े हुए हैं और यही संबंध भारतीय लोकतंत्र की शक्ति का आधार हैं।

सिंह (2009) ने पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और सभ्यता पर ऐतिहासिक शोध प्रस्तुत किया है, जिसमें क्षेत्रीय विविधताओं और सांस्कृतिक विशिष्टताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कार्य इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि यह भारत की बहुसांस्कृतिकता को केवल उत्तर भारत या मुख्यधारा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि भौगोलिक और सांस्कृतिक परिधि को भी व्यापक बनाता है। वहीं, जिया (2021) का शोध 1956 के एशियाई लेखक सम्मेलन के संदर्भ में भारत-चीन सांस्कृतिक संबंधों और शीत युद्ध की राजनीति को विश्लेषित करता है। इससे यह समझ आता है कि संस्कृति केवल आंतरिक नहीं होती, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में भी अपनी भूमिका निभाती है। इन दोनों अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संस्कृति एक ओर जहाँ क्षेत्रीय विशिष्टताओं से समृद्ध है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर संवाद और संघर्ष में भी सक्रिय भूमिका निभाती है।

पाठक (2022) का शोध खट्टर काका की रचनाओं के माध्यम से हास्य की साहित्यिक-सांस्कृतिक राजनीति को समझने का प्रयास करता है। इसमें यह दिखाया गया है कि हास्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने और सामाजिक यथास्थितिवाद की आलोचना करने का एक प्रभावी माध्यम है। इसी क्रम में मणि (2012) ने हिंदी और तमिल लघुकथाओं (1950–1970) में लिंग और शैली के प्रश्नों को उठाते हुए साहित्यिक विमर्श को स्त्रीवादी और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से जोड़ा है। दोनों ही स्रोत यह स्पष्ट करते हैं कि साहित्य संस्कृति और समाज का दर्पण है, जो समय-समय पर राजनीति, सत्ता और सामाजिक अन्याय का प्रतिरोध करता है तथा नए विमर्शों को जन्म देता है।

सिंह (2023) का कार्य अनुवाद के शुद्धिकरण और उपनिवेशवाद-मुक्त समाजभाषाविज्ञान पर केंद्रित है। इसमें अंग्रेज़ी और उर्दू प्रतीकों से हिंदी अनुवाद की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए यह दिखाया गया है कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र भी है। उपनिवेशवाद के बाद भाषाई शुद्धिकरण और अनुवाद की चुनौतियाँ भारतीय समाज के लिए विशेष महत्त्व रखती हैं, क्योंकि वे न केवल भाषायी पहचान से जुड़ी हैं, बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता के प्रश्न से भी गहराई से संबंधित हैं। यह अध्ययन भारतीय संस्कृति और साहित्य के विकास में अनुवाद की केंद्रीय भूमिका और उसके राजनीतिक निहितार्थों को उजागर करता है।

अंतिम स्रोत सिंह (2019) का है, जिसमें 21वीं सदी की भू-राजनीति, लोकतंत्र और शांति के बीच संबंधों की पड़ताल की गई है। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि वैश्वीकरण, आतंकवाद, क्षेत्रीय संघर्ष और महाशक्तियों की राजनीति के बीच लोकतंत्र और शांति कैसे प्रभावित होते हैं। यह विमर्श भारत जैसे देश के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करना आवश्यक है। इस शोध का महत्त्व इसलिए भी है कि यह संस्कृति और राजनीति को जोड़ता है और यह दिखाता है कि शांति और स्थिरता के लिए सांस्कृतिक कूटनीति कितनी महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष-रामधारी सिंह दिनकर की *संस्कृति के चार अध्याय* भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक यात्रा और तात्त्विक विवेचना का एक अद्वितीय ग्रंथ है, जो यह सिद्ध करता है कि भारत की संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाहमान धारा है, जिसने विभिन्न कालखंडों में आक्रमणों, संघर्षों, सामाजिक विद्रोहों और बाहरी प्रभावों के बावजूद अपनी आत्मा को सुरक्षित रखा और हर चुनौती को अवसर में बदलते हुए स्वयं को और अधिक समृद्ध किया। वैदिक काल की आध्यात्मिक चेतना, उपनिषदों और गीता की दार्शनिक गहराई, बौद्ध और जैन धर्मों की करुणा और अहिंसा, भक्ति आंदोलन की समरसता और मुस्लिम काल की गंगा-जमुनी तहज़ीब से लेकर आधुनिक युग में यूरोपीय विचारों से उत्पन्न लोकतांत्रिक चेतना तक—यह संपूर्ण यात्रा भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता, समावेशिता और निरंतर परिवर्तनशीलता को प्रमाणित करती है। दिनकर की दृष्टि में संस्कृति वह सूत्र है, जो भारत की विविधताओं को एक डोर में पिरोकर उसे राष्ट्र की आत्मा प्रदान करती है। उनका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि वास्तविक राष्ट्रनिर्माण तभी संभव है जब संस्कृति जनता की चेतना और जीवन-मूल्यों के केंद्र में हो। स्वतंत्रता-उत्तर भारत की सांस्कृतिक खोज के संदर्भ में यह कृति और भी प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि यह स्पष्ट करती है कि भारतीयता किसी एक धर्म, जाति या भाषा की देन नहीं, बल्कि विविधताओं का समन्वय है। आज के वैश्वीकरण, सांप्रदायिकता और सांस्कृतिक विखंडन के दौर में दिनकर का यह संदेश और भी आवश्यक हो उठता है कि संस्कृति की शक्ति ही राष्ट्र को स्थिरता और भविष्य की राह दिखा सकती है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि *संस्कृति के चार अध्याय* केवल साहित्यिक या ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा का घोषणापत्र है, जो हमारी जड़ों को पहचानने, वर्तमान को समझने और भविष्य की दिशा तय करने में निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

संदर्भ

1. कुमार, पी. (2020). संवैधानिक सिद्धांत के हैबरलीन दर्पण से भारत को देखना। रेविस्टा आर्गुमेंटम-आर्गुमेंटम जर्नल ऑफ लॉ, 21(3), 1413-1436.

2. सिंह, एम. पी. (2008). भारत में बहुसांस्कृतिक पहचान और लोकतंत्र। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र, विकास और असंतोष में (पृष्ठ 59-75)। सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

3. सिंह, जी. पी. (2009). पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और सभ्यता के कुछ पहलुओं पर ऐतिहासिक शोध। ज्ञान पब्लिशिंग हाउस।

4. जिया, वाई. (2021). सांस्कृतिक बांडुंग या लेखकीय शीत युद्ध? भारत-चीन परिप्रेक्ष्य से 1956 के एशियाई लेखक सम्मेलन का पुनरीक्षण। सांस्कृतिक शीत युद्ध और वैश्विक दक्षिण: संघर्ष और समुदाय के स्थल।

5. पाठक, डी. एन. (2022). खट्टर काका का विध्वंसकारी हिंदू धर्म: हास्य की साहित्यिक-सांस्कृतिक राजनीति का एक उदाहरण। दक्षिण एशिया में हास्य और शक्ति प्रदर्शन (पृष्ठ 45-64)। रूटलेज इंडिया।

6. मणि, पी. एल. (2012)। लिंग, शैली और भारतीय साहित्य की अवधारणा: हिंदी और तमिल में लघु कथाएँ, 1950-1970। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले।

7. सिंह, जे. एन. (2023)। 2 अंग्रेजी और उर्दू प्रतीकों से हिंदी अनुवाद का 'शुद्धिकरण': क. दक्षिणी सिद्धांत से उपनिवेशवाद-मुक्त समाजभाषाविज्ञान तक: आवाज़ें, प्रश्न और विकल्प, 5.

8. सिंह, बी. पी. (2019)। 21वीं सदी में भू-राजनीति, लोकतंत्र और शांति। रूटलेज इंडिया।

9. सिंह, बी. पी. (2020)। डॉ. बी.आर. अंबेडकर का न्याय के एक साधन के रूप में संविधानवाद का दर्शन: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 66(4), 596-608।

10. सिंह, बी.पी. (2010)। धागों से बुने आदर्श, सिद्धांत और प्रशासन। एलाइड पब्लिशर्स।

11. गांधी, ए.के. (2022)। लोकप्रिय भारतीय नेताओं की जीवनियाँ: लोकनायक जेपी की जीवनी/डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम: एक संत वैज्ञानिक की जीवनी/वीर सावरकर का जीवन और समय: सभी पाठकों के लिए प्रेरणादायक जीवनियाँ: लोकप्रिय भारतीय नेताओं की जीवनियाँ: लोकनायक जेपी की जीवनी/डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम: एक संत वैज्ञानिक की जीवनी/वीर सावरकर का जीवन और समय। प्रभात प्रकाशन।

12. कौर, आर., और माथुर, एन. (सं.) भारत के लोग: 21वीं सदी में नई भारतीय राजनीति। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

13. बटब्याल, आर. (2017, जनवरी)। जवाहरलाल नेहरू और एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय का विचार। भारतीय इतिहास कांग्रेस की कार्यवाही में (खंड 78, पृष्ठ 1193-1200)। भारतीय इतिहास कांग्रेस।

14. लोथस्पीच, पी. जे. (2003)। हिंदी साहित्य में महाभारत (1910-1940) और हिंदू राष्ट्रीय पहचान। कोलंबिया विश्वविद्यालय।

15. चौहान, ए. (2016)। गरीबी का सामाजिक मनोविज्ञान विकसित करना: सामाजिक वस्तुएँ और संवादात्मक निरूपण (डॉक्टरेट शोध प्रबंध, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस)।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 9-10
पृष्ठ : 228–232

हिन्दी उपन्यासों में 'किसान विमर्श'

हेमचंद साहू
शोधार्थी, हिन्दी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

शोध सार :-

बीसवीं सदी के कथा साहित्य में किसानों की आर्थिक और सामाजिक जीवन की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया हैं | भारत एक कृषि प्रधान देश हैं | भारत की लगभग 70% जनसँख्या कृषि पर आधारित है | भारत में किसान मुख्यतः 3 प्रकार के हैं -लघु, सीमांत और वृहद् | जिनमें से लघु और सीमांत किसानों की स्थिति दयनीय है | भारत को कृषि प्रधान होने के कारण किसानों का देश कहना उचित लगता है ,क्योकि किसान को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है | हिंदी साहित्य में किसानों के सहयोग एवं परिश्रम को देखते हुए सुनिश्चित करना चाहिये , साहित्य में अलग – अलग विमर्शो का अपना अलग विमर्श का इतिहास लेखन एवं साहित्य में उसका मूल्यांकन होना चाहिए | साहित्य समय के साथ बदलती रहती है | साहित्य में समय के साथ विभिन्न प्रकार के नए - नए विमर्श आये और साहित्य में अपना स्थान बना लिए – जैसे :- स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श तथा प्रवासी विमर्श आदि इसी प्रकार आज के समय में किसान विमर्श भी उभर के आये लेकिन किसान विमर्श आज भी उपेक्षित और समाज में पिछड़ा हुआ है | बाकि और अन्य विमर्शों की तरह किसान विमर्श पर भी शोध और संगोष्ठी होनी चाहिए |

गाँधी जी ने ठीक ही कहा है "भारत गाँव का देश है और कृषि भारत की आत्मा है |" किसानों का जीवन शुरू से अंत तक संघर्षो से घिरा रहा है इन्ही सब बातों पर बीसवीं सदी के कथाकारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास किया और उनकी समस्याओं पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई |

आधुनिक काल के बाद किसानों को साहित्य में स्थान **प्रेमचंद** की रचनाओं जैसे :- प्रेमाश्रय (1921) - जिसमें किसानों के दशा और दिशा की वास्तविकता को बखूबी दिखाया गया है | इस उपन्यास में किसान विमर्श प्रारंभिक स्तर पर है बीज रूप में |

गोदान (1936)- किसान विमर्श परिपक्व और व्यापक है | प्रेमचंद का यह उपन्यास किसानों की समस्याओं का महाकाव्य कहा जाता है

मूल शब्द :- उपन्यास , किसान , यथार्थ , ग्रामीण , शोषण , कर्ज , संघर्ष , त्रासदी

विषय वस्तु :- **आचार्य नन्ददुलारे बाजपाई :-** "मानव जीवन के विविध चित्रों को चित्रित करने का जितना अवकाश उपन्यासों में मिलता है , उतना अन्य साहित्यिक उपकरणों में नही |"

हिन्दी के अनेक कथाकारों ने कृषक जीवन को कहा है :-

- **डॉ. विवेकी राय –** प्रथम दशक वाले कथा साहित्य में तो ग्राम कथा को ही हिन्दी कथा सम्मान मिला था और शिव प्रसाद सिंह , नागार्जुन , फणीश्वरनाथ रेणु , रामदरश मिश्र , श्रीलाल शुक्ल , अमरकान्त , भैरव प्रसाद गुप्त , शैलेष मटियानी और पतुखोलिया आदि एक लम्बी कतार ग्राम कथा पर लिखने वालो की थी | तब सरकार का ध्यान गाँवों की ओर था | विकास योजनाएं असली रूप में ग्रामोन्मुख थी | और उसके बाद नगरबोध , इंडियाबोध , आधुनिकताबोध आदि की चकाचौंध बढती गई | विकास के अमानवीकरण चमक के साथ गाँव की उपेक्षा बढती गई और नगर के सुविधा से युक्त परिवेश में बैठकर लिखा जाने वाला गाँव से जुड़ा साहित्य फैशनेबुल ज्यादा होने लगा | (1)

- "हमारी ग्रामीण व्यवस्था पर आज भी जमीदार साहूकार और भूस्वामी वर्ग का दबदबा कायम है | भूमिसुधारों का अभाव , बेगार प्रथा , खेत मजदूरों का शोषण , उनकी उपज की कम कीमत देना , आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल द्वारा उन्हें रोजगार और व्यवसाय से वंचित करना | किसानों के कर्ज तले दबकर आत्महत्या करना | गरीब और निम्नवर्ग की स्त्रियों के साथ बलात्कार और जमीदारों और किसानों में संघर्ष हमारे गरमी एवं किसान जीवन की कटु वास्तविकतायें हैं | जब तक शोषण और उत्पीड़न की यह व्यवस्था हमारे देश में कायम है तब तक गाँव का किसान खुशहाल और शांति का जीवन कैसे बीता सकता है | हमारी ग्रामीण व्यवस्था अब भी शोषकों और उत्पीड़कों से त्रस्त है और उनके प्रति संघर्ष जारी है जो हर स्तर पर रहना चाहिए |(2)

प्रेमचंद का उपन्यास 'कर्मभूमि' नामक उपन्यास में किसान आन्दोलन जमीन की समस्या लगान कम करने और खेतिहर मजदूरों की समस्या पर यथार्थ से वर्णन प्राप्त होता है | अमरकान्त इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है जो किसान आन्दोलन का समर्थन करते हुए जेल की सजा काटता है और अमरकांत की पत्नी भी अछूतों के मंदिर प्रवेश को लेकर हुए आन्दोलन में हिस्सा लेने के कारण जेल चली जाती है | पत्रों के जीवन की विविध घटनाओं द्वारा प्रेमचंद ने अपने उदेश्यों को मूर्त रूप प्रदान किया |

रांगेय राघव द्वारा रचित उपन्यास 'विषाद मठ' में बंगाल की दुर्भिक्ष को चित्रित किया गया हैं | जमीन , घर , और लगान में पीस गये और दूसरी तरफ महाजन सूद पर पैसा देकर गरीब इंसानों की आर्थिक स्थिति को और अधुक कमजोर कर रहें थे | उपन्यास का नाम का चरितार्थ बताते हुए रांगेय राघव जी कहते हैं " जब मुगलों का राज समाप्त होने को आया था तब बंगाल की हरी भरी धरती पर आकर पडा था उस पर **बंकिम चन्द्र चटर्जी** ने 'आनंदमठ लिखा' उन्होंने बंगाल की अकाल पडा | उसका वर्णन करते हुए मैंने इसलिए इस पुस्तक को विषादमठ नाम दिया |'

स्वतंत्रता के पश्चात रांगेय राघव , फणीश्वर नाथ रेणु ,जगदीश चन्द्र , लक्ष्मी नारायण लाल , रामदरश मिश्र प्रमुख उपन्यास कर हैं | जिन्होने किसानों की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत किया | स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस्सान जीवां में बहुत से परिवर्तन हुए | जमींदार प्रथा को समाप्त कर दिया गया परन्तु जमींदारों द्वारा कई दशकों से एकत्रित धन संपत्ति और सामाजिक बाहुबलता का प्रयोग किसानों की स्थिति को कमजोर बना रहीं हैं |

जगदीश चन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास ' धरती धन न अपना' पंजाब की दोआब क्षेत्र के दलितों का उपन्यास हैं जिसमें काली प्रमुख पात्र हैं जो चमादड़ी नामक दलित जाति से संबंध रखता हैं और इस कारण सामाजिक तिरस्कार और विकट परिस्थतियों का सामना करता हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चलती हैं अर्थात दलित किसान आर्थिक रूप से इन पर निर्भर हैं | उपन्यास में एक ऐसी घटना का वर्णन हैं जिसमें बाढ़ आने पर दलितों के कुएं का पानी पीने योग्य नहीं रहता परन्तु तब भी जमींदारों द्वारा उनकी कोई सहायता नहीं की जाती हैं |

फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित उपन्यास ' मैला आँचल ' आंचलिक उपन्यास का महाकाव्य हैं | इस उपन्यास का केंद्र बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज हैं जहाँ ग्रामीण किसान के सामजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष को उकेरा गया हैं | जहाँ किस्सान या तो खेत में मजदुर हैं या बटाईदारी पर खेती करते हैं , उन्हें भरपेट भोजन और जीवन यापन की सामान्य सुविधाएँ भी नहीं मिलती हैं | जमींदारों, तहसीलदार द्वारा इनका शोषण किया जाता हैं | किसानों का अशिक्षित , अन्धविश्वासी होना कितना हानिकारक हो सकता हैं इस उपन्यास में साफ़ झलकता हैं |

लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा लिखित उपन्यास 'धरती की आँखें ' जिसमें जमींदारों और किसान का आपसी संघर्ष चित्रित हैं | किसान वर्ग का शोषण , आर्थिक संकट और सामाजिक उपेक्षा को दिखाया गया हैं | इस उपन्यास में किसान की अपनी जीवन रक्षा संघर्षशीलता , जिजीविषा और नैतिक मूल्यों को मार्मिकता से दिखाया गया हैं |

रामदरश मिश्र के उपन्यास 'पानी में प्राचीर ' में प्रमुख रूप से बाढ़ और ऋण समस्या तथा सुखा को दिखाया गया हैं | किसान जीवन की अस्थिरता , शोषण के बीच भी स्थायित्व की तलाश किसानों का प्रतिरोध , संघर्ष के लिए जाग्रत और परिवर्तन को दिखाया गया है |

गुलशेर खां शानी ने एक साल से अधिक समय अबूझमांड के बीहड़ जंगलों में आदिवासियों के बीच बिताया और उनके जीवन को नजदीक से देखा जिसका परिणाम हैं- 'साल वनों का द्वीप' जनजाति किसान जीवन पर आधारित उपन्यास है जो मढ़िया जनजाति हैं किसानों और उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालता हैं |

वीरेन्द्र जैन का उपन्यास 'डूब' तीन तरफ पहाड़ों से और एक तरफ बेतवा नदी से घिरे लडैइ गाँव का उपन्यास हैं जहाँ सरकार बांध बनाना चाहती हैं | माते इसका प्रमुख पात्र है जो अशिक्षित हैं परन्तु अनुभव सम्पन्न और राजनीतिक दांवपेंच को भलीभांति समझता हैं | जब किसानों को मुआवजे की आधी रकम भी नहीं मिलती तब इसी बात से क्षुब्ध होकर माते कहता है "और जो दाम दिए उसमें से भी आधे झपट लिए देने वाली हथेली नीचे रख भाई और मांगने वाले तेरे ऊपर या उल्टा चलन चलो आया इसलिए तो न देने वाले के हाथ में कुछ रह पाया ना पाने वाले तक कुछ पंहुचा सब का सब जा गिरा धरती पर |" (डूब पृष्ट 242) यह उपन्यास बांध बनने के कारण किसानों और उनके ग्रामीण जीवन पर पड़ने वाले दुष्परिणामों पर प्रकाश डालता है |

राजू शर्मा का 'हलफनामे ' 2007 में प्रकाशित हुआ है इस उपन्यास में किसान आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का पूरा प्रयास किया गया है | इस उपन्यास में पानी के संकट को लेकर किसान जीवन की संघर्ष को बताया गया है साथ ही शासन की निर्दयता और असंवेदनशीलता पूरी उपन्यास में दिखाई देगी |

पंकज सुबीर का उपन्यास 'अकाल में उत्सव' 2017 में प्रकाशित हुआ इस उपन्यास में कर्ज की समस्या को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हुए दिखाया गया है | सरकारी योजनाओं व् भ्रष्ट सरकार के कारण उनकी गलत योजनाओ के चलते किसान कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या करते हैं |

कृष्णा सोबती ने अपने उपन्यास 'जिंदगीनामा ' में बीसवीं सदी के आरम्भिक 15 वर्षों के मध्य एकीकृत पंजाब के किसानों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है | किसानों के प्रति संवेदनाएं रखते हुए उनकी समस्याओं को उकेरा जैसे प्रत्येक वर्ष मेहनत करने के पश्चात् भी भरपेट अनाज न मिलना , सूद के कुचक्र में फंस कर जमीन साहूकारों के हाथों में चली जाना |

शोध की प्रासंगिकता :- भारत किसानों का देश हैं, भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कृषि पर ही निर्भर हैं | किसान हमारें देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं | इन उपन्यासों में किसान जीवन की तात्कालिक समस्यों और उनके प्रति विषमताओं व्यस्था का वर्णन किया गया है जो की वर्तमान समय में व्याप्त हैं जिस पर शोध और सुधार की आवश्यकता हैं |

निष्कर्ष:- उपन्यासों में कृषि व्यवस्था और किसानों के जीवन पर विस्तृत और यथार्थ का वर्णन किया गया है | इन उपन्यासों के माध्यम से हम किसान जीवन की तह तक पहुच सकते हैं जिससे आने वाले समय में उनके लिए एक बेहतर योजनायें चला सकते हैं | इन उपन्यासों में बाढ़ , सुखा ,अकाल ,कर्ज, पानी आदि सभी के कारण किसानों की दयनीय स्थिति का यथार्थ चित्रण इन उपन्यासों में किया गया हैं| ऐसे ही सूक्ष्म समस्यों को ध्यान में रखकर उनसे जुड़े पहलुओं पर काम करके बेहतर बनाया जा सकता हैं |

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. कथादेश,मई-2012, सं.-हरिनारायण, अतिथि सं.- सुभाष चंद कुशवाहा, सहयात्रा प्रकाशन,प्रा. लि., दिल्ली, पृ.-16
2. प्रेमचंद का रचना संसार (पुनर्मूल्यांकन), डॉ. सुशीला गुप्ता, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा प्रकाशन, मुंबई, प्रथम संस्करण, पृ.-180
3. प्रेमचंद,कर्मभूमि,डायमंड पॉकेट बुक्स,प्रा.लि.,दिल्ली,संस्करण-2015
4. रांगेय, राघव, विषादमठ, किताबघर प्रकाशन,दिल्ली
5. चंद, जगदीश, धरती धन न अपना, राजकमल प्रकाशन,नई दिल्ली
6. रेणु, फणीश्वरनाथ, मैला आँचल , राजकमल प्रकाशन, दिल्ली,संस्करण 2016
7. लाल, लक्ष्मीनारायण, धरती की आँखे, सेट्रल बुक डिपो प्रकाशन ,इलाहाबाद
8. मिश्र, रामदरश , पानी के प्राचीर , वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली
9. शानी, गुलशेर खां, शाल वनों का द्वीप, सजिल्द संस्करण नेशनल पब्लिकेशन हाउस
10. जैन, वीरेंद्र , डूब, वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली , संस्करण 2014
11. शर्मा, राजू , हलफनामे,राधाकृष्ण प्रकाशन , नई दिल्ली , संस्करण 2007
12. सुबीर, पंकज, अकाल में उत्सव , शिवना पैपरबैग्स , संस्करण 2018
13. सोबती, कृष्णा , जिंदगीनामा , राजकमल प्रकाशन , नई दिल्ली , संस्करण 2019

ईमेल – hemchandsahu00@gmail.com

PRINTED MATTER/PRINTING BOOK CLAUSE 121 (A) P & T GUIDE

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)
द्वारा भिवानी (हरियाणा), काठमाण्डू (नेपाल) से प्रकाशित

ISSN : 2395-7115
Impact Factor 8.642

बोहल शोध मंजूषा
Bohal Shodh Manjusha
AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY, MULTIPLE LANGUAGES
PEER REVIEWED, REFREED RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Website :
www.bohalshodhmanjusha.com
Email : grsbohal@gmail.com

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate
HOD Hindi, Tantia University
M. : 8708822674, 9466532152

गीना देवी शोध संस्थान
द्वारा श्रीगंगानगर, (राजस्थान), पटियाला (पंजाब) व नेपाल से प्रकाशित

ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834

Gina Shodh
SANGAM
A Peer Reviewed & Refereed International Research Journal
Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Website : www.ginajournal.com
Email : grngobwn@gmail.com
Office : 8708822674

Editor :
Dr. Rekha Soni, Vice Principal
Education, Tantia University
M. 9828531975

गिरधारीलाल घासीराम शोधपीठ
द्वारा नई दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद एवं नेपाल से प्रसारित

ISSN : 2348-5639
Impact Factor 6.521

SHODH SAMALOCHAN
AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES QUARTERLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Website : https://ginajournal.com/shodh-samalochan/
Executive Editor : Dr. Varsha Rani M. 9671904323
Managing Editor : Dr. Mukesh Verma M. 9627912535

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate
M. 8708822674

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक गीना शोध संस्थान भिवानी के लिए डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज भिवानी से छपवाकर कार्यालय 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा) से वितरित की।

ISSN 2321:8037